

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

भारतीय-बैंकिंग

[भारतवर्षीय हिन्दी अर्थशास्त्र परिषद द्वारा सम्पादित]

CHECKED 2 MAY 1959

द्वारकालाल गुप्त,

मैनेजर

कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,

रामगंज मंडी

(कोटा-राजपूताना)

भूमिका लेखक

श्री० पं० दयाशंकर जी दुवे, एम० ए०, एल-एल० बी०,
अर्थशास्त्र-अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय

प्रकाशक

राय साहब रामदयाल अगरवाला

२१६ कटरा, इलाहाबाद

प्रथमावृत्ति

सजिले १॥]

जून सन् १९३४ ई०

[सादी १॥]

PRINTED BY K. B AGARWALA AT THE SHANTI PRESS.

NO. 12, BANK ROAD, ALLAHABAD

समर्पण

श्रीमान् बाबू घनश्याम दासजी साहिब गुप्त बी० ए०

चेयरमैन

दी कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोटा,

एवं रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव-सोसाइटीज़

और ज्वाइंट-स्टॉक-कम्पनीज़

कोटा राज्य

के

कर कपलों में

लेखक

की

ओर से

सादर समर्पित

दो शब्द

भारतवर्ष में नियमानुसार बैंकिंग-धन्धा वैदिक काल से चला आ रहा है। यहाँ हँडियों का प्रचलन भी अतीत काल से है। मुद्रा-विनिमय के धन्धे में भी यहाँ के सराफ लोग बड़े प्रवीण माने गये हैं, लेकिन ये सब बातें पुरानी हैं। आज का भारत अपने बैंकिंग-व्यवसाय में दूसरे देशों से बहुत पिछड़ा हुआ है।

भुगल साम्राज्य तक तो भारत का बैंकिंग व्यवसाय पूर्ण रूप से भारतीयों के हाथ में और उत्तम अवस्था में था। इसके बाद जब से यहाँ अंगरेज बणिकों का प्रवेश हुआ तबसे भारत की व्यापारिक प्रणाली में फेर-फारि शुरू हुआ और अंग्रेजों ने अपने सुभीते के लिये जोइन्ट स्टॉक प्रणाली पर बैंक स्थापित करने शुरू किये। इस प्रकार का सबसे पहला बैंक मेसर्स एलेग्जेण्डर एण्ड क० ने सन् १७७० ई० में बैंक ऑफ हिन्दुस्तान स्थापित किया था। इसके बाद कई अंग्रेजी बैंक भारत में खुले, किन्तु कई कारणों से उनको सफलता नहीं मिली, तब यहाँ अच्छे सुसर्गाठित विदेशी-विनिमय बैंकों की शाखाएँ खुलना आरम्भ हुआ। आज इन विदेशी विनिमय-बैंकों का न केवल भारत के समस्त विदेशी व्यवसाय पर ही कब्जा है, बल्कि देश के भीतरी व्यवसाय पर भी इनका शनैः शनैः अधिकार घटता जा रहा है और ये भारतीय बैंकों की उन्नति के मार्ग में बाधक बन रहे हैं।

सन् १७७० से १८७० तक खुलने वाले अंग्रेजी बैंकों में से तीन बँके, बैंक ऑव बँगाल, बैंक ऑव बम्बई और बैंक ऑव मद्रास, सरकारी बैंकिंग धन्धा भी करते थे । इनको नोट जारी करने का अधिकार था जो सन् १८६२ में वापस ले लिया गया । इस १०० वर्ष के समय में बहुत संख्यक बैंक फेल हुए, उनमें बैंक ऑव बम्बई भी शामिल था । इस बैंक की भारत सरकार भी हिस्सेदार थी इसलिये उसको भी हानि उठानी पड़ी । इसका परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने बैंकों के फेल होने के कारणों का अनुसन्धान करने के लिये सन् १८६६ ई० में एक कमीशन नियुक्त किया और उसकी सिफारिश के अनुसार सन् १८७६ ई० में प्रेसीडेन्सी-बैंक एक्ट पास हुआ, तदनुसार उक्त बँगाल, बम्बई और मद्रास बैंक प्रेसीडेन्सी बैंक कहलाये ।

लडाई के जमाने में सरकार को तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों के बजाय एक बैंक कायम करने की आवश्यकता अनुभव हुई और लडाई समाप्त होते ही सरकार ने तीनों बैंकों को मिलाकर सन् १८९१ में एक इम्पीरियल बैंक स्थापित कर दिया । इस बैंक के हिस्सेदारों में अधिक संख्या विदेशियों की है । इसके प्रबन्ध में भी विशेष हाथ अंगरेजों का है । इसलिये यह विदेशियों की अधिक सहायता करता है ।

भारत में अंग्रेजों द्वारा जोइन्ट स्टॉक प्रणाली पर बैंक स्थापित होने के पूरे ११० वर्ष बाद भारतवासियों का इस प्रणाली की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित हुआ और सबसे पहला

भारतीय जोइन्टस्टॉक-बैंक सन् १८८१ ई० में अवध कमिश्नियल बैंक स्थापित किया गया । इसके बाद प्रतिवर्ष सैंकड़ों नये भारतीय जोइन्टस्टॉक-बैंक खुलते गये और उनमें से अनेक काल कवलित होत गये । ५० वर्ष बीत जाने पर भी भारतीय बैंकों के फेल होने का ताँता कम नहीं हुआ और अब तक १०—१५ बैंक प्रतिवर्ष फेल होते रहते हैं । इससे प्रगट होता है कि भारतीय जोइन्ट-स्टॉक-बैंकों का संगठन और प्रबन्ध त्रुटि पूर्ण है और उसमें सुधार होने की गहरी आवश्यकता है ।

जोइन्ट-स्टॉक-बैंकों के अतिरिक्त भारत सरकार ने कृषि को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये सन् १९०४ में सहकारी समितियों की स्थापना के लिये कानून पास किया, जिससे बहुसंख्यक ग्रामीण-सहकारी-समितियाँ खुलीं । इसके बाद सन् १९१२ में उक्त सहकारी कानून में भारी परिवर्तन किया गया जिसके फलस्वरूप यहाँ प्रत्येक ज़िले में सेन्ट्रल-कोऑपरेटिव-बैंकों की स्थापना हुई और तदुपश्चात ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक खुले ।

उक्त वर्णित बैंकिंग संस्थाओं के अतिरिक्त पोस्टऑफिस सेविंग्स बैंक और जीवन-बीमा कम्पनियाँ भी बैंकिंग संस्थाओं के अन्तर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें सर्व साधारण की वचत अधिक संख्या में जमा होती है । अस्तु भारत में निम्न लिखित ६ प्रकार की बैंकिंग संस्थाएँ हैं :—

नाम	कुल दस्त
(१) विदेशी विनिमय बैंक	==
(२) इम्पीरियल बैंक	१६=
(३) जोइन्ट स्टॉक बैंक	६५०
(४) कोऑपरेटिव बैंक :—	
(अ) ग्रामीण समितियाँ	१ लाख
(ब) सेण्ट्रल बैंक*	६००
(स) प्रान्तीय बैंक*	=
(५) पोस्ट आफिस से० बैंक	१२३३६
(६) बीमा कम्पनिया :—	
(अ) देशी	१३०
(ब) विदेशी	१४७

भारत जैसे विशाल देश के लिये, जिसके सात लाख ग्रामों में सत्तर की पंचमांश जन संख्या निवास करती है, उक्त बैंकिंग संस्थाएँ बहुत कम संख्या में हैं । दूसरे देशों में, जो क्षेत्रफल और जन संख्या में भारत से बहुत छोटे हैं, यहाँ से कई गुने अधिक बैंक हैं । इतना ही नहीं विदेशों के अच्छे बड़े एक बैंक की पूँजी और जमा शुदा अमानतों से यहाँ के सब जोइन्टस्टॉक बैंक मिल कर भी मुकाबला नहीं कर सकते ।

* इनकी शाखाएँ अलग हैं—

भारतीय बैंकिंग का इतिहास पढ़ने के बाद प्रत्येक पाठक के हृदय में निम्नलिखित प्रश्नों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है—

- (१) उक्त वर्णित मित्र मित्र धेणी के बैंक क्या-क्या काम करते हैं ?
- (२) वर्तमान बैंक भारत के देशों और विदेशी व्यापार, कृषि तथा अन्य उद्योग-धन्यों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिये पर्याप्त हैं या नहीं ?
- (३) भारतीय बैंक प्रतिवर्ष क्यों फेल होते हैं ?
- (४) भारतीय बैंकों की उन्नति के मार्ग में क्या-क्या बाधाएँ हैं ?
- (५) भारतीय बैंकों के संगठन और प्रबन्ध में क्या-क्या त्रुटियाँ हैं ?
- (६) वे कौन-कौन से उपाय हैं, जिनको पूरा करने से, भारतीय बैंक त्रुटियों और बाधाओं से मुक्त होकर, भारत के देशी-विदेशी व्यापार, कृषि तथा अन्य उद्योग-धन्यों को यथोचित सहायता देने, वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने और सर्व साधारण की आर्थिक दशा सुधारने में, पूर्ण-रूप से समर्थ हो सकें ?

प्रस्तुत पुस्तक में, भारतीय बैंकिंग के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास के समुचित वर्णन के साथ-साथ उक्त प्रश्नों का

यथोचित उत्तर देने का भरसक प्रयत्न किया गया है। आशा है पाठक गण इसके अध्ययन से सतुष्ट होंगे।

श्री जगदीश्वर की असीम कृपा का फल है कि मैं इस पुस्तक को हिन्दी भाषा भाषियों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ। इसका श्रेय हिन्दी के परमभक्त श्री प० दयाशङ्कर जी दुवे एम० ए० एल एल० बी० अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय को है, जिनके बार बार प्रेरणा करने और सहायता प्रदान करने से मैं इस पुस्तक को लिखने में समर्थ हुआ हूँ।

मैंने यह साहस केवल हिन्दी में इस विषय की पुस्तकों का सर्वथा अभाव देखकर किया है, और वह भी इसलिये कि हिन्दी के विद्वान लेखकों का इस ओर ध्यान आकर्षित हो और इस महत्वपूर्ण और सर्व साधारण के जानते योग्य अत्यन्त आवश्यक विषय पर सुन्दर-सुन्दर उपयोगी पुस्तकें लिखी जायें।

मेरा यह प्रथम प्रयास है इसलिये इस पुस्तक में अनेक प्रकार की त्रुटियाँ रहना स्वाभाविक है, आशा है उनके लिये पाठक गण मुझे क्षमा करेंगे। जो विद्वान पाठक इसकी त्रुटियों से मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे उनका मैं बहुत ही अनुगृहीत होऊँगा।

मैंने इस पुस्तक के लिखने में जिन जिन पुस्तकों, सरकारी रिपोर्टों और पत्रों की सहायता ली है उनकी सूची अन्त में दी गई है। अस्तु मैं उन सब के लेखकों, सम्पादकों और प्रकाशकों का बहुत ही उपकृत हूँ, लेकिन श्री० बी० टी० ठाकुर, श्री० एम०

एल० टेनन, श्री० लक्ष्मी चन्द्र जैन, सर्व भारतीय और प्रान्तीय वैकिङ्ग इंक्वायरी कमेटियों के सदस्यों और इण्डियन फाइनेन्स तथा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ् वैडर्स के जरनल के सम्पादकों और लेखकों का मैं विशेष रूप से अनुगृहीत हूँ, क्योंकि मैंने सबसे अधिक सहायता इन महानुभावों की पुस्तकों, रिपोर्टों और पत्र-पत्रिकाओं के लेखों से ली है। ये समस्त पुस्तकें मुझे सहकारी विभाग, कोटा से प्राप्त हुई हैं इसलिये मैं इन विभाग के माननीय अधिकारियों का भी बहुत कृतज्ञ हूँ।

इनके अतिरिक्त मैं भारतीय लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली के माननीय प्रेसीडेण्ट, भावनगर राज्य के श्री दीवान साहब और कनाडा के जनाब डिप्टी फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का भी बड़ा आभारी हूँ। इन महानुभावों ने मुझे, साधारण सी प्रार्थना पर सरकारी बिल और रिपोर्टें प्रदान करने की अपरमित कृपा की है। जिससे मैं इस पुस्तक को अधिक उपयोगी बना सका हूँ।

श्री राय साहब लाला रामदयाल जी अगरवाला ने इस पुस्तक का प्रकाशन भार स्वीकार करके मेरे बोझ को हलका किया है इसलिये मैं आपका भी बहुत ही अनुगृहीत हूँ।

अंत में, मैं अपने उन तमाम मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस पुस्तक के लिखने और प्रूफ देखने आदि में बहुत सहायता दी है।

यदि मेरे इस छोट्टे से और नवीन प्रयत्न को हिन्दी भाषी-
भाषियों ने अपनाने की कृपा की तो मैं शीघ्र ही इस प्रकार की
दूसरी भेंट लेकर उपस्थित होऊँगा ।

रामगञ्ज मंडी (कोटा राज्य) }
ता० २६ जून सन् १९३४ ई० }

विनीत,
द्वारका लाल गुप्त

भूमिका

हिन्दी में अर्थशास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों की बहुत कमी है। इस विषय के कुछ अंग तो, ऐसे हैं जिन पर एक भी उत्तम पुस्तक अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है।

वर्तमान काल, में बैंक आर्थिक उन्नति का प्रधान साधन है। इसलिये बैंक सम्बन्धी, कार्यों का विवेचन अर्थशास्त्र का, प्रधान अंग माना जाता है। यद्यपि भारतीय बैंकों के सम्बन्ध में संक्षिप्त रूप से विवेचन हिन्दी की अर्थशास्त्र सम्बन्धी कुछ पुस्तकों में थोड़ा-बहुत दिया हुआ है, इस विषय पर हिन्दी में कोई स्वतन्त्र पुस्तक मेरे देखने में अभी तक नहीं आई। अंग्रेजी में इस विषय पर सैकड़ों उत्तम पुस्तकें हैं और भारतीय बैंकों के सम्बन्ध में भी पुस्तकें अब निकलने लगी हैं। हिन्दी में इस विषय की उत्तम पुस्तक का अभाव खटकता था। हर्ष की बात है कि हिन्दी के होनहार लेखक श्रीमान् द्वारकालाल जी गुप्त ने इसी कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया है।

मैंने इस पुस्तक की पांडुलिपि आदि से अन्त तक पढ़ी और मुझे वह बहुत पसंद आई। पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी गई है और उसमें भारतीय बैंक सम्बन्धी प्रायः सब आवश्यक बातों का समावेश कर दिया गया है। पुस्तक पढ़ने से मालूम

होता है कि श्रीमान् गुप्त जी को बैंक सम्बन्धी व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त है और उन्होंने अङ्गरेजी के बैंक सम्बन्धी पुराने और नवीन साहित्य का विद्वतापूर्वक उपयोग करने का पूर्ण प्रयत्न किया है ।

हिंदी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिये यह ग्रंथ विशेषरूप से उपयोगी होगा । अङ्गरेजी विश्वविद्यालयों के बी० ए० और एम० ए० के विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ होगा । आशा है, हिंदी सस्यार इस उत्तम पुस्तक का उचित आदर कर लेखक को अर्थशास्त्र सम्बन्धी अन्य उत्तम पुस्तक लिखने के लिये उत्साहित करेगा ।

दयाशङ्कर दुबे

दारागंज, प्रयाग } अर्थशास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय,
 विजया दशमी, १९२६ } समापति,
 ६ अक्टूबर, १९३२ } भारतवर्षीय हिंदी अर्थशास्त्र परिषद्

सहायक पुस्तकों और पत्रों की सूचि

पुस्तके

- (१) Organization of Indian Banking by
B T Thakur
- (२) Indigenous Banking in India by L C Jain
- (३) Banking Law and Practice in India by
M L Tannan
- (४) Regulation of Banks in India by M L
Tannan
- (५) Bank organisation Management and accounts
by J F Davis
- (६) Banking and currency by Sykes
- (७) Theory and practice of Banking by macleod
- (८) Rupee Problem by Dr. Ambedkar
- (९) Foreign Exchange in India by N S Aiyar
- (१०) Banking by Dr Walter leaf
- (११) Sixty years of Indian Finance by K T Shah
- (१२) Indian economics by Jathar and Beri
- (१३) Law and Practice of Banking by Davar
- (१४) Co operative movement in India by Eleanor
M Hough

- (१५) Co-operation in India and abroad by S S Talmaki.
- (१६) Co-operation in India Edited by H L Kaji
- (१७) ऋग्वेद } ये पुस्तकें मेरे पास से
- (१८) मनुस्मृति } काम। तिबटते ही चली गईं
- (१९) याज्ञवल्क्यस्मृति } इसलिये इनके भाष्यकारों
- (२०) महाभारत समापर्व } और टीकाकारों के नाम देते
- (२१) कौटिल्य अर्थशास्त्र } मैं असमर्थ हूँ । ले०—
- (२२) अष्टादश स्मृति ।
- (२३) विदेशी-विनिमय—लेखक श्री प० दयाशंकर जी दुबे ।

सरकारी रिपोर्टें

- (२४) Royal Commission on Agriculture in India 1926
- (२५) Central Banking Enquiry Committee (1931) Para I and II (Minority report by Mann Subedar).
- (२६) Reports of Provincial Banking Enquiry committees.
- (२७) Indian Insurance year book 1931.
- (२८) Statistical tables relating to Banks in india 1928—30.

- (२९) Report of the Khedut Debt inquiry Committee, Bhavnagar State 1931,
(३०) Reserve Bank of India Bill 1933

पत्र पत्रिकाएँ

- (३१) Indian Finance Calcutta
(३२) *The Journal of the Indian Institute of Bankers*, Bombay.
(३३) Times of India, Bombay
(३४) Bombay Chronicle Bombay
(३५) Hindustan Times, Delhi
(३६) 'स्वार्थ' काशी के पुराने श्रद्ध ।
-

विषय-सूची

विषय

पृष्ठ

प्रथम अध्याय

विषय-प्रवेश ... १—८

बैंकिंग प्रथा का श्रीगणेश—'बैंक' शब्द की उत्पत्ति, बैंकर की व्याख्या, भारतीय बैंकर की व्याख्या ।

दूसरा अध्याय

प्राचीन भारत में बैंकिंग-प्रथा ... ९—१५

वैदिक-काल—सूत्र-काल, स्मृति-काल, महाभारत-काल, मुगल साम्राज्य-काल ।

तीसरा अध्याय

भारत में आधुनिक बैंकिंग ... १६—६७

आरम्भ और विकास

जोइन्ट-स्टॉक-बैंक—असीमित ज़िम्मेदारी पर, सीमित ज़िम्मेदारी पर, अंगरेज़ी प्रयत्न, भारतीय प्रयत्न ।

विदेशी-विनिमय-बैंक—

इम्पीरियल-बैंक—हेड आफिस और शाखाएँ, संगठन, सरकारी हस्तक्षेप, काम-पहला भाग (वे धन्ये जो बैंक कर सकता है), दूसरा भाग (वे धन्ये जिनके बैंक का अधिकार बैंक को नहीं है) ।

विषय

पृष्ठ

कोऑपरेटिव-बैंक—ग्रामीण समितियाँ, सेन्ट्रल-बैंक,
ग्रान्तीय-बैंक ।

भूमि-बन्धक-बैंक, पोस्टऑफिस सेविंग्स-बैंक, बोमा
कम्पनियाँ, क्लियरिंग हाउसः—मेम्बर बैंक, जेन-देन
का तरीका ।

चौथा अध्याय

प्रचलित साख-पत्र ...

६८—६०

हुण्डी—ग्याख्या, उद्देश्य, श्रेणियाँ, धनी-जोग, शाह-जोग
फरमान-जोग, देरवाडनार-जोग, मुहती, जोखमी हुण्डी,
रिआयती दिन, क्लिया-बेची, भाव में कमी वेशी के
कारण, लिखना, बेचाण करना, खेणी भैजी, बटावणी
भैजी, हुण्डी बेची, विशेष बेचाण, सिरा या अंदास,
निशाणी, उपस्थित करना, प्रतिलिपियाँ, टयान कमाना ।
पुर्जा, प्रोमेसरी नोट, चेक—ग्याख्या, श्रेणियाँ—बेपरर,
प्रॉवर ।

बैंक-ड्राफ्ट—बिल ऑफ़ एक्सचेन्ज ।

एन्डोर्समेन्ट अथवा बेचाण—पुर्जा पर, अंगरेजी में
लिखे साख पत्रों पर, खाली एन्डोर्समेन्ट, विशेष
एन्डोर्समेन्ट, सीमित एन्डोर्समेन्ट ।

पाँचवाँ अध्याय

बैंक और उद्योग धन्धे ...

६१—६५

भारत में, जर्मनी में, अमेरिका में, इंग्लैण्ड में, जापान में ।

विषय

पृष्ठ

छठवाँ अध्याय

बैंक और विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता ६६—१०३

भारत का विदेशी-व्यापार—विदेशी बैंक, जातीय मेद-
भाव ।

सातवाँ अध्याय

कृषि और बैंक ... १०४—१११

भारत में, छोटी अवधि के लिये—जर्मनी में, फ्रांस में,
इंग्लैण्ड में, संयुक्त राज्य अमरीका में, लम्बी अवधि
के लिये:—इंग्लैण्ड में, सीबोन में, संयुक्त राज्य अम-
रीका में, फ्रान्स में, जर्मनी में, आस्ट्रेलिया में,
जापान में ।

आठवाँ अध्याय

पिछड़ी हुई अवस्था और उसके कारण ११२—१२७

पिछड़ी हुई अवस्था—विदेशों से तुलना:—दुश्तरों की
संख्या से, मूलधन से, अमानतों से ।

कारण—विदेशी-बैंकों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध, बैंकों
का प्रति वर्ष अधिक संख्या में फेल होना । भारत
सरकार की उदासीनता, अंगरेज़ी भाषा का प्राधान्य ।

नवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-बैंक कानून १२८—२११

कानून की आवश्यकता—वर्तमान कानून, तथा कानून,

भारत में बैंक कानून की मांग, कानून का उद्देश्य :—

विदेशी बैंकों के लिये प्रतिबन्ध लगाना—कार्य-क्षेत्र सीमा (अन्य देशों में) अन्य प्रतिबन्धः—डेनमार्क, फ्रान्स और इटली, जेको-स्लेवेकिया, जापान, टर्की, संयुक्त राज्य अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा, में, जॉर्जसेन्स की आवश्यकता, जॉर्जसेन्स की रोक, अमानतों की रोक, जमा रखनेवाले का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्ति और राष्ट्र, सरकार और व्यक्तिगत सम्पत्ति, क्रमेणारी, परामर्श मण्डल, खेसा-ओसा, दिवाला निकलने पर, टेक्स, विशुद्ध भाव ।

भारतीय बैंक सम्बन्धी कानून—दूर करने योग्य-द्रुतियाँ, उपयुक्त संगठन—जॉर्जसेन्स की आवश्यकता, बैंक शब्द का प्रयोग, दूसरे धन्धे की रोक, मैनेजिंग एजेन्सी प्रथा, आपत्ति जनक नियमों की रोक, मूलधन अमरीका में, जापान में, कनाडा में, भारत के लिये, भारतीय-करण ।

उत्तम प्रबन्ध—व्यवस्थापक मण्डल, जमा करने वालों का प्रतिनिधित्व, प्रोबसीः—इंग्लैण्ड में, कनाडा में, भारत

विषय

पृष्ठ

में, वैयक्तिक मताधिकार, रोशन रखना, रुपया खगाना, ऋण देना:—डाइरेक्टरों को, कर्मचारियों और आडिटरों को, कनाडा में, भारत में; अपने हिस्से की जमानत पर ऋण, एजेन्सी, ट्रस्ट व्यवसाय, रक्षार्थ वस्तुएँ जमा करना, लाभ वितरण:—अमरीका में, जापान में, कनाडा में, इटली में, भारत में ।

निरीक्षण—कनाडा में, जापान में, संयुक्तराज्य अमरीका में, भारत में, सरकारी निरीक्षण का प्रश्न, सरकारी निरीक्षण से लाभ; बैलेन्स शीट:—अमानतों का प्रयत्न-करण, लगे हुए रुपयों का प्रयत्न करण, फार्म का समूचा, मासिक स्थिति-सूचक पत्र; बैंकों की रक्षा:—इसलों से, मुकदमों से ।

दसवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-भारतीय विनिमय-बैंक २१२—२२०
आवश्यकता, विनिमय के धन्धे में जोखिम, मूलधन, सरकारी भुगतान का काम ।

ग्यारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-सेन्ट्रल या रिज़र्व-बैंक २२१—२३८
करेन्सी का इतिहास, क्रेडिट और करेन्सी का सम्बन्ध, करेन्सी और क्रेडिट की संचालन विधि, भारत में सेन्ट्रल बैंक का मांग, रिज़र्व-बैंक का संगठन:—मूलधन, सेन्ट्रल-

विषय

पृष्ठ

बोर्ड, स्थानीय बोर्ड, जनरल मीटिंग, शाखायें, कार्य,
कृषि की सहायता, समालोचनाः—कृषि प्रतिनिधित्व,
प्रबन्ध, रुपये का मूल्य ।

बारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय-कृषि-सहायक-बैंक २३६—२६२

कृषि की महिमा—सहायता को आवश्यकता, थोड़ा
अवधि के लिये—सहकारी समितियाँः—सहकारी
समितियाँ और साहूकारों में अन्तर, सहकारी समितियाँ
और ज्वान्ट स्टॉक बैंकों में अन्तर, भारत में सहकारी से
आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, राजनैतिक लाभ,
सफलता और असफलता, २० साला स्कीम, पिछड़ा
अनुभव, रजिस्ट्रार, ग्राम्य कर्मचारी, ग्राम, मेम्बर, उधार,
निरीक्षण, व्याज, सरकारी अफसरों का सहयोग, सार्व-
जनिक सेवकों का सहयोग, समय पर अदायगी न होने
का प्रश्न, कृषी घाटे का धन्धा है, ऋण का भारी बोझ,
बढ़ी कठिन समस्या और हल करने के उपाय ।

तेरहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय, भूमि बन्धक बैंक २६३—२७६

ग्रामी अवधि के लिये—भारत के अनुकूल प्रणाली,
भारतीय भूमि बन्धक बैंकों का संगठनः—मूलधन,
हिस्सेदारों का अधिकार, बोर्ड का संगठन, प्रबन्ध, उधार,

विषय

पृष्ठ

उधार की जमानत, मार्जिन, ऋण की वापसी, ऋण की अवधि, कार्य-कर्त्री-पूँजी प्राप्त करने के तरीके:—अमानतें और सेविंग्स सर्टिफिकेट, डिबेन्चर जारी करना:—उधार लेना, सरकारी सहायता, कानूनी सुविधायें, काम का विभाजन और रिज़र्व फंड, लेण्ड-क्रेडिट-बोर्ड ।

चौदहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—ओद्योगिक बैंक २७७—२८५

ओद्योगिक-संस्थाओं को आर्थिक सहायता—स्थायी सहायता, कार्याय सहायता, ग्राम्तीय ओद्योगिक बैंकों का संगठन:—मूलधन, काम, इन्वस्टिगल क्रेडिट-बोर्ड ।

पन्द्रहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—अन्य प्रयत्न २८६—२९६

पोस्टऑफिस सेविंग्स बैंक में सुधार—चेक द्वारा जमा व बरामद, वार्षिक जमा की सीमा, अधिक से अधिक जमा की सीमा, जमा शुदा रकम की कुर्की, ग्रामीण जनो को सुविधा ।

बैंकर्स एसोशियेशन

देशी भाषाओं को अपनाया जावे—

सोलहवाँ अध्याय

उपसंहार ... २९३—२९७

परिशिष्ट नं० १—साख-पत्र ।

परिशिष्ट नं० २—स्थिति-सूचक-पत्र ।

परिशिष्ट नं० ३—शुद्धि पत्र ।

भारतीय बैङ्किङ्ग

पहला अध्याय

विषय-प्रवेश

बैंकिंग प्रथा का श्रीगणेश—प्रत्येक देश की आर्थिक उन्नति उसकी उत्पादन-शक्ति पर निर्भर होती है, और उत्पादन-शक्ति, निर्भर होती है उत्पादन के साधन, भूमि, मज़दूरी और पूँजी के संगठन की श्रेष्ठता पर। इन तीनों साधनों में पूँजी एक साधन है, जिसके बिना शेष दोनों साधन निष्फल हो जाते हैं। जिस देश में पूँजी की प्रचुरता होती है, यही अपने उद्योग धंधों की उन्नति करके अपनी समृद्धि बढ़ा सकता है और जिसमें पूँजी की कमी होती है, उसमें भूमि की उत्तमता, सब प्रकार के खनिज पदार्थों का बाहुल्य और संसार के श्रेष्ठ कारोबार होते हुए भी बेकार हैं। पूँजी की प्रचुरता करके उत्पादन के शेष साधनों को गति देना ही बैंकों का प्रधान उद्देश्य है और इसके सुसंगठन पर ही प्रत्येक देश और जाति की आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक उन्नति निर्भर है।

मानव-समाज के आरंभिक काल में जब सिन्कों का चलन नहीं था, लोगों के पास अपनी पैदा की हुई सामग्री को तुरन्त उपयोग में लाने का कोई साधन नहीं था और हर एक परिवार अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुयें रखता था। उस समय जिन व्यक्तियों को किसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, यह इस शर्त पर उधार दे दी जाया करती थी कि उसी या दूसरी किस्म की उसी क्मीमत के बराबर चीज़ थोड़े समय बाद वापिस कर दी जावेगी, उदाहरणार्थ जो व्यक्ति ऊँई पैदा करता था, कुछ संख्या में कतईयों और जुलाहों को उधार दे दिया करता था और सूत या कपड़े के रूप में वापिस ले लिया करता था। यह लेन-देन पहले सीधा लेने और देनेवाले के बीच में होता था। तत्पश्चात् समाज ने उन्नति की, पहली सीढ़ी से आगे क़दम बढ़ाया, तो वस्तुओं के संग्रह-कर्त्ताओं के लिये, उधार लेनेवाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्राप्त करना सुविधा-रहित और कष्टप्रद हो गया; तब लेने और देनेवालों के बीच एक विशेष धंधा करनेवालों की सृष्टि हुई। यह लोग आवश्यकताओं से अधिक सामग्री लोगों से लेकर उन व्यक्तियों को, जिनको उनकी आवश्यकता होती थी, उधार देने का धंधा करने लगे। यही बीच के आदतिया आजकल के हमारे बैंकर हैं, जिनको बनिये, महाजन, चेष्टी, साहूकार, बोहरा, इत्यादि कहा जाता है।

बैंक शब्द की उत्पत्ति—इस विषय के कई विद्वानों का मत है कि बैंक (Bank) शब्द इटली के बैंको (Banco),

बैंक्स (Bancus) या बैंक (Banque) शब्दों से बना है; क्योंकि इन शब्दों का अर्थ है बैञ्च, टेबल या काउण्टर और इन पर सर्राफ लोग (Money Changers या Money dealers) भिन्न-भिन्न राशियों के सिक्के विनिमय करने के वास्ते फैलाया करते थे। मिस्टर गिलबर्ट ने इसका समर्थन करते हुए लिखा है कि लोम्बार्डी में यहूदी (Jews) बाज़ार में रुपये तथा हुण्डियों का विनिमय करने के लिये बैञ्च रखते थे। जब एक सर्राफ (Banker) दिवालिया निकाल देता था तो उसकी बैच सर्व-साधारण द्वारा बाज़ार में से हटा दी जाती थी। इसी कारण हमने बैंकrupt (Bankrupt) या दिवालिया शब्द अपना रखा है, किन्तु मिस्टर हेनरी ड्रिंग मेकलायड ने बैंक शब्द की उक्त उत्पत्ति पर आपत्ति प्रगट करते हुए यह बतलाया है कि इटली के सर्राफ कभी भी बैञ्चरी (Banchieri) नहीं कहलाये। कितने ही दूसरे विद्वानों का मत है कि बैंक जर्मन शब्द (Bank) का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ उवाइएट स्टाक फंड है और इटली का शब्द बैंको भी जर्मनी के उक्त शब्द से बना है, जिसका सबसे पहले ब्रेसिया (Brescia) नामक क़स्बे में दूकान के अर्थ में उपयोग किया गया है।

बैंकर की व्याख्या—इस विषय के विद्वानों ने बैंकर के भिन्न-भिन्न अर्थ किये हैं, अभी तक न तो किसी विद्वान् ने ही इसका निश्चित अर्थ बतलाया और न क़ानून में ही इसकी स्पष्ट और पूर्ण व्याख्या बतलाई गई। डाक्टर वाल्टर लीफ़

को, जो कि स्वयं भी एक बैंक के अनुभवी चेयरमैन हैं, वैडूर की आम व्याख्या करना असम्भव मालूम हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक में मिस्टर गिल्वर्ट द्वारा हाउस आव् कामन्स में सन् १७४६ ई० में दिये गये एक व्याख्यान से उद्धृत की हुई व्याख्या दी है, वह इस प्रकार है —

“रिवाज के अनुसार हम बैंकर उस व्यक्ति को पुकारते हैं, जो गुमाशतों, काउण्टर्स और यहीखातों के साथ व्यवस्थापूर्वक एक दुकान खोलकर बैठता है और दूसरे आदमियों का रुपया सुरक्षित रखने के लिये जमा करता है और माँगने पर वापस करता है।” गिल्वर्ट स्वयं वैडूर का अर्थ यह करते हैं—

“वैडूर एक व्यापारी है, जो पूँजी और रुपये का लेन-देन करता है, वह फ़र्ज़ लेने और देनेवालों के बीच में मध्यस्थ है, क्योंकि वह एक पार्टी से फ़र्ज़ लेता है और दूसरी को देता है और उसके जमा रखने और उधार देने की दरों में जो अन्तर होता है, वही उसकी कमाई है।” कानून में इसकी एक व्याख्या फ़ाइनैन्स ऐक्ट सन् १८१७ ई० में मिलती है—“वैडू एक व्यक्ति या संस्था है, जो दक्कीकत में (Bonafide) वैद्विज्ञ व्यवसाय करता है।” इसके अतिरिक्त कानून नुडियात (Negotiable Instrument act 1881) की दफ़ा ३ में वैडूर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है —

“वैडू में वे व्यक्ति, संस्थाएँ और कम्पनीज़ शामिल हैं, जो बतौर वैडू के काम करते हैं।” किन्तु बैद्विज्ञ धंधा क्या

है, यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया। अब तक जो भी बैंकर की व्याख्यायें ऊपर बताई गई हैं, वे लगभग सभी अपूर्ण मालूम होती हैं, क्योंकि बैंकों के काम केवल जमा रखने और जमा-शुदा अमानतों को माँगने पर वापस देने तथा उधार देने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि और भी ऐसे अनेक काम हैं, जो बैंक करते हैं, जैसे—चेक, बिल, हुंडी द्वारा रुपया इकट्ठा करना, एक जगह से दूसरी जगह रकम का भुगतान करना तथा विदेशी व्यापार के लहने पावने को चुकाना और वसूल करना इत्यादि। मिस्टर एम० एल० टेनन ने अपनी पुस्तक “बैंकिंग लॉ ऐण्ड प्रैक्टिस इन इण्डिया” में इस विषय के कई विद्वानों के कहे हुए बँकर के अर्थ उद्धृत किये हैं; किन्तु इस शब्द का जो अर्थ भारतीय तथा अंग्रेजी विद्वानों ने किया है, उन सबकी अपेक्षा अमेरिका के संयुक्त राज्य के कानून-रचयिताओं ने जो निम्न-लिखित व्याख्या की है, वह अधिक सफल मानी जाती है :—

“बैंक में हम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति अथवा दूकान अथवा कम्पनी को शामिल करते हैं, जिनका कारोबार किसी निश्चित स्थान पर हो, जहाँ सदैव वापस देने के लिये अमानतें, रुपयों का संग्रह या सिक्के जमा रखें (क़र्ज़ लिये) जाते हों और जिनका भुगतान हुंडी, चेक या हिदायत (Order) द्वारा किया जाता हो और जहाँ पर हिस्से (Stocks) बोण्ड, सोने, चाँदी के डलों, हुंडियों और प्रोमेसरी नोटों पर उधार दिया जाता हो या प्रोमेसरी नोट, डिस्काउण्ट या बेचने के लिये लिये जाते हों”।

इससे भी अधिक स्पष्ट बैंकिंग घन्धे की व्याख्या ब्रिटिश सरकार द्वारा सन् १९१८ ई० में शत्रु देश के बैंकिंग घन्धे को रोकने के लिये बनाये हुए नियमों में की गई है, * यथा—

“चालू खातों में या अमानत के तौर पर रुपया जमा करना; विनिमय-बिल स्वीकार करना, विनिमय-बिल, प्रोमेसरी नोट तथा ड्राफ्ट खरीदना, बेचना, संग्रह करना और उनका लेन-देन करना; सूद तथा मुनाफ़ों के स्वीकार पत्र बेचना या इनकी रकम संग्रह करना; विदेशी तारकी अथवा दूसरे प्रकार की हुंडियाँ खरीदना और बेचना; जारी-शुदा फ़र्ज़, शेयर या लिफ्टरिटीज़ को मेम्बर होकर लेने (Subscriptions) खरीदने या अएडरराइट करने के लिये जारी करना; व्यापार या औद्योगिक काम के लिये फ़र्ज़ देना या फ़र्ज़ दिये जाने का प्रबन्ध करना या साख-पत्र (Letter of credit) और चलते फिरते नोट (Circular Note) देना या जारी करना।”

भारतीय बैंकर की व्याख्या—पाश्चात्य विद्वानों द्वारा बैंकर अथवा बैंकिङ्ग व्यवसाय की जो व्याख्या की गई है, वह भारतीय देशी बैंकर के लिये पूर्ण रूप से घटित नहीं होती है, क्योंकि सभी देशों बैंकर न तो अमानतें जमा रखते हैं, न सभी हुंडियों का कारोबार करते हैं और न सभी उधार ही देते हैं। कुछ जमा रखते हैं, कुछ उधार देते हैं, कुछ हुंडियों का कारो-

वार करते हैं; बहुत से जमा नहीं रखते और केवल अपनी ही सम्पत्ति उधार देते हैं; बहुत से ऐसे हैं, जो जमा भी नहीं रखते और उधार भी नहीं देते और केवल हुंडियों का ही काराबार करते हैं तथा इसके साथ दूसरा भी धन्धा करते हैं। इस तरह केवल कर्ज देनेवाले (Money Lender) और बैंकर मिश्रित हो रहे हैं और लगभग सभी बैंकर सम्मिलित लिये जाते हैं। हालांकि मनीलेण्डर बैंकर नहीं कहे जा सकते; परन्तु इसका अन्तर करना थड़ा कठिन है। कानून में भी इनकी व्याख्या नहीं पाई जाती और न मर्दमशुमारों की किसी रिपोर्ट में ही इनका पृथक्करण किया गया है। अभी हाल में पंजाब प्रान्तीय बैंकिंग एम्बवायरी कमेटी (१९३०) ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नं० १६६ में मनीलेण्डर और बैंकर का अन्तर बताते हुए लिखा है —

“देशी बैंकर, बैंकिंग और व्यापार सम्मिलित रूप से करता है; किन्तु उसका प्रधान धन्धा बैंकिंग ही होता है। यह विशेष अन्तर है। इसके अतिरिक्त दूसरे अन्तर भी इसी प्रकार के हैं, जैसे—देशी बैंकर केवल खुल्ली उधार देने की अपेक्षा व्यापार और उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता अधिक रूप से देता है और मनीलेण्डर व्यापार की अपेक्षा खुल्ली उधार ज्यादा देता है। बैंकर और मनीलेण्डर दोनों कुछ तो ज़मानत पर और कुछ बिना ज़मानत पर उधार देते हैं। इन दोनों में, बैंकर जिन-जिन कामों के लिये उधार चाहा जाता है, उनके लिये विशेष सावधान रहता है, किन्तु मनीलेण्डर इसकी कम परवाह

करता है। पिछले दो कारखों से और भी अन्तर यह मालूम होते हैं कि बैंकर के अधिकांश खातेदार चांदे पर रुपया चुकाते हैं। 'मनीलेण्डर' के अधिकांश खातेदारों से अधिक तकाज़े और दबाव से रुपया वसूल होता है; इसीलिये बैंकर ६ से ६ प्रतिशत सुद पर उधार देता है। ऐसे अवसर बहुत कम होते हैं, जब १२ प्रतिशत से अधिक लेता है; किन्तु मनीलेण्डर आम तौर पर ६ से १२ प्रतिशत व्याज पर उधार देता है और १८ प्रतिशत तक पहुँच जाता है।”

इन सब कठिनाइयों पर प्रकाश डालते हुए बैंकर और मनीलेण्डर का अन्तर बतलाते हुए जो व्याख्या डाक्टर जैन ने की है, वह युक्ति-युक्त है —

“बैंकर का यह अर्थ लेना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति या प्राइवेट फ़र्म जो उधार देती हो या जमा रखती हो या हुंडियों का कारबार करती हो या दोनों काम करती हो, जिसमें से प्रत्येक काम बैंकिंग की सीमा में आता हो” “मनीलेण्डर शब्द का उपयोग उन व्यक्तियों या फ़र्मों के लिये किया जावेगा, जो उधार देते हों, किन्तु आम तौर पर जमा न रखते हों और न हुंडियों का कारोबार करते हों”।



दूसरा अध्याय

प्राचीन भारत में वैदिक काल की प्रथा

वैदिक काल—यदि कोई भारतीय वैदिक काल का प्राचीन इतिहास अध्ययन करने में थोड़ा भी समय लगावे तो उसे यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में यह धन्या अनादि काल से अर्थात् मानव समाज की सस्कृति के विकास के आरम्भिक काल से प्रचलित है। इसकी प्राचीनता की दौड़ में संसार का कोई भी देश भारत की समानता नहीं कर सकता। इस देश में यह धन्या वैदिक काल में अर्थात् ४०००—२००० बी० सी० के बीच में आम तौर से होता था। इसका पूरा दिग्दर्शन इस विषय के विशेषज्ञ श्री० डा० लक्ष्मीचन्द जी जैन ने अपनी पुस्तक (Indigenous Banking in India) में कराया है। आपने कई प्रमाण देते हुए लिखा है कि ऋग्वेद और उसके बाद ऋण शब्द कई दफा आया है। जुवा खेलने के लिये ऋण लेने के विषय में बहुधा हवाले दिये गये हैं। * ऋण का चुकाना “ऋण सामनो” कहलाता था।

* यद्वस्ताभ्या चक्रेम किल्बिषायचार्णा—

—गलु मुपलिप्स माना । उग्रपरये उग्र जितौ—

सद्घाप्सर सावतु दत्ता मृणं न ॥ छठा काण्ड सूत्र ११८

अर्थात् धन के लोभ से जब जब हम जुवा आदि कामों में हाथ डालें तब तब प्रगट की हुई व्यवस्थापक सस्याये हमें पकड़ ले और दण्ड-पूर्वक हमारा ऋण हमसे चुका पावे ।

चुकाने की नीयत के बिना लिये जानेवाले कर्जों के कई भेद बतलाये हैं। वेदों में व्याज का लेना-देना भी पाया जाता है; क्योंकि सत्यपथ ब्राह्मण में, निरुक्त तथा सूत्रों में सूद लेने-वाले को “कुसीदिन” कहा है। इन उदाहरणों से मालूम होता है कि वैदिक काल में यह धन्धा आम तौर पर होता रहा है। सम्भव है, वैदिक काल के लिये कोई यह कहे कि वह समय भारतीय सभ्यता का उत्कृष्ट और देदीप्यमान युग था, जिसने संसार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से चकाचौंध कर दिया था। उसी की एक झलक वैदिक व्यवसाय भी है। केवल ऐसा ही नहीं है; बल्कि इस देश का सारा इतिहास इसका साक्षी है कि भारत में वैदिक व्यवसाय वैदिक काल से लेकर अब तक यहाँ के सेठ-साहूकारों तथा सराफों द्वारा समान रूप से संचालित होता चला आ रहा है।

सूत्र-काल—वेदों के बाद दूसरी से सातवीं सदी बी० सी० यानी सूत्र काल में भी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी पर किसी वस्तु के रहन रखने तथा व्यक्तिगत ज़मानत पर व्याज से ऋण लेने-देने के नियम पाये जाते हैं यथा—

(१) द्विकं त्रिकं चतुष्कं च शतं स्मृतम् ।

मासस्य वृद्धिं गृहीतया द्विवर्णानामनुपूर्वशः ॥ ५४ ॥

चशिष्ट-स्मृति, अध्याय २

अर्थ—सोपण का व्याज प्रति महीने में ब्राह्मण से २ पण, क्षत्रिय

से ३ पण, वैश्य से ४ पण और शूद्र से पाँच पण लेना चाहिये और भी—

(२) कुसीद वृद्धिर्धर्म्मा विंशतिः पंचमासि ॥

गोतम-स्मृति, अध्याय १२

(३) ऋणि कस्तत्प्रति भुवे द्विगुणं प्रति दाययेत् ।

अधिक्रियत इत्यादि स विक्षेपो द्विलक्षणः ॥ ५२ ॥

नारद-स्मृति १ विवाद पद, अध्याय ४

(४) कृत कालोपनेयश्च याचद्देयो व्यतस्तथा ।

स पुनर्द्विविधः प्रोक्तो गोप्यो भोग्यस्तथैवच ॥ ५३ ॥

नारद-स्मृति १ विवाद-पद, अध्याय ४

अर्थ—जो वस्तु किसी के अधिकार में कर दी जाती है, उसको आधिबन्धक (Pledge) कहते हैं । वह दो प्रकार की होती है । एक छुड़ाने का समय निश्चय करके रखी हुई, दूसरी बिना समय निश्चय किये रखी हुई । फिर ये भी दो प्रकार की होती है । एक रक्षा करने के लिये और दूसरी महाजन के भोगने के लिये । रहन की लगभग यही व्याख्या याज्ञवल्क्य स्मृति अध्याय २ और मनुस्मृति अध्याय ८ श्लोक ४५ में की गई है ।

स्मृति-काल—इसके अतिरिक्त संसार को क़ानून का ज्ञान प्रदान करनेवाले भगवान् मनु ने ८ वें अध्याय में, याज्ञवल्क्य जी महाराज ने याज्ञ-स्मृति के दूसरे अध्याय में, नारद जी महाराज तथा दूसरे ऋषि-महर्षियों ने अपनी-अपनी स्मृतियाँ

में व्यक्तिगत हैसियत पर तथा वस्तुओं के रहन रखने पर या किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मानत पर ऋण देने के नियम विस्तृत रूप से बतलाये हैं। उदाहरणार्थ कुछ प्रमाण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :—

ऋण (Loan)

कुसीद वृद्धि इ गुरयं नाव्येति सकृदा हता

(मनुस्मृति अध्याय ८, श्लोक १५१)

अर्थ—धन का सब व्याज एक ही बार लेने से मूलधन के दूने से अधिक नहीं मिल सकता है।

धरोहर (Deposits)

कुलजेवृत्त सम्पन्ने धर्मद्वे सत्यवादिनि ।

यहा पद्मे धनि न्धाये निक्षेपं निक्षिपेदवदः ॥

(मनुस्मृति, अध्याय ८)

अर्थ—बुद्धिमान् मनुष्य को उचित है कि अच्छे कुल में उत्पन्न, सदाचारवाले, धर्म-निष्ठ, सत्यवादी, अधिक परिवार-वाले, धनवान्, कोमल स्वभाववाले के पास धरोहर रखे—

महाभारत काल—महाभारत के जमाने में भी सुद से रुपया लेने-देने का नियम था, जैसा कि नारद जी के युधिष्ठिर से किये हुए प्रश्नों से प्रगट होता है—

कचित्र भक्तं योजम् च कर्पं कस्याऽवसीदति ।

प्रत्येक चरातं वृद्धया ददास्यृणमनुग्रहम् ॥

(सभाष्वं पाँचवाँ अध्याय श्लोक ८१)

अर्थ—हर सैकड़े में चौथा भाग बढ़ती लेकर कृपाचित्त से उनको ऋण तो देते हो ! तुम्हारी कृषि, वाणिज्य, पशु-पालन और ऋण-दान यह चार प्रकार की वार्ता तो सुचरित्र जनों से भले प्रकार की जाती है !

शुक्रनीति में लिखा है कि सूद, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा, इत्यादि अर्थोपाजनों के मुख्य साधन विज्ञान-वार्ता (अर्थ-शास्त्र) के विषय थे। (कुसीद कृषि वाणिज्य गोरक्षा वार्तायोच्यते । १५६ ।) कोटिल्य अर्थशास्त्र में लिखा है कि सौ पण पर सवापण व्याज ही न्याय-युक्त है, व्यापारियों से पाँच पण, जंगल में रहनेवालों से दस पण तथा समुद्र के व्यापारियों से बीस पण तक व्याज लिया जा सकता है। इससे अधिक जो व्याज ले या दे उसको साहस-दण्ड और सान्धियों को आधा दण्ड दिया जावे।

यह तो हुआ भारतीय शास्त्रों के प्रमाणों का नमूना। अब हम एक लघु-प्रतिष्ठ विदेशी यात्री जे० बी० टेवेरनियर, जो सत्रहवीं सदी के मध्य में फ्रांस से भारत में यात्रा करने को आया था का लेख उद्धृत करते हैं। उसने भारतीय बैंकिंग के सम्बन्ध में लिखा है—

“भारत में उस गाँव को बहुत ही छोटा समझना चाहिये। जहाँ सराफ़ (Money changers) न हों, जो कि एक पैङ्कर के तौर पर काम करता है और एक जगह से दूसरी जगह रुपये का भुगतान करता है तथा विनिमय पत्र जारी करता है……

तमाम यहूदी, जिन्होंने अपने आसपास के राष्ट्रों में रुपया तथा विनिमय के सम्बन्ध में बहुत ही होशियारी का स्थान प्राप्त कर रखा है, वे भारतीय सर्राफ़ों के उम्मेदवार भी मुश्किल से हो सकते हैं।" आगे उसने यह भी बतलाया है कि "१७ वीं सदी में यह सर्राफ़ लोग विदेशी व्यापार को कुछ नक़दी से और कुछ सूरत पर दो महीने की मुहती हुंडियाँ करके आर्थिक सहायता देते थे।"

मुग़ल साम्राज्य में भी देशी बैंकर्स द्वारा देश के व्यापार को पर्याप्त आर्थिक सहायता मिलती थी। इस समय के बैंकर धन-कुबेर थे। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि औरंगज़ेब ने सेठ माणिकचन्द को सेठ की उपाधि से सम्मानित किया था और उसके भतीजे फ़तेचन्द को फ़र्रुख़शियर ने जगत्-सेठ की उपाधि से विभूषित किया था।

अब से ७० वर्ष पूर्व मिस्टर कूक (Cooke) ने अपनी पुस्तक *Rise progress and present condition of Banking in India* में लिखा है, "अज्ञात काल से भारतीय समाज के बैंकर एक प्रधान स्थान रखते आये हैं। साम्राज्य अपना बैंकर रखता था, सूबा अपना बैंकर रखता था, ज़िला अपना बैंकर रखता था और गाँव अपना बैंकर रखता था। हर एक बैंकर अपने-अपने क्षेत्र में गहरा प्रभाव रखता था। हिन्दुओं के परम्परागत रिवाज और मुसलमानों के ऐतिहासिक साहित्य से प्रगट होता है कि प्रतिष्ठित बैंकर को बड़ी इज़्ज़त और राज्य-

शासन के अधिकार दिये जाते थे । कोई शाही दरिखाना ऐसा न होता था, जिसमें वैक्कर नहीं होते थे ।”

उपरोक्त विवरण से यह तो भली भाँति प्रमाणित हो गया कि भारत में वैदिक की प्रथा वैदिक काल से लगातार अच्छी अवस्था में चली आ रही है और मुगल साम्राज्य तक इस पर पूर्ण रूप से भारतीयों ही का अधिकार था ।



तीसरा अध्याय

भारत में आधुनिक बैङ्किङ्ग

आरम्भ और विकास

आरम्भ—“मुगल साम्राज्य के अन्त तक उस समय की तुलना में भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से एक उन्नतिशील देश था। इसका व्यापार विस्तृत था। इसकी बैङ्किङ्ग संस्थायें अछड़ी उन्नतावस्था में थीं। व्यावसायिक क्षेत्र में इसकी साख प्रतिष्ठा-पूर्ण स्थान रखती थीं”*। मुगल साम्राज्य की इतिश्री हो जाने पर यह अभागा देश पश्चिमीयणिकों के हाथ में पड़ा। इनके पधारते ही—अंग्रेजों का सूत्रपात होते ही यहाँ की स्थिति में भयङ्कर फेर-फार शुरू हो गया। लार्ड क्लाइव व हेस्टिंग्स की हुकूमत, पोलिसी और भारतवासियों के सीधेपन से इस देश के व्यापार की जड़ में कुठाराघात होने लगा। जैसे-जैसे अंग्रेजों का राज्य भारत में

*“At the close of the Moghul Empire, India judged by the standards of the time, was economically an advanced country Her trade was large; her banking institutions were well developed and credit played an appreciable part in her transactions.”—“The problem of the rupee” by Dr Ambedkar Page 2.

फैलता गया और कला-कौशल, उद्योग-धन्धे खिसक-खिसक कर इनके हाथों में पहुँचने लगे, वैसे-वैसे हमारे देशी साहूकार निर्वल होते गये और विदेशी कोठियाँ (Agency Houses) की स्थापना के साथ-साथ सरकारी और व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विदेशी बैंकिंग-संस्थाओं का जन्म होना आरम्भ हो गया और शनैः शनैः भारतवर्ष का बैंकिंग व्यवसाय भारतीय साहूकारों के हाथों में से निकलकर विदेशी बैंकों में पहुँचता गया* ।

जोइन्ट-स्टॉट बैंक

असीमित ज़िम्मेदारी पर—सन् १७७०-१८००-भारत में पाश्चात्य प्रणाली पर बैंकिंग का आरम्भ करनेवाली कलकत्ते की प्रतिष्ठित विदेशी कोठियाँ मेसर्स एलेक्ज़ेंडर ऐण्ड कम्पनी फ़र-ग्यूरान ऐण्ड कम्पनी आदि थीं। मेसर्स एलेक्ज़ेंडर ऐण्ड कम्पनी को हिन्दुस्तान बैंक स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। यह बैंक अंग्रेज़ों के संरक्षण में १७७० ई० में क़ायम हुआ था, किन्तु यह अपनी संस्थापक एलेक्ज़ेंडर ऐण्ड कम्पनी के साथ-साथ सन् १८३२ ई० में फेल

*With the decline of the Indigenous bankers and the gradual progress of English trade and dominion in India, the need was felt by the East India Co. for the establishment of banks which would meet both administrative requirements and the demands of trade. The result was the creation of government treasuries and the foundation of early Banking institutions on Western lines and these have operated to the farther disadvantage of the Indigenous Banker I B. I by Jain 23

हो गया। उस समय की तमाम संस्थाओं के समान यह बैंक भी नोट जारी करता था, जो हालाँकि चालू सिक्के के तौर पर रायज़ नहीं थे, किन्तु फिर भी विस्तृत रूप से व्यवहार में आते थे। इन जारी शुदा नोटों की संख्या ५ लाख तक रही, जो कि उस समय की विशेषता की धोतक है। तत्पश्चात् लगभग १८८५ के बङ्गाल-बैंक और जनरल-बैंक आधु इण्डिया की स्थापना हुई, किन्तु थोड़ा बहुत दिलचस्प जीवन बिताने के बाद पिछला बैंक तो १७६१ में स्वयं टूट गया और इसके थोड़े समय बाद पहले बैंक ने भी भुगतान करना बन्द कर दिया।

सन् १८०१-३०—सन् १८०१ में एकाउण्टेण्ट जनरल मिस्टर हेनरी जी ठक्कर ने भारत सरकार का, सरकारी और व्यापारिक हित की दृष्टि से एक बैंक की आवश्यकता पर, ध्यान आकर्षित करते हुए बड़ा जोर दिया, जिसके परिणाम-स्वरूप १८०६ ई० में बङ्गाल बैंक की स्थापना हुई। इसका मसविदा कुछ दिन बाद यानी सन् १८०६ ई० में प्राप्त हुआ था। इस बैंक का मूलधन पाँच लाख पाँड था। इसमें से पाँचवाँ हिस्सा सरकार यानी ईस्ट इण्डिया कम्पनी का था। उस वक्त बैंक के कारोबार में सुप्रबन्ध, निगरानी और योग्य सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार का शेयर-होल्डर के तौर पर बैंक के मूलधन में भाग लेना आवश्यक समझा गया था। गवर्नमेण्ट को इस की प्रबन्धक कमेटी में तीन व्यवस्थापक चुनने का अधिकार था और बैंक का सेक्रेटरी आम तौर पर सिविल सर्विस

का मेम्बर होता था। सन् १८१३ ई० में भारत में अंग्रेजों के बसने की कुछ रुकावटों को दूर करने के लिये एक कानून पास किया गया था, जिससे बैंकिंग को भारी उत्तेजना मिली, कुछ बैंकों की स्थापना हुई; किन्तु उनमें से कई अधिक समय तक कायम नहीं रह सके। इस प्रथम प्रयास के असफल होने के लिये अधिकांश में अंगरेज लोग ही ज़िम्मेदार थे। मिस्टर ठाकुर का कहना है कि अधिकांश बैंकों के दिवालें न केवल फुप्रबन्ध या व्यवस्थित रूप से काम करने की क्षमता के अभाव से, बल्कि बैंक के रूपों का अनुचित उपयोग करने से निकले थे। उस समय बैंक, बैंकिंग धन्धे के साथ-साथ व्यवसाय भी करते थे; इसलिये व्यापारिक हास के साथ साथ बैंक भी बैठते चले गये।

सन् १८३१-१८७० ई०—सन् १८३३ ई० में कमर्शियल बैंक ऑफ़ कलकत्ता, मेसर्स मेकिंगटो पैंड कम्पनी के साथ साथ फ़ेल हो गया और सन् १८२६ ई० में मेसर्स फ़ारमर पैंड कम्पनी द्वारा जोला हुआ बैंक फ़ेल हो गया। सन् १८४० ई० में बैंक ऑफ़ बम्बई पहिली बार ५२,२५,००० के मूलधन से कायम हुआ था, जिसमें से ३००००० के हिस्से गवर्नमेण्ट ने ख़रीदे थे। इसके तीन वर्ष पश्चात् मद्रास बैंक ३०००००० के मूलधन से कायम हुआ, उसमें से ३००००० के हिस्से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ख़रीदे थे। बैंक ऑफ़ बङ्गाल की तरह सरकार का इन बैंकों से भी भीतरी सम्बन्ध था। इन बैंकों में भी सरकार को कुछ डायरेक्टर चुनने का अधिकार था और इनके सेक्रेटरी

ट्रेजरर भी भारतीय सिविल-सर्विस के मेम्बर होते थे। इन तीनों बैंकों को सरकार से बड़ी सुविधायें प्राप्त थीं। मुख्यतः सरकारी बैंकिंग-घन्या इन्हीं बैंकों द्वारा होता था। इसके अतिरिक्त इन बैंकों को नोट जारी करने का भी अधिकार था। इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध भी लगे हुए थे अर्थात् प्रत्येक बैंक के नोट निकालने की सीमा नियत थी। मद्रास बैंक को एक करोड़, बङ्गाल और बम्बई बैंक को दो-दो करोड़ के नोट निकालने का अधिकार प्राप्त था। इन बैंकों को माँगने पर अदा करनेवाली जमा पेंजी (Demand Liabilities) का ३३½ प्रतिशत नङ्गदी रोशन रखना पड़ता था। बाद में यह घटाकर २५ प्रतिशत कर दी गई। सन् १८६२ ई० में इन बैंकों से नोट जारी करने का अधिकार वापिस ले लिया गया और पेपर करेन्सी ऐक्ट सन् १८६२ ई० लागू हो गया। इस विशेष सुविधा के हटा देने से होनेवाली हानि की पूर्ति के लिये सरकार ने अपने सारे फण्ड्स का रुपया इन बैंकों में रखने का वादा किया। बैंक ऑफ बम्बई का मूलधन सन् १८६४ ई० में बढ़कर २०६ करोड़ हो गया था, किन्तु रुई का भाव बढ़ जाने और अमरीका की लड़ाई में चीजों के भावों में अधिक मात्रा में घटाव देती हो जाने से भारी नुकसान उठाकर यह बैंक सन् १८६८ ई० में बन्द हो गया। इसने अमानतें जमा रखनेवालों को पूरा रुपया चुका दिया था, लेकिन इसके शेयर होल्डरों को सारा धन खोना पड़ा था। इतने पर भी फिर उसी वर्ष इस

बैंक ने बैंक ऑफ़ बम्बई लिमिटेड के नाम से जन्म लिया। इसका संगठन कम्पनीज़ ऐक्ट सन् १८६६ के आर्टिकिल्स ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार हुआ था; परन्तु सरकार ने इसके पहले फ़ेल हो जाने के कारण यह उचित समझा कि मूलधन में से अपना हिस्सा वापस ले लिया जावे और डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ट्रेज़रर को नियुक्त करने का अधिकार भी छोड़ दिया जावे।

प्रेसीडेन्सी बैंक

बैंकों के लगातार फ़ेल होने के कारण सरकार ने इस सम्बन्ध में जाँच कराने और उचित परामर्श प्राप्त करने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया, जिसने सन् १८६६ ई० में अपना रिपोर्ट पेश की थी। तदनुसार प्रेसीडेन्सी बैंक ऐक्ट सन् १८७६ ई० पास हुआ और इसके द्वारा बम्बई, बङ्गाल, मद्रास बैंक प्रेसीडेन्सी बैंक कहलाये। इस क़ानून के आधार पर ही इन प्रेसीडेन्सी बैंकों का संचालन होने लगा। सरकार ने अपना बैंकिंग का सारा काम इनको सौंप दिया, इससे इनकी साख़ में वृद्धि हुई और सार्वजनिक प्रजा से भी बैंकिंग धन्या इनको काफी मात्रा में मिलने लग गया। इन बैंकों पर जो क़ानून द्वारा प्रतिबन्ध लगाये गये थे, वे हालाँकि बैंकों के प्रबन्धकों को पसन्द नहीं थे; किन्तु पब्लिक हित की दृष्टि से लाभदायक थे। इन तीनों बैंकों के शेयर-होल्डर्स में अधिक संख्या यूरोपियन पूँजीपतियों की थी, जिसका दिग्दर्शन बैंक ऑफ़ बम्बई की शेयर-होल्डर्स की सूची से भली प्रकार हो जाता है; यथा—

१७३	अंग्रेज भारतवासी के खरीदे हुए	३२६१	शेयर्स
१२	देशी क्रिश्चियन के	४६	"
३	मुसलमानों के	५५	"
१०६	पारसियों के	१२३३	"
३५	हिन्दुओं के	३२७	"
	गवर्नमेण्ट के हिस्से	३००	"
<hr/>		<hr/>	
३३२		५२२५	

काम—इन तीनों बैंकों को यथा-सम्भव नुकसान से बचाने के लिये विनिमय का घन्घा करने की आज्ञा नहीं थी और न ये विदेशी हुँडियों की लिया-बेची ही कर सकते थे। भारत में ये अधिक से अधिक ६ मास के लिये उधार देते थे; किन्तु जायदाद गैर मनकूला की ज़मानत पर उधार देने की, इनको पूँजी उलझ जाने की आशङ्का से, मनाही थी।

शाखायें—इन प्रेसिडेन्सी बैंकों की भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तों में कई शाखायें थीं, जिनकी संख्या इम्पीरियल बैंक के रूप में स्थापित होने के समय ५६ थीं तथा मूलधन, रिज़र्व फंड आदि का व्योरा इस प्रकार था—

	रु०	१०००) में
मूलधन
रिज़र्व फंड
सरकारी जमा
निजी जमा
नकदी रोशन

सीमित-जिम्मेदारी के आधार पर

सन् १८६०-१८८०—सन् १८६० ई० के पहले पहले जितने भी बैंक खुल थे, उनमें से अधिकांश असीमित जिम्मेदारी पर खुले थे। इस वर्ष कानून न० ७ के पास होने से सीमित जिम्मेदारी की प्रणाली सर्वप्रथम आरम्भ हुई, जिनसे भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक बैंकिंग को अच्छी उत्तेजना मिली।

अंग्रेजों द्वारा प्रयत्न—सन् १८६५ ई० में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई और लगभग दस वर्ष बाद अलाहमस बैंक आबू शिमला का जन्म हुआ, जिसने सन् १८२३ ई० में दिवाला निकाल दिया। ये दोनों बैंक भी अंग्रेजों के प्रयत्न के परिणाम हैं। सन् १८८० ई० के पहले पहले भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक बैंकिंग की तमाम हलचल अंग्रेजों द्वारा आरम्भ की गई थी। विदेशी विनिमय का धन्धा, विदेशी-बैंकों के हाथ में था, जिस पर अब भी उन्हीं का ठेका है।

भारतीय प्रयत्न—सन् १८८१-१८०४—सबसे पहले विशुद्ध भारतीय बैंकिंग का प्रयत्न सीमित जिम्मेदारी के उसूल पर सन् १८८१ ई० में आरम्भ हुआ था, जब कि अवध कमिश्नरल बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद सन् १८८४ ई० में लाला हर-किशनलाल, जा कि पंजाब प्रांत में भारतीय उद्योग धर्मों के अगुवा हैं, उनका भरसक प्रयत्न और भारी शक्ति खर्च करने पर पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी। यह बैंक बहुत ही सफलता-पूर्वक कार्य करता हुआ उत्तरात्तर उन्नति करता जा रहा है।

सन् १९०१ ई० में फिर लाला हरकिशनलाल जी ने पीपल्स बैंक ऑफ इण्डिया चालू किया था, जो कि सन् १९१३ ई० तक बड़ी खूबी से काम करता रहा, इन्ने पंजाब नेशनल बैंक की अपेक्षा अधिक व्याप्ति प्राप्त कर ली थी। इसकी सौ से लगभग शाखाएँ थीं और उनमें सवा करोड़ से ऊपर अमानतें जमा थीं। अचानक इसको अपने दरवाजे बन्द करने के लिये विवश होना पड़ा था। इस बैंक के फेल होने का कारण न तो वेईमानी थी और न कोई प्रबन्ध-सम्बन्धी योग्यता का अभाव था। इसका कारण विशेषकर भारतीय बैंकों के अमानतदारों की बैंकिंग के उसूलों के प्रति अनभिज्ञता थी, इसके अतिरिक्त अङ्गरेजी बैंकों और सरकारी अफसरों की जलन और प्रेसीडेन्सी बैंकों का लापरवाही और अदृष्ट-शिता पूर्वक व्यवहार था, जिन्होंने गवर्नमेंट के कागज पर भी रुपया नहीं दिया। प्रसन्नता की बात है कि रिलीयर लोगों ने बैंक के अमानतदारों को सौ फीसदी चुका दिया। हाँ, शेयरहोल्डर्स को अवश्य कुछ नहीं मिला। इससे लाला हरकिशनलाल जी का मुख उज्ज्वल हो गया और लोगों की फेल होने का भीतरी रहस्य मालूम हो गया। फलतः लाला साहब ने २ वर्ष बाद ही पीपल्स बैंक ऑफ नार्दर्न इण्डिया लि० के नाम से दूसरा बैंक स्थापित कर दिया, जिसने भी लगभग वही स्थान प्राप्त कर लिया था, जो पूर्व बैंक का था।^१ लेकिन अब इसकी वह बात नहीं रही है।

* इस बैंक ने भी सन् १९११ ई० में अपने दरवाजे बन्द कर दिये थे लेकिन कुछ महीनों बाद ही हाईकोर्ट से स्वीकृत नवीन स्कीम के अनुसार पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

विकास-१८०५-१३—सन् १८०५ ई० में बङ्गाल-विच्छेद के समय से स्वदेशी आन्दोलन ने स्यानीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन दिया, जिसके फलस्वरूप इस देश में बँकों की स्थापना बड़े वेग से आरम्भ हो गई। सन् १८०६ ई० से सन् १८१३ ई० तक ८ वर्षों में पाँच लाख से ऊपर मूलधनवाले बँकों की संख्या में इस प्रकार वृद्धि हुई थी :—

रुपये लाखों में

वर्ष	बँकों की संख्या	मूलधन तथा संचित फण्ड	अमानतों जमा	नकदी	अमानतों से नकदी का प्रतिशत अनुपात
१८०६	१०	१६०	१११८	१४३	१३
१८०७	११	२६२	१४००	१६४	१४
१८०८	१४	३०६	१६२६	२४८	१८
१८०९	१८	३८४	२०४३	२७३	१४
१८१०	१६	३७६	२२६६	२८०	११
१८११	१८	४१२	२८२६	३६२	१४
१८१२	१८	४२६	२७२६	४००	१८
१८१३	१८	३६४	२२२६	४००	१८

उक्त तालिका से मालूम होता है कि पाँच लाख से ऊपर-वाले बँकों की संख्या लगभग दूनी हो गई थी। अतिरिक्त इसके दूसरे छोटे बँकों की संख्या विशेष रूप से बढ़ी थी अर्थात् सन् १८१० ई० में कुल बँकों की संख्या ४७६ थी। इस समय में

स्थापित होनेवाले बैंकों में प्रमुख, बैंक ऑफ इण्डिया, इण्डियन स्वदेशी बैंक १९०६, बंगाल नेशनल बैंक, इण्डियन बैंक ऑफ मद्रास १९०७, वम्बई मरचेण्ट्स बैंक, क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया १९०६, कठियावाड अहमदाबाद बैंकिंग-कॉरपोरेशन १९१०, सेण्ट्रल-बैंक ऑफ इण्डिया १९११ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

५ वर्षों में फेल होनेवाले बैंक

वर्ष	संख्या	मूलधन लाखों में	
		स्वीकृत	प्राप्त
१९१३	१२	२७४	३६
१९१४	४२	७१०	१०६
१९१५	११	२६	४
१९१६	१३	२३१	४
१९१७	६	७६	२५
जोड़	८७	१३४७	१७८

सन् १९१३-१७—सन् १९१३ ई० में बैंकों पर फिर विपत्ति आई, जिसने इनमें से बहुतों का गला घोट दिया और भारतीय बैंकिंग को भारी धक्का पहुँचाया। उसका अनुमान ऊपर की तालिका से स्वयं हो जाता है :—

उक्त ५ वर्षों में ८७ बैंक, जिनका प्राप्त मूलधन १७८ लाख

था, फेल हुए हैं। यह सत्य है कि इनमें से कुछ के फेल होने की कारण, बैंक के फण्डों का बेईमानी के साथ उपयोग करना, बैंकिंग व्यवसाय के साथ साथ व्यापार को मिश्रित करना तथा इस बात के ज्ञान का अभाव कि सुरक्षित धन का किस प्रकार किया जाता है, आदि थे, किन्तु इनके साथ साथ दूसरे कारण ये थे—(१) भारतीय बैंकों में आपसी सहकारिता का अभाव, (२) विदेशी, अंग्रेजी और प्रेसीडेन्सी बैंकों का द्वेष-पूर्ण तथा सहानुभूति रहित व्यवहार, (३) सरकार की लापरवाही के साथ तमाशा देखनेवाली नीति।

सन् १८१८-१८३० लड़ाई के जमाने में भारत के कम्पनी व्यवसाय को पुनः उत्तेजना मिली, साथ ही थोड़ी बहुत भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकिंग की भी उन्नति आरम्भ हुई। परिणाम स्वरूप टाटा इण्डस्ट्रियल-बैंक सन् १८१८ में बड़ी ऊँची आशाओं के साथ और उपयुक्त परिस्थिति में स्थापित हुआ था। इसका फलने फूलने के अच्छे लक्षण दिखाई देते थे, किन्तु दुःख है कि भारत जैसे देश में, जहाँ आधुनिक बैंकिंग का व्यवसाय पूरे तौर पर जन्म नहीं पाया था, वहाँ साधारण बैंकिंग धंधे के साथ-साथ लम्बी अवधि के लिये उधार देना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त बैंक के अमले में अधिकतर अनुभव रहित अंग्रेजी नौकरों का बोलबाला था जिनके हाथ में बैंक के प्रमुख कार्यों का संचालन था और जिन्होंने विकट परिस्थिति के अवसर पर भारतीय नौकरों के अधिकार छीन लिये थे ऐसे अनेक कारणों से भारतीय-नौकरों

य भारतीय-प्रजा की सहानुभूति, बैंक से हट गई, फल-स्वरूप अल्प समय में अर्थात् ६ वर्ष की अवस्था में ही यह बैंक स्वयं लिक्विडेशन में आ गया और सन् १९२३ में सेण्ट्रल-बैंक आव् इण्डिया के साथ मिल गया। इसी प्रकार इंडस्ट्रीयल-बैंक

११ वर्षों में फल होने वाले बैंक

वर्ष	संख्या	मूलधन		
		मंजूर शुदा	जारी शुदा	वसूल शुदा
१९१८	७	२,०६,४६,६७०	४,८२,६२१	१,४६,१८२
१९१९	४	२२,२०,०००	६,४७,१८२	४,०२,७३७
१९२०	३	१०,४०,०००	७६,७७००	७,२४,७१७
१९२१	७	७०,४०,०००	२८,०६,६२	१,२२,६२६
१९२२	१२	१०,१२,२२,०००	२७,२२,७४४	३,२२,६६१
१९२३	२०	२१,८६,८६,६६२	६,६२,३६,४८०	४,६२,४७,३२२
१९२४	१८	६,३०,३०,६२२	२६,४६,३७०	११,६२,६२३
१९२५	१७	१,८६,८०,०००	२२,४१,६६२	१८,७२,७६२
१९२६	१४	७१,८०,०००	७,०२,८१२	३,६८,१४२
१९२७	१६	६६,३०,०००	६,८८,३७२	३,१०,२१८
१९२८	१३	८१,००,०००	३१,६२,७४०	२३,११,७१७

आव् वेस्ट-इण्डिया, दी करमानी इण्डस्ट्रीयल-बैंक, दी कलकत्ता इण्डस्ट्रीयल बैंक-आदि अधिकांश प्रमुख-प्रमुख बैंक, जो लडाई के

जमाने में पैदा हुए थे, लड़ाई के बाद ज्वाइट-स्टॉक कम्पनियों के असफल होने के साथ साथ बन्द हो गये। पृ० २८ की तालिका भारतीय-बैंकिंग व्यवसाय की दयनीय दशा का पूरा रूप से दिग्दर्शन कराती है।

बैंकों के फेल होने में सन् १९२२ ई० से सन् १९२८ ई० तक, सात वर्ष का समय, पिछले ५ वर्ष (सन् १९१३—१९१७ ई०) से भी अधिक भयकर निकला है। उन ५ वर्षों में तो केवल एक वर्ष सन् १९१४ ई० ही अधिक भयकर था, किन्तु सन् १९२२ ई० से लगातार फेल होनेवाले बैंकों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। प्रति वर्ष ७५ लाख वाले १६ बैंकों के फेल होने का औसत है, जब कि पहले पाँच वर्षों (सन् १९१३—१७ ई०) में फेल होने वाले बैंकों का प्रातः मूलधन प्रतिवर्ष ३५ लाख से अधिक नहीं आता है।

सन् १९३१ ई० का आर्थिक-संकट—महासमर के साथ साथ बृटेन की सरकार को आर्थिक घुन ऐसा लग गया है, जिससे वह अब तक भी नहीं सुधर पाई है बल्कि सन् १९३० ई० और ३१ ई० के व्यापारिक हास के कारण उसकी आर्थिक स्थिति और भी शोचनीय दशा को पहुँच गई, जिससे निवृत्त होकर उसको अपने कागजी सिक्के की पीठ पर से स्वर्णधार (Gold standard) उठाना पड़ा। फलस्वरूप बैंक ऑफ़ इंग्लैंड से सम्बन्ध रखनेवाले बैंकों में हलचल मच गई और बृटेन की कागजी मुद्रा (sterling) के साथ रुपये का,

१ शि० ६ पै० की दर से, सम्बन्ध जोड़ देने के कारण भारतीय बैंक भी हिल उठे; किन्तु इम्पीरियल बैंक के गवर्नर की ओर से सहायता देने के आश्वासन के कारण अधिक संख्या में बैंक फ़ेल न हो सके और राम-राम करके अधिकांश बैंकों ने जान बचाई। फिर भी लाला हरकिशन लाल का पीपल्स-बैंक आर्न्स्ट नार्दन इंडिया और पंजाब काश्मीर बैंक फ़ेल हो गये। अपने बैंक के फ़ेल होने का कारण बताते हुए पीपल्स-बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर ने एक्सप्रेस ट्रेड प्रेस को यह बयान दिया था—

“हमने १ जुलाई सन् १९३१ ई० से अब तक (२३ सितम्बर सन् १९३१ ई०) ८० लाख रुपयों का पेमेंट दिया, फिर भी माँग बनी रही। इस माँग का कारण यह है कि गवर्नमेंट इतने अधिक व्याज की दर से कर्ज़ ले रही है कि जितना व्याज बैंक नहीं दे सकता। अन्तिम ट्रेज़री बिल ७½ प्रतिशत का था। नये कर्ज़ों के कारण थोड़ी थोड़ी-रकम भी खिंच गईं। बैंक की स्थिति अच्छी है। इसमें जितना रुपया दूसरों का जमा है, उससे अधिक रुपया बैंक का वसूल होने को है; परन्तु किसी देश या सस्था की साथ नक़दी नहीं बना सकती।”

सारांश यह है कि लड़ाई के बाद से अब तक भारतीय बैंकिंग व्यवसाय की अवस्था गिरती हुई चली आ रही है, अभी तक सुधरी नहीं है।

विदेशीय-विनिमय बैंक—ये बैंक विदेशीय व्यापार के लहने-पावने की भुगतान करने का धन्धा करते हैं; इसलिये विनिमय

बैंक कहलाते हैं। भारत में इनका जन्म ७५ वर्ष पूर्व हुआ था। सन् १८७० ई० में इस प्रकार के केवल ३ बैंक थे। इसके पश्चात् १८८० ई० में ४, सन् १८९० में ५, १९०० ई० में ८, सन् १९२० ई० में १५ और सन् १९२८ ई० में धीरे धीरे उन्नति करते हुए इसकी संख्या १८ तक पहुँच गई। पिछली संख्या जन् १९२२ से समान चली आ रही है। महायुद्ध के पहले यहाँ केवल १२ विनिमय बैंक थे, जिनका मूलधन व रिजर्व फण्ड ३७८ करोड़ पौण्ड था और ४४ लाख पौण्ड का लगभग नकदी रोशनी थी। इन उक्त बारह बैंकों में आधे से अधिक का हेड आफिस लन्दन में थे। शेष के हेड आफिस जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका में बटे हुए थे। महासमर के अवसर पर भारत का व्यापारिक सम्बन्ध अनेक भिन्न भिन्न देशों से स्थापित हुआ, जिसके कारण दूसरे देशों के बैंकों को यहाँ शाखाएँ खोलने के लिये उत्तेजना मिली। सन् १३ और २४ के बीच में इन बैंकों की संख्या में ५० प्रतिशतक वृद्धि हुई है। सन् १९१८, १९१९ ई० में दो जापानी, १९२० में “बैंकों नेशनल उल्ट्रा मैरोना” और दो नेदरलैण्ड बैंकों ने अपने दस्तूर भारत में खोले। आरम्भ में इन बैंकों का धन साधारण सा था, किन्तु धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ गया कि आज इन्होंने भारतीय बैंकिंग व्यवसाय पर पर्याप्त अधिकार जमा लिया है और भारतीय ज्याइ टस्टॉक बैंकों की अपेक्षा अत्यधिक शक्तिशाली बन गये हैं। पाठक पृष्ठ ३२ के कोष्ठक से लडाइ रु बाद इसकी बढ़ती हुई गति का अनुमान स्वयं लगा सकेंगे—

नीचे के कोष्ठक में सन् १९२८ में विदेशी बैंकों की संख्या १८ बतलाई गई है। इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक की अनेक शाखाएँ भारत की मुफ़्तसलात में फैली हुई हैं, जिनकी कुल संख्या ८८ होती

लड़ाई के पश्चात् से विनिमय बैंकों की उन्नति

वर्ष	संख्या	मूलधन वधु प्रत्येक १००० पौंड में	भारत की जमा १००० पौंड में	भारत में रोशन १००० पौंड में
{ १९१३ महा युद्ध से पूर्व }	१२	३७,८२६	२३,२७६	४,४११
१९१६	११	२६,०७०	२२,७६६	२२,४८७
१९२०	१६	६०,२१७	२६,१०६	१८,८८१
१९२१	१७	१११,६३२	२६,३२७	१७,६७६
१९२२	१८	११२, २२१	२६,०३८	१२,१३२
१९२३	१८	१४०,१०३	२१,३३२	१०,८६६
१९२४	१८	१३०,४६४	२२,६७६	१२,२७६
१९२५	१८	११८,३११	२२,६०६	७,०६२
१९२६	१८	१४८,००३	२३,६२८	८,०४६
१९२७	१८	१८०,६१६	२१,६४१	६,०६८
१९२८	१८	१८८,६२३	२३,३६४	७,०४२

है। ये विदेशी-व्यापार को आर्थिक सहायता देने के अतिरिक्त सब प्रकार का बैंकिंग-धन्धा भी करते हैं। ये भारतीय-प्रजा की अमानतें जमा रखते हैं और सदैव अधिक से अधिक इस देश का

रुपया रखने के प्रयत्न में रहते हैं। प्रमाण के लिये इम्पीरियल बैंक चल्नु खाते (Current deposits) पर ब्याज नहीं देता; किन्तु ये बैंक आम तौर पर २) प्रतिशत सालाना ब्याज देते हैं। ऐसे अनेक कारण हैं, जिनकी वजह से इनमें भारतीय प्रजा की जमा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जहाँ सन् १९१३ में २३२ करोड़ रुपये इनमें जमा थे, वहाँ सन् १९२८ में जमा की संख्या ५३३ करोड़ रुपया हो गई। इस संक्षिप्त धन-राशि से यह बैंक अधिक मात्रा में विदेशी व्यापार की सहायता करते हैं, जिसका अधिकांश भाग विदेशी व्यापारियों के हाथ में है। विदेशों में धन की तंगी आने पर ये बैंक भारत के धन को भारत के बाहर भेजकर दूसरे देशों की ऊँचे ब्याज की दर से लाभ उठा लेते हैं। यही कारण है कि भारत में इन बैंकों की तृकदी रोशन कम होती जा रही है, जैसाकि पृ० ३२ के कोष्ठक से प्रकट होता है। विदेशी बैंकों की उत्तरोत्तर वृद्धि का यह परिणाम हो रहा है कि भारत के उद्योग-धन्धे धनाभाव से पनपने नहीं पाते और भारत के धन से विदेशी लोग लाभ उठाते हैं। इन बैंकों का दृष्टिकोण सदैव विदेशी व्यापारियों को सहायता पहुँचाना और विदेशी लोगों को बड़ी बड़ी तनख्वाहें देना रहा है। ७५ वर्ष से भारत में काम करते रहने पर भी इन्होंने आज तक एक भी भारतीय को उत्तरदायित्व के पद पर स्थान नहीं दिया है। भारत ही एक ऐसा पराधीन देश है, जहाँ ये बैंक मनमाने रूप से इस देश के धन का व्यवहार करते हैं और इस देश के

हित का ध्यान नहीं रखते (इस सम्बन्ध में अगले पृष्ठों में विशेष रूप से विचार किया गया है) ।

इम्पीरियल बैंक—बीसवीं सदी के प्रथम दस वर्षों में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता अत्यधिक रूप से अनुभव हुई और यह अनुमान किया गया कि इस देश की व्यापारिक उन्नति के लिये बैंकिंग-सम्बन्धी आवश्यक सुविधा प्राप्त होने और सरकारी सहायता से लाभ उठाने के लिये तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों की अपेक्षा एक केन्द्रीय बैंक अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । अस्तु इस प्रकार के बैंक की स्थापना के सम्बन्ध में मिस्टर जे० एम० कीन्स ने एक स्कीम बनाई थी, जो सन् १९१३ ई० के भारतीय करेंसी कमीशन की रिपोर्ट के साथ शामिल कर दी गई, परन्तु लड़ाई के छिड़ जाने की वजह से उस समय उस पर विचार करना स्थगित कर दिया गया । लड़ाई के जमाने में सरकार को करेंसी सम्बन्धी जो कठिनाइयाँ हुईं, उन्होंने उस प्रकार के बैंक की स्थापना की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान शीघ्र ध्यान आकर्षित किया और बैंकिंग की उन्नति के लिये एक ठोस क्षेत्र तैयार कर दिया । लड़ाई समाप्त होते ही सरकार और तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों के बीच में एक समझौता हुआ । फल स्वरूप तीनों बैंकों के सम्मिश्रण से सीमित जिम्मेदारी के आधार पर इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई । इसकी व्यवस्था और कार्य की व्याख्या के लिये एक विशेष कानून इम्पीरियल बैंक ऐक्ट सितम्बर सन् १९२० ई० में पास हुआ ।

इसके साथ एक एग्रीमेण्ट शामिल किया गया है, जिसके द्वारा सरकार और बैंक के बीच में सम्बन्ध स्थापित किये गये हैं। इस बैंक ने २७ जनवरी सन् १९२१ ई० में कार्य आरम्भ किया है। इस

इम्पीरियल बैंक का प्रगति-सूचक कोष्ठक

[लाखों में]

वर्ष	मूलधन	रिज़र्व फंड	गवर्नमेंट की और सार्वजनिक जमायें	निजी जमायें	रोशन
१९२२	२६२	४३३	१४१६	२७००	१२०७
१९२३	२६२	४२६	८२७	७४१६	१२०१
१९२४	२६२	४८०	७२०	७६७१	१२६०
१९२५	२६२	४६३	२४६	७७८३	१०४७
१९२६	२६२	२०६	६४६	७३६०	२०६०
१९२७	२६२	२२४	७२०	७२०७	१०८६
१९२८	२६२	२३६	७६६	७१३०	१०६७
१९२९	२६२	२४८	७६०	७१६	१४००
१९३०	२६२	२६३	७३७	७५६	१३०४

बैंक का मूलधन ११२५ लाख रुपया निश्चित हुआ। जब कि तीनों प्रेसीडेन्सी बैंकों का इकजाई मूलधन सिर्फ ३७५ लाख ही था। सन् १९२१ ई० के बाद इस बैंक ने इस प्रकार उन्नति की है।

इस बैंक से जैसी आशा थी, वैसी भारतीय व्यवसाय को सहायता नहीं मिली और न राष्ट्रीय बैंक की आवश्यकता ही पूरी हुई। इसके लिये यह आम शिकायत है कि यह देशी कम्पनियाँ, बैंकों और संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में उपेक्षा करता है; किन्तु विदेशी संस्थाएँ इससे पूरा पूरा लाभ उठा लेती हैं। इस कथन की पुष्टि मिस्टर मेकडोनाल्ड के उस वयान से होती है, जो उन्होंने सेण्ट्रल बैंकिंग इन्कायरी कमेटी (सन् १९३१ ई०) के सामने बैंक की जमा-शुदा अमानतों और दिये हुए कर्जों की बाबत पेश किया था। यथा—

जमा		नावें
विदेशियों की	लाख	११७० लाख
चलू खाते में	५६४	०
मियादी अमानतें	२६४	०
जोड़	८२८	११७०
भारतीयों की	लाख	३०३८
चलू खाता	१७३२	०
मियादी अमानतें	२१४६	०
जोड़	३८८१	३०३८

इससे प्रकट होता है कि विदेशियों को उनकी जमा की अपेक्षा अधिक उधार दिया जाता है और भारतीयों को उनकी जमा से कम उधार मिलता है। इसके अतिरिक्त इस बैंक में शेयर-होल्डरों का बहुमत विदेशियों का है। यथा—

भारतीय शेयर-होल्डरों की पूँजी
विदेशी

२५८०=२५०

२=३४१७५०

इसलिये इसमें विदेशियों ही का अधिक बोलबाला है।

हेड ऑफिस और शाखाएँ—इसके तीन हेड ऑफिस—बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हैं और इनके आधीन भारत के समस्त प्रान्तों में १६६ शाखाएँ हैं।

संगठन—इसका संचालन एक सेण्ट्रल बोर्ड के आधीन है, जिसके १६ सदस्य हैं। उनका चुनाव इस प्रकार होता है :—

६ उक्त तीनों हेड आफिसों के प्रेसीडेण्ट, वाइस प्रेसीडेण्ट और सेक्रेटरी। ये शेयर-होल्डरों के प्रतिनिधि होते हैं।

५ गवर्नर जनरल द्वारा मनानीत होते हैं। इनमें एक कएट्रोलर आफ् करेन्सी और चार भारतीय मेम्बर होते हैं, इनका चुनाव प्रति वर्ष होता है; किन्तु दुबारा भी पहिले-वाले मेम्बर चुने जा सकते हैं। ये सदस्य गैर सरकारी होते हैं।

२ मैनेजिंग गवर्नर—उनको सपरिषद् गवर्नर जनरल सेंट्रल बोर्ड की सिफ़ारिश पर विचार करके नियत करते हैं और वेही इनका प्रबन्ध-काल भी निश्चित करते हैं।

ये सोलह सदस्य गवर्नर कहलाते हैं। बैंक के दैनिक कार्य का संचालन मैनेजिंग गवर्नरों द्वारा होता है।

तीनों हेड ऑफिसों के अधिकार-क्षेत्रों (circles) का धन्या उनके अपने अपने स्थानीय बोर्ड द्वारा संचालित होता है, जिसका

चुनाव शेयर-होल्डर करते हैं। तीनों स्थानीय बोर्ड, जहाँ तक ग्राम नीति और भूय का सम्बन्ध है, वहाँ तक सेण्ट्रल बोर्ड की आधीनता में काम करते हैं। इन तीनों केन्द्रीय दफ्तरों के सेक्रेटरी और ट्रेज़रर अपने अपने केन्द्र की व्यवस्था और प्रबन्ध के ज़िम्मेदार हैं।

सरकारी हस्तक्षेप—गवर्नरों की नियुक्ति करने के अतिरिक्त गवर्नर जनरल को बैंक के नाम हर एक ऐसे मामले के सम्बन्ध में, जो उसकी सम्मति में सरकारी अर्थनीति पर गम्भीर असर डालनेवाला हो या सरकारी जमा की सुरक्षा के लिये आवश्यक हो, चेतावनी देने का अधिकार है। बैंक द्वारा ऐसी चेतावनियों की अवज्ञा होने पर उसे अधिकार है कि वह सरकारी बैंकिंग धन्धे के सम्बन्ध में इकरारनामे का पालन न करे और जब भी वह आवश्यक समझे, बैंक के हिसाबत व कारोबार का विशेष निरीक्षण करा सकता है।

काम—यह बैंक सरकारी बैंकिंग धन्धे का अकेला अधिकारी है और तमाम सरकारी जमाओं का बिना व्याज उपभोग करता है। यह सरकारी बैंकर है। जहाँ जहाँ इसकी शाखाएँ हैं, वहाँ वहाँ यह सरकारी खज़ानची का काम करता है, सरकार के खाते जमा होनेवाली समस्त रक़मों सर्वसाधारण से वसूल करता है और सरकार के वास्ते सदैव आवश्यकतानुसार रोशन तैयार रखता है। यह भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण का प्रबन्धक है और केन्द्रीय बैंक के कुछ काम भी अंजाम देता है। यह बैंकों का बैंक

है। भारत के प्रमुख प्रमुख बैंक इसके साथ हिसाब रखते हैं; लेकिन ऐसा कोई क़ानूनी नियम नहीं है, जिससे भारत के बैंकों को अपनी ज़िम्मेदारी का कुछ निश्चित भाग इसमें अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता हो। यह भारत के ११ क्लियरिंग हाउसों का संचालक भी है। इन सबके अतिरिक्त यह सब प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय भी करता है, जिसको इम्पीरियल बैंक ऐक्ट की आठवीं धारा के अनुसार परिशिष्ट (Shedule) नं० १ में २ भागों में विभक्त किया गया है।

(१) वे धन्ये, जो बैंक कर सकता है।

(२) वे धन्ये, जो बैंक नहीं कर सकता।

पहिला भाग

बैंक को अधिकार है कि वह वे तमाम धन्ये करे, जिनका कि नीचे वर्णन किया गया है—

(१) नीचे लिखी ज़मानत पर रुपया उधार देना या खाते में बाक़ी रखना—

अ—हिस्सों, जमाशुदा ज़मानतों और अन्य ज़मानतों पर (अचल सम्पत्ति के अतिरिक्त) तथा किसी स्थानीय गवर्नमेंट और सीलोन की गवर्नमेंट की ज़मानतों पर।

आ—ऐसी ज़मानतों पर, जो सरकारी सहायता-प्राप्त रेलवे-कम्पनी द्वारा जारी की गई हों, जिनके

निस्वत सपरिपदु गवर्नर जनरल द्वारा प्रेसी-डेन्सी बैंक ऐक्ट सन् १८७६ ई० की दफ़ा ३६ के अनुसार प्रसिद्धि हो चुकी हो ।

इ—डिवेन्चर या दूसरी रुपयों की ज़मानतों पर, जो ब्रिटिश भारत के क़ानून के अनुसार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या उनकी तरफ़ से जारी की गई हो ।

उ—उस भाल की ज़मानत पर, जिसको या जिसका स्वत्व पत्र ऐसे थोड़े समय या अधिक समय के लिये लिये हुए क़र्ज़ या खाता पेटे ली हुई रक़म के लिये बर्तौर ज़मानत बैंक में जमा किया हो या बैंक के दफ़्तर में लिख दिया हो ।

ए—सही किये हुए बिल ऑफ़ एम्सचेज़ और प्रोमेसरी नोट पर, जो राख्यावाला (Payee) के द्वारा येचान किये गये हों और उन सम्मिलित प्रोमेसरी नोटों पर, जो दो या ज़्यादा व्यक्ति या दूकानों, जिनका आपस में साझेदारी का सम्बन्ध न हो, के लिखे हुए हों; और

ऐ—सीमित जिम्मेदारी पर क़ायम होनेवाली कम्पनियों के पूरे दाम चुकाये हुए शेयर और डिवेन्चर या जायदाद ग़ैरमनकूला या तत्सम्बन्धी स्वत्व पत्र की सहायक ज़मानत पर केवल उस हालत में, जब कि असली ज़मानत “अ” से “इ”

तक वर्णन की हुई में से कोई एक हो और यदि सेण्ट्रल बोर्ड ने आम या खास हिदायत द्वारा अधिकार दिया हो तो—असली जमानत “ए” में वर्णन की हुई होने की हालत में भी। इससे अतिरिक्त यदि सेण्ट्रल बोर्ड उचित समझे तो सपरिषद् भारतमंत्री को बिना किसी खास जमानत पर भी उधार दिया जा सकता है।

- (२) प्रत्येक ऐसे प्रोमेसरी नोट, डिपेन्चर बॉण्ड, स्टाफ, शेयर, लिम्यूनिटी या माल को या उसने हफ की दस्तावजों का, जो बैंक से उधार ली हुई रकम की पथज में यतौर जमानत के जमा की गई हो या बैंक के हफ में लिखी गई हो और बैंक ने कब्जे में हो और जिनपर बैंक का कोई कर्जा हो या ऐसे कर्जों से सम्बन्ध रखनेवाला कोई खर्चा हो या दावा हो, जो मुताबिक शरायत और इकरार के (यदि कोई हो) निर्धारित समय में बसूल न हुआ हो, बेचना और बिक्री की कीमत को बसूल करना।

- (३) कोर्ट ऑफ् चार्ज्स को उस आयदाद और जागीर की जमानत पर, जो उनके अधिकार या प्रबन्ध में हो कर्ज देना तथा ऐसे कर्जों व सूद को, जो उन पर हो, बसूल करना, किन्तु ऐसा कोई कर्जा तब तक नहीं दिया जावेगा, जब तक सम्बन्धित लोकल गवर्नमेंट

से आज्ञा प्राप्त न की गई हो और न ६ महीने से अधिक अवधि के लिये दिया जावेगा।

- (४) ऐसे बिल आब्सचेंज या दूसरे बेचे जाने योग्य (Negotiable) साखपत्र जारी करना, स्वीकार करना, डिस्काउंट करना, खरीदना और बेचना, जो हिन्दुस्तान और सीलों में चुकाने के काबिल हों और सपरिपट्टु गवर्नर जनरल की आम या खास हिदायत के अनुसार हों। उन बैंकों के वास्ते या उन बैंकों से या उन बैंकों को, जिनके लिये इस सम्बन्ध में सपरिपट्टु गवर्नर जनरल ने स्वीकृति दे दी हो। ऐसे बिल आब्सचेंज को खरीदना, बेचना, डिस्काउंट करना, जो हिन्दुस्तान के बाहर चुकाये जाने वाले हों।
- (५) बैंक की जमाओं को उन जमानतों पर सूद से लगाना, जिनका वर्णन दफा १ में “अ” से “ई” तक किया गया है और ऐसी जमानतों को जब आवश्यकता हो तभी नकदी में बदलना तथा ऊपर वर्णन की हुई जैसे कोई दूसरी जमानतों में बदलना।
- (६) ऐसे बैंक पोस्ट बिल और लेटर आब्सचेंज लिखना, जारी करना और बनाना, जो हिन्दुस्तान और सीलों में काबिल अदायगी हों और हिदायती (Order)

या भाँगने पर उपस्थित करनेवाले (Bearer) को देने के सिवाय दूसरे प्रकार के हों ।

- (७) सोना और चाँदी खरीदना या बेचना चाहे सिन्के-वाली हो या बिना सिन्केवाली ।
- (८) अमानतें जमा रखना और मंजूर की हुई शर्तों के अनुसार नक़दी का खाता रखना ।
- (९) सोना-चाँदी के पाँसे, जवाहिरात, दस्तावेजात—हकी-यत या दूसरी मूल्यवान् वस्तुओं को क़र्ज़ में मंजूर की हुई शर्तों पर मंजूर करना ।
- (१०) उस जायदाद मनकूला और ग़ैरमनकूला को बेचना और उसकी कीमत वसूल करना, जो किसी प्रकार से बैंक के क़ब्जे में उसके दावे की पूर्ति या उसके किसी हिस्से की पूर्ति में आई हो ।
- (११) दफ़्ता-पैसा-सम्बन्धी एजेन्सी का काम करना ।
- (१२) वहैसियत ऐडमिनिस्ट्रेटर, प्रबन्धक या अमानतदार जायदाद का तस्फ़ीया करने के वास्ते काम करना और वतौर एजेण्ट के नीचे लिखे हुए धन्धों का लेन-देन कमीशन पर करना :—
क—किसी सार्वजनिक कम्पनी की जमानतों या हिस्सों को खरीदना, बेचना, मुन्तक़िल करना और अपनी सहवील में लेना ।

घ—हर एक प्रकार की जमानत और शेयर की असली कीमत, सूद या मुनाफा वसूल करना ।

ग—ग्रौर ऐसी वसूल शुदा रकम का मालिक की जोखिम पर सार्वजनिक या निजी विनिमय बिल, जो भारत या अन्य किसी देश में काबिल वसूल हा, के द्वारा भुगतान करना ।

(१३) विनिमय बिल और लेटर आव् क्रेडिट, जो भारत के बाहर काबिल वसूल हों, न० ११ में वर्णन किये कामों के लिये या अपने ग्राहकों की निजी जरूरियात के लिये जारी करना ।

(१४) ड—उक्त प्रकार के जारी किये हुए बिल आव् एक्सचेज और लेटर आव् क्रेडिट की अदायगी के वास्ते मेजने के लिये ऐसे विनिमय बिल खरीदना, जो भारत के बाहर काबिल वसूल हों और किसी भी मुद्दत के हों, जो ६ महीने से अधिक की न हो ।

(१५) घ—बैंक के कारबार के लिये भारत में रुपया उधार लेना और ऐसी उधार की हुई रकमात के लिये बैंक की सम्पत्ति को रहन करके या दूसरे तरीके से जमानत देना ।

(१६) छ—इंग्लैण्ड में बैंक के कारबार के लिये बैंक की सम्पत्ति की जमानत पर रुपया उधार लेना न कि दूसरे तरीके पर ।

ज—आम तौर पर ऐसे मामले और काम करना, जो ऊपर वर्णन किये हुए भिन्न भिन्न प्रकार के धंधों को पूरा करने और उनकी मदद के लिये आवश्यक हों।

दूसरा भाग

वे काम, जिनको करने का अधिकार बैंक को नहीं है।

बैंक उन कामों के अतिरिक्त, जो पहिले हिस्से में वर्णन किये गये हैं, अन्य किसी प्रकार का भी बैंकिंग धन्धा नहीं कर सकेगा और विशेष तौर से—

(१) वह उधार नहीं दे सकेगा—

अ—लम्बे समय के लिये, जो ६ माह से अधिक हो।

आ—बैंक के स्टॉक या शेयर की ज़मानत पर।

इ—सिवाय उन जायदादों के, जिनके लिये पहिले हिस्से के क्लॉज़ नं० ३ में वर्णन किया है, किसी जायदाद गैर-मनकूला या तत्सम्बन्धी दस्तावेज़ात—हकीयत की (रहन रखकर या किसी तरह से) ज़मानत पर।

(२) बैंक (सिवाय पहिले हिस्से के क्लॉज़ नं० १ के सब क्लॉज़ “अ” से “उ” तक नियत की हुई ज़मानतों के)

किसी एक व्यक्ति या शराकती दूकान के बिल किसी एक समय में सब मिलाकर उस रकम से अधिक, जो नियत कर दी जावे, डिस्काउण्ट नहीं कर सकेगा या किसी एक व्यक्ति या शराकती दूकान को किसी एक समय में सब मिलाकर उस रकम से अधिक, जो उसक लिये नियत कर दी जावे, उधार न दिया जावेगा।

(३) धक किसी व्यक्ति या शराकती फर्म की ऐसा बेची जाने योग्य दस्तावेज को न डिस्काउण्ट कर सकेगा न खरीद सकेगा और न उसकी जमानत पर उधार दे सकेगा या धाकी रख सकेगा, जो उसी कस्बे या स्थान पर काबिल अदायगी हो, जहाँ डिस्काउण्ट के लिये उपस्थित की जावे, जब तक उस पर कम से कम ऐसे दो व्यक्ति या दो फर्मों की, जिनका एक दूसरे के साथ आम शराकती सम्बन्ध न हो, जिम्मेदारी शामिल न हो गई हो।

(४) धक किसी बेचे जाने योग्य दस्तावेजों को डिस्काउण्ट नहीं कर सकेगा और न खरीद सकेगा या उनकी जमानतों पर उधार दे सकेगा अथवा धाकी रख सकेगा, जो लेन-देन की तारीख से छ माह से अधिक मुदत की हों या यदि देखने के बाद की मुदत की लिखी हों तो छ माह से अधिक मुदत के

लिये लिखी हुई न हो; किन्तु इस हिस्से से यह न समझा जावेगा कि बैंक के लिये किसी व्यक्ति को, जो उससे खाता रखता है, जमा से अधिक विला ज़मानत उस हद तक, जो नियत कर दी जावे, देने की हकायत है।

सारांश यह है कि यह इस देश का एक प्रमुख व्यवसायिक बैंक है और सब प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय करता है, लेकिन इसको छः माह से अधिक अवधि के लिये और अचल सम्पत्ति की ज़मानत पर उधार देने का अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष ध्यान देने योग्य यह बात है कि यह बैंक भारत के बाहर बिना ज़मानत दिये न तो रुपया उधार दे सकेगा और न अमानतें जमा कर सकेगा। इसका यह अभिप्राय है कि यह भारत, ब्रह्मा और सीलोन के बाहर कोई धनधा नहीं कर सकता। लन्दन में ब्राञ्च खोलने की आज्ञा केवल सरकारी काम धर्तौर आदृतिया करने के लिये दी गई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस प्रकार इसको विदेशी विनिमय का धनधा करने की आज्ञा न देकर विदेशी बैंकों के अधिकृत व्यापार की रक्षा की गई है, उस प्रकार भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करके व्यापार न छीन सकने के वास्ते कोई उपाय नहीं किया गया; इसलिये यह स्वतन्त्रता-पूर्वक उन स्थानों पर, जहाँ पहिले से अच्छे अच्छे ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के दफ्तर मौजूद हैं, अपनी शाखाएँ खोल रहा है और

उसका व्यवसाय छीन रहा है। इसको कहते हैं, “जितकी लाठी उसकी भैंस।”

कोऑपरेटिव बैंक

उक्त वर्णित ३ प्रकार (इम्पीरियल बैंक, विनिमय बैंक और ज्वाइंट स्टॉक बैंक) के बैंकों के अतिरिक्त कोऑपरेटिव बैंक भी भारत के बैंकिंग व्यवसाय में विशेष स्थान रखते हैं। इसका जन्म भारत में सहकारिता के प्रचार के साथ साथ हुआ है।

कृषकों की भलाई के लिये सहकारिता को जन्म देने का विचार भारत में सबसे पहले सन् १८६२ ई० में उत्पन्न हुआ था। मद्रास सरकार ने सर फ्रेडरिक निकोलसन I. C. S. को भारत में इसका प्रचार करने के हेतु थोरप में अनुभव प्राप्त करने के लिये भेजा था। इन्होंने सन् ८६ ई० में अपनी रिपोर्ट (सन् १८६५-६७ ई०) मद्रास सरकार के सामने उपस्थित की थी, जो भारत सरकार के सामने सन् १९०० ई० में आई थी। इसी समय के लगभग कुछ सहकारी समितियाँ मि० हूपर मेन्स I. C. S ने संयुक्त प्रान्त में और मि० मेन्लेगन I. C. S ने पंजाब में स्थापित की थीं। सन् १९०१ ई० में भारत सरकार ने इस देश में सहकारिता के प्रचार के प्रश्न पर विचार करने के लिये सर एडवर्ड ला के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की थी। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के उपयुक्त रेफीशन प्रणाली

के अनुसार सहकारी-समितियाँ स्थापित करने के लिये सिफ़ारिश की थी । इसके अतिरिक्त फ़ेमिन कमेटी १९०१ ने भी पारस्परिक साख-संस्थाओं (Mutual Credit associations) की स्थापना के लिये सिफ़ारिश की थी । इन सिफ़ारिशों के परिणाम-स्वरूप सर डेनज़िल इच्चेटसन ने व्यवस्थापक सभा में एक बिल उपस्थित किया, जो सन् १९०४ ई० में क़ानून नं० १० पहला कोआपरेटिव ऐक्ट के नाम से पास हुआ । इसके पास होने से २ वर्ष के अन्दर २८०० समितियाँ की स्थापना हुई और प्रति वर्ष उत्तरोत्तर संख्या बढ़ती गई । कुछ समय कार्य करने के बाद यह क़ानून कुछ भ्रष्टि-पूर्ण सात हुआ और उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई । तब सन् १९१२ ई० में दूसरा क़ानून नं० ११ पास हुआ । इसी क़ानून के आधार पर भारत में आज कल सहकारी-समितियों का संचालन होता है । केवल बम्बई और ग्रह्या में अभी हाल में बने हुये स्थानीय क़ानून द्वारा कार्य होता है । सन् १९१५ में फिर सरकार ने सहकारिता के प्रचार का अनुसन्धान करने के लिये मेक्लेगन कमीशन बिठाया । इसकी रिपोर्ट प्रकाशित होने के पश्चात् इस धन्धे को गहरी उत्तेजना मिली । प्रान्तीय बैंकों की स्थापना का श्रेय इसी कमीशन को प्राप्त है ।

वर्त्तमान सहकारी संस्थाओं को ३ श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :—

१—ग्रामीण समितियाँ, २—सेण्ट्रल बैंक, ३—प्रान्तीय बैंक ।

ग्रामीण समितियाँ—सहकारिता का आर्थिक संगठन इन ग्रामीण समितियों से आरम्भ होता है। यह समितियाँ ऋण लेने और न लेनेवालों को, जो एक गाँव में रहते हैं, एक दूसरे को जानते पहचानते हैं और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की भलाई-बुराई में दिलचस्पी लेते रहते हैं, मण्डली होती है। इस मंडली द्वारा एक गाँव के भिन्न भिन्न स्थिति के लोग उस गाँव के आर्थिक संगठन में शामिल होते हैं और एक दूसरे को भ्रातृभाव पूर्वक सहायता पहुँचाते हैं। इस प्रकार की समितियों का जन्म सत्तार में सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ और ऐसे समय में हुआ, जब वहाँ के कृषक आर्थिक संकट से पिस रहे थे और कृषक तथा छोटे कारीगर लालची सूदखोरों द्वारा लूटे जा रहे थे। उनको बढती हुई इस असह्य गरीबी और असहाय अवस्था को देखकर उस देश की दो परोपकारी आत्माओं का हृदय स्तब्ध हो उठा और उन्होंने अर्थ पीड़ितों का संकट दूर करने के लिये सहकारिता की स्थापना की। मिस्टर शुल्ज़ेडेलिट्ज़ (Schulze Delitzsch) ने छोटे दस्तकारों और व्यापारियों को और मिस्टर रेफिशन ने कृषकों की समितियाँ बनाना आरम्भ किया। वहाँ इन समितियों से ऋण ग्रस्त कृषकों और छोटे कारीगरों को अधिक लाभ पहुँचा, इसलिये इस प्रणाली का सत्तार के प्रत्येक देश ने अनुकरण किया है। भारत में भी सहकारी समितियाँ रेफिशन की सूझ क नमूने की नकल है, लेकिन यहाँ इन समितियों की स्थापना प्रजा के उद्योग से नहीं हुई,

बलिक भारत-सरकार ने कृषक-समुदाय की बढ़ी हुई सुदखोरी से रक्षा करने और कृषि कार्य के लिये कम व्याज पर आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से को है। इनके प्रबन्ध और संचालन के लिये प्रत्येक प्रान्त में एक-एक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है, जो इन समितियों के तमाम मामलों को देखता व सुनता है और इनके सदस्यों के कार्य का निरीक्षण और प्रबन्ध करता है। निःसन्देह रजिस्ट्रार कृषक-प्रजा का परम मित्र, शुभ-चिन्तक और पथ-प्रदर्शक होता है।

इनका संगठन बिल्कुल साधारण है। उस गाँव का प्रत्येक रहनेवाला, जो साथी मेम्बरों की दृष्टि में भला आदमी हो, समिति का मेम्बर बन सकता है। दस व्यक्ति मिलकर एक सभा बना सकते हैं। सभा की पूँजी में वह तमाम ज़मीन, जायदाद, पशु इत्यादि सम्पत्ति शामिल है, जो उसके मेम्बरों की है। इसका व्योरा नक़शा हैसियत (Property statement) में दर्ज किया जाता है। इस नक़शा हैसियत का पुनर्मीलान प्रति वर्ष होता रहता है और इसको हमेशा सही रखा जाता है। इसको सावधानी से तैयार करना और पुनर्मीलान करना सभा का प्रमुख कार्य है। क्योंकि ऋण देने का सारा आधार इसके अंकों पर निर्भर रहता है। नक़शा हैसियत के आधार पर मेम्बर को ऋण देने की सीमा कायम की जाती है। यह समितियाँ अपने मेम्बरों की सम्मिलित और असीमित ज़िम्मेदारी पर बड़ी समितियों—सेण्ट्रल-बैंक और प्रान्तीय-बैंकों से ऋण लेती हैं और अपने

मेम्बरों को उधार देती हैं, लेकिन ये समितियाँ अपने सदस्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों की श्रमानतें जमा नहीं रखती हैं। ऐसी समितियाँ ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में लगभग १ लाख के हैं, जिनके सदस्यों की संख्या लगभग ४० लाख तक पहुँच चुकी है।

सेंट्रल-बैंक—एक ज़िले की समस्त समितियाँ मिलकर एक केन्द्रीय समिति कायम करती हैं, जिसे सेंट्रल-बैंक कहते हैं और इनका दफ्तर आमतौर पर ज़िले के सदर मुक़ाम पर या किसी खास क़सबे में होता है। ये बैंक अधिकांश में सीमित ज़िम्मेदारी के साथ स्थापित किये जाते हैं और इनकी पूँजी हिस्सों द्वारा संप्रदा की जाती है। इनके मेम्बर सहकारी समितियों के अतिरिक्त दूसरे लोग व्यक्तिगत रूप से भी हो सकते हैं। इनका संचालन एक व्यवस्थापक-मण्डल (Board of Directors) द्वारा होता है, जिसमें सहकारी समितियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत मेम्बरों के चुने हुए व्यवस्थापक भी होने हैं। ये बैंक ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों की भाँति, सयंसाधारण की सब प्रकार की श्रमानतें जैसे मियादी, करेंट और सेविंगज़ बैंक आदि की कम सूद पर जमा रखते हैं। ये इम्पीरियल बैंक से भी उधार लेते हैं। ये जमा रखी हुई और उधार ली हुई रक़मों ग्रामीण सहकारी समितियों को कुछ अधिक व्याज की दर से उधार देते हैं। व्याज की न्यूनाधिक दर से इनको जो लाभ होता है, उसको ये अपने हिस्सेदारों में विभाजित करते हैं, लेकिन आम तौर पर ६ प्रतिशत से अधिक

मुनाफ़ा नहीं वांटने। कहीं कहीं बारह प्रतिशत भी वांटा जाता है। बम्बई प्रोविन्शियल कोऑपरेटिव बैंक ने दस प्रतिशत और कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कोटा ने ६ प्रतिशत से अधिक मुनाफ़ा बांटने की क़ानून द्वारा रोक लगा रखी है। इस प्रकार के बैंकों की संख्या ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों में लगभग छः सौ के है, जिनका मूलधन और रिजर्व फ़ंड लगभग चार करोड़ के है और जिनमें २० करोड़ के लगभग अमानतें जमा हैं।

प्रान्तीय बैंक—प्रत्येक गवर्नरी-प्रान्त के समस्त सेण्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक मिलकर एक बड़ी केन्द्रीय समा स्थापित करते हैं, जिसको प्रान्तीय बैंक कहते हैं। यह बैंक सर्वसाधारण की अमानतें कम ब्याज पर खींचने में समर्थ हो जाते हैं। इन्होंने इम्पीरियल बैंक तथा ज्वाइण्ट स्टॉक बैंकों से उधार लेने का प्रबन्ध भी कर रखा है। इस प्रकार संग्रह की हुई पूँजी को ये सेंट्रल बैंकों को उधार देते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक ज्वाइण्ट स्टॉक बैंकों की भाँति सब प्रकार का बैंकिङ्ग व्यवसाय जैसे व्यक्तिगत मेम्बरों को अनाज, ज़ेवर आदि वस्तुओं पर उधार देना चेक, हुण्डी, बिल को संग्रह करना और देश के अन्दर भुगतान करना आदि करते हैं। इन बैंकों का एक संयुक्त इंडियन प्रोविन्शियल को-ऑपरेटिव बैंक एसोसियेशन है, जो इनको आर्थिक, क़ानूनी और शासन-सम्बन्धी सहायता दिलाने के लिये प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार के भारत में ८ बैंक हैं यथा :—आसाम, बंगाल, बिहार,

उड़ीसा, बम्बई, ब्रह्मा, मध्य-प्रान्त, मद्रास और पंजाब में। इन सब का मूल धन और रक्षित-फंड रु० १,४५,५४,०००) है और इनमें रु० ६,१२,२१,०००) की अमानतें जमा हैं। गवर्नरी प्रान्तों में केवल संयुक्त प्रान्त ही ऐसा है, जहाँ इस प्रकार का बैंक नहीं है। यह इस प्रान्त में भारी कमी है, जिसको दूर करने के लिये संयुक्त प्रान्तीय बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटी ने जोरों के साथ सिफारिश की है।

सहकारिता की उन्नति समस्त भारत में एक सी नहीं हुई है। रोयल कमीशन के शब्दों में पंजाब, मद्रास और बम्बई के अतिरिक्त प्रान्तों में यह प्रथा ग्रामीण प्रजा तक बहुत कम पहुँची है। संयुक्त प्रान्त में केवल १८ प्रतिशत लोग इससे लाभ उठा पाये हैं। इससे यह परिणाम निकलता है कि भारतीय कोओपरेटिव बैंकिंग की उन्नति संतोष-जनक नहीं हो रही है। बीस वर्ष के प्रचार के बाद भारत में कृषि-उधार-सहकारी समितियाँ द्वारा उधार दी हुई पूँजी ३० करोड़ से अधिक नहीं बढ़ी। भारत के कृषकों पर अनुमानतः ६०० करोड़ रुपयों का ऋण समझा जाता है; अतः जहाँ ७ रुपया कोओपरेटिव सोसाइटी का एक कृषक परिवार की ओर लेना है, वहाँ २०० रु० महाजनों का उन पर चाहिये। इसके अलावा २५ वर्षों में एक लाख जनसंख्या पीछे ३३५ समितियाँ* स्थापित हुई हैं, जो इसकी

* एक समिति में ४० सदस्यों का औसत है।

पिछड़ी हुई अवस्था की द्योतक है। इस सम्बन्ध में सर डेनियल हेमिल्टन ने निराशाजनक शब्दों में यह कहा है :—

“हमारे यहाँ (भारत में) सात लाख गाँव हैं। वर्तमान प्रगति के अनुपात से प्रत्येक गाँव में सहकारी समिति स्थापित होने के लिये सन् २२०० तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है।”

भूमि-बन्धक बैंक

(LAND MORTGAGE BANK)

जो बैंक जुताऊ-भूमि को रहन रखकर लम्बी अवधि अर्थात् ५०-६० वर्ष तक के लिये उधार देते हैं, उन्हें भूमि-बंधक बैंक कहते हैं।

उधार लेनेवाला व्यक्ति अपनी भूमि को इन बैंकों में रहन कर देता है और उसकी ज़मानत पर उधार ली हुई रकम को धीरे धीरे ५०-६० वर्षों में छोटी छोटी किस्तों से, जो व्याज से कुछ ही अधिक रकम की होती हैं, चुका देता है। इस प्रकार के बैंक ज्वाइंट स्टॉक बैंक या व्यावसायिक बैंक के समान और कोई धन्दा नहीं करते और न चल्लु खाते में तथा थोड़ी अवधि की मियादी अमानतें, जमा रखते हैं। ये आम तौर पर लम्बी मियाद के लिये रकम जमा रखकर और डिबेञ्चर जारी करके पूँजी बढ़ाते हैं।

लम्बी अवधि के लिये अमानतें प्राप्त करना बड़ा कठिन होता है, इसलिये अधिकतर ये बैंक डिबेञ्चर द्वारा पूँजी संग्रह करते

हैं। डिपेंडर छोटी रकम के होते हैं, जिन्हें साधारण स्थिति के लोग भी खरीद सकने में समर्थ हो सकते हैं।

इस प्रकार के बैंकों का सूत्रपात सर्वप्रथम जर्मनी में हुआ है। वहाँ इनके द्वारा कृषि की पर्याप्त उन्नति हुई है। उसको देखकर दूसरे देशों ने भी अपने यहाँ इस प्रकार के बैंकों का प्रचार बढ़ाया है। अनेक देशों में इन बैंकों को सरकार से यह कानूनी सुविधा प्राप्त है कि ये प्रतिष्ठानुसार कृषक के रुपया न चुकाने पर भूमि पर बिना अदालती कार्रवाई किये अधिकार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार इस प्रकार के बैंकों को हर तरह से अधिक सहायता प्रदान करती है—ये तीन प्रकार के होते हैं :—

१—सहकारी (Co-operative)

२—असहकारी (Non-co-operative)

३—अर्ध सहकारी (Quasi-co-operative)

भारत में केवल पहिली श्रेणी के बैंकों का कोओपरेटिव कानून के आधीन स्थापित होना आरम्भ हुआ है। इस प्रकार के बैंक पंजाब, मद्रास, बम्बई और छोटे रूप में आसाम और बंगाल में काम कर रहे हैं, इनकी कुल संख्या ६४ है :—

पंजाब १२

मद्रास ४२ (इस प्रान्त में सेण्ट्रल मोर्टगेज बैंक भी है।)

बम्बई ३

बंगाल २

आसाम ५

जोड़ ६४

शेष प्रान्तों में ऐसे बैंक नहीं हैं। वहाँ अनुभव रूप में चालू करने के लिये सम्बन्धित प्रान्तीय बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटियों ने सिफारिशों की हैं।

पोस्ट-आफिस-सेविंग्स बैंक

इम्पीरियल - बैंक, ज्वाइंट स्टॉक बैंक और कोओपरेटिव बैंकों ने अपने यहाँ दूसरी प्रकार की जमाओं के साथ साथ सर्व-साधारण द्वारा बचाई हुई पूँजी को जमा करने के लिये सेविंग्स बैंक के नाम से खाते खोल रखे हैं, लेकिन इस प्रकार की वचन को जमा करने में प्रमुख स्थान पोस्ट आफिस सेविंग्स-बैंक ने प्राप्त कर रखा है। भारत में इस प्रणाली का सूत्रपात सन् १८३३ ई० से हुआ है। आरम्भ में सरकारी सेविंग्स बैंक प्रेसीडेन्सी शहरों में खोले गये थे। सबसे पहिला गवर्नमेण्ट सेविंग्स बैंक १ नवम्बर सन् १८३३ ई० को कलकत्ते में स्थापित हुआ था। इसके बाद सन् १८७० में चुने हुये स्वजानों से सम्बन्धित जिला सेविंग्स बैंक खोले गये। सन् १८८२ ई० में एक बहुत उपयोगी पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक सम्बन्धी कानून पास हुआ तब से पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंकों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही। पोस्ट आफिस का विस्तृत और सुदृढ संगठन है। प्रत्येक अच्छे बड़े गाँव के पोस्ट आफिस में सेविंग्स बैंक का धन्धा होता है। इनमें छोटी छोटी श्रमानतें बहुत अधिक जमा होती हैं, जिनमें अधिकतर जमा करनेवाले मध्य श्रेणी के तनखाहदार

नौकर होते हैं। सन् १९२८ के अन्त तक १२,३२६ सेविंग्स-बैंक थे, जिनमें २६,०६,०७१ जमा करनेवालों के ३२,६६,६८,१८८ रु० जमा थे। इससे यह प्रगट होता है कि प्रत्येक पोस्ट-ऑफिस में २६,८२७ रुपये और प्रत्येक जमा करनेवाले के पीछे १२६ रुपये जमा थे। सन् २८ के बाद सम्भव है थोड़ी-बहुत और वृद्धि हुई हो, लेकिन अभी पोस्ट-ऑफिसों द्वारा और सुविधाएँ दी जाकर लोगों की बचाकर जमा करने की आदत को और बढ़ाया जा सकता है।

भारतवर्ष में सेविंग्स-बैंक के खातों और उनमें जमाशुदा रकमों की संख्या संसार के किसी भी दूसरे देश की तुलना में बहुत ही कम है। इसका कारण यह है कि भारत की अधिक जनसंख्या देहात में रहती है। उसमें से भी अधिकांश ऋण के भार से पेशी बंधी हुई है कि सेविंग्स बैंक में जमा करने के लिये १ पाई भी नहीं बचा पाती। जो थोड़ी-बहुत संख्या बचानेवाली है, वह अनुकूल साधन न होने से या तो ज़मीन में गाड़ती है या ज़ेबरा बगैरह बनाकर रखती है।

बीमा-कम्पनियाँ

बीमा-कम्पनियाँ भी भारतीय बैंकिंग की उन्नति का एक अंग है। एक बीमा-कम्पनी न केवल सेविंग्स बैंक की तरह सर्व-साधारण को बचत करने के लिये उत्साहित करती है, बल्कि सर्वसाधारण की बचत को देश के व्यापार और उद्योग-धन्धों

को आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये सदैव तत्पर रखने में सहायता देती हैं; इसलिये बिना इनके विवेचन के भारतीय बैंकिंग का अन्वेषण अधूरा रह जाता है।

बीमा कम्पनियाँ मनुष्य के जीवन के बीमे के अतिरिक्त जल और अग्नि से नष्ट होनेवाले चल और अचल पदार्थों का और कुछ प्रकार की दुर्घटनाओं का बीमा भी चुकाती हैं। भारत में जीवन-बीमा-प्रणाली का जन्म अंग्रेज़ी राज्य के संस्थापन के बाद हुआ है, लेकिन व्यापारिक राहदारी-माल (Goods in transit) का बीमा भारत में अधिक प्राचीन काल से चला आता है। जोखमी हुएड़ी खरीदनेवाला ठीक ऐसा ही काम करता था जैसा कि आजकल बीमा कम्पनियाँ करती हैं।*

भारत में कुल २७७ (सन् १९३० ई०) बीमा कम्पनियाँ हैं। इनमें १३० भारतीय और १४७ विदेशी हैं। भारतीय कम्पनियों में ६२ कम्पनियाँ केवल जीवन-बीमा का काम करती हैं, १८ जीवन-बीमा के साथ दूसरी प्रकार का बीमा भी करती हैं। २० कम्पनियाँ केवल दूसरी प्रकार का बीमा करती हैं, जीवन-बीमा का काम नहीं करतीं। विदेशी कम्पनियों में ६ कम्पनियाँ

* The buyer of such hundis (Jokhami) therefore acts, as an insurance Agent. "*Indigenous Banking in India*" P. 78.

केवल जीवन बीमा, १४ कम्पनियाँ जीवन व दूसरी प्रकार का और १२४ कम्पनियाँ जीवन-बीमा को छोड़कर दूसरी प्रकार का बीमा करती हैं।

बैंकिंग का सम्बन्ध अधिकांश में जीवन बीमा कम्पनियों से ही है, क्योंकि सर्वसाधारण को बचत यापस देने के लिये इन्हीं में जमा होती है, इसलिये यहाँ विशेष तौर से इन्हीं पर विचार किया जाता है।

भारतीय बीमा कम्पनियाँ का व्यवसाय दूसरे देशों की समता में अभी तक बहुत पिछड़ा हुआ है, हालाँकि यहाँ जीवन बीमा का प्रचार १९ वीं सदी के मध्य ही में आरम्भ हो गया था। सबसे पहिली जीवन बीमा कम्पनी का मद्रास प्रान्त में, मद्रास इक्वीटेबल कम्पनी के नाम से सन् १८२६ ई० में जन्म हुआ था, किन्तु महायुद्ध के बाद इसका अन्त हो गया। पुरानी कम्पनियाँ में सबसे प्रसिद्ध भारतीय कम्पनी, जो आज तक उत्तरोत्तर उन्नति करती चली आ रही है, बम्बई की ओरियण्टल कम्पनी है, जो सन् १८७४ ई० में स्थापित हुई थी। तत्पश्चात् स्थापित होनेवाली अनेक कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की है, लेकिन इनकी विशेष उन्नति सन् १९२० ई० के बाद आरम्भ हुई है:—

बीमा कम्पनियों का प्रगति-सूचक कोष्ठक*

वर्ष	वर्षान्तर्गत काम	वर्ष के अन्त में रहा हुआ काम
१९२०	५१७ लाख	३१ करोड़
१९२१	५४६ "	३८ "
१९२२	५६४ "	३७ "
१९२३	५८५ "	३६ "
१९२४	६८६ "	४२ "
१९२५	८१५ "	४७ "
१९२६	१०३५ "	५३ "
१९२७	१२७७ "	६० "
१९२८	१५४१ "	८१ "
१९२९	१७२६ "	८२ "
१९३०	१६५० "	८६ "

उपरोक्त कोष्ठक से पता चलता है कि सन् १९२० ई० से सन् १९३० ई० तक लगभग तिगुनी उन्नति हुई है। दूसरे देशों में यह घन्धा कहीं अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है। उनसे तुलना करने पर हम अपने आपको सबसे पीछे पाते हैं। यथा :—

* The Indian Insurance Year-book 1931. P. 4

[प्रति मनुष्य पीछे बीमे का तुलनात्मक कोष्ठक]*

देश	प्रति मनुष्य (डालर)	प्रति मनुष्य (रुपया)
संयुक्त राज्य अमेरिका	८४३	२३१८'२
कनाडा	६४०	१८६०'०
न्यूजीलैण्ड	३५८	६८४'५
आस्ट्रेलिया	२७३	७५०'७
संयुक्त प्रदेश	२६६	७३१'५
स्वीडन	२०५	५६३'७
इटली	१५२	४१८'०
मार्शे	१३७	३७६०'७
नेदरलैण्ड	१२३	३३८'२
भारतवर्ष ^१	२	५'५

भारतीय बीमा-कम्पनियों के पास सर्वसाधारण की २७ करोड़ के लगभग पूँजी है, जिसका ७६ प्रतिशत सरकारी ज़मानतों पर लगा हुआ है, लगभग १ प्रतिशत पोलिसियों की वसूल-शुदा रकम की ज़मानत पर उधार दे रक्खा है और ३३ करोड़ के लगभग भारत के बाहर लगाया हुआ है। विदेशी कम्पनियों के पास भारतवासियों की लगभग ३४ करोड़ की सम्पत्ति है। इसके

* Indian Finance Year-book 1932 P 113.

लिये ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि यह किन किस में और कहाँ कहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन यह अवश्य कहा जा सकता है कि इन विदेशी कम्पनियों में जमा की हुई भारतीय पूँजी का बहुत बड़ा भाग विदेशों में भेजकर उधार दिया जाता है। भारतीय सराफा-बाजार (Money-Market) को विदेशी कम्पनियों के पास की भारतीय पूँजी ने कोई लाभ नहीं पहुँचता। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रीमियम का एक निश्चित भाग सरकारी जमानतों में रखना पड़ता है। यहाँ भी भारतीय कम्पनियों के लिये कानून में इस प्रकार का विधान है, लेकिन विदेशी कम्पनियों को इससे मुस्तसना रक्खा गया है। यह भेद-भाव भी भारतीयों के लिये लज्जाजनक है। दूसरे देशों में बीमा-कम्पनियाँ न केवल सरकारी जमानतों पर बल्कि औद्योगिक डिबेन्चर और भूमि-बन्धक डिबेन्चर तक पर रुपया लगाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो ऐसी कम्पनियाँ कृषकों को जमीन ख़रीदने के लिये साधारण किस्तों पर उधार देती हैं। यदि यहाँ भी ये कम्पनियाँ इस प्रकार उद्योग धन्धों और कृषि की सहायता करें तो यहाँ के उद्योग-धन्धे आर्थिक सहायता के अभाव में असफल न हो सकें। हर्ष की बात है कि सेण्ट्रल बैंडिङ्ग इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में सतोष-जनक सिफारिश की है।*

* We consider it essential for the economic development of the country that all insurance companies doing business in it, whether Indian or non-Indian

क्लियरिंग हाउस

क्लियरिंग हाउस की स्थापना के पहिले बैंकों के क्लर्क चेकों के बण्डल अपने साथ लेकर अनेक सम्बन्धित बैंकों में जाकर रुपया वसूल करते थे। इस प्रणाली से एक तो अधिक समय नष्ट होता था, दूसरे उन्हें मिहनत बहुत करनी पड़ती थी, इसलिये ये क्लर्क कहीं एक जगह बैठकर इन चेकों का विनिमय करने लगे। इस प्रकार से क्लियरिंग हाउस की स्थापना का बीजा-रोपण हुआ। गितवर्ट के कथमानुसार सर्वप्रथम लन्दन क्लियरिंग हाउस सन् १७७५ ई० में स्थापित हुआ था। आरम्भ में बहुत से बैंकर उससे अलग रहे, लेकिन बाद में सुविधा देखकर शनैः शनैः सब शामिल हो गये। भारत में भी १० जगह क्लियरिंग हाउस हैं :—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, रंगून, कराँची, दिल्ली, लाहौर, शिमला, अहमदाबाद और कानपुर। ये क्लियरिंग हाउस केवल स्थानीय चेकों का लेन-देन तय करते हैं न कि अपने नगर से बाहर के बैंकों पर जारी किये हुए चेकों का। ऐसे चेक सम्बन्धित बैंकों या एजेण्टों द्वारा संग्रह किये जाते हैं। यह धनचा इम्पोरियल बैंक की निगरानी और उसकी इमारतों में होता है।

should by a Judicious investment of their funds assist in the promotion of public utility undertakings and the finance of the trade and industry of the country generally 'Para 660'

मेम्बर बैंक—वर्म्बई क्लियरिंग हाउस का मेम्बर वह बैंक हो सकता है, जिसको मेम्बर बनाने के लिये २ मेम्बर बैंकों के प्रस्ताव और अनुमोदन करने पर समस्त बैंकों ने लिखित मत (Ballot) द्वारा स्वीकार कर लिया हो । इस समय इसके निम्न लिखित बैंक और कम्पनियाँ मेम्बर हैं :—

१ इलाहाबाद बैंक, २ बैंक आफ् बडोदा, ३ बैंक आफ् इडिया, ७ बैंक आफ् टैवन, ५ बोम्बे-प्रासिन्धियाल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, ६ सेण्ट्रल बैंक आफ् इडिया, ७ चार्टर्ड बैंक आफ् इडिया, आस्ट्रेलिया और चाइना, ८ कोम्पटोयर डि एस्कोम्प्ट डी पेरिस, ९ थोमस कुक ऐण्ड सन्, १० ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, ११ ग्रीण्डले ऐण्ड कम्पनी, १२ हॉगफॉग ऐण्ड संघाई बैंकिंग कोरपोरेशन, १३ इम्पीरियल बैंक आफ् परसिया, १४ लोयड्स बैंक, १५ मरकेण्टाइल बैंक आफ् इडिया लिमिटेड, १६ मिटसुई बैंक लिमिटेड, १७ नेशनल बैंक आफ् इण्डिया लिमिटेड, १८ नेशनल सिटी बैंक आफ् न्यूयार्क, १९ नेदरलैण्ड इण्डिया कमर्शियल बैंक, २० नेदरलैण्ड ट्रेडिंग सोसाइटी, २१ पी० ऐण्ड ओ० बैंकिंग कोरपोरेशन, २२ पंजाब-नेशनल बैंक लिमिटेड, २३ सुमीटोमो बैंक, २४ यूनियन बैंक आफ् इण्डिया, २५ योकोहामा स्पेसी बैंक लिमिटेड ।

लेन-देन तय करने का तरीका—नियत समय पर मेम्बर बैंकों के क्लर्क क्लियरिंग हाउस के अन्दर पहुँचकर अपने स्थानों पर बैठ जाते हैं । वहाँ प्रत्येक मेम्बर बैंक को क्लियरिंग भा० बैं०—५

हाउस से एक विवरण-पत्रिका (Summary Sheet) दी जाती है, जिसमें प्रत्येक मेम्बर बैंक के नाम का खाता जमानावे के कालमें सहित होता है। प्रत्येक बैंक-कलक अपनी-अपनी विवरण पत्रिका में दूसरे बैंकों से उस पर आये हुए चेक आदि उन देने-वाले बैंकों के कालमें जमा दाँघ लेता है और दूसरे बैंकों पर आये हुए चेकों के बराबर वह अपने पास से उन्हें देकर उनको रकम उनके कालमें में नावे लिख देता है। समय समाप्त होने पर प्रत्येक बैंक-कलक अपनी अपनी विवरण पत्रिका के कालमें का जोड़ लगाते हैं और दूसरे बैंकों के साथ अपनी आवजाब का मीलान करके लेनी देने की बकाया निकालते हैं। यदि बकाया देने निकलती है तो वह इम्पीरियल बैंक में अपने चालूखाते नावे लिखाकर क्लियरिंग-बैंकर्स एकाउण्ट खाते जमा करवा देते हैं और यदि बकाया लेनी निकलती हो तो इम्पीरियल बैंक उतनी रकम क्लियरिंग बैंकर्स एकाउण्ट खाते नावे लिखकर उस बैंक के चालू खाने जमा कर लेता है।

यदि बैंक रुपया जमा न होने या हस्ताक्षर न मिलने अथवा बेचाण (endorsement) ठीक न होने आदि कारणों से वापस लौटाये जाते हैं तो उसी दिन दूसरी क्लियरिंग के अवसर पर वापस लौटा दिये जाते हैं और उनको रकम ऊपर की तरह दोनों बैंक अपनी अपनी शीट में नावे जमा कर लेने हैं।

इत प्रकार क्लियरिंग कहीं कहीं दो बार और कहीं एक बार होता है, लेकिन शनिवार को सब जगह १ बार होता है।

इन क्लियरिङ्ग हाउसों में बहुमत विदेशी बैंकों का है; इसलिये इनमें भारतीय बैंकर मुश्किल से शामिल होने पाते हैं। कनाडा में क्लियरिङ्ग हाउस के मेम्बर वे ही बैंकर हो सकते हैं, जिनकी रजिस्ट्री उस देश में हुई हो। आम तौर से तमाम देशों में क्लियरिङ्ग हाउस का संचालन सेण्ट्रल बैंक द्वारा होता है, लेकिन यहाँ सेण्ट्रल बैंक के अभाव में क्लियरिङ्ग हाउस का संगठन विदेशी विनिमय बैंकों का निजी है; इसलिये कनाड़े की तरह नियम सेण्ट्रल बैंक की स्थापना के बिना नहीं बन सकते।

क्लियरिङ्ग हाउस के प्रबन्ध से बैंकों का आपस में रुपया या नोट की भुगतान करने की दिक्कत से छुटकारा होता है और रोशन रखने की आवश्यकता भी बहुत कम रह जाती है। इससे सम्बन्धित लोगों के समय की बचत होती है और यह रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग सस्थाओं का सम्बन्ध स्थापित रखने के लिये बड़ा मूल्यवान साधन है। अस्तु, रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद यह आशा की जाती है कि भारतीय क्लियरिङ्ग हाउसों की उन्नति संतोषजनक रूप में हो सकेगी जैसी कि दूसरे देशों में है।

चौथा अध्याय

प्रचलित साख-पत्र

आरम्भ काल में सर्वप्रथम वस्तु का वस्तु से विनिमय होता था, तत्पश्चात् मुद्रा ने जन्म लिया लेकिन जब मुद्रा को एक जगह से दूसरे जगह लाने से जाने में अधिक खर्चा और असुविधा होने लगी तो संसार में साख-पत्रों की सृष्टि हुई। इस समय भारत में करेन्सी नोटों के अतिरिक्त निम्नलिखित साख-पत्र प्रचलित हैं :—

- (१) हुंडी
- (२) पुर्जा
- (३) प्रोमेसरी नोट
- (४) चेक
- (५) बैङ्क-ड्राफ्ट
- (६) बिल आबू एक्सचेंज

हुंडी भारतीय बैङ्किंग प्रणाली में अति प्राचीन साख-पत्री (Instrument of credit) है, जिसके द्वारा लेनदेन का भुगतान बड़ी सरलता से होता रहा है। वेदों, सूत्रों और स्मृतियों में तो हुंडी शब्द नहीं आया है; लेकिन हुंडियों का व्यवहार भारतवर्ष में अज्ञात काल से प्रचलित है। हुंडी शब्द की उत्पत्ति के सम्बन्ध

में भिन्न भिन्न मत हैं। “कलकत्ता के प्रोफ़ेसर रामचन्द्र राव तो इसे फ़ारसी भाषा का शब्द बतलाते हैं, जिसका अर्थ है, संग्रह करना (To collect)। दूसरे मिस्टर सी० एन० कूक का कथन है कि यह शब्द हिन्दी और हिन्दू का अपभ्रंश है”।* बम्बई के प्रोफ़ेसर टैनम के शब्दों में हुंडी शब्द संस्कृत के ‘हुण्ड’ शब्द से बना है, इसका अर्थ करते हुए बंगला के शब्द कल्पद्रुम कोष में लिखा है “राशिः करोतीत्यर्थः” अर्थात् धन संग्रह करना। हुंडी भी धन संग्रह करने का ही काम करती है। इसका लिखनेवाला अपना इधर उधर पड़ा हुआ रुपया बड़ी आसानी के साथ संग्रह कर सकता है। अस्तु, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के ‘हुण्ड’ शब्द से होना अधिक सही है। इसके विशद प्रचार के सम्बन्ध में अति प्राचीन दो-तीन कथायें भी लोक में प्रसिद्ध हैं।

कथायें—(१) वस्तुपाल ने एक हुंडी दस करोड़ रुपये की अहमदाबाद के एक नगरसेठ पर बारहवीं सदी में की थी। इसी रकम से दिलवारा का मन्दिर सन् ११६७ और १२४७ के बीच में बनाया गया है। (२) दूसरी प्राचीन और प्रसिद्ध कथा नृसिंह मेहता के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें लिखा है कि जूनागढ़ के नृसिंह मेहता ने द्वारिका के साँवला सेठ पर लगभग २५०० वर्ष पहले भगवान् कृष्ण के ज़माने में हुंडी की थी। (३) इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि शिवाजी के समय में सूरत के आत्मा-

* Journal of the Indian Institute of Bankers, Jan 1932, P 27

राम बुखानन् के यहाँ बड़ा विस्तृत साहूकारी धन्धा था। उसकी हुण्डियाँ सुदूरस्थ स्थानों में सिकारी जातो थीं। उसकी ऊँची साख के सम्बन्ध में यह कथा प्रसिद्ध है—एक पुरुष को, जब वह जंगल में होकर गुज़र रहा था, रुपये की आवश्यकता हुई। उसने पास आत्माराम बुखानन् की हुण्डियाँ थीं।* उनमें से एक को उसने वृक्ष की एक शाखा से बाँध दिया। एक व्यापारी ने जो उसी मार्ग से होकर गुज़र रहा था, यह समझकर कि वह एक बड़े साहूकार की हुण्डी है, वहीं उस हुण्डी का रुपया दे दिया।

हुण्डी की व्याख्या—यद्यपि हुण्डी का विस्तृत व्यवहार एक बड़े प्राचीन काल से चला आता है, परन्तु अभी तक इसकी कोई व्याख्या किसी क़ानून में उपलब्ध नहीं है, निगोशियेबिल इम्स्ट्रूमेण्ट ऐक्ट की दफ़ा ५ में बिल्ट आक् एक्सचेन्ज़ की व्याख्या की गई है, जो बिल, प्रोमेसरी नोट, चेक और बहुधा हुण्डियाँ पर लागू होती है। हुण्डियाँ के भगड़े सिकारने के समय जहाँ जैसा रिवाज और अमल होता है, उसके अनुसार तय किये जाते हैं। जहाँ विशेष रिवाज नहीं होता है, वहाँ क़ानून में किये गये अर्थानुसार बिल आक् एक्सचेन्ज़ के तौर पर अमल किया जाता है, क्योंकि स्टाम्प ऐक्ट में

* पुराने ज़माने में रुपया साथ में ले जाना बड़ा जोखिम का काम था; इसलिये लोग बहुधा अपने साथ मोतबिर साहूकारों की हुण्डियाँ रखते थे।

बिल आबू एक्सचेंज की व्याख्या के अन्तर्गत हुण्डी को शामिल कर लिया गया है। साधारण शब्दों में हुण्डी का अर्थ यह है—“हुण्डी आम तौर पर शर्त-रहित एक आज्ञापत्रिका होती है, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है कि माँगने पर या कुछ निर्धारित समय पश्चात् एक खास रकम, जो उसमें लिखी गई हो, उस व्यक्ति को, जिसका नाम उसमें लिखा हो, दे दी जाय।” हुण्डी की इस व्याख्या और बिल आबू एक्सचेंज की व्याख्या में एक विशेष अन्तर है, क्योंकि अंग्रेजी बिल सर्वथा शर्त या हिदायत रहित होता है और जोखमी हुण्डी कुछ शर्त या हिदायत के साथ होती है, जिसके पूरा होने पर रुपया दिया जाता है। इस प्रकार की हुण्डी पहले जमाने में बहुधा की जाती थी। आजकल इसका रिवाज नहीं है।

हुण्डियों का उद्देश्य—हुण्डी न केवल अन्तर्राष्ट्रीय “विनिमय पत्र” का काम करती है, प्रत्युन इसके कई काम लिये जाते हैं। जो मुख्यतः ये हैं (१) निश्चित समय पर वापिस किये जाने की शर्त पर उधार भी लिया जा सकता है। (२) दूसरे दिसावर भेजे जानेवाले माल पर उसको बिक्री होने से पहले हुण्डी के द्वारा एडवान्स (पेशगी) लिया जा सकता है (३) इसके द्वारा एक दिसावर से दूसरे दिसावर में रुपये का भुगतान किया जा सकता है। हुण्डी से केवल वे ही व्यक्ति लाभ उठा सकते हैं, जिनकी साख बाजार में अच्छी

होती है। हर एक व्यक्ति जो बाज़ार में अपरिचित हो अथवा प्रतिष्ठित न हो, लाभ नहीं उठा सकता।

हुण्डियों की श्रेणियाँ—हुण्डियाँ दो प्रकार की होती हैं—(१) दर्शनी, (२) हुण्डी। इनका लिखनेवाला कहलाता है “लिखनेवाला धनी (Drawer)”, जिसके ऊपर यानी जिसको रुपया चुकाने के लिये सम्बोधन करके लिखी जाती है, उसको “ऊपरवाला धनी (Drawee)” कहते हैं और जिसके हक में लिखी जाती है, उसको “राखयावाला धनी (Payee)” कहते हैं।

दर्शनी-हुण्डी—दर्शनी-हुण्डी उसको कहते हैं, जिसका रुपया माँगते ही या दिखाते ही दिया जाता है। अंग्रेज़ी में इसको (Sight or demand bill) कहने हैं। इस प्रकार की हुण्डियों में कई जगह रिवाज के अनुसार खरीदने, बेचने या लिखने के रोज़ से रुपया दिलाने की तारीख़ कुछ रोज़ बाद की लिखी जाती है, लेकिन हुण्डी लिखने की तारीख़ भी वही लिखी जाती है, जो दिखाने की होती है; जैसे— १ मार्च को रतलाम का १ व्यापारी रामलाल-शिवलाल, दूसरे व्यापारी को १०००) की बम्बई की दर्शनी हुण्डी बेचता है तो वह बम्बई में रुपया देने की ६ तारीख़ दर्ज करेगा और नीचे भी जो लिखने की तारीख़ से मुराद है ६ मार्च दर्ज करेगा।

दर्शनी हुण्डियाँ पर पहले स्टाम्प छूटी लगती थी; किन्तु अब बन्द हो गई है। दर्शनो हुण्डियाँ ४ प्रकार की होती हैं—(१) धनीजोग, (२) शाहजोग, (३) फरमानजोग, (४) देखाडनार जोग।

धनीजोग उस हुण्डी को कहते हैं, जिसका रुपया केवल उसी व्यक्ति को मिल सकता है, जिसके हक में वह लिखी गई है या जिसके ऊपर लिखी गई है।

शाहजोग उस हुण्डी को कहते हैं, जिसका रुपया मोतबिर व्यक्ति या फर्म ही को दिया जा सकता है। 'मोतबिर' उस व्यक्ति या फर्म से मुराद है, जो बाज़ार में जाना या जानो हुई हो या जिसको ऊपरवाला धनी जानता पहचानता हो—यह एक प्रकार की क्रोस चेक की तरह होती है। यदि 'शाह' किसी अनधिकारी व्यक्ति की ओर से या खोई हुई, जाली यथवा भूठी हुण्डी का रुपया संग्रह कर लेगा तो ६% सूद-सहित वह हुण्डी का रुपया वापस देने का जिम्मेदार है।*

फरमान जोग—हुण्डी का रुपया 'राख्यावाला' की हिदायत के अनुसार दिया जा सकता है, अंग्रेजी में इसको Payable to Order bills कहते हैं।

* Bansidhar V/S Jwala Prasad 16 Bombay L. R. 434, 1 Lah 429 (1920)

देखाड़नार जोग—हुण्डी का रुपया प्रत्येक हुण्डी दिखानेवाले व्यक्ति को मिल सकता है, यह Bearer चेक के तौर पर है। इसका रिवाज इसी सदी से बम्बई प्रान्त में चालू हुआ है। देखाड़नार हुण्डी को रिवाज में लाने का श्रेय सराफ़ा एन्क्विरी कमेटी बम्बई को है।*

इन उपरोक्त चार प्रकार की हुण्डियों में शाहजोग हुण्डी ही अधिक व्यवहार में लाई जाती है; क्योंकि इसमें गुम होने पर या धोखा देकर अनजान आदमी के रुपया वसूल करने की बहुत कम सम्भावना होती है। नमूने के लिये हुण्डो का मज-मून परिशिष्ट न० १ में देखिये—

मुद्दती हुण्डी उस हुण्डी को कहते हैं, जिसका रुपया उस मियाद के बाद मिलता है, जो उसमें लिखी हुई होती है। ऐसी हुण्डियाँ ११, २१, ४१, ५१, ६१ और इस तरह से ३६१ दिन तक की होती हैं। राजपूताना व सेण्ट्रल इण्डिया में ४१ व ६१ दिन की मियादी, बम्बई में ४१, पंजाब में १२१ और यू० पी० में ६१ व ६१ दिन, बंगाल में ६१ दिन की अधिकतर व्यवहार में लाई जाती हैं। इनको अंग्रेजी में *Deferred and*

* Bombay Provincial Banking Enquiry Committee
1929-30 para 194

Usance Bills कहते हैं। इन पर स्टाम्प छूटी इस प्रकार ली जाती है :—

२००) तक	३)	५०००) से ऊपर ७५००) तक ६॥)
२००) से ऊपर ४००) तक ॥=)		७५००) " " १००००) " ६)
४००) " " ६००) " ॥=)		१००००) " " १५०००) " १३॥)
६००) " " ८००) " ॥=)		१५०००) " " २००००) " १८)
८००) " " १०००) " ॥=)		२००००) " " २५०००) " २२॥)
१०००) " " १२००) " १=)		२५०००) " " ३००००) " २७)
१२००) " " १६००) " १॥)		और ३००००) से ऊपर प्रत्येक
१६००) " " २५००) " २॥)		१००००) या इसके किंसा भाग
२५००) " " ५०००) " ४॥)		पर ६) अधिक।

ये हुण्डियाँ अधिकतर उधार या माल पर एडवान्स लेने के लिये जारी की जाती हैं। इन हुण्डियों में और तो सभी बातें दर्शनी हुण्डी के समान होती हैं, केवल ये देखाडनार जोग नहीं होती हैं।

जोखमी हुण्डी—प्राचीन काल में जोखमी हुण्डी होती थी, जो भेजे हुये माल की कीमत के बदले में की जाती थी, जैसे अंग्रेजी में Documentary bill of exchange होते हैं। इसमें कई शर्तें दर्ज रहती थीं, उनके अनुसार अगर माल रास्ते में गुम जाय अथवा नष्ट हो जाय तो लेखक वा 'राख्यावाला' उस नुकसान को भुगतता था। ऊपरवाला धनी का हित सर्वथा सुरक्षित

रहता था। ऐसी हुण्डियों के खरीदनेवाले एक बीमा-कम्पनी के एजेंट के तौर पर होते थे। इसमें ३ आसामियाँ होती हैं।

- (१) माल भेजनेवाला या लेखक
- (२) हुण्डी वाला (हुण्डी का खरीदनेवाला)
- (३) मालवाला (माल पानेवाला)

मान लीजिये कि 'माल भेजनेवाला' एक दूकानदार कच्छ से बम्बई, जहाज़ के द्वारा अपने आदृतिया को माल भेजता है। तब वह माल की कीमत वसूल करने के लिये एक हुंडी मालवाले (माल पानेवाले) के ऊपर उस माल की कीमत के बराबर लिखकर हुण्डीवाले या बीमावाले को बेचता है और बीमा का शुल्क (Premium) काटकर बाकी रुपया नकद वसूल कर लेता है। हुंडीवाला हुण्डी को बम्बई अपनी दूकान या आदृतिया के नाम भेज देता है। वह हुण्डी उस माल के, जिसकी कीमत के लिये वह की गई, बम्बई सुरक्षित पहुँच जाने पर मालवाले की दूकान पर उपस्थित की जावेगी। वह या तो उसमें लिखा रुपया चुकाकर माल छुड़ा लेगा या माल लेने की इच्छा न होने की हालत में उस माल को हुण्डीवाले के हवाले कर देगा। हुण्डीवाला अपने नफ़ा-नुक़सान के लिये माल भेजनेवाले से रक़म वसूल कर सकता है, लेकिन मालवाले (माल पानेवाले) पर कोई नालिश दायर नहीं कर सकता। यदि सारा माल रास्ते में गुम जावे या नष्ट हो जावे तो हुण्डी

उपस्थित नहीं की जावेगी और उसका नुकसान हुण्डीवाले (हुण्डी खरीदनेवाले) को भुगतना पड़ेगा ।

रिश्रायती दिन (Days of Grace)—इनको साहूकारी भाषा में गिलास के दिन कहते हैं । अंग्रेजी बिल आर्ब एक्सचेज में ३ दिन मिलते हैं, किन्तु मुहती हुण्डियों में रिश्रायत के दिनों का तरीका भिन्न है । दर्शनी हुण्डी में, जो ११ दिन से कम की होती है, बिल्कुल भी रिश्रायत के दिन नहीं मिलते । मुहती हुण्डी में ११ दिन या इससे ऊपर २० दिन तक की मुहती हुण्डी में ३ दिन रिश्रायत के मिलते हैं । २० दिन से ऊपर के दिनों की हुण्डी में ५ दिन रिश्रायत के मिलते हैं ।

हुण्डियों की लिया-बेची—एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित रीति से रुपया भेजने के लिये जैसे नोटों का व्यवहार होता है, उसी तरह व्यापारी लोग अपनी सुगमता के लिये हुण्डी का व्यवहार करते हैं । नोटों में रजिस्ट्रेशन फ़ोस २) सैकड़ा अधिक लगता है तथा एक रजिस्टर्ड लिफ़ाफ़े का ३०००) से ज्यादा का बीमा नहीं चुकाया जाता; इसलिये अधिकांश में व्यापारी लोग हुण्डियाँ ही द्वारा एक से दूसरे देश में रुपये भेजते हैं ।

नियमानुसार लिखी हुई हुण्डी बाज़ार भाव से हर वक्, हर जगह और हर एक को बेची जा सकती है और हर एक खरीद सकता है । बेची हुई हुण्डी पुनः बेची जा सकती है ।

इस तरह एक हुण्डी कई दफा बिक सकती है और सुदूरस्थ देशों में रुपया चुकाने के लिये भेजी जा सकती है।

मान लो अमरावती का एक व्यापारी कोटे से चने खरीदकर मँगाता है, अमरावती का दूसरा व्यापारी रुई खरीदकर बम्बई भेजता है और कोटे का एक व्यापारी बम्बई से शक्कर और कपड़ा मँगाता है। अब अमरावती के एक व्यापारी को चने की रकम कोटा भेजनी है, दूसरे व्यापारी को बम्बई से रुई की रकम मँगानी है और कोटे के व्यापारी को कपड़े और शक्कर की रकम बम्बई भेजनी है। इन तीनों जगह का भुगतान एक हुण्डी से इस तरह हो सकता है कि अमरावती का चने मँगानेवाला व्यापारी अपने शहर के बम्बई रुई भेजनेवाले व्यापारी की हुण्डी खरीद लेगा और रुपया उसको अमरावती में चुका देगा। यह हुण्डी वह कोटे के व्यापारी के यहाँ भेज देगा। कोटे में चने भेजनेवाला व्यापारी इस हुण्डी को बम्बई से कपड़ा और शक्कर मँगानेवाले अपने शहर के व्यापारी की बेच देगा और नक़द रुपया ले लेगा। यह व्यापारी बम्बई के व्यापारी को, जिसके यहाँ से या जिसकी मारफ़त इसने शक्कर व कपड़ा मँगाया है, भेज देगा। वह व्यापारी बम्बई में उस व्यापारी को, जिसके ऊपर हुण्डी लिखी हुई है, दिखाकर रुपये ले लेगा और हुण्डी पर रसीद लिखकर दे देगा। इस तरह तीनों स्थानों के व्यापारियों को अपना अपना रुपया आसानी से मिल गया और कोई दिक्कत नहीं आई।

हुण्डी के भाव में कमीबेशी का कारण—जब हुण्डी खरीदनेवाले ज्यादा और बेचनेवाले कम होते हैं तो हुण्डी का भाव १०० से ऊपर ॥ १०॥ अधिक बढ़ जाता है और जब बेचनेवाले अधिक और खरीदनेवाले कम होते हैं तब १०० से ॥ १०॥ तक नीचे गिर जाता है । इस कमीबेशी को 'हुण्डावन' कहते हैं । लाभ उठाने के लिये व्यापारी लोग आवश्यकता न होने पर भी भविष्य में लाभ होने की दृष्टि से हुण्डी की लियावेची करते रहते हैं ।

हुण्डी का लिखना, बेचाण करना

(ENDORSEMENT)

दिखाना, सिकारना इत्यादि

लिखना—हुण्डी के लिखने का नमूना परिशिष्ट नं० १ में देखिये ।

बेचाण करना (Endorsement)—बेचाण पाँच प्रकार की होती है, यथा :—(१) लेणी-भेजी, (२) बटावणी-भेजी (३) खरीद-भेजी, (४) हुण्डी-बेची, (५) विशेष बेचाण ।

(१) लेणी-भेजी उस हुण्डी पर लिखते हैं, जो उसी जगह भेजी जाती है, जहाँ के ऊपर वह हुण्डी लिखी गई है अर्थात् जब बम्बई के व्यापारी पर की हुई हुण्डी बम्बई भेजी जावेगी तब उस पर लेणी-भेजी लिखा जावेगा ।

(२) बटावणी-भेजी उस हुण्डी पर लिखते हैं, जो तोसरी जगह भेजी जाती है, जैसे बम्बई की हुण्डी बम्बई न भेजकर दिल्ली भेजी जावे, उस पर बटावणी भेजी लिखा जायगा ।

(३) खरीद-भेजी उस अवस्था में लिखा जावेगा जब कि हुण्डी का भेजनेवाला हुण्डी मँगानेवाले की जोखम पर हुण्डी खरीद कर भेजेगा । उदाहरणार्थ—बम्बई के एक व्यापारी ने कोटे के एक व्यापारी के यहाँ बीस बोरी बादाम अपने घर बेचने के लिये भेजी और यह आदेश दिया कि इसकी बिक्री की रकम की हुण्डी खरीदकर भेज देना । कोटे का व्यापारी बादाम की बिक्री की रकम, कोटे के किसी व्यापारी से हुण्डी खरीदकर बम्बई भेजेगा । उसमें वह खरीद भेजी करके लिखेगा । इसमें हुण्डी खरीदकर भेजनेवाला व्यापारी उसने न सिकारने की जोखम से सुरक्षित रहता है ।

(४) हुण्डी-बेची उस वक्त लिखते हैं जब कि 'राख्या वाला धणी' या वह व्यक्ति, जिसके पास कारवार का सम्बन्ध में हुण्डी पहुँची हो, नकद रुपया लेकर किसी को मुन्तकिल करे ।

(५) विशेष बेचाख उसको कहते हैं, जो लेणी भेजी के स्थान पर काम में लाई जाती है और उसमें यह हिदायत होती है कि इसका रुपया केवल श्रमुक व्यक्ति को दिया जावे । उस हालत में उस हुण्डी का रुपया उस श्रमुक व्यक्ति ही को मिलेगा और वह दूसरे को मुन्तकिल न हो सकेगी ।

सिरा या अण्डास—साधारण बेचाण के अतिरिक्त “ऊपरवाला धणी नहीं सिकारे तो अमुक धणी को दिखाई जावे” इवारत बढाई जाती है, इसको सिरा या अण्डास कहते हैं। इस प्रकार सिरा मारने पर अर्थात् उक्त इवारत लिखने पर ऊपरवाला धणी नहीं सिकारे तो वह हुण्डी उस व्यक्ति का दिखाई जायगी, जिसके लिये बेचाण में हिदायत की गई है। इसको अंग्रेजी में भारतीय कानून के अनुसार Drawee in case of need कहते हैं। यह व्यक्ति ऊपरवाला धणी का स्थान ग्रहण करके बेचाण करनेवाले आसामी के खाते हुण्डी सिकार देता है। यह सिरा इसलिये मारा जाता है कि हुण्डी के न सिकरने पर निकराई सिकराई का, जो लिखनेवाले को हज्ज के रूप में देनी पडती है, लाभ सिरा मारनेवाले को मिल जाता है। यदि जिसके नाम सिरा मारा गया है, वह भी हुण्डी को नहीं सिकारे तो सिरा मारना कोई मूल्य नहीं रखता और साधारण बेचाण के समान उसका असर रहता है। खरीद भेजी बेचाण करनेवाले के सिवाय हर एक प्रकार का बेचाण करनेवाला (Endorser) हुण्डी के जायज काबिज के प्रति रुपये का जिम्मेदार है।

निशाणी—निशाणी का अर्थ है ‘बाबत’ (On account of) इसके लिखने की हर वक्त आवश्यकता रहती है। इससे ऊपरवाले धणी को यह मालूम करने में सुभीता रहता है कि हुण्डी का रुपया किसके खाते नार्ने लिखा जायगा।

हुण्डी का उपस्थित करना—जिस तारीख को हुण्डी पहुँचती हो, उस दिन या बाद में कभी भी जिसके ऊपर वह हो उसे स्थानीय रिवाज के मुताबिक दिखाई जाती है। यदि ऊपरवाला धनी हुण्डी सिकारना स्वीकार करेगा तो उसका रुपया उसी रोज या बाद में जैसा रिवाज होगा, भेज देगा। यदि उसको सिकारना मंजूर न होगा तो खड़ी बोल देगा।

खड़ी रखना या नहीं सिकारना:—हुण्डी लिखने के साथ ही हुण्डी का लेखक ऊपरवाले धनी को हुण्डी की नक़ल लिखकर सिकारने की हिदायत करता है। नक़ल में साफ़ तौर से लेखक, राख्यावाला, ऊपरवाला धनी का नाम, अदायगी की तारीख, मन्सर व निशानी लिखी हुई होती है। जब तक नक़ल नहीं मिल जावे, ऊपरवाला धनी बिना उक्त बातें मिलान किये हुण्डी नहीं सिकार सकता; इसलिये ऐसी हालत में खड़ी बोलना है। खड़ी बोली हुई हुण्डी ३ या ६ दिन तक रिवाज के मुताबिक सिकारने के इन्तज़ार में, उपस्थित करनेवाले के पास रखी रहती है। इस अवधि के अन्दर तार द्वारा या पत्र द्वारा समाचार प्राप्त कर लिये जाते हैं और समाचार आने ही हुण्डी सिकार दी जाती है। यदि लिखनेवाले धनी का रुपया ऊपरवाले धनी के पास हुण्डी से कम हो या न हो और खड़ी रहने की अवधि के अन्दर भी रुपया न आवे तथा ऊपरवाला धनी लेखक की रक़म से अधिक की हुण्डी सिकारना न चाहे तो सिकारने से इंकार कर सकता है। इसके अलावा अगर

हुण्डी के लिखने में कोई त्रुटि जैसे दस्तखत वगैरह न करना या सूचना के अभाव में अन्य व्यक्ति के दस्तखत होना आदि रहने से भी सिकारने से इकार कर दिया जाता है। इस प्रकार हुण्डी न सिकारने से लेखक की स्थिति पर सन्देह उत्पन्न होता है और कभी कभी दिवालिया समझा जाने लगता है। हुण्डो के सिकारने से इकार होने पर हुण्डी पचायती दूकान या देशी बैंकर्स एसोसिएशन के यहाँ भेजी जाती है। वह ऊपरवाला धणी को बुलाकर उस हुंडो पर तस्वीक को मोहर लगा देती है। यह मोहर इस बात का प्रमाण होती है कि ऊपरवाले धणी ने हुण्डी सिकारने से इकार कर दिया है। तत्पश्चात् हुण्डी सिल-सिले से तत्सम्बन्धी आसामियों के पास होती हुई लिखने-वाले धणी के पास वापस आ जाती है। उसको उसी वक्त हुण्डो की रकम, निकराई-सिकराई, व्याज तथा अन्य खर्च सहित देनी पड़ती है। निकराई सिकराई २) ६० सैकड़ा तक होती है।

हुण्डी की प्रतिलिपियाँ—असली हुण्डी के खो जाने पर लेखक से उसकी प्रतिलिपि मिलती है। उसको 'पेठ' कहते हैं। यदि 'पेठ' भी गुम हो जाय तो दूसरी प्रतिलिपि दी जाती है, जिसको 'पर-पेठ' कहते हैं। यदि 'पर-पेठ' भी गुम जाये तो तीसरी प्रतिलिपि और दी जाती है, जिसको 'मेजर' कहते हैं। पहली दो प्रतिलिपियाँ तो लेखक द्वारा ही लिखी जाती हैं, किन्तु तीसरी प्रतिलिपि (मेजर) जिस शहर से हुंडी लिखी हुई होती है, वहाँ

के सराफा पंचायत के पाँच पंचों की ओर से ऊपरवाले शहर के पाँच पंचों के नाम लिखी जाती है।

हुण्डियों द्वारा व्याज कमाना—पाठकों को यह तो भली भाँति मालूम हो गया होगा कि हुण्डियाँ भारत में विनिमय और भुगतान का उसी तरह का प्रधान साधन है, जैसे विदेशों में अंग्रेजी बिल आर्म्सचेज; लेकिन ये व्याज पर रुपया लगाने के लिये भी अच्छा साधन बन रही हैं। देशी बैंकर्स में बहुत से ऐसे हैं, जो हुण्डियाँ बेचते नहीं हैं, बल्कि दो या तीन महीने की मुदती हुण्डियाँ खरीदकर रख लेते हैं और अच्छा व्याज कमाते हैं। बम्बई के मुल्तानी बैंकर इस धन्धे को विशेष तौर पर करते हैं, ऐसी मुदती हुण्डियाँ ॥१ से ॥११ सैकड़ा मासिक तक कमी के साथ खरीदी बेची जाती हैं और पुनः इम्पीरियल बैंक द्वारा भी खरीद की जाती हैं। मुल्तानी बैंकर व इम्पीरियल बैंक के पुनः खरीदने में भाव का जो अन्तर होता है, वही मुल्तानी बैंकर कमाते हैं। भारतीय जाइएट-स्टॉक बैंक भी इन हुण्डियों का लेन-देन करते हैं, किन्तु विदेशी बैंक मुदती हुण्डियों से कोई सरोकार नहीं रखते।

पुर्जा

हुण्डियों के अतिरिक्त दूसरा प्राचीन साख-पत्र पुर्जा है। इसका बङ्गाल प्रान्त में अधिक चलन है। यह उधार लेनेवाले की ओर

से देनेवाले के नाम उसमें लिखी हुई रकम, उस व्यक्ति को और उस सूद की दर से, जिसका वर्णन उसमें होता है, देने के लिये एक प्रार्थना-पत्र होता है। अदायगी का समय उसमें नहीं लिखा जाता। इसका अनुमान या तो प्रचलित प्रथा के अनुसार किया जाता है या उस पुर्ज के साथ नथी किये हुए एक पर्चे पर समय लिख दिया जाता है। इस पर कोई गवाही नहीं होती। यह केवल उधार ली हुई रकम की रसीद के रूप में होता है। इसका उपयोग थोड़े अक्सर पर अर्थात् अधिक से अधिक ३ महीने की मुदत के लिये ली हुई उधार के वास्ते किया जाता है।

प्रोमेसरी नोट

प्रोमेसरी नोट वह लिखित दस्तावेज है, जिसमें बिना शर्त के लिखनेवाले के हस्ताक्षर से केवल एक नियत सख्या में नक़द रुपये अदा करने की प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई हो कि एक खास मनुष्य को या जिसको वह दिलावे, उसको या उस दस्तावेज के उपस्थित करनेवाले (हामिल) को उसमें लिखा हुआ रुपया दिया जावेगा। यह भी हुडी की तरह दो प्रकार का बचे जाने योग्य (Negotiable) साखपत्र होता है—दर्शनी और मुदती। मुदती प्रोमेसरी नोट बहुत कम लिखे जाते हैं। यह साख-पत्र दूसरे तमाम साखपत्रों से आसान हैं। इसका मज़मून निश्चित सा है। इसमें कानूनी कार्रवाई बहुत थोड़ी होती है। गवाही

नहीं होती; किन्तु तारीख होना आवश्यक है। यह कागज के एक तरफ लिखा जाता है और माँगने पर अदा करने योग्य (on demand) होता है, इस पर २५०) रुपये तक १) आने का इससे ऊपर १०००) तक २) आने का और तद् उपरान्त ३) आने का टिकट लगता है। मुहती प्रामेसरी नोट पर मुहती हुंडी के अनुसार स्टाम्प लगाये जाते हैं। इसका प्रयोग मध्यप्रान्त, सयुक्त प्रान्त तथा भारत के अन्य प्रान्तों में पुराने ज़माने से था। अब इसको लगभग समस्त बैंकों ने थोड़ी बहुत भाषा में परिवर्तन करके विशेष रूप से अपना लिया है। इससे इसका चलन बहुत बढ़ गया है।

चेक

प्रचार—भारत में चेकों का प्रचार आधुनिक बैंकों के जन्म के साथ हुआ है। बैंकों से लेन-देन रखनेवाले व्यक्तियों को इस साखपत्र से रुपया संग्रह करने और भेजने में हुडियों की भाँति बड़ी सुविधा होती है। प्रत्येक देश में साख की वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि मुद्रा का प्रयोग कम किया जावे और इसके स्थान पर चेकों का चलन बढ़ाया जावे। यही कारण है कि तमाम प्रमुख देशों में चेकों के प्रचार के लिये हर प्रकार की सुविधा दी जा रही है। हमारे देश में भी इन पर से स्टाम्प ड्यूटी हटाई जाकर इनके प्रचार को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है। क्लियरेन्स हाउसों की स्थापना से इनका लेना-देना बड़ी आसानी से निपट

जाता है; इसलिये इनका प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। लड़ाई से पहले अर्थात् सन् १८१३ ई० में पैंसठ हजार पैंतीस रुपये के चेक क्लियेरिङ्ग हाउसों द्वारा सिकारे गये थे। उसके बाद बढ़ते बढ़ते उनकी तादाद सन् १८२८ ई० में तिगुनी हो गई अर्थात् दो लाख तीन हजार आठ सौ सात के चेक क्लियेरिङ्ग हाउसों द्वारा सिकारे गये।

व्याख्या—चेक भी एक लिखित दस्तावेज़ होती है, जिसके द्वारा लेखक अपने बैंकर को यह हिदायत करता है कि उस व्यक्ति को, जिसका नाम उसमें लिखा है या उसकी हिदायत के अनुसार किसी दूसरे व्यक्ति को या उपस्थित करनेवाले किसी व्यक्ति को उसमें लिखी हुई रकम अदा की जावे, लेकिन इसमें प्रोमेसरी नोट की तरह सूद की दर लिखी हुई नहीं होती। इसमें भी हुण्डियों की तरह तीन आसामियाँ होती हैं :—

(१) लेखक।

(२) ऊपरवाला।

(३) राख्यावाला।

चेक तीन प्रकार के होते हैं :—

अे णियाँ—(१) बेयरर (Bearer) इसका रुपया देखाड़-नार हुण्डी की तरह बैंक के काउण्टर पर हर एक उपस्थित करनेवाले को मिल जाता है।

(२) ऑर्डर (Order) यानी हिदायती चेक, इसका रुपया उस व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके लिये बैंक को

हिदायत की गई हो या जिसके नाम अन्तिम बार मुन्तकिल हुआ हो ।

(३) क्रॉस्ड (Crossed)—इसका रुपया किसी व्यक्ति या सस्या को नक़द नहीं दिया जाता, बल्कि बैंक के खाते में जमा किया जाता है । डेयरर और आर्डर चेक में राखयावाला (Payee) के नाम के आगे तत्सम्बन्धी शब्द लिखे हुए होते हैं । इन दोनों प्रकार के चेकों को कास किया जाता है । पहचान के वास्ते चेक के सीधी ओर पूरी चौड़ाई पर दो समानान्तर रेखाएँ खींच दी जाती हैं । इस प्रकार कास किया हुआ चेक 'क्रॉस्ड-चेक' कहलाता है । चेक वही लोग लिखते हैं, जिनके खाते बैंकों में होते हैं और उन्हीं फार्मों पर लिखे जाते हैं; जो बैंक द्वारा अपने खातेदारों को चेकबुक के रूप में दिये जाते हैं ।

बैंक-ड्राफ्ट

हुण्डियों की भाँति बैंकों द्वारा जो ड्राफ्ट उनकी निजी ब्राञ्चों या एजेंटों पर लिखे जाते हैं, उनको बैंक-ड्राफ्ट कहते हैं । ये भी दर्शनी और मुद्दती दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन आम तौर पर दर्शनी लिखे जाते हैं । उनका मजमून हिदायती चेक की भाँति होता है । इन पर स्टाम्प नहीं लगाया जाता ।

बिल ऑफ़ एक्सचेञ

ये बिलाशर्ती मुद्दती हुंडी के समान और देशी या विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं उदाहरणार्थ :—'क' एक व्यापारी 'ख'

से १५०) रुपयों का माल एक महीने की उधार पर खरीदता है, इसलिये 'ख' वेचे हुये माल के बीजक के साथ एक महीने की मुदती हुण्डी 'क' पर लिखता है, उसको 'क' सिकारना स्वीकार कर लेता है तब माल या बिल्टी 'क' के हवाले कर दी जाती है। यह माल के परिवर्तन में लिखी हुई हुण्डी बिल आंव् एक्सचेंज कहलाती है। इसी प्रकार विदेशी बिल देश के बाहर रहनेवाले व्यापारियों पर लिखे जाते हैं। इनकी आम तौर पर ३ प्रतियाँ होती हैं, जो भिन्न भिन्न डॉक से इसलिये भेजी जाती हैं कि किसी एक प्रति के गुम जाने से रुपया मिलने में देर न हो और दूसरी प्रति से रुपया वसूल कर लिया जावे। तीनों प्रतियों में से किसी एक को सिकार देने पर शेष दोनों प्रतियाँ रद्द हो जाती हैं। ये आम तौर पर मुदती होते हैं।

एण्डोर्समेण्ट अथवा वेचान

हुंडियों की वेचान प्रणाली पर ऊपर पर्याप्त रूप से लिखा जा चुका है। 'पुर्जा' वेचाण योग्य (Negotiable) नहीं है। प्रोमेसरी नोट यदि देशी भाषा में लिखा हो तब तो उसके लिये किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अंग्रेजी भाषा में लिखा होने पर तथा अन्य साख-पत्र, जैसे—चेक, बैंड डाफ्ट, बिल आंव् एक्सचेंज पर, नियमित रूप से एण्डोर्स किया जाता है। अंग्रेजी में लिखे साख-पत्रों पर आम तौर से अंग्रेजी एण्डोर्समेण्ट स्वीकार किये जाते हैं। देशी भाषा के एण्डोर्समेण्ट

से लेनेवाले को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। एण्डोर्समेण्ट आम तौर पर ३ प्रकार के प्रयोग में आते हैं—खाली (Blank), विशेष (Special) और सीमित (Restrictive)।

खाली एण्डोर्समेण्ट में केवल इस्ताफ़र पर्याप्त होते हैं।

विशेष एण्डोर्समेण्ट में जिसके पक्ष में एण्डोर्स किया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है और उसको दूसरे के नाम पर मुन्तकिल (Transfer) करने का अधिकार होता है।

सीमित एण्डोर्समेण्ट में साख-पत्र का रुपया केवल वह व्यक्ति पा सकता है, जिसके पक्ष में एण्डोर्समेण्ट किया गया है। यह दूसरे को मुन्तकिल नहीं कर सकता।

१—इस अध्याय में के सब साखपत्रों के नमूने परिशिष्ट नं० १ में देखिये।

२—इन साखपत्रों के सम्बन्ध में विशेषकर कानूनी और व्यावहारिक बातें जानने के वास्ते लेखक की दूसरी पुस्तक “भारतीय बैङ्किङ्ग का व्यावहारिक और कानूनी ज्ञान” की प्रतीक्षा कीजिये।



पाँचवाँ अध्याय

बैंक और उद्योग-धन्धे

भारत में जितने ज्वाइट-स्टाक-बैंक हैं, वे सब व्यापारिक शहरों और कस्बों में सजाऊनी या रोकडिया का काम करते हैं और थोड़ी-बहुत रुपयों के भुगतान में सुविधा और कुछ कुछ बड़ी बड़ी व्यापारिक फर्मों को मानी हुई जमानतों पर आर्थिक सहायता देते हैं। इस देश के उद्योग धन्धों को न तो ज्वाइट स्टोक बैंकों से जैसी चाहिये वैसी सहायता मिल रही है और न इम्पीरियल बैंक ही इस सम्बन्ध में कुछ मदद करता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि यहाँ के अधिकांश धन्धे पनपने नहीं पाते और जीवन के थोड़े समय बाद ही काल के ग्रास बन जाते हैं। इस सम्बन्ध में कभी कोई विशेष उल्लेखनीय उद्योग भी नहीं हुआ है। सन् १९१८ ई० में भारतीय-इण्डस्ट्रियल-कमीशन ने उद्योग-धन्धा-सहायक बैंकों की आवश्यकता पर विशेष प्रकाश डाला था, जिसका अनु-करण करते हुए जैसा कि पीछे बताया जा चुका है, प्राइ-वेट प्रयत्न से टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक की स्थापना हुई थी, किन्तु दुःख है कि यह बैंक अपनी ५६ वर्ष की अवस्था में ही असफल होकर सन् १९२३ में सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

में मिल गया। इससे भारतीय बैंकिंग संसार में निराशा सी छा गई और इस प्रकार का फिर कोई प्रयास नहीं किया गया। वास्तव में वर्तमान ज्वाइट-स्टाक बैंक अपने पिछले कटु अनुभवों के कारण भारतीय उद्योग-धन्धों को आर्थिक सहायता देने में असमर्थ हैं और जब तक इनकी पोठ पर सहायता करनेवाला बैंकों का बैंक राष्ट्रीय-बैंक स्थापित न हो जाय तब तक ये बैंक सहायता कर नहीं सकते।

जर्मनी में उद्योग-धन्धों की सहायता करने के लिये वहाँ के बैंक संगठित रूप से भारी प्रयत्न करते हैं। उनके लिये यह माना हुई बात है कि उनमें और उद्योग-धन्धों के बीच में गहरा प्रेम और सहानुभूति-पूर्ण सम्बन्ध स्थापित है। ये बैंक जिस ढङ्ग से जर्मनी में उद्योग-धन्धे की सहायता करते हैं, उसका सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

सहायता इच्छुक प्रत्येक संस्था, दुकान या कम्पनी को सहायता माँगने से पहले किसी बैंक के साथ चल्लू खाता खोलना पड़ता है। चल्लू खाते के साधारण लेन-देन में कभी खातेदार के रुपये बैंक में जमा रहते हैं और कभी खातेदार बैंक का देनदार हो जाता है। ब्याज दोनों ही ओर से लिया दिया जाता है। लड़ाई के पहिले आम तौर पर जर्मन-बैंक चल्लू खातों के लिये बैंक रेट से एक या डेढ़ परसेण्ट ब्याज कम देते थे और एक प्रति शतक बैंक रेट से अधिक; किन्तु कम से कम ५ प्रति शतक ब्याज खातेदार से वसूल करते थे। इस हिसाब की अवधि कम

से कम छः माह रहती है; किन्तु बीच में भी दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को खाता बन्द करने और बाकी रुपया माँगने का अधिकार हर वक्त रहता है। यहाँ पर यह बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ की अधिकांश टूकानें चल्लुखाते में जमा से अधिक रुपया उधार लेने की चेष्टा करती हैं। यह केवल इसलिये नहीं कि चल्लू काम के लिये रुपया मिल जाता है, बल्कि भविष्य में स्थायी रूप से सहायता प्राप्त करने के लिये पेश-बन्दी करते हैं।

पर्याप्त समय तक चल्लू खाता रख लेने पर यदि कोई कम्पनी अपना मूलधन बढ़ाना या स्थायी भूख की वृद्धि करना चाहती है तो वह उसके लिये अपने बैंक को दरख्वास्त करती है। प्रायः एक बैंक तमाम जोखिम उठाना नहीं चाहता; बल्कि कुछ बैंक मिलकर जोखिम उठाते हैं। इस काम के लिये एक अस्थायी रूप से संगठित संस्था बनाते हैं, जिसको कन्सोर्ट्यून (Konsortium) कहते हैं। यों तो इस सम्बन्ध में कई प्रणालियाँ प्रचलित हैं; किन्तु दृष्टान्त रूप से यहाँ एक प्रणाली का वर्णन किया जाता है। उस संस्था (Konsortium) का प्रत्येक सदस्य उस धन्ये में होनेवाले नफ़ा-नुक़सान का हिस्सा इच्छानुसार उठाना स्वीकार करता है और तदनुसार रक़म देता है। जैसे एक प्रार्थी कम्पनी को १००००) देना निश्चय हुआ और उस Konsortium में ५ सदस्य हैं, उनमें से प्रत्येक सदस्य १०, १५, २०, २५, ३० प्रतिशतक नफ़े-नुक़-

सान का साभेदार क्रमश बनता है तो उनको १०००) १५००), २०००), २५००) और ३०००) देने होंगे। बैंक सदस्यों में से एक बैंक, हिसाबात करने और लेन-देन करने के लिये डाइरेक्टर चुन लिया जाता है। इस भय से कि उन सदस्यों में से कोई नियम विरुद्ध काम न कर सके, प्राप्त जमानतें आपस में नहीं बाँटी जाती हैं, किन्तु जब तक निश्चित मूल्य को जमानतें न बिक जायँ, सब जमानतें डाइरेक्टर बैंक के पास रक्खी रहती हैं। यह बैंक मध्यस्थ बनकर पुरानी जमानतों की असली कीमत कायम रखने का प्रबन्ध करता है और तत्सम्बन्धी हिसाबात रखता है तथा आवश्यकतानुसार रकम समझ करने तथा बाँटने के लिये सदस्यों को बुलाता है। इस Konsortium क टूट जाने पर मेम्बर नफा नुकसान या बची हुई जमानतें अपने अपने हिस्सों के अनुसार विभाजित कर लेते हैं। ये सस्थाएँ एक निश्चित अवधि के लिये कायम की जाती हैं, किन्तु बीच में भी तोड़ी जा सकती हैं और पुन इच्छा होने पर नवीन शतों के साथ फिर चालू की जा सकती हैं।

अमेरिका के बैंकों ने भी जर्मनी के बैंकों का अनुसरण किया है।

अंगरेजी बैंकों ने भी तटस्थ रहने की अपनी पुरानी रस्म छोड़ दी है। इन्होंने बैङ्कर्स-इण्डस्ट्रियल डिवलपमेण्ट कम्पनी संगठित की है, जो औद्योगिक सस्थाओं के चालू करने की स्कीम को तत्सम्बन्धी विशेषज्ञों से अनुसन्धान कराकर उस उद्योग की उपयुक्तता और लाभ हानि के सम्बन्ध में तत्दीक

करती है और इसकी सिफ़ारिश पर उन उद्योगों को आवश्यक धन प्राप्त होता है।

जापानियों ने भी ५ करोड़ 'यन' के मूलधन से एक इण्डस्ट्रियल बैंक कायम किया है। इसको अपने मूलधन से १० गुने डिबेन्चर जारी करने का अधिकार है। यह औद्योगिक संस्थाओं के बोर्ड्स, डिबेन्चर, शेयर, जहाज़ और जहाज़ों के सामान की ज़मानतों पर उधार देता है। जापान के उद्योग-धन्यों की उन्नति करने में वहाँ की सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग रहा है। यही कारण है कि जापान की काया एक दम पलट गई। सन् १८६८ में जापान की आर्थिक अवस्था भारत की सन् १७५७ की आर्थिक अवस्था से भी ख़राब थी; किन्तु अर्धशताब्दी के थोड़े से समय में यह देश जहाँ तक उद्योग-धन्यों से सम्बन्ध है, संसार के अत्यधिक उन्नतिशील देशों की ध्रेणी में आ पहुँचा। सन् १८६८ में जापान के निर्यात व्यापार में घनी हुई चीज़ों का औसत १.१४ प्रतिशतक था। सन् १९२८ में यह औसत बढ़ कर ४२.५२ प्रतिशतक हो गया। इसी तरह सन् १८६८ से बनी हुई चीज़ें बाहर से ६०.५७ प्रतिशतक में आती थीं, जो सन् १९२८ में घट कर १५.१६ प्रतिशतक रह गईं। यह सब कुछ उन्नति योकोहामा स्पेशी बैंक (१८८०) और इण्डस्ट्रीयल बैंक ऑफ़ जापान (१९०२) के कायम होने के पश्चात् हुई है। अस्तु, भारत के उद्योग-धन्यों की उन्नति के लिये भी इसी प्रकार के बैंकों की स्थापना की आवश्यकता है।

छठा अध्याय

वैद्व और विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता

भारत के विदेशी व्यापार (आयात और निर्यात दोनों) का जोड़ लगभग ६ सौ करोड़ रुपया वार्षिक है । सन् १९२८-२९ में दस करोड़ से ऊपर का लेनदेन जिन देशों से हुआ है, वे इस प्रकार हैं —

(१) यूनाइटेड किंगडम्स	१८३ करोड़
(२) संयुक्त राज्य अमेरिका	५६ "
(३) जापान	५१ "
(४) जर्मनी	४७ "
(५) नीदर लैण्ड, डच और ईस्ट इण्डोज	३० "
(६) फ्रांस	२२ "
(७) इटली	२२ "
(८) बेलजियम	२० "
(९) सीलोन	१६ "
(१०) स्ट्रेट सेटलमेण्ट्स	१३ "
(११) ऑस्ट्रेलिया	१५ "

इस विदेशी व्यापार को दो प्रकार से आर्थिक सहायता दी जाती है—(१) भारतीय बन्दरगाह से विदेशी बन्दरगाह तक या विदेशी बन्दरगाह से भारतीय बन्दरगाह तक, (२) भारतीय व्यापारिक शहरों से भारतीय बन्दरगाहों तक माल पहुँचाने या भारतीय बन्दरगाहों से भारतीय व्यापारिक शहरों को माल विभाजित करने में।

विदेशी बैंक—प्रथम श्रेणी में वर्णित व्यवसाय विदेशी हुण्डियों द्वारा निपटाया जाता है, जो पूर्णतया विदेशी विनिमय बैंकों के हाथ में है। जैसा कि पिछले पृष्ठों में वर्णन किया जा चुका है, इनकी संख्या १८ है। इनमें से दो मेसर्स थामस कुक ऐण्ड सन (बैंकर्स) और अमेरिकन एक्सप्रेस कम्पनी इन्कॉर्पोरेटेड विदेशी विनिमय की आर्थिक सहायता-सम्बन्धी धन्ये में कोई विशेष उल्लेखनीय भाग नहीं लेते। यह अधिकतर यात्रियों के लेन-देन (Tourist traffic) हो से अपना सम्बन्ध रखते हैं। शेष में से निम्नलिखित ५ का अधिकांश व्यापार भारत में है (१) चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना, (२) नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, (३) पी० ऐण्ड ओ० बैंकिंग कॉरपोरेशन, (४) ईस्टर्न बैंक, (५) मरकेण्टायल बैंक ऑफ इण्डिया।

बाकी ११ उन बड़े बैंक-संस्थाओं की शाखाएँ और एजेन्सियाँ हैं, जिनका अधिकांश व्यापार विदेशों में है। यह विनिमय बैंक ब्रिटिश चेम्बर ऑफ कॉमर्स के मेम्बर हैं और ये जो कुछ भी खेल भारत में खेलते हैं, वह सब ब्रिटिश बैंकों के इशारे पर खेलते हैं।

जातीय भेदभाव—इन बैंकों के द्वारा जो सुविधा और आर्थिक सहायता विदेशी व्यापार को मिलती है, वह सेण्ट्रल बैंकिंग इंकायरी कमेटी की बहुमत रिपोर्ट के शब्दों में व्यापारिक दृष्टि से संतोषजनक है; किन्तु अंग्रेजी और विदेशी व्यापारियों के दृष्टिकोण से है न कि भारतीय दृष्टिकोण से। इन बैंकों का सभी जातियों के व्यापारियों के प्रति समान व्यवहार नहीं है। जहाँ ये साधारण से साधारण अंग्रेज़ व्यापारियों और कम्पनियों को अधिक से अधिक सहायता और सुविधा देने में प्रस्तुत रहते हैं, वहाँ भारत के बड़े से बड़े और अच्छी स्थितिवाले व्यापारी, बैंक और कम्पनी की सहायता करने में सदा उपेक्षा करते हैं। यह विदेशी बैंकों के लिये आम शिकायत है। इस सम्बन्ध में सेण्ट्रल बैंकिंग इंकायरी कमेटी के सामने भारतीय व्यापारियों, बैंकों और कम्पनियों ने अनेक आपत्तियाँ प्रकट की हैं। उनमें से उदाहरणार्थ कुछ का सारांश नीचे दिया जाता है :—

(१) विदेशी माल, जो भारत में आता है और भारत से बाहर जाता है, की रकम दो प्रकार के बिलों (हुण्डियों) से वसूल की जाती है और चुकाई जाती है। इनको डी० ए०* और डी० पी०† ड्राफ्ट कहते हैं। डी० ए० का अर्थ है हुण्डी को स्वीकार कर

* Documents against acceptance

† Documents against payment.

लेने पर ही तत्सम्बन्धी बिलिटियाँ ऊपरवाले धनी को अर्थात् माल मँगवानेवाले को दे देना और डी० पी० का अर्थ है—रुपये चुकाने पर माल की बिलिटियाँ देना । भारत से जो विदेशों में माल जाता है, उसको कीमत की हुण्डी भारत का व्यापारी डी० पी० श्रेणी को ओर तीन महीने की मुद्दती करता है और विदेशों से भारत में आनेवाले माल की कीमत की हुण्डी विदेशी व्यापारी भारत के व्यापारी पर डी० पी० श्रेणी और ६० दिन की मुद्दती करते हैं । विदेशी व्यापारियों को डी० पी० श्रेणी की हुण्डियों से यह सुविधा है कि बिना रकम चुकाये केवल साख पर हुण्डी सही करते ही बिलिटियाँ मिल जाती हैं, जिससे माल बेचकर तीन महीने बाद इनका रुपया चुका देते हैं, लेकिन भारतीय व्यापारी को इस तरह केवल हुण्डी लिखारना स्वीकार कर लेने पर बिलिटियाँ नहीं मिलती; बल्कि रुपया चुकाने पर मिलती है । इस सुविधा के अभाव के कारण विदेशी बैंक ही हैं, क्योंकि ये भारतीय व्यापारियों को अच्छी आर्थिक स्थिति का हवाला (Reference) विदेशी व्यापारी को नहीं देते । इसमें इनका स्वार्थ यह है कि डी० पी० श्रेणी के बिलिस प्रचलित रहने से विदेशों से आनेवाले माल की ज़मानत पर ऊँचे ब्याज की दर से रुपया उधार देने पर इनको अच्छी आमदनी होती है ।

(२) दूसरी शिकायत यह है कि साख-पत्र प्राप्त करने के

* यह एक पत्र होता है, जिसमें भारत-स्थित बैंक, दूसरे किसी देश के व्यापारी या बैंक को यह लिखता है कि अमुक समय तक अमुक आसामी

लिये भारतीय माल मँगानेवालों ऊँचे दर्जे की कम्पनियों को भी माल की कीमत का दस से पन्द्रह रुपया सैकड़ा तक विदेशी विनिमय बैंकों में जमा करना पड़ता है; किन्तु कलकत्ते को अंग्रेज़ों कोठियों से इस प्रकार की जमा नहीं माँगी जाती।

(३) भारतीय बड़ी बड़ी और सुसंगठित फ़र्मों के लिये भी यह बैंक संतोषजनक हवाला (Reference) विदेशी व्यापारियों को नहीं देते; लेकिन भारत-स्थित विदेशी फ़र्मों को, जिनकी आर्थिक स्थिति भारतीय व्यापारियों से कम दर्जे की होती है, संतोषजनक हवाला (Reference) मिल जाता है।

(४) जब विदेशी व्यापारी भारतीय व्यापारी पर हुएड़ी करता है और वह हुएड़ी भारत में स्थित विनिमय बैंकों के यहाँ रुपये संग्रह करने के लिये आती है तब माल मँगानेवाले भारतीय व्यापारी को बैंक के घेचनेवाले दर्शनी हुएड़ी के भाव पर रुपया जमा करना पड़ता है; किन्तु किसी दूसरे विनिमय बैंक की दर्शनी हुएड़ी, जो अधिक अनुकूल भावों में मिल सकती है, ख़रीदकर या अपने किसी लन्दन के आदृतिया पर चेक जारी करके

के अमुक तादाद तक ख़रीदे हुए माल की कीमत के बदले बिल्टियों के साथ-वाली अमुक दिन की मुहती हुएड़ी हमारे ऊपर की जा सकती है। उसको हम सिकारना स्वीकार करेंगे और ठीक समय पर उसका रुपया चुकावेंगे। इस साख-पत्र को पाकर दूसरे देशों के व्यापारी बिना कुछ पेशगी लिये भारत के व्यापारी को माल ख़ाना कर देते हैं।

अदायगी नहीं कर सकता। जहाँ तक कलकत्ते के व्यापार से सम्बन्ध है, भारतीय माल मँगानेवाला अपने ऊपर आनेवाली हुण्डी की अदायगी में ऐम्सचेम्ब बैंक एसोसियेशन के किसी दूसरे बैंक को तार की हुण्डी दे सकता है, उस पर कोई चार्ज नहीं किया जाता; किन्तु और जगह ऐसा नहीं होता। सेण्ट्रल बैंकिंग इंकॉर्पोरेटेड के सामने विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि भी यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि भारतीय माल मँगानेवाले से उसके ऊपर आनेवाली हुण्डी की अदायगी में लन्दन-स्थित आइरिया पर चेक लेने के लिये इंकार करना न्यायोचित नहीं है।

(५) विदेशी बैंक भारतीय माल भेजनेवाले को अपने माल का बीमा विदेशी बीमा कम्पनी में कराने के लिये मजबूर करते हैं और हिन्दुस्तानी बीमा कम्पनी में कराया हुआ बीमा स्वीकार नहीं करते।

इस जातीय भेद-भाव और पक्षपात के कारण विदेशियों को भारत के विदेशी व्यापार में भारतीयों की अपेक्षा अधिक सुविधा और सहायता दी जाती है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि विदेशी कोठियाँ अपने अतुलित साधनों से भारतीय व्यवसायियों के साथ प्रतियोगिता कर रही हैं और भारतीय व्यापारियों के हाथ में जो कुछ थोड़ा-बहुत धन्य रह गया है, उसको भी छीनने की कोशिश कर रही हैं।

इस व्यवसाय में विदेशी बैंकों या अन्य व्यापारियों की आय का औसत कमीशन के रूप में दो प्रतिशत है। इससे दस

करोड़ रुपये के लगभग विदेशी फ़र्मों को आय होती है। अतिरिक्त इसके, वे माल के क्रय-विक्रय की दलाली, विनिमय और बोमा की दलाली आदि अनेक प्रकार से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया कमाती हैं। इससे भारतीय व्यापारियों की बड़ी हक़तलफ़ी हो रही है।

दूसरी श्रेणी में वर्णित व्यवसाय अर्थात् उत्पादक क्षेत्र से बन्दरगाहों तक पैदावार पहुँचाना और बन्दरगाहों से आयात माल को भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में विभक्त करना भारतीय व्यापारियों के हिस्से में आया है।

यहाँ हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि भारतीयों में विदेशियों के समान देशी और विदेशी व्यापार को किसी भी प्रकार से सुचारु रूप से सम्पादन करने की योग्यता और क्षमता नहीं है। अंग्रेजों के आगमन और विदेशी बैंकों की स्थापना से पूर्व विदेशी व्यापार सोलहो आना भारतीयों के हाथ में था और अनेक लब्धप्रतिष्ठित व्यापारी इस व्यवसाय को बहुत बड़े पैमाने पर, साधारण से डोंगों और लकड़ी के बने हुए जहाज़ों द्वारा संसार के भिन्न भिन्न देशों से सफलता-पूर्वक करने में सफल हुए हैं। इस पर यह प्रश्न होता है कि फिर क्या कारण है कि यह व्यवसाय इन सौ वर्षों में भारतीयों के हाथों में से विदेशियों के पास सिमिट गया? इसके प्रधान कारण हैं सारे जहाज़ों पर विदेशियों का अधिकार होना और विदेशी विनिमय बैंकों को सरकार द्वारा अनेक सुविधाएँ मिलते रहना।

जहाँ दूसरे देशों में विदेशी बैंक खोलनेवालों के मार्ग में अनेक

रुकावटें तथा प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं, जिनकी वजह से वे वहाँ के स्थानीय बैंकों से प्रतियोगिता करके उनका व्यवसाय अपहरण करने में असमर्थ हो पाते हैं; वहाँ दुःख है कि भारत में विदेशी कम्पनियों, फ़र्मों और बैंकों के लिये न केवल हर वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है; बल्कि उनको उनके भाई-बन्धु द्वारा सब प्रकार की सुविधाएँ दी जाकर, फलने-फूलने का अवसर दिया जाता है। इस भेदभाव के कारण भारतीयों द्वारा होनेवाला व्यापार विदेशी कम्पनियों, बैंकों और व्यापारियों के पास पहुँच गया है। अब इन विदेशी संस्थाओं ने अपना संगठन व शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि ये हर वक्त भारतीय प्रयास को दबाने में सफल हो जाती हैं और भारत में भारतीयों द्वारा चालू की हुई संस्थाएँ पनपने नहीं पातीं। उदाहरणार्थ :—(१) मौजूदा विनियम बैंकों में से नेशनल बैंक ऑफ़ इण्डिया रुपयों के मूलधन से भारत में कायम हुआ था और जिसके बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स में भारतीय डायरेक्टर्स भी थे, इसको अपना मूलधन शीघ्र ही पाँडों में बदलना पड़ा और अपना हेड ऑफ़िस भारत से लन्दन ले जाना पड़ा। (२) अलाइन्स बैंक शिमला को, जो विदेशी विनियम का प्वास्ता व्यापार करता था, सन् १९२३ ई० में अपने दरवाज़े बन्द करने पड़े। (३) टाटा इण्डस्ट्रीयल बैंक को भी, जिसने विदेशी विनियम और व्यापार में अपना क़दम बढ़ाया था, छः वर्ष की आयु में मृत्यु की गोद में सोना पड़ा।

सातवाँ अध्याय

कृषि और बैंक

भारतवर्ष कृषि-प्रधान देश है। यहाँ का सबसे बड़ा, विस्तृत और प्रधान उद्योग-धंधा कृषि है। इस पर २३ करोड़ अर्थात् ७० प्रतिशत मनुष्यों का जीवन-निर्वाह निर्भर है। खेती के लिये भी दूसरे उद्योग-धंधों से धन की कम आवश्यकता नहीं होती है—यह निर्विवाद बात है और जिसको एक स्वर से सभी देशों ने माना है। भारतीय कृषकों को ऋण की पद पद पर आवश्यकता होती रहती है। उनका कोई कार्य ऐसा नहीं है, जो ऋण लिये बिना आरंभ और पूरा हो सके; क्योंकि उनके पास कुटुम्बी जगों के अनुपात से भूमि कम होती है, उत्पादन सदैव समयानुकूल और आवश्यकतानुसार वर्षा पर निर्भर रहता है। आधे दिन अर्थात् तीन वर्ष में एक बार अतिवृष्टि और अनावृष्टि से दुष्काल पड़ते रहते हैं, जिनके कारण उनकी आशाओं और परिश्रम का सर्वनाश हो जाता है और उनको राज का लगान चुकाने, महाजनों की किस्त देने, आगे के लिये

खेती करने और अपने जीवन की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति के लिये ऋण लेना पड़ता है। जैसा कि सर एफ निकोलसन ने उनकी इस कष्टमय दशा का चित्र चित्रित करते हुए लिखा है :—

They Could not begin to Cultivate without borrowing seed, Cattle grain for maintenance etc, so that their crop is pledged in advance, so that on settlement of accounts the cultivator has little to go on with and must again borrow In famine years these men have practically no resource The raiyat must feed himself and his family He must pay his kists and if there is no money to pay them with as is usually the case and the Revenue officer stands at the door there is no alternative but to go to the *mahajan*

भारत में एक्सचेंज बैंक हैं, वे केवल विदेशी व्यवसाय को सहायता करते हैं, ज्वाइट स्टॉक बैंक हैं, वे देश के भीतरी व्यापार के पोषक हैं और इम्पीरियल बैंक भी, जो कृषकों से सम्बन्धित सार्वजनिक धन का बिना व्याज उपभोग करता है, इनकी बात नहीं पूछता। इन्स्योरेन्स कंपनियाँ अपना रुपया केवल सरकारी जमानतों पर लगाती हैं, रहे कोआपरेटिव बैंक—इनके द्वारा जो कुछ भी कृषकों को आर्थिक सहायता दी जाती है, वह

तदर्थ आवश्यकता को देखते हुए आटे में नमक के बराबर भी नहीं है* ।

कृषि को, जिस पर संसार के समस्त उद्योग-धंधे निर्भर हैं और जिसके बिना न व्यापारी न बैंकर और न सरकार जीवित रह सकते हैं, भारतीय बैंकिंग संगठन से सहायता नहीं मिलती, यह आश्चर्य की बात है। इससे यह कहा जा सकता है कि भारत का बैंकिंग संगठन अभी अपूर्ण है।† दुःख की बात है कि हमारी सरकार भी इस ओर जैसा चाहिये, वैसा ध्यान नहीं देती।

दूसरे देशों में कृषि को थोड़ी और लम्बी अवधि के लिये सहायता देनेवाली अलग अलग संस्थाएँ स्थापित हैं,

* The co-operative movement, therefore, provides about 7% of the finance required for this purpose. Bom P BK I C. 1929-30 p 227 The credit facilities now provided by co-operative movement to agriculturists cover but a very small proportion of their needs C.BK I Co P 199.

† When we have agriculture, which is by far the largest "INDUSTRY" in India, entirely out of touch, with the Commercial Banking ORGANISATIONS "Sir OSBORNE A Smith"

जिनको वहाँ की सरकारें सदैव आर्थिक, क़ानूनी और प्रबन्ध-सम्बन्धी यथोचित सहायता देती रहती हैं।

थोड़ी अवधि के लिये

जर्मनी में सरकारी कृषि-बैंक (Preussische Central Genö.) को सरकारी पूँजी से २५ लाख पौंड सहायतार्थ प्रदान किया गया था।

फ़्रान्स में सरकार सहकारिता के प्रचार को सरकारी अधिकारियों के बोर्ड द्वारा, जो Credit Agricole कहलाता है, विशेष सहायता प्रदान करती है। कुछ वर्ष पहले जब बैंक आब् फ़्रान्स का संस्थापन पत्र संशोधित हुआ था, उसके द्वारा बैंक आब् फ़्रान्स Credit agricole बोर्ड को ४ करोड़ स्वर्ण-फ़्रान्क बिना व्याज उधार देने और अपने लाभ में से एक लाख बीस हजार पौंड प्रति वर्ष सहायता-स्वरूप देने के लिये बाध्य है। Credit agricole इस रुपये को Regional Banks (ज़िला कोऑपरेटिव बैंकों के समान होते हैं) को बिना व्याज उधार देता है। ये पिछले बैंक ग्रामीण सहकारी सभाओं को अधिक से अधिक ३% पर उधार देते हैं।

इंग्लैण्ड में कृषकों को थोड़ी अवधि के लिये बैंक द्वारा उधार दिलाने के वास्ते सन् १८२८ ई० में एक विशेष क़ानून की रचना की गई है।

संयुक्त राज्य अमेरिका में उधार देनेवाली (Credit) और क्रयविक्रय करनेवाली (Marketing) सहकारी समाएँ हैं, जिनको Federal Intermediate Banks और National agricultural credit Corporation कहते हैं। ये सब संस्थाएँ कृषकों को थोड़ी अवधि के बास्ते उधार देती हैं। इनकी स्थापना स्पेशल एग्रीकल्चर क्रानून १९२३ के द्वारा हुई है। पहली प्रकार के बैंकों की संख्या १२ है, जो अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं। प्रत्येक का मूलधन ५० लाख डालर है, जो सबका सब सरकार द्वारा खरीदा जाता है।

लम्बी अवधि के लिये

(१) इंग्लैण्ड में सरकार भूमि-बंधक बैंकों को The Agriculture Credit Act of 1928 के अनुसार सहायता-स्वरूप (१) ७५,००,००० पाँड तक ६० वर्ष के लिये बिना व्याज उधार देने, (२) प्रबन्ध-वर्च के लिये १०,००० पाँड वार्षिक सहायता देने और (३) १२,५०,००० पाँड के डिबेञ्चर खुद खरीदने को वाध्य है। इसके अतिरिक्त ५ करोड पाँड के डिबेञ्चर अंडर राइट करने में सहायता करती है। इन बैंकों के डिबेञ्चर ट्रस्टी सिन्डोरिटी माने जाते हैं।

(२) सीलोन में एक कमेटी ने स्टेट मोर्टगेज बैंक की स्थापना के बास्ते एक तजवीज उपस्थित की है और सिफ़ारिश की है कि "सरकार २,५०,००,०००) ४० तक के

- डिवेन्चर की असल रकम और ब्याज की गारंटी लेवे, ३०,००,०००) रु० तक के डिवेन्चर खुद खरीदे और बैंक को अपना रुपया जमानत में आई हुई जायदाद से कोर्ट में पुकार किये बिना ही वसूल करने का पूर्ण अधिकार दे।

(३) संयुक्त राज्य अमरीका में फ़ेडरल भूमि-बन्धक बैंकों की संख्या, फ़ेडरल इंटरमीडियट क्रेडिट बैंकों की भांति १२ है। ये समस्त देश के १२ ज़िलों में बँटे हुए हैं। प्रत्येक बैंक को कार्य प्रारम्भ करने से पहले ७,५०,००० डालर के मूलधन की आवश्यकता होती थी। इस पूँजी के हिस्से बेचना प्रारम्भ करने की तारीख़ से ३० दिन के अन्दर बिना बिके हुए हिस्से सब सरकार को खरीदने पड़ते थे।

(४) फ़्रांस में The Credit Foncier de France बैंक सन् १८५२ में स्थापित हुआ था, जिसको सरकार ने १ करोड़ स्वर्ण फ़्रांक की सहायता दान के तौर पर दी थी। इसके बॉण्ड ट्रस्टी-सिफ़्योरिटी समझे जाते हैं।

(५) जर्मनी में भूमि-बन्धक बैंकों के संचालन के वास्ते एक विशेष क़ानून है, जिसके द्वारा सरकार ऐसे बैंकों का प्रबन्ध करती है। सरकारी सहायता के कुछ उदाहरण यहाँ उद्धृत किये जाते हैं :—

(१) Preussische Central-Boden Credit Actiengessellschaft बैंक जब सन् १८७० में स्थापित हुआ था तब सरकार और सरकार से सम्बन्धित बैंकों ने

इसके मूलधन में हाथ घँटाया था। बाद में जब बैंक अपनी उन्नतावस्था में पहुँच गया तब हिस्से बाज़ार में बेचे गये थे।

- (२) Kur-und Newmarkisches Ritterschaftliches Kredit Institut etc. बैंक फ्रेडरिक दी ग्रेट द्वारा स्थापित किया गया था, जिसने इसको २०,००० डालर (जर्मनी का पुराना सिक्का १ डालर = ३ मार्क) दान के तौर पर प्रदान किये थे। आरंभ में यही इसका मूलधन था। इसका समस्त लाभ बैंक ही में रहता था और मूलधन में शामिल कर दिया जाता था। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते इसका मूलधन सन् १६०८ ई० में ७० लाख स्वर्ण-मार्क हो गया। साधारण से अधिक लाभ होने की हालत में बैंक के अधिकारी अधिक लाभ को उधार लेनेवालों में बाँटकर उनके ऋण में जमा कर लेते थे।

- (६) आस्ट्रेलिया में भी कृषि को सहायता देने के वास्ते खास तौर से सरकारी बैंक स्थापित किये गये हैं। ये अपनी पूँजी कुछ तो सरकार से प्राप्त करते हैं और कुछ डिबेन्चर जारी करते हैं। ग्रामीण सहायता (Rural Credit) मित्त मित्त प्रकार की सहकारी समितियों और कोमनवेल्थ बैंक के Rural Credit डिपार्टमेण्ट द्वारा दी जाती है। इस बैंक को ३० लाख पाँड तक तो इस कार्य के

लिये सरकार सहायता देती है और २० लाख पाँड स्वयं अपने पास से लगाता है।

- (७) जापान में कृषि तथा दूसरे छोटे छोटे उद्योगों को छोटे छोटे कृषि और औद्योगिक बैंकों द्वारा सहायता दी जाती है। इन बैंकों को Hypothec Bank of Japan, जो कि उनका केंद्रीय बैंक है, सहायता देता है। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य जायदाद की जमानत पर अधिक से अधिक ५० वर्ष की अवधि तक के लिये उधार देना है। Hypothec Bank of Japan का मूलधन ७,४८,७६,०६० येन है और इसको अपने मूलधन से ५० गुने डिपेंडेंसर निकालने का अधिकार है। इसके समस्त व्यवस्थापक सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं।

उक्त उद्धृत किये हुए उदाहरणों से स्पष्ट हो गया है कि कृषि-उद्योग को संसार के दूसरे देशों में कितना महत्व-पूर्ण स्थान दिया गया है और उसको उन्नत करने के लिये किस प्रकार से आर्थिक सहायता पहुँचाने के साधन जुटा रखे हैं। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भी इसी प्रकार के कृषि-सहायक बैंकों की आवश्यकता है।

आठवाँ अध्याय

पिछड़ी हुई अवस्था और उसके कारण

पिछड़ी हुई अवस्था—पिछले अध्यायों में संक्षिप्त रूप से कई प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का, जो भारत में काम कर रही हैं, वर्णन किया जा चुका है। यहाँ पर यह बतलाये जाने का प्रयत्न किया जाता है कि भारतीय बैंकिंग धन्धा दूसरे देशों की तुलना में कहाँ पर स्थित है और कितना पिछड़ा हुआ है या जो कुछ इस समय है, वह कहाँ तक पर्याप्त है। अतिरिक्त इसके उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है, जो भारतीय बैंकिंग की उन्नति में रोड़े अटकाते हैं।

पिछले अध्याय में भारत में ज्वाइएंट स्टॉक बैंकिंग तीन श्रेणियों में विभक्त हुई है—इम्पीरियल बैंक, ज्वाइएंट स्टॉक बैंक और विनिमय बैंक। इन तीनों के हेड ऑफिस और शाखाएँ इस प्रकार हैं :—

नाम	हेड आफिस	शाखाएँ
इम्पीरियल-बैंक	३	१६५
विदेशी विनिमय-बैंक	०	८८
उवाइएट स्ट्राक बैंक	१७०	४८०
इलाहाबाद-बैंक	१	३२
जोड़	१७४	७६५

उक्त ७६५ बैंकों में विदेशी विनिमय बैंकों की शाखाएँ और इलाहाबाद बैंक, जो विदेशियों द्वारा संचालित होता है, भारतीय बैंकिंग का वास्तविक भाग नहीं कहा जा सकता, की ३२ शाखाएँ भी शामिल हैं। भारत में लगभग २३०० शहर हैं। बैंकों की उक्त संख्या केवल ३३६ शहरों में विभक्त है, परन्तु यह विभाजन समस्त देश में समान रूप से न होने के कारण इस देश का बहुत बड़ा भाग बैंकिंग की सुविधाओं से लाभ उठाने से वञ्चित रहता है।

विदेशों से तुलना—भारतीय बैंकों की उक्त संख्या को यदि हम जनसंख्या में बाँटते हैं तो ४,४०,००० मनुष्यों के पीछे एक शाखा का औसत आता है। इन आँकों को जब हम विदेशों के बैंकों की संख्या से तुलना करते हैं तो अपने आपको बहुत पीछे पाते हैं। इंग्लैण्ड और वेल्स में ४५०० मनुष्यों के पीछे और यूनाइटेड किंगडम में ३५०० मनुष्यों के पीछे एक बैंक है। अतिरिक्त इसके सन् २७ २८ ई० में ससार के कुछ भाग बैंक—८

देशों की बैंकिंग अवस्था का दिग्दर्शन “बैंकर्स-पलमेनिक” इस प्रकार करता है:—

देश	बैंकों के दल्लर
संयुक्त राज्य अमेरिका	२५०००
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड	१३१००
फ्रांस	४४००
जर्मनी	३१००
बेलजियम	१२००

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका से भारत की जनसंख्या तिगुनी है; किन्तु वहाँ बैंकों के दल्लर भारत से ३३ गुने अधिक हैं। इस तरह वहाँ पर भारत से सौगुना अधिक बैंकिंग धन्ये का प्रचार है। यदि हम मूलधन और जमाशुदा अमानतों पर दृष्टि डालते हैं तो अमेरिका को तुलना में भारतीय बैंकों का मूलधन २ प्रतिशत भी नहीं है और अमानतें ३ प्रतिशत से भी कम जमा हैं। जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में ८७ पौंड प्रति मनुष्य के पीछे रकम जमा है, वहाँ भारतीय बैंकों में जमाशुदा अमानतों का औसत १५ शिलिङ्ग प्रति मनुष्य आता है। ऐसा ही परिणाम लगभग और देशों की तुलना से निकलता है। यह तो हुई एक देश से दूसरे देश के बैंकिंग की सामुहिक तुलना। अब हम कुछ विदेशों के प्रधान प्रधान बैंकों से भारत के बड़े बड़े बैंकों की तुलना करते हैं।

संसार के कुछ बैंकों का पूँजी-सूचक कोष्ठक

नाम बैंक	लाख पौण्ड में	
	मूलधन	जमा (अमानतें)
चार्टर्ड बैंक आफ इण्डिया, आस्ट्रे- लिया ऐण्ड चाइना	७०'००	४४०
कॉमर्स बैंक	२२८'१०	३२२१'२७
नेशनल सिटी बैंक आफ न्यूयार्क	३२१'४०	२७८१'४७
कॉम्पटॉन नेशनल डी एसकोम्प्ट डी पेरिस	१२७'८३	३६७०'२७
स्प्रीमोडोमा बैंक	७१'०३	४२७'६१
योकोहामा स्पेसी बैंक	११६'२०	४८३'३३
इलाहाबाद बैंक	२'८६	८३'३४
बैंक आफ इण्डिया	७'२०	८३'०४
सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	१२'६१	१०३'२५
ज्वाइंट स्टॉक बैंक ५ लाख से ऊपर मूलधनवाले	२१'६३	४२६'३०
ज्वाइंट स्टॉक बैंक ५ लाख से कम तथा १ लाख से अधिक मूलधनवाले	६'३७	२५'६१
इम्पीरियल बैंक	४०'२२	२६४'३३

पृष्ठ नं० ११५ का कोष्ठक यह बतला रहा है :—

मूलधन से तुलना

ब्रिटेन के बैंकों में लॉयड्स-बैंक का मूलधन इम्पीरियल बैंक से ६ गुना, सेण्ट्रल-बैंक ऑफ इण्डिया से २१ गुना और इलाहाबाद-बैंक से ८६ गुना अधिक है। इसी प्रकार चार्टर्ड-बैंक का मूलधन भी इम्पीरियल-बैंक से दूना, सेण्ट्रल बैंक से ५ गुना और इलाहाबाद-बैंक से २४ गुना अधिक है।

अमरीका के बैंकों में नेशनल-सिटी बैंक ऑफ न्यूयार्क का मूलधन इम्पीरियल-बैंक से ८ गुना, सेण्ट्रल-बैंक से २६ गुना और इलाहाबाद-बैंक से ११० गुना अधिक है।

फ्रांस के बैंकों में कोम्पटोयर नेशनल डी पेरिस का मूलधन, इम्पीरियल-बैंक से चौगुना, सेण्ट्रल बैंक से १२ गुना और इलाहाबाद-बैंक से ५३ गुना अधिक है।

जापान के बैंकों में म्यूमीटोमा का मूलधन इम्पीरियल-बैंक से १॥ गुना, सेण्ट्रल-बैंक से ५ गुना और इलाहाबाद-बैंक से २५ गुना अधिक है। इसी तरह योकोहामा स्पेसी-बैंक का मूलधन इम्पीरियल-बैंक से ५ गुना, सेण्ट्रल-बैंक से १६ गुना और इलाहाबाद-बैंक से ६६ गुना अधिक है।

यदि हम एक लाख और इससे ऊपर मूलधनवाले समस्त ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों का मूलधन मिलाकर तुलना करने बैठें तो भी चार्टर्ड-बैंक ऑफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना और

स्यूमीटोमा-वैङ्क में से प्रत्येक के मूलधन से हमारे समस्त ज्वाइण्ट-स्टाक वैङ्कों का मूलधन कम है। यदि हम भारतीय ज्वाइण्ट-स्टाक-वैङ्कों के मूलधन में इम्पीरियल-वैङ्क का मूलधन मिला देते हैं तो भी हमारे समस्त वैङ्कों के मूलधन से लॉयड्स-वैङ्क का मूलधन ढाई गुना और नेशनल-सिटी-वैङ्क आर्न्ड न्यूयार्क का सवा तीन गुना अधिक होता है।

अमानतों से तुलना

ब्रिटेन के लॉयड्स वैङ्क में इम्पीरियल-वैङ्क से ६ गुनी, सेंट्रल वैङ्क से सत्ताईस गुनी और इलाहाबाद-वैङ्क से बयालीस गुनी अमानतें अधिक जमा हैं।

अमरीका के नेशनल-सिटी-वैङ्क आर्न्ड न्यूयार्क में इम्पीरियल वैङ्क से चौगुनी, सेण्ट्रल-वैङ्क से २१ गुनी और इलाहाबाद-वैङ्क से ३३ गुनी अधिक अमानतें जमा हैं।

यदि हम अपने १ लाख से ऊपरवाले समस्त ज्वाइण्ट-स्टाक-वैङ्कों की धरोहर से, जिनमें इम्पीरियल-वैङ्क से भी कम धरोहर जमा है, तुलना करें तो उससे कहीं अधिक जमा विदेशों के प्रत्येक अच्छे बड़े वैङ्क में पाई जाती है। कितना आकाश-पाताल का अन्तर है।

भारतीय-वैङ्क की दुरवस्था की वरुण-कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती; बल्कि जब हम भारत के भिन्न-भिन्न श्रेणी के वैङ्कों के अङ्कों पर दृष्टि डालते हैं तो शोचनीय दशा का नम्ररूप और भी सामने आ जाता है; यथा—

बैंड	मूलधन तथा रक्षित फंड (१००० रुपयों में)	जमाशुदा श्रमान्त (१००० रुपयों में)
इम्पीरियल-बैंड	१,१०,१७२	७,६२,५३०
विदेशी विनिमय-बैंड	२५,०५,६४०	७,११,३८६
उवाइंट-स्टॉक-बैंड	१,२२,६३६	६,६३,५०२
योग	२७,३८,४५१	२१,६७,४१८

उक्त तालिका से पता चलता है कि भारत-स्थित समस्त बैंकों में २१६.७ करोड़ रुपया जमा है। इनमें से ७१.१ करोड़ अर्थात् ३३ प्रतिशत विदेशी-विनिमय-बैंकों में, ७६.२ करोड़ अर्थात् ३६ प्रतिशत इम्पीरियल-बैंड में और ६६.३ करोड़ अर्थात् ३१ प्रतिशत उवाइंट-स्टॉक-बैंकों में जमा है। पिछले बैंकों की जमा का बहुत कुछ भाग उन बैंकों में जमा है, जो विदेशी प्रबन्ध और पूँजी से संचालित होते हैं। केवल विशुद्ध भारतीय बैंकों में तो ४५ करोड़ के लगभग अर्थात् उक्त समस्त बैंकों की कुल भारतीय जमा का २० प्रतिशत जमा है। इतनी शोचनीय दशा संसार में किसी देश के बैंकिङ्ग-धंधे की नहीं है।

कारण

भारतीय बैंकिङ्ग व्यवसाय के इतना पिछड़ा हुआ होने के वैसे तो कई राजनीतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक कारण हैं; किन्तु उनमें चार ऐसे हैं, जिनका सुधार होने की अत्यन्त आवश्यकता है; यथा—

- (१) विदेशी-बैंकों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध ।
- (२) बैंकों का प्रतिवर्ष अधिक संख्या में फ़ेल होना ।
- (३) भारत सरकार की उदासीनता ।
- (४) अंग्रेज़ी भाषा का प्राधान्य ।

अब हम इन पर संक्षिप्त रूप से पृथक्-पृथक् विचार करना चाहते हैं ।

विदेशी बैंकों द्वारा प्रतियोगिता और विरोध—इन विदेशी विनिमय-बैंकों के विस्तार, प्रतियोगिता करने की नीति और भारतीय व्यापारियों की अपेक्षा विदेशी व्यापारियों को सुविधा और साधन देने में तरजीह देने की संकुचित मनोवृत्ति आदि के सम्बन्ध में पिछले पृष्ठों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है, जिसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

इनका प्रभाव न केवल देश-विदेश के बाज़ारों ही पर है, प्रत्युत ये भारत सरकार और भारत मंत्री की कौंसिल तक में अपना प्रभाव रखते हैं । उन मामलात में, जिनका इन बैंकों पर असर पड़ता है, ये हमेशा अपना मतलब सीधा कर लेते हैं । इस प्रकार के अनेक उदाहरण ऐसे हैं, जहाँ इनका विरोध सफल हुआ है । श्री० मनु सूवेदार तो यहाँ तक कहते हैं—“जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनका विरोध कभी असफल नहीं हुआ । सरकार से इनका मेलजोल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों ही रूप से बढ़ा हुआ है । पेंशन-प्राप्त सरकारी अफ़सर इन विदेशी विनिमय बैंकों के होम-वार्ड्स को सुशोभित करते हैं, जो इंडिया कौंसिल

की फ़ाइनेन्स कमिटी-द्वारा, जिसको सलाह पर भारत मंत्री आमतौर पर काम करते हैं, अपने विचारों का दबाव डालने में सफल हो जाते हैं” ।*

“भारत सरकार इनके प्रतिनिधियों से मिलने में बड़ी दिल-चस्पी लेती है। इंडिया आफिस के अफसर भी इनको बड़ी हिमायत करते हैं, चाहे उससे प्रजाहित की उपेक्षा क्यों न होती हो।”*

एक ओर इनका इस प्रकार बड़ा हुआ प्रभाव है, दूसरी ओर ये केवल अपने ही लाभ की ओर दृष्टि रखते हैं। इनके हृदय में सार्वजनिक-हित का भाव अथवा इस देश (भारत) की भलाई का ध्यान किंचित् भी नहीं है; इसलिये इनका व्यवहार भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से असतोषजनक है। इनकी बड़ी हुई शक्ति और विरोधात्मक व्यवहार के जो परिणाम हो चुके हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं—

(१) टकसाल का बन्द होना ।

(२) प्रेसीडेंसी बैंकों और बाद में इम्पीरियल-बैंक को लन्दन में दफ्तर खोलने तथा वहाँ अमानतें लेने और विनिमय का धन्धा करने में बाधाएँ उपस्थित होना और मनाही होना ।

(३) कौंसिल बिल की बिक्री की परिपाटी और परिमाण

* Minority Report Para 175.

T „—d—„ Para 174

भारत के हितों के विपरीत होना। इन्होंने चाहा है कि कौंसिल-बिल अधिक मात्रा में चेचे जावें, चाहे लंदन में रुपये की आवश्यकता न हो और यह इस-लिये कि इनको सोना लाने का कष्ट न उठाना पड़े। साथ ही इन्होंने यह भी चाहा है कि भारत मंत्री कौंसिल-बिल इन्हीं के द्वारा चेचा करें।

- (४) टाटा इंडस्ट्रियल-बैंक के कौंसिल बिल खरीदने के लिये ग्रहण करने योग्य बैंकों की नामावलि में स्थान प्राप्त करने में, बाधा उपस्थित होना।
- (५) भारत में सोने का माध्यम तथा सोने का सिक्का स्थापित होने और स्वतंत्र रूप से सोने का सिक्का ढालनेवाली टकसाल के खुलने में बाधा पड़ना।
- (६) दूसरे देशों के नमूने के समान “सेट्रल-बैंक” की स्थापना में रुकावट होना।

ये सदैव उन उपायों का विरोध करते रहते हैं, जिनसे किसी दूसरी एजेंसी का लन्दन या किसी दूसरे अर्थ-केन्द्र (Financial centre) से रकम लाने में कदम बढ़ता हो या जिनसे भारत में रुपये का मूल्य घटता हो, विशेष कर उस अवसर पर जब भारत से विदेशों में माल का निर्यात अधिक होता हो। इससे भारतवासियों को अपनी पैदावार सस्ते दामों में बेचकर गला कटाना पड़ता है।

उक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि इनके प्रभाव और स्वच्छंदता से भारतीय बैंकिंग को कितना धक्का लग रहा है, इससे अधिक लिखना पुस्तक को विस्तार देना है।

बैंकों का प्रतिवर्ष अधिक संख्या में फेल होना—
 “भारत में आधुनिक बैंकिंग का आरंभ और विकास” शीर्षक अध्याय में बैंकों के फेल होने का विवरण विस्तृत रूप से दिया जा चुका है। सन् १३ के आर्थिक-संकट में अर्थात् सन् १३—१७ पाँच वर्षों में १७८ लाख की प्राप्त पूँजीवाले बैंक फेल हुए हैं, जो पिछले वर्ष के कुल ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की प्राप्त पूँजी से ५१ प्रति शत पूँजी के अधिपति थे। यह ठीक है कि इनमें अधिकांश बैंक बहुत छोटे और निर्बल थे, किन्तु बड़े बैंकों की संख्या भी कम नहीं थी। यथा*—

(१) दी इंडस्ट्रियल स्पेसी-बैंक	पूँजी ७५ लाख
(२) दी पीपल्स-बैंक	" १३ "
(३) दी क्रेडिट बैंक ऑफ इंडिया	" १० "
(४) स्टैंडर्ड बैंक ऑफ बम्बई	" १० "
(५) दी बैंक ऑफ अपर-इंडिया	" १० "
योग " ११८ "	

इसके बाद फिर लडाई की समाप्ति पर भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक-कंपनियों के अधिक मात्रा में असफल होने के साथ साथ

अनेक बैङ्क फेल हुए हैं। केवल सन् २३ में २० बैङ्कों के, जिनकी प्राप्त पूँजी ४६५ लाख रुपया थी, दर्वाजे बन्द हुए हैं। इनमें प्रमुख-प्रमुख बैङ्क ये थे।*

(१) अलायंस-बैङ्क आफ़ शिमला प्रांत	पूँजी =	लाख
(२) टाटा इंडस्ट्रियल-बैङ्क	"	२२६ "
(३) कलकत्ता इंडस्ट्रियल-बैङ्क	"	७६ "
	योग "	३६३ "

इस प्रकार एक बार नहीं बार बार और प्रति वर्ष बैङ्कों के फेल होने का ताँता लग गया। सन् १९२२ से सन् १९३० तक १३६ बैङ्क ५७५ लाख की प्राप्त पूँजी के फेल हुए हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष १६ बैङ्कों के ६४ लाख की पूँजी ले लेकर डूबते रहने के कारण भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक-बैंकिंग को धक्का लगाना स्वाभाविक है। धरोहर रखनेवाले लोगों के मन मर गये और शेयर-होल्डरों का दिल टूट गया; क्योंकि अधिकांश फेल होनेवाले बैङ्कों के शेयर-होल्डरों को अपनी पूरी पूँजी से हाथ धोना पड़ा। फल-स्वरूप नये बैंक चालू करनेवाले लोगों का उत्साह भग हो गया और इनकी बढ़ती हुई प्रगति रुक ही नहीं गई, बल्कि और पीछे को पिछड़ गई। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि सन् १९२२ से ३० तक बैंकों की संख्या और पूँजी में कोई उल्लेखनीय उन्नति नहीं हुई। इतना ही

नहीं; बल्कि सन् १९२१ की अवस्था के बराबर भी नहीं पहुँचे; जैसा कि निम्नलिखित तालिका* से प्रगट होता है :—

प्रगति-सूचक तालिका

सन् १९२१				सन् १९३०		
श्रेणी	बैंकों की संख्या	प्राप्त मूलधन	धरोहर	बैंकों की संख्या	प्राप्त मूलधन	धरोहर
अ ^१	२७	१२४०	७६६०	३०	११८२	६३२२
ब ^२	३८	१००	३२६	२४	१३७	४३१
योग	६५	१३४०	८०१६	५४	१३२२	६७५३

उक्त तालिका के अवलोकन से यह साफ़ ज़ाहिर होता है कि सन् १९२१ में “अ” श्रेणी के बैंकों की संख्या २७ थी, उनका मूलधन १२४० लाख था और उनमें ७६६० लाख रुपये की धरोहर जमा थी। सन् १९३० में केवल ३ बैंक बढ़कर बैंकों की संख्या ३०

*Statistical tables relating to Banks in India 1930, page 3.

- १ “अ” श्रेणी—जिनका मूलधन और रचित फंड ५ लाख और ऊपर है।
- २ “ब” श्रेणी—जिनका मूलधन और रचित फंड १ लाख और ५ लाख के बीच में है।

हो गई; किंतु मूलधन और धरोहर की जमा में भारी कमी बनी हुई है अर्थात् ११८५ और ६३२२ लाख की पूँजी क्रमशः रह गई। हाँ, “ब” श्रेणी के बैंकों में अवश्य थोड़ी सी वृद्धि हुई है, जिसको भारत जैसे विशाल देश के लिए संतोषजनक नहीं कहा जा सकता।

भारत-सरकार की उदासीनता—यह मानी हुई बात है कि सरकार को देश के बैंकों का माता की तरह संरक्षण करना चाहिये; किन्तु भारत सरकार जहाँ रेलवे, पास्ट, टेलीग्राफ आदि की उन्नति के लिए भरसक प्रयत्न करती है, वहाँ बैंकिंग की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देती; बल्कि बेसरोकार तमाशगीर की तरह विदेशी-बैंकों की बढ़ती हुई स्वच्छंदता को, प्रति वर्ष फ़ेल होने-वाले भारतीय बैंकों की संख्या को और भारत की पिछड़ी हुई आर्थिक अवस्था को देख रही है। “पहिले जब एसेम्बली के माननीय मेम्बर कंपनी-क़ानून के संशोधन के लिए प्रश्न पूछते थे तब उनको यह उत्तर मिलता था कि इंग्लैंड में कंपनी क़ानून के विचार के लिए ग्रीन्स-कमेटी बैठी हुई है, उसकी रिपोर्ट बन जाने पर भारत सरकार इस काम को हाथ में लेगी। सन् १९२६ में माननीय फ़ाइनैस मेम्बर ने एसेम्बली के मेम्बरों को सूचित किया था कि इस विषय का विशेष कमेटी द्वारा विचार कराया जावेगा; किन्तु इन तमाम आश्वासनों के बाद कोई भी होने-वाली बात दिखाई नहीं दी। ग्रीन्स कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुए ७ वर्ष हो गये, उसकी सिफ़ारिशों के आधार पर इंग्लैंड की

पार्लियामेंट ने सन् १८२६ में क़ानून भी बना दिया ; किन्तु यहाँ अभी तक उसके कोई चिह्न दिखाई नहीं देते ।* सन् १८३० में सेंट्रल-बैंकिंग-इंक्वायरी कमेटी ने भी विशेष बैंक-क़ानून बनाने और सब प्रकार की बैंकिंग उन्नति के लिए अनेक सिफ़ारिशें की हैं । इसे भी ३ वर्ष पूरे हो गये; किन्तु उसपर कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं देता ।

अंग्रेज़ी भाषा का प्राधान्य—भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों का भी सारा हिसाब-किताब अंग्रेज़ी में होता है, नियम अंग्रेज़ी में छपते हैं, बैलेंस शीट अंग्रेज़ी में प्रकाशित होती है और हिंदुस्तानी खातेदारों से पत्र-व्यवहार भी अंग्रेज़ी में होता है । चेक अंग्रेज़ी में छपते हैं और लिखे जाते हैं । यहाँ तक कि रक़म को जमा और बरामद भी अंग्रेज़ी के छपे हुए फ़ार्मों द्वारा कराया जाता है और उन पर हस्ताक्षर भी अंग्रेज़ी में कराये जाते हैं । जो खातेदार अंग्रेज़ी नहीं जानते, उनको बैंकों के अफ़सर के सामने चेक पर दस्तख़त करने के लिये विवश किया जाता है तथा चेक पर देशी भाषा में येचाण (Endorsement) होने की हालत में किसी बैंक की तसदीक (Confirmation) माँगी जाती है । जो बैंक देशी भाषा के हस्ताक्षरों को अपनाते हैं, उनके यहाँ इस सम्बन्ध में ऐसे कड़े नियम हैं कि जिनके कारण चेक में

*Bombay Chronicle, 6th march 1931

†Vernacular signature on the cheques should be made in the presence of, and initialed by, one of the officers of

रहनेवाली त्रुटियों से होनेवाली हानियों के प्रति ज़िम्मेदारी खातेदार की रहती है और बैंक सुरक्षित रहते हैं। संसार में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ चेक-सम्बन्धी लेन-देन में देशी भाषा को नहीं अपनाया जाता। यह अड़चन ऐसी है कि अंग्रेज़ी नहीं पढ़े-लिखे लोग, जिनकी संख्या १०० में ६६ हैं, बैंकों के साथ व्यवहार करने से वंचित रहते हैं।

the Bank. The Bank reserves to itself the right to refuse payment of cheques bearing vernacular signatures not so authenticated—

Central Bank of India's Delhi Current Account rule 13

नवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—बैंक-कानून

पिछले अध्याय में भारतीय-बैंकिंग की वर्तमान पिछड़ी हुई अवस्था की कठना-जनक कहानी पाठक पढ़ चुके हैं। अब स्वभावतः प्रत्येक पाठक के हृदय में यह प्रश्न उठता होगा कि भारतीय-बैंकिंग को इस निर्बल, असहाय और अरक्षित अवस्था से मुक्त करके किस प्रकार सबल, सुदृढ़ और सुरक्षित बनाया जा सकता है ? इसका उत्तर देना ही इस अध्याय का उद्देश्य है।

भारतीय-बैंकिंग को उन्नतिशील बनाने के लिये पहिली आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बैंकों की विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता से रक्षा का जाय और भारतीय प्रजा के धन का, जो बैंकों में जमा हो, दुरुपयोग न हो और सुरक्षित रहे। दूसरी आवश्यकता पड़ने पर आर्थिक सहायता देकर आगन्तुक विपत्ति से बैंकों की रक्षा की जावे और फ़ेल होने से बचाने के उपाय किये जायँ। तीसरी आवश्यकता है—भारतीय-बैंकों के प्रति भारतीय जनता का गहरा विश्वास स्थापित हो और विदेशी बैंकों की अपेक्षा भारतीय-बैंकों को अधिक अपनाया जावे।

ये तीनों आवश्यकताएँ इस प्रकार पूरी की जा सकती हैं:—

(१) नवीन बैंक-कानून की रचना की जावे, जिसमें (अ)—

विदेशी-बैंकों के फैलाव और घन्धे पर आवश्यक प्रतिबन्ध हों, (ब) भारतीय बैंकों का संगठन, प्रबन्ध और निरीक्षण उचित रूप से होने के नियम हों और हिस्सेदारों तथा धरोहर जमा करनेवालों को अपने हितों की रक्षार्थ आवश्यक अधिकार हों ।

- (२) एक ऐसे बैंकों के बैंक राष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जावे, जैसे कि दूसरे देशों में सेंट्रल-बैंक स्थापित हैं ।
- (३) भारतीय विदेशी-व्यापार, उद्योग-धन्धों और कृषि को आर्थिक सहायता देने के धास्ते भारतीय विनिमय-बैंक, औद्योगिक-बैंक, कृषि-सहायक बैंक स्थापित हों ।
- (४) भारतीय बैंकों का आपस में संगठन हो ।
- (५) देशी भाषा को अपनाया जावे ।
- (६) भारतीय जनता आतुरता त्यागकर धैर्य के साथ अपने बैंकों के प्रति विश्वास रखना सीखे । इसके लिये देश की सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से धृष्ट आन्दोलन किया जावे ।

क़ानून की आवश्यकता—एक विशद और विभिन्न श्रेणियों से संयुक्त समाज में, जहाँ अधिकार, स्वत्व और कर्तव्यों के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न भिन्न भिन्न श्रेणियों के बीच में उठ मचते हैं या उठा करते हैं, वहाँ सामाजिक व्यवस्था, सुधार तथा शान्ति स्थापित रखने के उद्देश्य से समय समय पर परिस्थिति के अनुकूल क़ानून की सृष्टि होती रहती है । क़ानून का यह भी उद्देश्य है कि वह आर्थिक अवस्था का यथावत् सञ्चालन करे, जिससे समाज

रूपी यन्त्र सुगमता के साथ चलता रहे। क़ानून का धर्म है कि वह न्याय-तुला को संतुलन पर स्थिर रखे और सदैव सबल से निर्बल को रक्षा करने में तत्पर रहे। यह निश्चित है कि बिना सब प्रकार के क़ानून के मनुष्य-समाज व्यवस्थित रूप से नहीं रह सकता; किन्तु इसके साथ ही आदर्श स्वतन्त्रता-वादियों का यह भी सिद्धान्त है कि यथासम्भव राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये; पर इसके विरुद्ध प्रत्येक देश में विशेष कर युनाइटेड किंगडम में समाज के जीवन और हल-चल के लिये अनेक क़ानून प्रचलित हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का, समष्टि की हित-रक्षा के सामने, गौण रूप से ध्यान रखा जाता है। जो राजकीय अधिक हस्तक्षेप के अनेकानुक हैं, उनका यह कहना है कि “पार्लियामेण्ट के क़ानून द्वारा तुम किसी आदमी को संयमो नहीं बना सकते।”^{*} इस पर भी बहुत कुछ विपरीत परिस्थितियों के वशीभूत होकर क़त्त और अमरीका में नशीली चीज़ों का बनाना और बेचना क़ानून-विरुद्ध करार दिया गया है। भारत में इस कम से कम हस्तक्षेप के आदर्श को आर्थिक-समस्या के हल करते समय सामने रखने का यह अर्थ है कि भारत को संसार-व्यापी उन्नति की दौड़ में पीछा रखना है और बलवान संगठित और प्रभावशाली प्रतियोगिता

* “You can not make a people sober by an act of parliament”

† अमरीका में मदिरा-निषेध-अनून अभी हाल में मंजूर हो चुका है।

से यहाँ के उद्योग-धन्धे और व्यापार को चौपट करके इस दरिद्र देश को और भी दरिद्री बनाना है। बैंक कानून के सम्बन्ध में तो यह आदर्श रखना भारत-विरोधी प्रबल शक्तियों की काली करतूतों पर पर्दा डालना है और साथ ही भारतीय बैंकों के सवालकों को मनमानी करते रहने के लिये स्वच्छन्द छोड़ देना है।

बैंक देश के सार्वजनिक कोषागार हैं। इनके सुसंगठन, सुप्रबन्ध और सहव्यवहार का देश की आर्थिक अवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिये बैंकों के नियन्त्रण और सवालन के वास्ते उपयुक्त होना अनिवार्य है।

वर्तमान बैंक-कानून—इस समय भारतीय बैंकों का नियन्त्रण भारतीय कम्पनी कानून १९१३ के अनुसार होता है। इस कानून में ७ दफायें (४, ३२, १३२, १३६, १३८, १४५ और २५६) ऐसी हैं, जो बैंकिङ्ग धन्धा करनेवाली कम्पनियों का दूसरी प्रकार की कम्पनियों से पृथक्करण करती हुई बैंकों के लिये विशेष नियम होना सूचित करती हैं, जैसे—१० से अधिक व्यक्तियों को शामिल होकर बिना कम्पनी की भांति रजिस्ट्री कराये बैंकिङ्ग-धन्धा करने से रोकना, प्रतिवर्ष हिस्सेदारों की नामावलि रजिस्ट्रार के यहाँ प्रेषित कराना, नियत किये हुए फार्म (एफ) के अनुसार वेलेन्स-शीट तय्यार कराना और स्थानीय सरकार (Local Government) को, जारी-शुदा पूँजी (Issued capital) के $\frac{1}{4}$ के मालिक हिस्सेदारान की ओर से दरखास्त प्राप्त होने पर

उस बैंक के मामलात की, एक या अधिक हिसाब-निरीक्षण नियुक्त करके जाँच कराने का अधिकार होना, इत्यादि । इतना भर बैंकों पर यथोचित नियन्त्रण रखने के लिये पर्याप्त नहीं है । प्रतिवर्ष फ़ेल होनेवाले बैंकों की संख्या इसका प्रबल प्रमाण है; अतएव बैंक-सम्बन्धी कानून में सुधार की भारी आवश्यकता है । इसकी पूर्ति का प्रकार से की जा सकती है :—

(१) वर्तमान कम्पनी-क़ानून में बैंक सम्बन्धी कुछ धाराएँ और जोड़कर ।

(२) बिल्कुल नया क़ानून बनाया जाकर ।

नया क़ानून—पहले की अपेक्षा दूसरा उपाय अधिक स्पष्ट और उपयुक्त प्रतीत होता है । सैद्धान्तिक दृष्टि से 'ज्वाइंट-स्टॉक' का सिद्धान्त बैंकिंग और दूसरे धन्धों के लिये समान है, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से दोनों में गहरा भेद है । साधारण 'ज्वाइंट स्टॉक' कम्पनी के धन्धों में कुप्रबन्ध तथा अन्य कारणों से होनेवाले नुकसान का असर सबसे पहिले हिस्सेदारों पर होता है । यदि कभी कम्पनी के पावनेदारों पर इसका असर पड़ता है तो प्रथम तो वे व्यापारिक सिलसिले में विचार-पूर्वक पावनेदार बनते हैं, दूसरे जो लोग इन कम्पनियों को उधार देते हैं, वे भी यह बात जानते हैं कि हम ऐसी कम्पनी को उधार दे रहे हैं, जो नफ़ा नुकसान उठाने के लिये खुद का धन्धा करती है और कभी भी व्यापारिक तेजी मन्दी के कारण असफल हो

सकनी है। उन्हें कोई विवश नहीं करता; बल्कि वे लोभ के कारण स्वयं जोखिम उठाना स्वीकार करते हैं।

बैंक के पावनेदारों की स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न होती है। बैंकों के लिये लोगों का ऐसा ख़्याल होता है कि ये केवल कम ब्याज पर उधार लेकर कुछ अधिक ब्याज पर बड़े सांच-विचार के साथ सुरक्षित अवस्था में उधार देते हैं, खुद कोई नफ़े-नुक़सान की जोखिम उठाकर व्यापार नहीं करते; इसलिये इनमें नुक़सान होने की सम्भावना बहुत ही कम रहती है। इसके अतिरिक्त बैंक छोटी छोटी रक़मों माँगते ही वापस देने के लिये ब्याज पर जमा रखते हैं और चेकों द्वारा छोटी छोटी रक़मों अदा भी कर देते हैं। इन सुविधाओं से प्रेरित होकर लोग बैंक के साथ हिताश रखने के लिये विवश होते हैं। आम तौर पर इनमें रक़मों सुरक्षित रहने की दृष्टि से जमा की जाती है न कि केवल ब्याज कमाने के लिये। इस प्रकार बैंक देश के व्यवसाय और उद्योग-धन्धों के लिये सर्वसाधारण की बचत (Savings) को संग्रह करने में समर्थ होते हैं। इनके फ़ैल होने का, दूसरे धन्धों की अपेक्षा, लोगों पर अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है और देश के आर्थिक संगठन की लड़ी कमज़ोर होती है; अतएव बैंक-सम्बन्धी क़ानून कम्पनी-क़ानून से बिल्कुल पृथक् होना चाहिये ताकि बैंक और प्रजा दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ व्यवहार करने के लिये स्थिति स्पष्ट हो जावे।

भारत में बैंक-क़ानून की माँग “सन् १९१३ से की

जा रही है। सर्वप्रथम कराँची में होनेवाली भारतीय-इण्डस्ट्रीयल-कॉन्फ्रेंस ने इसके लिये प्रस्ताव पास करके बैंकिंग-कानून बनाने के लिये सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। इसके बाद सन् १९१३—१५ में फुल होनेवाले बैंकों की सख्या से भारत सरकार की आँखें खुलीं और उसने स्थानीय सरकारों और व्यापारिक संस्थाओं से इस सम्बन्ध में सम्मतियाँ माँगीं, उनमें बहुमत जल्दी क़ानून बनाये जाने के पक्ष में था। तब पश्चात् सन् १९२० में बंगाल चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स की प्रार्थना पर एक कमेटी ने इस प्रश्न पर विचार किया। उसने भी मूलधन-सम्बन्धी पाबन्धियाँ लगाने और उचित निरीक्षण होने के लिये नियम बनाने की सिफ़ारिश की थी।”* सन् १९३० में समस्त प्रांतीय बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटियों ने और अन्त में सेंट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने नवीन बैंक क़ानून बनाने की जोरों से सिफ़ारिश की है।

क़ानून का उद्देश्य—क़ानून ऐसा सुगम, उपयुक्त और पूर्ण होना चाहिये, जिससे भारत-स्थित विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता से भारतीय-बैंकों की रक्षा हो, फुल होने से बचें और पिछड़ी हुई अवस्था दूर होकर भारतीय बैंकिंग धन्धा उन्नति को प्राप्त हो। इसके निम्नलिखित ५ उद्देश्य होने चाहिये :—

* Regulation of Banks in India by M. L. Tannan

- (१) विदेशी-बैंकों के कारोबार पर प्रतिबन्ध लगाना ।
- (२) भारतीय बैंकों का 'उपयुक्त संगठन' होना ।
- (३) भारतीय बैंकों का 'उत्तम प्रबन्ध' होना ।
- (४) भारतीय बैंकों का 'उचित निरीक्षण' होना ।
- (५) छेप-पूर्ण और झूठे आरोपों और आक्रमणों से बैंकों की रक्षा करना ।

विदेशी बैंकों के लिये प्रतिबन्ध

कार्य-क्षेत्र-सीमा—विदेशी बैंक, जो विनिमय का धन्धा करते हैं, अपनी अपनी शाखायें उन देशों में, जिनसे उनके देश का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, खोलते हैं, ताकि व्यापारिक भुगतान और चुकौता आसानी से हो सके। इनका व्यवसाय दूसरे देशों में विनिमय-सम्बन्धी लेन-देन तक ही सीमित रहता है। इनका काम केवल एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक आने-जानेवाले माल को आर्थिक सहायता देना है, किन्तु देश के भीतरी व्यवसाय से इनका कोई प्रयोजन नहीं होता है। "सन् १९२६ ई० में एक अन्तर्राष्ट्रीय-कान्फ़ेरेन्स पेरिस में बैठी थी, उसके सामने यह माँग पेश की गई थी कि विदेशियों के काम-काज और हलचल पर, जहाँ तक उसका अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय की आवश्यकता से सम्बन्ध है, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। इस पर वाद-विवाद होने के पश्चात् यह बात मान ली गई है कि विदेशियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के अधिकारों

में देश के अन्दरूनी व्यापार से कोई सम्बन्ध नहीं होगा। इसको प्रत्येक राष्ट्र अपने देशवासियों के लिये सुरक्षित रख सकेगा।”^{*} दूसरे शब्दों में यों कहना चाहिये कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सीमा केवल एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक आयात-निर्यात से है, न कि उस माल को देश के भीतरी भागों में बिभक्त करने और भीतरी भागों से सग्रह करके निर्यात के लिये बन्दरगाह तक पहुँचाने के व्यवसाय से।

“दूसरे देशों में विदेशी बैंकों का फैलाव इस बात की पुष्टि करता है। लगभग सभी देशों में विदेशी बैंकों का व्यावसायिक क्षेत्र मुख्य मुख्य व्यावसायिक केन्द्र, जैसे—पेरिस, बर्लिन, मिन्न, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, अर्जन्टाइन आदि के बन्दरगाहों के शहरों में सीमित है। ये अपने विज्ञापनों में भी यही प्रकट करते हैं कि उनकी शाखाएँ समस्त मुख्य मुख्य बन्दरगाहों में हैं; किन्तु देशों के भीतरी व्यापारिक शहरों में शाखाएँ होने का दावा नहीं करते। योकोहामा स्पेसी बैंक की ४० शाखाएँ हैं और सबकी सब बन्दरगाही शहरों में हैं। दी गारण्टी ट्रस्ट कम्पनी आबू न्यूयार्क की शाखाएँ केवल लन्दन, लिबरपूल, पेरिस, हावर्, ब्रुसेल्स और ऐंस्टर्प में हैं। दी कोम्टोयर नेशनल फ्रान्स की चन्द शाखाएँ इङ्ग्लैण्ड, बेल्जियम, आस्ट्रेलिया, भारत और इजिप्ट में खुली हुई हैं। ये सबकी सब बन्दरगाही शहरों में

*Minute of Dissent by Nalini Ranjan Sarkar, Para II,

हैं।" तात्पर्य यह है कि समस्त विनिमय बैंकों ने दूसरे देशों में अपना कार्य-क्षेत्र बन्दरगाही शहरों तक समझा हुआ है; लेकिन भारत में इनकी शाखाएँ बन्दरगाही शहरों की सीमा को छलांग मारकर देश के भीतरी भाग; जैसे—अमृतसर, देहली, कानपुर, लाहौर, रावलपिण्डी, शिमला और भीनमर आदि अनेक शहरों में फैली हुई हैं, जो भारतीय बैंकों की उन्नति के मार्ग में अत्यन्त बाधक हो रही हैं।

अन्य प्रतिबन्ध—दूसरे देशों में केवल बन्दरगाही शहरों में विदेशी-बैंकों की खुलनेवाली शाखाओं पर, उस देश के बैंकों के साथ प्रतियोगिता, उस देश की पूँजी का दुरुपयोग और उस देश के निवासियों को उपेक्षा करना रोकने के लिये, अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगा रखे हैं; यथा—

डेनमार्क में विदेशी-बैंकों को अपना कारोबार फैलाने के लिये विशेष आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। यह आज्ञा आसानी से नहीं दे दी जाती है, आज्ञा देने के साथ साथ कुछ शर्तें लगाई जाती हैं; जैसे—शाखाओं के कार्य-कर्त्ता, मैनेजर उस देश के निवासी (डेनिश) होने चाहिये।

फ़्रान्स और इटली में शाखा खोलनेवाले विदेशी बैंकों पर उनके मूलधन और विनिमय के व्यवसाय पर विशेष टैक्स लगाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतियोगिता रोकना होता है।

जेको-स्लेवेकिया में वहाँ की सरकार विदेशी-बैंकों को शाखाएँ खोलने से रोकती है।

जापान में विदेशी बैंकों को वहाँ के अर्थ-सचिव (Finance Minister) से लाइसेन्स प्राप्त करना पड़ता है; किन्तु लाइसेन्स का देना या न देना उसकी इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे तो इंकार कर सकता है या स्थानीय अमानतों के जमा रखने की रुकावट डालकर और ऐसे कर लगाकर, जो उसके नज़दीक आवश्यक हो, लाइसेन्स दे देता है। इस पर भी वे बैंक जापान में अपने नाम के साथ 'बैंक' शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। साथ ही जापानी सरकार विदेशी बैंक की प्रत्येक शाखा से १ लाख 'येन' ज़मानत के तौर पर जमा कराती है।

टर्की में कमाल पाशा की नवीन सरकार विदेशी-बैंकों की शाखाओं को ५० प्रतिशत तुर्की मौक़र रखने के लिये विवश करती है। यह नियम पुराने समय से स्थापित बैंकों पर भी उसी प्रकार लागू है जैसा कि नवीन खुलनेवाले प्रार्थी बैंकों पर।

संयुक्त राज्य अमरीका में विदेशी बैंकों की शाखाओं को अमानतें जमा रखने का अधिकार नहीं है।

आस्ट्रेलिया और कनाडा—घर के नज़दीक ब्रिटिश साम्राज्य की गोद में इन दो बड़े उपनिवेशों के उदाहरण भी मौजूद हैं। आस्ट्रेलिया में कोई विदेशी बैंक शाखा नहीं खोल सकता। 'चार्टर्ड-बैंक ऑफ़ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चीना' की शाखा

भी आस्ट्रेलिया में नहीं है, हालाँकि यह बैंक अपने नाम में 'आस्ट्रेलिया' शब्द का प्रयोग करता है। कनाडा में भी विदेशी बैंकों पर कानून-द्वारा प्रतिबन्ध लगे हुए हैं।

हंगलैण्ड जैसा शक्तिशाली देश भी, जिसका बैंकिंग धन्धा पूर्ण संगठित है और सुदृढ़ रूप से जमा हुआ है, व्यापारिक स्वतन्त्रता के विरुद्ध आवाज उठाने लगा है। कन्फ़्रमेटी ने, जो लंडन के वाद करेन्सी और विदेशी विनिमय पर विचार करने के लिये बैठी थी, अपनी रिपोर्ट में कहा है—

“हमारे सामने चन्द गवाहों ने उस अवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो इस देश में विदेशी बैंकों के जमने के लिये खुला द्वार होने से उपस्थित हुई है; अतः हम प्रस्ताव करते हैं कि सम्राट की सरकार को इस ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिये।”*

इस रिपोर्ट पर उक्त कमेटी के समस्त सदस्यों ने एक मत होकर हस्ताक्षर किये हैं, जिनमें हमारे भूतपूर्व फ़ाइनेन्स मेम्बर

*“Several of our witnesses have called attention to the condition under which it is open to foreign banks to establish themselves in this country. We suggest that this is a matter which should receive the early attention of His Majesty's Government. “Organization of Indian Banking” by ‘Thakur’ page 249 ”

सर बेसिल ब्लेकिट के, जो उस वक्त ब्रिटिश ट्रेजरी के अर्थ-सचिव थे, हस्ताक्षर शामिल हैं।

लाइसेन्स की आवश्यकता—उपरोक्त पंक्तियों का सारांश यह है कि अधिकांश देशों में विदेशी बैंकों को अपनी शाखाएँ खोलने के लिये उस देश की सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है। इस आज्ञापत्र ही को 'लाइसेन्स' कहते हैं। आज्ञा देना न देना उस देश के तत्सम्बन्धी अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर होता है। आज्ञा देते समय कुछ बन्धन ऐसे लगा दिये जाते हैं, जिनसे वे बैंक वहाँ के देशी बैंकों के साथ प्रति-योगिता करके उनका व्यापार अपहरण करने में सफल न हो, सकें और वहाँ की राष्ट्रीयता को धक्का न लगे। इंग्लैण्ड जैसे जिन देशों में अब तक प्रतिबन्ध नहीं है, वहाँ अब लगाने के लिये सोचा जा रहा है। हालाँकि उनकी सुसंगठित बैंकिंग को देखते हुए किसी प्रकार के प्रतिबन्धों की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हालत में भारत जैसे देश में, जहाँ का बैंकिंग धन्धा निर्वल अवस्था में है और जो विदेशी बैंकों के संगठन, प्रभाव और समृद्धि के आगे पनपने नहीं पाता और भी आवश्यकता इस बात की है कि स्थानीय बैंकों के संरक्षण के लिये, राष्ट्र हित की रक्षार्थ तथा यहाँ की आर्थिक अवस्था को उन्नत करने के हेतु, भारत-स्थित विदेशी बैंकों की स्वच्छन्दता को रोकने और भविष्य में नवीन विदेशी बैंकों की स्थापना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक प्रतिबन्ध लगाये जाकर लाइसेन्स-प्रथा जारी की

जाय। इसको भारतीय संसदल बैंकिङ्ग इन्क्वायरी कमेटी (१९३१) ने भी एक स्वर से मान लिया है और साथ ही विदेशी बैंकों के प्रतिनिधि ने उस कमेटी के सामने गवाही देते समय स्वीकार कर लिया है; यथा—“मैं यह कह सकता हूँ कि विनिमय बैंक किसी भी प्रकार के लाइसेन्स को, जो सरकार-द्वारा नियत किया जा सके, पूर्ण रूप से स्वीकृत करने को तैयार हैं।”*

लाइसेन्स की शर्तें—भारत की राष्ट्रीय दृष्टि से भारतीय बैंक और व्यापारियों की उन्नति के निमित्त तथा सार्वजनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये निम्नलिखित शर्तें उपयोगी मालूम होती हैं—

(१) विदेशी विनिमय बैंकों की कार्यक्षेत्र-सीमा बन्दरगाही शहरों तक सीमित हो।

(२) इनका व्यवसाय केवल एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक आने-जानेवाले माल को आर्थिक सहयोग देने तक रहे। देश के भीतरी भाग के व्यवसाय से इनका कोई सम्बन्ध न हो।

(३) ये भारतीय प्रजा की मियादी और सेविंग बैंक खाते की श्रमानतें (Deposits) जमा न रख सकें, केवल चलू खाते में जमा रखने की स्वतन्त्रता हो।

* “ I can say that the exchange Banks are perfectly willing to agree to any licence which government may prescribe ”

(४) इनकी भारतीय शाखाओं के कर्मचारियों में केवल मैनेजर को छोड़कर शेष श्रमला भारतीय हो ।

(५) इनकी भारतीय शाखाओं के संचालन के लिये प्रत्येक शाखा के शहर में वहाँ के भारतीय व्योपारियों के बहुमत के साथ एक परामर्श-मंडल स्थापित करना आवश्यक हो ।

(६) भारतीय क़ानून के अनुसार और भारतीय इवाइएड-स्टाक-बैंकों के समान, भारतीय शाखाओं के सम्बन्ध का लेखा-जोखा प्रकाशित करने के लिये बाबन्द हों ।

(७) इनके फ़ैल होने पर लेने-देने का चुकौता करने के लिये भारतीय हाईकोर्ट द्वारा रिसीवर नियुक्त हों, जिनको इनकी पूँजी अपने अधिकार में लेने का अधिकार हो और ऐसी पूँजी के विभाजन पर सर्वप्रथम भारतीय पावनेदारों का स्वत्व रहे । यदि भारत-स्थित सम्पत्ति से भारतीय पावनेदारों की रक़म वसूल न हो सके तो विदेशों में होनेवाले सम्पत्ति-विभाजन में भारतीयों को हिस्सा बँटाने का अधिकार हो ।

(८) इनको भी भारतीय बैंकों के समान इकम्-टैप्स देना पड़े ।

पहली और दूसरी शतों के सम्बन्ध में ऊपर विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है । इनसे यह लाभ होगा कि मौजूदा भारतीय बैंकों को उन्नति करने का अवसर मिलेगा और नवीन खुलनेवाले बैंकों को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिये उत्तम क्षेत्र प्राप्त होगा । अतिरिक्त इसके उन भारतीय व्योपारियों के हितों की

रहा होगी, जो देश के भीतर का व्यवसाय करते हैं और अब तक विदेशी बैंकों द्वारा सहायता-प्राप्त विदेशी कम्पनियों और व्यापारियों की प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने में समर्थ नहीं होते हैं।

अमानतों की रोक—यह माना हुआ सिद्धान्त है कि “सार्वजनिक प्रजा का धन सराफ़ा बाज़ार को धनी बनाने के काम आना चाहिये न कि विदेशों में भेजा जावे।”* संसार के समस्त देश इसका अनुकरण करते हैं। अमरीका में विदेशी बैंकों का अमानतें जमा रखना कानून द्वारा वर्जित है। दूसरे देशों ने भी अन्य कई प्रकार के प्रतिबन्ध लगाकर इस सम्बन्ध में रोक-वटें डाल रखी हैं, जिनका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है।

“यह मानी हुई बात है कि भारत-स्थित विदेशी बैंकों के पास भारतीय विदेशी व्यापार के लिये जितने धन की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक अमानतें जमा हैं। सन् १९२८ में इन बैंकों में ६६३ करोड़ में से ३८८६ करोड़ रुपया केवल भारतीय-प्रजा का जमा था, जब कि विदेशी-विनिमय बिलों में केवल ११ करोड़ रुपया लगा हुआ था। प्रस्तावित-प्रतिबन्ध केवल भारतीय बचत (Savings) अर्थात् मियादी और सेविंग्स-बैंक की अमानतों को जमा होने से रोकता है और भारतीय लोगों के चल्लू खातों की जमाओं को तथा विदेशी लोगों, कम्पनियों और संस्थाओं की सब प्रकार की ‘जमा’ रखने के लिये स्वतन्त्रता

*Minority Report, para 222, para 204

देता है; अतः विदेशी लोगों की हर प्रकार की 'जमा' २७ करोड़ और चल्लूखाते की भारतीय 'जमा' २० करोड़ मिलकर ४७ करोड़ के लगभग होती है, जो इन बैंकों के विदेशी धन्ये की आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त ही नहीं, बल्कि अत्यधिक है। हाँ, यह अग्रश्य है कि मुफस्सलात से शाखाएँ हटा लेने पर इस जमा में अवश्य कमा आ जावेगी, लेकिन फिर भी चल्लूखाते की भारतीय 'जमा' में ११ करोड़ से कम हाने की सम्भावना नहीं है।"

सेण्ट्रल बैंकिंग इक्वाइटी कमेटी (१९३१) ने भी इस सम्बन्ध में पूर्ण विचार किया है। बहुमत रिपोर्ट में तो किसी भी प्रकार की 'जमा' पर प्रतिबन्ध लगाने की सिफारिश नहीं की गई है। लेकिन श्रीमनु सूवेदार ने अपनी अल्पमत रिपोर्ट में जो सिफारिशें की हैं, उनमें चल्लूखातों की जमाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाया है, किन्तु हमने चल्लूखातों की 'जमा' को प्रतिबन्धों से मुक्त रक्खा है। उसके कारण हैं :—

(१) जब तक भारतीय विनियम बैंक स्थापित होकर चल न निकले तब तक विदेशी व्यापार में गति रखनेवाले व्यापारियों को इन्हीं बैंकों से काम लेना पड़ेगा और एक बैंक को अपनी साख का परिचय दिलाने के लिये अनेक साधनों के साथ साथ चल्लूखाता रखना भी एक आवश्यक साधन है।

(२) चल्लूखातों की रकम संचित-धन (Savings) नहीं कही जा सकती और न यह केवल सूद कमाने के लिये ही जमा की जाती है। यह बाजारू व्यापारिक रूपरा होता है, जो व्यापा-

रिक लेन-देन का चुकौता करने के लिये दैनिक उपयोग में आता रहता है। भारतीय विनिमय बैंक स्थापित होने पर भारतीय व्यापारियों का उससे लेन देन आरम्भ होने के साथ इन विदेशी बैंकों से अधिक सम्बन्ध न रहने के कारण भारतीय व्यापारियों के चल्लू खाते की जमा अपने आप कम होती चली जायगी, इस-लिये इस 'जमा' पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

जमा रखनेवाले का अधिकार—प्रत्येक मनुष्य अपने रुपये को अपनी इच्छानुसार उपयोग में लाने का पूर्ण अधिकारी है। बाजार में अनेक बैंक हैं, जो जनता का रुपया खींचने के लिये प्रतिस्पर्धावश एक दूसरे से उत्तम सुविधा उपस्थित करते हैं। इस विशेष साधन से जनता क्यों न विशेष लाभ उठावे ? यह एक आवश्यक और महत्व पूर्ण प्रश्न है, जो सर ओसबॉर्न स्मिथ ने सरदूल बैंकिंग इन्व्हाइरी कमेटी के सामने उठाया था।* इसका युक्ति-

* "There should be no interference with the deposit of Indian Money with foreign banks in India I am strongly against any interference in matters on this sort, as people should have the right to invest their money as they wish. the more banks there are that compete for their money, the greater facilities the public will enjoy" Sir Osborne Smith (Minority Report, para 228).

युक्त और मार्मिक उत्तर श्रीमनु सूवेदार ने अपनी अल्पमत रिपोर्ट के पैरा न० २२८ में बड़ी योग्यता से दिया है।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रता—अपने निजी हित के लिये इच्छा-नुसार कार्य करने के वास्ते प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है। यह सिद्धान्त उचित अवश्य है; किन्तु फिर भी नियन्त्रण-रहित नहीं है। उदाहरणार्थ—इस समय चीन और जापान दो देशों में लड़ाई है। जापान के व्यापारों को युद्ध-सम्बन्धी सामान की कीमत जापान की अपेक्षा उसके शत्रु-देश चीन से अच्छी मिलती है और उसको बेचने में निःसन्देह जापान के व्यापारी को बड़ा लाभ होता है, लेकिन घट्ट ऐसा करने पर देशद्रोही समझा जाकर तुरन्त गिरफ्तार कर लिया जावेगा और उसको कठोर दंड दिया जायगा।

व्यक्ति और राष्ट्र—शान्ति काल में देश-विरुद्ध कार्यों की ध्यातया करना और उनसे मालूम करना अधिक कठिन होता है, लेकिन प्रत्येक सुसंगठित राष्ट्र इस बात का सदैव ध्यान रखता है कि सामुहिक हित को व्यक्ति विशेष द्वारा हानि न पहुँचने पावे। इसकी वजह से कोई व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं कर सकता, जिससे राष्ट्र के सामुहिक कार्यों में बाधा पहुँचे। इस प्रकार देश के आर्थिक छिद्रों की ओर सचेत रहना प्रत्येक राष्ट्र का प्रधान कर्त्तव्य है। इसका ठीक ठीक पालन जापान, इटली और टर्की जैसे देशों ने किया है, जो किसी जमाने में भारत से भी अधिक पिछड़ी हुई अवस्था में होने पर भी उन्नति करते हुए

अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में स्थान प्राप्त कर सके हैं। भारत-सरकार कई कारणों से इस कर्त्तव्य का पालन करने में उपेक्षा कर रही है, जिनका विवेचन करना यहाँ अप्रासंगिक है।

उपस्थित प्रश्न राष्ट्र के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकारों का है। राष्ट्रीय जीवन का प्रथम उद्देश्य यह है कि समस्त व्यक्तियों को मिलकर विदेशी शक्तियों के विरुद्ध, चाहे लड़ाई का जमाना हो या शान्ति का, सभी बातों में एक दूसरे को सहायता पहुँचाने का ध्यान रखना चाहिये। चूँकि सब देशवासी मिलकर राष्ट्र और व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये बाध्य हैं, इसलिये राष्ट्र की काम में आनेवाली शक्तियों से, चाहे सामुहिक हो या व्यक्ति विशेष की, लाभ उठाने का पहला अधिकार उस राष्ट्र के निवासियों का है। एतदर्थ राष्ट्र को सरकारी और निजी नौकरियों पर नियुक्त होने का सबसे पहले उस देश के कदीमी नागरिकों का अधिकार है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दी जानेवाली सरकारी सहायता और रियायतों का उपभोग करने के एक मात्र अधिकारी उस देश के असली निवासी हैं। सरकार से सरक्षण पाने का केवल और सर्वोपरि अधिकार देश के पैतृक निवासियों का है। अस्तु भारत में भी देश के साधनों का उपभोग करने में पहला स्वत्व भारतीय जनों का है। चूँकि सर्वसाधारण की बचाई हुई पूँजी (Savings) देश की पूँजी है। इसकी देश को व्यापार और उद्योग-धंधे बढ़ाने के लिये भारी आवश्यकता है,

इसलिये इसको कोई, भारतीय जनों के अतिरिक्त, किसी दूसरे के हाथ में नहीं सौंप सकता ।

सरकार और व्यक्तिगत सम्पत्ति—समस्त देशों में व्यक्तिगत सम्पत्ति पर मालिकाना अधिकार पहले राष्ट्र का और बाद में मालिक का माना गया है । अनेक देशों ने झगड़े टटों से बचने और अधिक मात्रा में पराये स्वार्थ को दूर रखने के उद्देश्य से अपने यहाँ विदेशियों के लिये जायदाद खरीदने की मनाही कर रखी है । प्रत्येक राज्य के अन्दर व्यक्तिगत सम्पत्ति सरकार के दखल से सुरक्षित रहती है । जायदाद सम्बन्धी समस्त व्यक्तिगत अधिकार सरकार द्वारा बनाय हुए कानून के आधीन हाते हैं, जिनको सरकार देश के सम्मिलित हित के धास्ते हमेशा बदलने का अधिकार रखती है । जायदाद में मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिये मालिक द्वारा चुकाया हुआ प्रत्येक 'बदल' उचित नहीं होता, बल्कि वह बदल उचित होता है, जिसको सरकार उचित समझती है । सरकारी कानून जायदाद की मिलकियत की परिपाटी नियत करता है, उसके स्वत्व-परिवर्तन और दालिल खारिज होने के सिद्धान्त बनाता है । प्रत्येक सरकार को राष्ट्र के सम्मिलित हित के लिये जायदाद के लाभ में से टैक्स के रूप में हिस्सा बाँटने का अधिकार होता है, जिसको चुकाना प्रत्येक व्यक्ति के लिये अनिवार्य होता है और ऐसा टैक्स व्यक्तिगत लोगों के सब प्रकार के निजी लेन देन से सर्वप्रथम वसूल किये जाने योग्य होता है । इस प्रकार कानून और टैक्स

की स्थापना करके भी सरकार व्यक्तिगत मिलकियत और उससे प्राप्त होनेवाले अधिकारों की सीमा बांधने का अधिकार रखती है।

इन मौलिक सिद्धान्तों पर गहरा विचार करने के बाद यही परिणाम निकलता है कि एक व्यक्ति को अपनी बचाई हुई पूँजी पर देश के दूसरे व्यक्तियों के मुकाबले में अपनी इच्छानुसार उपभोग करने का अधिकार है, न कि राष्ट्र के मुकाबले में। सरकार राष्ट्र की संचालक है। वह राष्ट्र के खर्च से प्रत्येक व्यक्ति की पूँजी की रक्षा करने का प्रयत्न करती है; इसलिये वह राष्ट्र के सम्मिलित हित को सामने रखकर आज्ञा दे सकती है कि व्यक्ति-विशेष को अपनी बचाई हुई पूँजी का क्या उपयोग करना चाहिये और क्या नहीं।

इन्हीं सिद्धान्तों की दुहाई देकर भारत सरकार ने कांग्रेस के सत्याग्रह-आन्दोलन जारी कर देने पर उसके सहायकों को सहायता देने से रोकने के लिये हुक्म जारी किये थे। दुःख तो इस बात का है कि ब्रिटिश-सरकार अपने या अपने देश (ब्रिटेन) वासियों के हित के लिये तो इन सिद्धान्तों का अनु-करण कर लेती है, लेकिन जब ब्रिटेन के विरुद्ध भारतीय-प्रजा के हित का प्रश्न सामने आता है तब व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का राग अलापती है। अस्तु

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्र के सम्मिलित हित की दृष्टि से संचालन करने के लिये सरकार का निजी

पूँजी के उपयोग-सम्बन्धी व्यक्तिगत अधिकारों में दखल देना सर्वथा उचित और दूसरे देशों में स्वीकृत नीति के अनुसार है; अतएव भारत सरकार को चाहिये कि विदेशी बैंकों में जमा होनेवाली भारतीय अमानतों को रोकने के लिये कानूनी नियम अवश्य बनाये।

कर्मचारी—विदेशी बैंक लगभग ७५ वर्ष से भारतीय पूँजी और व्यापार से लाभ उठाते आ रहे हैं, किन्तु इन्होंने इतने लम्बे समय के अन्दर एक भी भारतीय को उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया। इससे अधिक भारतीयों की उपेक्षा का और क्या प्रमाण हो सकता है? सेण्ट्रल-बैंकिंग इम्बार्सी कमेटी के समस्त सदस्यों ने भी इस पर बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है और उन्होंने यह परामर्श दिया है कि इनको इम्पीरियल बैंक की भाँति भारतीयों के लिये शिक्षण-योजना आरम्भ करनी चाहिये और काम के योग्य हो जाने पर उनको जिम्मेदारी के पदों पर नियुक्त करना चाहिये।* उक्त कमेटी के

* We are impressed by the fact that though the exchange banks have been operating in India for more than half a century, they have not employed a single Indian in the superior grades of their service. It can hardly be contended that the banks have been unable during all this time to find even one competent Indian who could be entrusted with a superior officer's position.

सदस्यों में से श्री० नल्लनिरंजन सरकार और श्री० मनुसूवेदार ने केवल परामर्श से सन्तुष्ट न होकर चौथी शर्त के अनुसार प्रतिबन्ध न लगाये जाने की सिफ़ारिश की है। ऊपर टर्कों का उदाहरण उद्धृत किया जा चुका है। वहाँ विदेशी-बैंकों के लिये क़ानूनी नियम है कि ५० फ़ीसदी अमला तुर्की होना चाहिये। इसी प्रकार इटली में भी विदेशी-बैंक अपनी शाखाओं में अपने देश के मैनेजर कठिनता से रख सकते हैं। जब दूसरे उन्नतिशील देशों का यह हाल है तो भारत जैसे देश में फ़ोरे उपदेशों से कैसे काम चल सकता है; अतएव इस सम्बन्ध में शर्त नं० ४ के अनुसार क़ानूनी नियम होना आवश्यक है।

परामर्श-मंडल—“बैंक और विदेशी व्यापार” शीर्षक अध्याय में बताया जा चुका है कि इन बैंकों का व्यवहार जातीय पक्षपात से पूर्ण और भारतीय-राष्ट्रीयता के विरुद्ध होता आ रहा है। ये सदैव विदेशी संस्थाओं को लाभ पहुँचाने के लिये भारतीय संस्थाओं की उपेक्षा करते रहते हैं; इसलिये भविष्य में इस कुटिल नीति पर शंकुश रखने के वास्ते आवश्यक है कि पाँचवीं शर्त के अनुसार परामर्श-मंडल की योजना का नियम हो।

in their organization We recommend for the consideration of exchange banks that they should have scheme of probationary assistants on the model of the Imperial Bank of India Scheme (Majority Report, p 474)

लेखा-जोखा—ये बैंक विदेशों में रजिस्टर्ड होते हैं। इनक डाइरेक्टर विदेशी होते हैं। इनका निरीक्षण बाहर होता है और ये भारतीय व्यापार का लेखा-जोखा भी उपयुक्त मात्रा में प्रकाशित नहीं करते, इसलिये इनक सम्बन्ध में भारत वासियों को कोई जानकारी नहीं होने पाती, अंधेरे में रहते हैं। अस्तु।

भारतवासियों को इनकी स्थिति से परिचित रखने के वास्ते छठवीं शर्त भी होनी चाहिये।

दिवाला निकलने पर—ऊपर लिखे हुए कारणों से भारतीय पाधनेदारों के हितों की रक्षार्थ इस शर्त का होना बहुत जरूरी है। इसके लिये से० वी० ३० कमेटी ने भी सिफारिश की है। *

टैक्स सम्बन्धी आठवीं शर्त इस प्रयोजन से होना चाहिये कि इन विदेशी बैंकों के साथ भारतीय बैंकों की अपेक्षा कोई विशेष रिश्तायत न हो ताकि ये प्रतियोगिता करके भारतीय बैंकों को हानि पहुँचाने में समर्थ न हो सकें।

विशुद्ध भाव—जिन प्रतिद्वन्द्वों को लगाये जाने के लिये ऊपर जो प्रस्ताव किये हैं, वे द्वेष-वश नहीं किये हैं और न विदेशी बैंकों की बढ़ती हुई समृद्धि से हमें डाढ़ है। हम हृदय से चाहते हैं कि इनकी उन्नति दिन दूनी और रात चौगुनी होती रहे।

हमारी प्राचीन सभ्यता हमें यही सिखाती है कि हम स्वयं में भी किसी का बुरा न चाहें; लेकिन साथ ही हम यह अवश्य चाहते हैं कि दूसरों के प्रहारों से हम अपनी रक्षा कर सकें। हमारा देश भी दूसरे देशों के समान समृद्धिशाली हो, उद्योग-धन्यों से भरा-पूरा और कला-कौशल का केन्द्र हो, हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में स्वयं समर्थ हों और परमुखापेक्षी न रहें। भारतवासियों को भर-पेट रोटी मिले, इनका मान-सम्मान और गौरव संसार की किसी जाति से कम न रहे। अस्तु, ये प्रतिबन्ध केवल आत्म-रक्षा और स्वदेश के लिये चाहे गये हैं। हमारा ऐसा चाहना कोई नई बात नहीं है। हमारी परिस्थिति के समान ही नहीं, वरन् हमसे अधिक समुन्नत-वस्था में होते हुए भी दूसरे देशों ने इनसे भी अधिक कठोर प्रतिबन्ध लगाये हैं। स्वयं इंग्लैण्ड ने इस सम्बन्ध में अधिक कठोरता का परिचय दिया है।

“लगभग चौदहवीं शताब्दी में लोम्बार्डी लोगों ने अपने देश लोम्बार्डी (इटली के उत्तरी भाग) को विदेशियों के लगातार आक्रमण से तंग आकर त्याग दिया था और वे मारसी भूमि पर, जो उस समय लन्दन शहर का बाहरी हिस्सा था, बस गये थे। वहाँ उन्होंने बैंकिंग, बीमा और आयात-निर्यात का व्यवसाय आरम्भ किया था। इंग्लैण्ड में बैंकिंग धन्धे के जन्मदाता ये लोम्बार्ड लोग ही थे। उन्होंने वहाँ थोड़ी ही अवधि में इंग्लैण्डवालों से कमाई करके अपरिमित उन्नति

कर ली थी। यह अंग्रेजों से सह्य नहीं गया। फल-स्वरूप वहाँ के राजाओं ने उनके विरुद्ध प्रतिबन्धक कानून पास किये। इतना ही नहीं, रानी एलिजाबेथ ने तो उनको निकल जाने का हुक्म दे दिया था।”* इस ऐतिहासिक घटना को हम अंग्रेजी बैंकों के सामने, जो उन्हीं के देश की है, उपस्थित करते हैं और विश्वास करते हैं कि वे हमारे प्रस्ताविन बहुत हलके प्रतिबन्धों से रुष्ट न होंगे। विशेष कर इस अवस्था में कि जब इस प्रकार के प्रतिबन्ध आधुनिक जगत् के अनेक देशों में मौजूद हैं।

भारतीय-बैंक-सम्बन्धी कानून

दूर करने योग्य त्रुटियाँ—बैंकों का उपयुक्त संगठन, प्रबन्ध और निरीक्षण होने के वास्ते कानूनी नियम तजवीज करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वे कौन सी त्रुटियाँ हैं, जिनको कानून द्वारा दूर करना है। सेण्ट्रल बैंकिंग इक्वाइटी कमेटी ने इस सम्बन्ध में गहरा अनुसन्धान करके निम्नलिखित त्रुटियाँ प्रमुख बताई हैं † —

(१) प्रबन्ध में बेईमानी ।

(२) डाइरेक्टरों की अयोग्यता, जो व्यावहारिक बैंकिंग या व्यावसायिक चातुर्य से विलकुल अनभिज्ञ होने के कारण चालाक

* Bombay chronicle, 2nd March, 1931

† Its Report Para, 674

प्रबन्धक, डाइरेक्टरों और मैनेजरो की कारस्तानियों को पकड़ने में असमर्थ पाये गये ।

(३) छोटे और जोखमी धन्धों में रुपया लगाना ।

(४) डाइरेक्टरों और उनसे सम्बन्धित संस्थाओं को बे रोक-टोक अंधाधुन्ध रुपया उधार देना ।

(५) असावधानी से रुपया उधार देना ।

(६) अल्पकालीन जमाओं को लम्बी अवधि के लिये उधार देना ।

(७) प्राप्त पूँजी (paid-up capital) का अपर्याप्त होना और उसका बहुत बड़ा भाग अवल-सम्यत्ति में लगा देना ।

(८) रक्षित फ़ंड (reserves) का कम होना ।

(९) नक़दी के साधन कम होना । अस्तु,

इन त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए ही आगे उपाय बताये गये हैं ।

उपयुक्त-संगठन

लाइसेन्स की आवश्यकता—भारत में शिक्षा का गहरा अभाव है । केवल १५ प्रतिशत आबाल-वृद्ध ऐसे हैं, जो लिख-पढ़ सकते हैं । इन पढ़े-लिखे लोगों में बहुत कम संख्या ऐसे लोगों की है, जो वर्तमान आधुनिक बैंकिंग प्रणाली से परिचित हैं । दुनिया में धोखा देनेवाले लोगों को कमी नहीं है । आजकल धोखेबाजी का कला की तरह प्रयोग होता है । मौजूदा क़ानून के

अनुसार कोई भी सात आदमी मिलकर एक बैंक खोल सकते हैं और रजिस्ट्रार उसकी रजिस्ट्री कर सकता है। इस सरलता का येईमान लोग अनुचित लाभ उठाने में सफल हो जाते हैं। कितनी ही घटनायें ऐसी हुई हैं कि कुछ लोग बैंकिंग-संस्था खोलकर बैठ गये और थोड़े ही दिनों में जनता का रुपया खींचकर दिवाला निकाल दिया; इसलिये इस बात की परम आवश्यकता है कि किसी भी प्रार्थी बैंकिंग-संस्था की रजिस्ट्री होने से पहले उसकी आर्थिक-अवस्था, उसके डाइरेक्टरों की योग्यता, क्षमता, मोताबेरी और निरीक्षकों की प्रतिष्ठा, आदि बातों की जांच की जावे। ऐसी जांच का परिणाम सतोष-जनक निकलने ही पर रजिस्ट्री कराने की आज्ञा दी जावे। श्री० ठाकुर* और टेननां का भी यही मत है। सेण्ट्रल-बैंकिंग-इक्वाइटी कमेटी† (बहुमत) ने भी लाइसेन्स-प्रथा खालू करने की सिफारिश की है; लेकिन श्री० मनुसूवेदार‡ ने अपनी अल्प मत रिपोर्ट में भारतीय बैंकों के लिये लाइसेन्स-प्रथा के विरुद्ध सम्मति दी है। भारत जैसे देश में उपरोक्त कारणों को देखते हुए लाइसेन्स-प्रथा किसी अंश में भी हानिप्रद नहीं है। इससे भले और सत्पात्र लोगों के मार्ग में कोई बाधा उपस्थित नहीं होगी और साथ ही धोखेबाज़ और

* Organization of Indian Banking, P 214

† Regulation of Banks in India, P 8, 9

‡ Majority Report, Para 634.

Minority Report, Para 315

चालाक लोगों से भोलीमाली प्रजा की बहुत-कुछ अंश में रक्षा होगी।

जिस प्रकार लाइसेन्स की आवश्यकता नये खुलनेवाले बैंक के लिये है, उसी प्रकार हेड आफ़िस के स्थान के अतिरिक्त दूसरे स्थानों में ब्राञ्च खोलने के लिये भी लाइसेन्स लेना अनिवार्य होना चाहिये।

‘बैंक’ शब्द का प्रयोग—यह कई बार आ चुका है कि भारत में शिक्का का अभाव है। यहाँ के अधिकांश लोग बैंक क़ानून से अपरिचित हैं और बैलेन्स शीट इत्यादि समझने का ज्ञान नहीं रखते। जिस दुकान या कम्पनी के नाम के साथ ‘बैंक’, ‘बैंकिंग’ या ‘बैंकर’ शब्द देख लेते हैं, उसी पर विश्वास करने लग जाते हैं और अपना रुपया जमा कर देते हैं, लेकिन बाद में उसका दिवाला निकलने पर पछताते हैं; इसलिये क़ानून के अनुसार लाइसेन्स-प्राप्त करके रजिस्ट्री कराये बिना किसी दुकान या कम्पनी को अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या तद्वरूप शब्द का प्रयोग करने की मनाही होनी चाहिये। जापान में ठीक-पेसा ही नियम है। “वहाँ कोई ‘बैंक’ शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, सिवाय इसके कि वह ज्वाइण्ट स्टॉक कम्पनी हो और उसकी बैंक-क़ानून के अनुसार रजिस्ट्री हो रही हो”।

सेण्ट्रल बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटी ने अ-रजिस्टर्ड कम्पनियों

और व्यक्तिगत फ़र्मों को 'बैंक' शब्द का प्रयोग करने के लिये स्वतन्त्र छोड़ देने की सिफ़ारिश की है। श्री० ट्रेनर ने व्यक्तिगत रूप से देशी बैंकों के व्यापार के लिये राज-नियम होने के पक्ष में होते हुए भी फ़िलहाल उन्हें उक्त नियम से बाहर रखने की सलाह दी है।* हमें खेद है कि हम बहुत कुछ सोच-विचार और प्रयत्न करने पर भी इस विषय में उक्त प्रामाणिक महानुभावों की सम्मति से सहमत होने में असमर्थ रहे। नवीन बैंक-क़ानून बन जाने पर लोगों का यह विश्वास और भी बढ़ जायगा कि बैंकों की राज पूरी देख-रेख करता है और फल-स्वरूप वे प्रत्येक 'बैंक' शब्द का प्रयोग करनेवाली सस्था या दूकान को राज्य की देख-रेख में समझकर धोखा खावेंगे और इस प्रकार लाइसेन्स प्रथा का उद्देश्य पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकेगा; बल्कि निरर्थक सिद्ध होगी। 'बैंक' या 'बैंकर' शब्द की मनाही होने से देशी बैंकर्स को कोई हानि नहीं हो सकती, क्योंकि ये भारत के प्राचीन शब्द नहीं हैं। भारत में इनका प्रयोग अंगरेजों द्वारा बैंकिङ्ग व्यवसाय प्रारम्भ होने के साथ साथ हुआ है। देशी बैंकर्स की प्रतिष्ठा तो 'सेठ', 'साहूकार', 'बोहरा' इत्यादि शब्दों के विशेषण से ज्ञात हो जाती है, जिनका वे प्रयोग करते हैं और करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त 'अन्य प्रयत्न' शीर्षक अध्याय में 'सर्व भारतीय बैंकर्स एसोसियेशन' के संगठन की

योजना बतलाई है। उसके मेम्बर, भारत के सभी प्रान्तों के प्रतिष्ठित देशी बैंकर भी हो सकेंगे और वे 'बैंकर्स-एसोसियेशन के मेम्बर' शब्द का प्रयोग करने में स्वतन्त्र होंगे। इससे उनकी प्रतिष्ठा सुरक्षित रहेगी।

इस नियम से केवल बाजार में अनजान और साधारण व्यक्ति नवीन आइडम्बर के साथ दुकान घोलकर बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकेंगे और ऐसा होना सर्वसाधारण के हित के लिये अच्छा भी है; अतएव यह नियम रजिस्टर्ड और वैयक्तिक फ़र्मों पर समान रूप से लागू होना चाहिये।

दूसरे धन्धे की रोक—दूसरी औद्योगिक-कम्पनियों की अपेक्षा बैंकों में कम सूद होते हुए भी लोग 'जमा' रखते हैं; क्योंकि इनमें रखा हुआ रुपया अधिक सुरक्षित समझा जाता है। यदि बैंक भी बैंडिंग धन्धे के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के धन्धे करेंगे या करते रहेंगे तो औद्योगिक तथा व्यावसायिक कम्पनियों से इनका विशेषत्व जाता रहेगा। तीसरे अध्याय में ऐसे कई बैंकों के उदाहरण मौजूद हैं, जिनके दिवाले निकलने का कारण बैंकिंग धन्धे के साथ साथ व्यापार करना था। ताजा उदाहरण 'पलाइन्स बैंक ऑफ़ शिमला' का है, जो एक व्यापारिक फ़र्म से सम्बन्ध रखने के कारण डूबा है*; इसलिये बैंकों को

* सेण्ट्रल बैंडिंग इन्क्वायरी कमेटी की बहुमत रिपोर्ट, पैरा ६५२।

वैकिंग-घन्धे के सिवाय दूसरा घन्धा करने की कानून-द्वारा सर्वथा मनाही होनी चाहिये ।

मैनेजिंग-एजेन्सी-प्रथा सत्सार के किसी देश में नहीं है । इसका सूत्रपात भारत ही में हुआ है । पहले पहल इस देश में जो उद्योग घन्धे खुले, वे ब्रिटिश पूँजी और उन कम्पनियों के प्रयत्न से, जिनको रजिस्ट्री इङ्ग्लैण्ड में हुई, ऐसी अवस्था में सात समुद्र पार इङ्ग्लैण्ड के रहनेवाले हिस्सेदार और उनके डाइरेक्टर्स के लिये भारत स्थित कारखानों का संचालन करना वहाँ की उस समय की प्रचलित प्रणाली से कठिन था, इसलिये उन्होंने अपने सुमीने के लिये भारतीय कारखानों का संचालन करने के हेतु यहाँ की कुछ प्रतिष्ठित ब्रिटिश फर्मों को अपना मैनेजिंग एजेण्ट बनाना शुरू कर दिया । इन कार्य संचालक एजेण्टों ही को 'मैनेजिंग एजेण्ट' कहते हैं ।

भारतीय कम्पनियों के सामने उक्त समस्या उपस्थित नहीं था । इनमें यहाँ की पूँजी और यहाँ के डाइरेक्टर थे । इनका संचालन बोर्ड श्राव् डाइरेक्टर्स, एक होशियार मैनेजर के द्वारा भली प्रकार से कर सकते थे, लेकिन यह देखकर कि मैनेजिंग एजेन्सी कामधेनु का काम करती है, हमारे व्यवसायी इस प्रणाली का यहाँ भी चलाने का प्रयत्न करते गये और अब इस का इतना विस्तार हो गया कि कोई कम्पनी ऐसी नहीं हाती, जिसमें मैनेजिंग एजेण्ट न हो । यहाँ कम्पनियाँ मैनेजिंग एजेण्ट तलाश नहीं करतीं, बल्कि मैनेजिंग एजेण्ट बनने की इच्छा रखने

वाले ही कम्पनी को जन्म देते हैं। मैनेजिंग एजेण्टों को कम्पनी का कर्ता-धर्ता समझना चाहिये। वार्ड आर्बु डाइरेक्टर्स की मीटिंग केवल उसकी बातों पर मोहर लगाने के लिये होती है।

सम्भव है यह प्रथा अन्य कामों में चाहे उपयोगी हो, किन्तु बैंकिङ्ग धन्धे के लिये यह हानिप्रद सिद्ध हुई है। आज-कल उद्योग-धन्धों के सम्यन्त्र में भी इसकी खरी और आशेष-पूर्ण आलोचना होने लगी है। बैंकिङ्ग व्यवसाय क्षेत्र में तो इस प्रथा के विरुद्ध एक स्वर से आवाज आती है। इसमें सन्देह नहीं कि मैनेजिङ्ग एजेण्ट एक संस्था के आरम्भ करने में अग्रगण्य होते हैं; परन्तु ये इतने स्वार्थी होते हैं कि संस्था का धन्धा चल जाने पर, अपने परिश्रम का उचित पारिश्रमिक लेकर भी पद नहीं छोड़ते; बल्कि स्थायी रूप से अपना अधिकार और प्रभुत्व बनाये रखते हैं। यह इनके लिये बड़ा आसाम होता है; क्योंकि कम्पनी की नियमावली और सिद्धान्त-पत्र इत्यादि ये अपनी मर्जी के वकीलों से इच्छानुसार बनवा लेते हैं, जो हिस्सेदारों के सामने स्वीकृति के लिये उपस्थित नहीं किये जाते। बाद में उनमें परिवर्तन होना असम्भव हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ये लोग हमेशा के लिये पुश्त दर पुश्त उस संस्था के सर्वेसर्वा बन जाते हैं और उसके धन का मनमाना उपयोग करते हैं। एक बैंक का मैनेजिङ्ग एजेण्ट दूसरी और भी कई औद्योगिक और व्यापारिक संस्थाओं का मैनेजिङ्ग एजेण्ट होता है और वह इस नाते से बैंक की पूँजी का बहुत

बड़ा भाग उन उद्योग-धन्यों को खुले दिल से उधार दे देता है। जब कभी किसी बैंक के मैनेजिङ्ग एजेण्ट से सम्बन्धित दूसरी कम्पनी की साख्त में कमजोरी आती है, तब उस बैंक पर जमा करनेवाले अपना रुपया वापस लेने के लिये दृढ़ पड़ते हैं। इसके फल-स्वरूप कई बैंक डूब चुके हैं; इसलिये क़ानून-बारा यह प्रथा रोकी जानी चाहिये।

आपत्ति-जनक नियमों की रोक—यह ऊपर बताया जा चुका है कि कम्पनी के संस्थापक कम्पनी के नियम, सिद्धान्त पत्र अपनी इच्छानुसार तैयार करा लेते हैं। इन नियमों में वे ऐसे अधिकार ले लेते हैं, जो हिस्सेदारों के हितों के विपरीत होते हैं। इस अमल को रोकने की अत्यन्त आवश्यकता है। नमूने के तौर पर कुछ नियम परिणाम-सहित दिये जाते हैं:—

(१) एक हिस्सेदार को, जिस पर कम्पनी का किसी रूप में और किसी अवस्था में कुछ भी ऋण हो, मत देने और सदस्यता के किसी भी अधिकार का उपयोग करने से रोकना, विशेष आपत्ति-जनक है। यह रुकावट आवश्यकता से आगे बढ़ी हुई है। केवल बढ़ी हुई किस्तों के वाजिब होने पर न देने की अवस्था तक इसे सीमाबद्ध कर देना उचित है। बैंक के दिये हुए ऋणों के विरुद्ध अपने हिस्सों पर यह अधिकार (Lien) बरतना बाज़ार में अनजान हिस्से ख़रीदनेवालों के लिये बड़ा हानिकार होता है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि भारत और इंग्लैण्ड दोनों जगह स्टॉक एक्सचेंज का व्यापार

करनेवाले साहूकारों ने ऐसे बैंकों के हिस्सों की लिया-येची से हाथ खींच लिया है।

(२) बिना कारण बताये हुए हिस्से मुन्तक़िल करने से इंकार कर देने का सर्वथा अधिकार डाइरेक्टरों को रहता है। क़ानूनी फ़ैसलों ने भी इसको उचित मान लिया है, इसलिये डाइरेक्टरों की इस मनमानी के विरुद्ध अदालत में तब तक दावा नहीं किया जा सकता, जब तक मनोधिकार और कपट साबित न किया जा सके और ऐसा तहरीर में कारण बताये बिना साबित होना कठिन है। इम्पीरियल बैंक ऑफ़ इण्डिया का बोर्ड पूरा मूल्य चुकाये हुए हिस्सों को मुन्तक़िल करने से इंकार नहीं कर सकता, फिर कोई कारण समझ में नहीं आता कि कम्पनी-क़ानून के अनुसार स्थापित बैंक ऐसा मनमाना अधिकार क्यों बरत सकते हैं। यदि कभी किसी मामले में उचित कारणों से इंकार करने की आवश्यकता हो तो डाइरेक्टर्स इंकार कर सकते हैं, किन्तु ऐसे इंकार के कारण उन्हें तहरीर में लाने चाहिये, ताकि ख़रीददार को अपने अधिकारों पर भगडने का मौक़ा मिल सके। ऐसे अनेक उदाहरण भोज़ूद हैं कि जब कभी हिस्सेदारों ने न्यायोचित अधिकारों के अनुसार बहुत वाजिब तरीक़े से जनरल मीटिंग में डाइरेक्टरों के कार्य की करारी आलोचना की तो, उनको बाद में न केवल उस कम्पनी के हिस्से देना रोक दिया, बल्कि दूसरी कम्पनियों के हिस्से भी, जिनमें डाइरेक्टर वही लोग थे, जो आलोचित कम्पनी के डाइरेक्टर

थे, नहीं दिये गये। यह कितना अनुचित है। इंग्लैण्ड में लोयड्स मिडलैण्ड, वार्कले आदि बैंकों की नियमावली में केवल आशिक चुके हुए हिस्सों के लिये ऐसा नियम है। पूरे चुके हुए हिस्सों के लिये ऐसी रक़ावट नहीं है। ऐसे ही नियम यहाँ के बैंकों की नियमावली में होने चाहिये।

(३) नियमावली में बोर्ड ऑफ़ डाइरेक्टर्स के लिये बे मांगी हिस्सा पूँजी (Uncalled Capital) रहन रखने का अधिकार भी ले लिया जाता है, जो औचित्य की सीमा से परे है। अमानतें जमा करनेवाले व्यक्तियों को यह पूँजी उनकी अमानतें सुरक्षित रहने का विश्वास दिलाती है। इसको रहन करने का अर्थ दुनिया को धोखा देना है, इसलिये कानून द्वारा बिना मांगे हुए मूलधन को रहन रखने की मनाही अवश्य होनी चाहिये।

मूलधन—इसकी सख्या लोगों की अमानतें खींचने में बड़ी सहायक होती है, इसलिये प्रायः बैंक मूलधन की एक बड़ी सख्या नियत कर लेते हैं और बेचने के लिये उसका कम भाग रखते हैं। इसमें भी प्राप्त मूलधन की सख्या बहुत कम होती है, यहाँ तक कि कई बैंकों में प्राप्त मूलधन नहीं होता और वे कार्य प्रारम्भ करने लग जाते हैं। सन् १९३० में फेल होनेवाले बैंकों की सख्या १२ थी। उनमें ६ का ब्योरा इस प्रकार है* :—

* The Statistical tables relating to banks in India for 1930 P 35

निराधार बैंक

संख्या	नाम	मूलधन (रुपये में)			तारीख रजिस्ट्री	तारीख दिवाला
		निर्धारित	विका हुआ	प्राप्त		
१	पब्लिक प्रॉपर्टी डेवलप कॉ (पंजाब)	१,००,०००)	+	+	७३९	३०३०
२	कलकत्ता बैंक (बंगाल)	१०,०००)	+	+	८३७	१११०
३	बिहार नेशनल बैंक (बिहार)	२,००,०००)	१७२०	१२३७	८३३	११६०
४	रमा नाटकारा बैंक (मद्रास)	१०,०००)	२७७१	२१००	८३३	१०४०
५	पुर्णिया कमर्शियल बैंक (बिहार)	२०,०००)	१०१०	३४०	१५३	१७४०
६	देहली सिस्टीकेट	२०,०००)	१२१०	१११०	८२३	१०४०

पृष्ठ नं० १६५ के कोष्ठक से प्रगट है कि पहले दो बैंकों के तो हिस्से बिलकुल ही नहीं बिके, शेष चार के हिस्से बराय नाम बिके हैं। उनमें भी ३ बैंक तो बिके हुए हिस्सों की पूरी पूँजी भी बसूल नहीं कर सके और काल-कवलित हो गये। अब अनुमान लगाया जा सकता है कि इनमें जमाशुदा श्रमांतकों का, दिवाला निकलने पर क्या परिणाम निकला होगा। ऐसे छोटे निराधार बैंकों के खुलने से, जो अधिक दिन तक जीवित नहीं रह सकते, इस व्यवसाय को भारी धक्का पहुँचता है; अतः धार्यावस्था में काल-कवलित होनेवाले बैंकों की उत्पत्ति रोकने के लिये नवीन क़ानून में इस बात की परम आवश्यकता है कि निर्धारित, बिके हुए और प्राप्त मूलधन की अलग अलग संख्या निश्चित कर दी जाय और तदनुसार धन संग्रह हो जाने पर धम्या करने का प्रमाण-पत्र दिया जावे। इस सम्बन्ध में विदेशों में इस प्रकार नियम हैं :—

अमरीका में १९२३ में संशोधित नेशनल बैंक क़ानून के अनुसार बैंकों का मूलधन इस प्रकार होना चाहिये :—

शहर की जनसंख्या

कम से कम मूलधन

निम्नलिखित हो या कम

३,०००	२५,००० डालर
६,०००	५०,००० „
५०,०००	१,००,००० „
५०,००० से अधिक	२,००,००० „

इसके साथ वहाँ पर बैंक तब तक धन्या प्रारम्भ नहीं कर सकता, जब तक आधी पूँजी वसूल न हो जावे ।*

जापान में १० लाख येन से कम मूलधन का कोई बैंक स्थापित नहीं किया जा सकता । केवल छोटे क़स्बों में, जिनकी जनसंख्या १० हजार से कम है, ५ लाख येन के मूलधन से बैंक खोला जा सकता है । बड़े बड़े शहरों में खुलनेवाले बैंकों का मूलधन अर्थ-सचिव के आदेशानुसार रखना पड़ता है, जो किसी भी हालत में २० लाख येन से कम नहीं होता ।

कनाडा में मूलधन की कम से कम संख्या ५ लाख डालर निश्चित है । इसके आधे का, धन्या प्रारम्भ करने से पहले वसूल होना अनिवार्य है ।

भारत के लिये भी अमरीका और जापान के समान, जन-संख्या के अनुपात से मूलधन रखने की लोगों ने सलाह दी है । श्री टेन्म ने इस प्रकार श्रेणीकरण किया है† :—

बैंकों की श्रेणियाँ कम से कम बिका हुआ मूलधन
रुपयों में

१—स्थानीय-बैंक :—

उन शहरों में, जिनकी आबादी

५,००० से अधिक न हो ३०,०००)

१०,००० " " " ६०,०००)

* Regulation of Banks in India by Tannan P. 7, 8

† Regulation of Banks in India P 6

२०,००० " " "	१,००,०००)
५०,००० " " "	२,५०,०००)

१ लाख से ऊपर डाइरेक्टर

जनरल के आदेशानुसार; निम्न

कम से कम	१०,००,०००)
२—ग्रान्तीय-बैंक	५,००,०००)
३—सर्व-भारतीय बैंक	१०,००,०००)
४—चार्ज-भौमिक बैंक	३०,००,०००)

श्री० बी० टी० ठाकुर ने भी लगभग इसी प्रकार धोषीकरण किया है, केवल संख्या में थोड़ा सा अन्तर है। * इसमें सन्देह नहीं कि बैंकों की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिये और हैसियत से अधिक पाँच पसारने से रोकने के लिये उक्त महानुमाओं की सम्मतियाँ महत्त्वपूर्ण हैं; परन्तु भारत में अभी तक ज्वार्ट स्टॉफ बैंकिंग प्रणाली शिशु अवस्था में है; इसलिये उक्त प्रकार का धोषीकरण अधिक प्रतिबन्धों का द्योतक है और इससे बैंकों की वृद्धि में भारी रुकावट होने की सम्भावना है। मान लीजिये बीकानेर-निवासियों ने एक बैंक बीकानेर में खोला। इसका विरा हुआ मूलधन १० लाख से कम है। इस बैंक को बीकानेर की सरकार ने अपने राज्य निवासी व्यापारियों को राज्य के भीतर और बाहर आर्थिक सहायता देने के लिये

विशेष सहायता और सुविधा दे रखी है, अधिक संख्यक बीकानेरी कलकत्ते में व्यापार करते हैं; इसलिये वे अपने बैंक की शाखा कलकत्ते में ख़ुलवाना चाहते हैं; क्योंकि उस बैंक पर उनका भी गहरा विश्वास है और बैंक भी उनके राज्य का होने से उनकी आर्थिक स्थिति से भली प्रकार अलग है; अतएव कलकत्ता-प्रवासी बीकानेरियों को अपने यहाँ के बैंक से सहायता प्राप्त करने में बड़ी आसानी हो सकती है, लेकिन उक्त प्रस्तावित श्रेणीकरण से ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी हालत में बीकानेरियों को यह एक प्रकार की बाधा अनुभव होगी। इस प्रकार की बाधाएँ इस समय, जब कि भारतीय बैंकिंग को उत्तेजना देना है, अधिकांश में हितकर प्रमाणित नहीं हो सकते। अस्तु, कनाडा के समान सेण्ट्रल बैंकिंग इन्वार्डरी-कमेटी की सिफ़ारिश उपयुक्त है। उसके अनुसार एक बैंक के लिये धन्धा प्रारम्भ करने से पहले ५०,०००) का प्राप्त मूलधन होना चाहिये। निर्धारित मूलधन बिके हुए के दूने से अधिक और प्राप्त मूलधन बिके हुए के आधे से कम नहीं होना चाहिये।* रही हैसियत से अधिक क़दम बढ़ाने से रोकने के लिये नियमों की आवश्यकता, उसकी भी पूर्ति लाइसेन्स प्रणाली से हो जाती है; क्योंकि ब्राञ्च के लिये भी लाइसेन्स लेना आवश्यक रखा गया है। चूँकि लाइसेन्स देनेवाला अधिकारी प्रार्थी पैदा

की आर्थिक अवस्था, ब्रांच के स्थान की उपयुक्तता और आवश्यकता आदि पर विचार करके ब्रांच खोलने के लिये लाइसेन्स देगा, इसलिये कोई निर्वल बैंक अधिक ब्रांचें नहीं खोल सकेगा ।

भारतीयकरण—पिछले पृष्ठों में भारत के प्रति विदेशियों की मनोवृत्ति क्या है, बताई जा चुकी है और विदेशी पूँजी से विदेशों में रजिस्टर्ड होनेवाले बैंकों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने के प्रस्ताव भी लिख चुके हैं । यह सब व्यर्थ होगा, यदि भारत में रजिस्टर्ड होनेवाले बैंकों में विदेशियों के प्रवेश को न रोका गया, अतएव भारत के हितों की रक्षार्थ, भारतीय बैंकिंग को समुन्नत करने के लिये यह परम आवश्यक है कि भारतवर्ष में रजिस्टर्ड होनेवाले बैंकों पर निम्नलिखित प्रतिबन्ध लगाये जायें :—

- (१) कुल पूँजी के ३ हिस्से भारतीयों को देवे जायें ।
- (२) डाइरेक्टरों की संख्या में ३ भारतीय हों ।
- (३) समस्त कर्मचारी भारतीय हों ।

उत्तम प्रबन्ध

व्यवस्थापक-मंडल—बैंक का कार्य संचालन करने के हेतु एक व्यवस्थापक-मंडल (Board of Directors) बनाया जाता है । इसमें प्रतिष्ठित और अनुभवो आदमी होते हैं, जिनको पहले बैंक के संस्थापक चुन लेते हैं, बाद में हिस्सेदारों को इसमें परिवर्तन करने का अधिकार होता है, लेकिन प्रायः वही लोग

चुन लिये जाते हैं। इस व्यवस्थापक-मंडल की नामावली में प्रतिष्ठित और अनुभवहीन सज्जनों के नाम देखकर सर्वसाधारण उस संस्था के सुप्रबन्ध साख़ और सफलता का अनुमान लगाते हैं; इसलिये व्यवस्थापकों का कर्तव्य है कि उस संस्था (बैंक) के लेन-देन पर पूर्ण निगरानी रखें, उधार दी हुई रक़मों और ज़मानत में आनेवाली घस्तुओं के सम्बन्ध में पूरी सावधानी और उनके मूल्य में कमीयेशी होने का पूरा ध्यान रखें, बैंक की उत्तरोत्तर उन्नति हो, ऐसे उपाय सोचते रहें, उनको कार्य रूप में परिणत करने रहें और आर्थिक अवस्था की ओर सदैव सचेत रहें। यह सब तभी हो सकता है, जब मंडल की होनेवाली सब बैठकों में सब व्यवस्थापक उपस्थित हों; किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता। एक एक सज्जन पचास-पचास, साठ-साठ कम्पनियों के डाइरेक्टर होते हैं, इसके अतिरिक्त अपने निज के विस्तृत धन्धे भी करते हैं। यह निश्चित है कि एक शरीर से जितना काम हो सकता है, उतना ही वह करेगा, उससे अधिक की आशा करना भूल है। यही कारण है कि हमारे डाइरेक्टरों को अधिक काम होने और समय कम होने के कारण बैंकों के काम में यथोचित भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। फलस्वरूप बैंक उनके अनुभव और शक्ति से कोई लाभ नहीं उठाने पाते। साथ ही जैसा चाहिये, वैसा नियन्त्रण भी नहीं होने पाता। इसका परिणाम यह हो रहा है कि सारा काम मैनेजिंग-पेजेण्ट या कर्मचारी गण अपनी इच्छानुसार चलाते हैं।

युनाइटेड किंगडम में भी, जहाँ ज्वाइंट-स्टॉक-प्रणाली विस्तृत और उन्नततायस्था में है, अत्यधिक व्यवस्थापकता (Multiple Directorship) को बहुत ही अनुचित समझा जाता है और इसके विरोध में वहाँ गहरा बावेल मचा हुआ है।* भारत में भी क़ानून-द्वारा इस त्रुटि को दूर करने की अत्यन्त आवश्यकता है। अतएव इस सम्बन्ध में यह क़ानूनी नियम होना चाहिये कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक केवल दस कम्पनियों ही का व्यवस्थापक बन सकता है और उनमें भी बैंकिंग कम्पनियों में दो से अधिक का नहीं। इससे दो लाभ होंगे—एक तो अब तक व्यवस्थापक के पद पर केवल कुछ सीमित व्यक्तियों का ही अधिकार है, वह बढ़ जायगा और आधुनिक शिक्षित नव-युवकों को योग्य व्यवस्थापक बनने का अवसर प्राप्त होगा। दूसरे मौजूदा प्रतियोगिता के ज़माने में, एक कम्पनी के आन्तरिक भेद दूसरी कम्पनी को, जिसके साथ प्रतियोगिता है, दोनों में एक ही व्यवस्थापक होने से मालूम हो जाते हैं, न होंगे और कई कम्पनियाँ हानि उठाने से बचेंगी।

जमा करनेवालों का प्रतिनिधित्व—यह मानी हुई बात है कि प्रत्येक बैंकिंग संस्था में मूलधन से कई गुनी अमानतें जमा रहती हैं, जिनकी बदौलत बैंक को भारी लाभ होता है और हिस्सेदारों को अधिक से अधिक मुनाफ़ा मिलता है। हिस्सेदारों का बैंकों के प्रबन्ध में पूरा अधिकार है। इनके चुने हुए डाइरेक्टर

* Bombay Chronicle, 14th March, 1931.

लोग बैंक का सारा प्रबन्ध करते और अमानतदारों की अमानतों का अपनी इच्छानुसार उपभोग करते हैं। इनकी भूल, लापरवाही और बेईमानी का शिकार हिस्सेदारों के साथ साथ अमानतदारों को भी बनना पड़ता है और अमानतदार, अपना कोई प्रतिनिधि बोर्ड में न होने के कारण, चूँ तक नहीं कर सकते। सारांश यह है कि अमानतदारों को अपनी पूँजी जमा करने के एवज में केवल व्याज मिलता है और बैंक के प्रबन्ध में उनका कोई हस्त-क्षेप नहीं होता। यह अन्याय है। इसको दूर करने के लिये इस बात की आवश्यकता है कि व्यवस्थापक-मण्डल में अमानतदारों के भी कुछ चुने हुए प्रतिनिधि हों, जिनकी सख्या समस्त बोर्ड के मेम्बरों में $\frac{1}{3}$ और कम से कम २ नियत होनी चाहिये। इन डाइरेक्टर्स की भी वही योग्यता हो, जो हिस्सेदारों के डाइरेक्टर्स की होती है, केवल हिस्सों की रकम के स्थान पर रकम जमा की सख्या नियत कर दी जाये और इनका चुनाव जमा करनेवाले व्यक्तियों द्वारा हो; लेकिन ऐसी जमाओं पर उधार लेनेवालों में से नहीं होना चाहिये, यह अधिक कठिन नहीं है। करेंट एकाउण्ट के खातेदार लगभग स्थायी रूप से रहते हैं। मियादी अमानतों में अलबत्ता एक वर्ष या किसी निश्चित समय के लिये रकम जमा होती है; किन्तु फिर भी उनका बहुत बड़ा भाग लगातार पुनः पुनः जमा (renew) होता जाता है। यह नवीन बात भी नहीं है। पोपल्स बैंक आफ़ नोदर्न इण्डिया, के फ़ेल होने पर इसके पुनः चालू करने की स्कीम, जो ता० २२ दिसम्बर, सन् १९३१ ई० को हाईकोर्ट से

स्वीकृत हुई है, मैं अमानत जमा करनेवालों को बोर्ड में ३ डाइरेक्टर चुनने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार ५०) से अधिक जमा करनेवाले को डाइरेक्टरों के चुनाव में मत देने का अधिकार है और १५ हजार या इससे ऊपर रकम का अमानतदार डाइरेक्टर बनने का अधिकारी है। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनियों में भी पोलिसी-होल्डरों द्वारा डाइरेक्टरों का चुनाव होता है; अतः यह प्रणाली किसी न किसी रूप में इस समय प्रचलित है और कुछ संशोधन के साथ बड़ी आसानी से चालू की जा सकती है। यह बड़ी लाभदायक साबित होगी और इससे बैंकों पर विपत्ति के अवसर कम उपस्थित होंगे।

प्रोक्सी (प्रतिनिधि)—वर्तमान कम्पनी-कानून के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार, कम्पनी के प्रबंध में भाग लेने के लिये उसकी जनरल मीटिंग में एक हिस्से पीछे एक मत देने का अधिकारी है। मत स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि-द्वारा दिया जा सकता है। इस प्रतिनिधि-प्रथा का आजकल बड़ा दुरुपयोग होने लगा है। जहाँ जनरल मीटिंग होने का समय आता है कि बैंक या कम्पनी के क्लर्क नगर में घूम घूमकर हिस्सेदारों से तत्सम्बन्धी संस्था के कर्मचारियों, डाइरेक्टरों और उनके पृष्ठ-पोषकों के नाम के प्रतिनिधि-पत्र संग्रह करते फिरते हैं। अधिकांश हिस्सेदार कम्पनी की कार्य-प्रणाली से अनभिज्ञ होने के कारण बिना इस सोच-विचार के कि इस मत का क्या उपयोग

होगा, कम्पनी या बैंक के कर्मचारियों या डाइरेक्टरों को प्रसन्न करने के लिये उनके नाम का प्रतिनिधि-पत्र लिख देते हैं। इसका परिणाम ठीक वैसा ही हानिकारक होता है, जैसा कि अपने पास का शस्त्र, शत्रु को सौंप देने पर निकलता है। यह बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, बल्कि कम्पनी के प्रबन्धक अपने क्लर्कों और असिस्टेंटों से, जो अधिकांश में दगावटी या स्वार्थी प्रबन्धकों के नियोजित (nominee) हिस्सेदार होते हैं, जनरल मीटिंग को भर देते हैं। ये लोग प्रबन्धकों के अनुकूल प्रस्तावों पर अपने अपने हाथ उठाकर प्रबन्धकों का अभिप्राय पूरा करने में सहायक होते हैं। इतना ही नहीं, ये लोग बीच में बाधा डालकर दूसरे हिस्सेदारों को भी स्वतन्त्र सम्मति देने से रोकने हैं, अतएव प्रतिनिधि-प्रणाली की आड़ में कम्पनी के प्रबन्धकों को अपनी मनमानी कार्यवाही करने का पूरा अवसर मिल जाता है। इससे हिस्सेदारों को कभी कभी गहरी क्षति उठानी पड़ती है। यह घुराई केवल भारत ही में नहीं है, दूसरे देशों में भी बेहद बढ़ी हुई है। वहाँ इसके रोकने के लिये उपाय भी किये गये हैं :—

इंग्लैण्ड में इस घुराई को कानून-द्वारा रोकने के लिये बड़ा आन्दोलन हो रहा है। वहाँ के एक प्रसिद्ध पत्र 'एकाउंटेण्ट' ने इस प्रथा की घुराई करते हुए लिखा है—“यह प्रणाली स्वयं दोष-पूर्ण है, क्योंकि प्रतिनिधि-पत्र देना, हस्ताक्षर-युक्त कोरा (Blank) चेक देने के समान है। ऐसा केवल दस्तूर पूरा करना समझकर किया जाता है; लेकिन अकस्मात् मीटिंग के सामने

ऐसे प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं कि यदि उस समय प्रतिनिधि भेजनेवाला अनुपस्थित हिस्सेदार वहाँ उपस्थित होता तो वह प्रतिनिधि के मत के विरुद्ध सम्मति देता..... । इस कुप्रथा को रोकने का एक मात्र उपाय है कि प्रबन्धक लोगों का प्रोत्सी प्राप्त करना कानून-द्वारा रोका जावे” ।*

कनाडा में जब इस प्रतिनिधि-प्रथा का अधिक दुरुपयोग किया जाने लगा तब वहाँ की सरकार ने वैद्व के घेतनभोगी कर्मचारी हिस्सेदारों के वास्ते यह नियम बना दिया—“वैद्व का कोई जनरल मैनेजर, मैनेजर, क्लर्क या दूसरे मातहत नौकर स्वयं उपस्थित होकर या प्रतिनिधि-द्वारा मत नहीं दे सकेगा और न मत देने के वास्ते प्रतिनिधि पत्र प्राप्त कर सकेगा ।” †

भारत में सेण्ट्रल-वैद्विज्ञ-इंकाइरी कमेटी के सामने उपस्थित होनेवाले गवाहों ने कनाड़े की भाँति नियम बनाने के लिये बड़ा जोर दिया था; किन्तु उक्त कमेटी ने वैद्व के कर्मचारी हिस्सेदारों का केवल प्रतिनिधि-पत्र प्राप्त करना रोकने के लिये सिफ़ारिश की है, लेकिन उनको हिस्सेदार के नाते से खुद की सम्मति देने से रोकना उचित नहीं समझा। हमारी समझ में केवल इतने ही से इस प्रथा की वर्तमान खुरादियाँ दूर नहीं हो सकती।

* Bombay Chronicle, 14th March, 1931.

† Bombay Chronicle, 18th March, 1931.

‡ Majority Report, Para 714

यह पर मैनेजिङ्ग एजेण्ट कम्पनी का सर्वाधिकारी होता है। बैंक के कर्मचारियों की नौकरी, वेतन वृद्धि आदि उसकी इच्छा पर निर्भर होती है। ऐसी अवस्था में ये लोग अपनी स्वतन्त्र सम्मति नहीं दे सकते, क्योंकि उनको हिस्सेदार की अपेक्षा अपने दूसरे स्वार्थों का अधिक ध्यान रखना पड़ता है, अतएव कनाडे की तरह यहाँ भी कर्मचारियों के लिये मत देने की सर्वथा मनाही होना ही उचित है।

वैयक्तिक मताधिकार—जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक हिस्से पीछे एक मत का अधिकार होता है। इस नियम से बैंक के ऊपर सारा अधिकार चढ़ हिस्सेदारों का हो जाता है। अधिकांश में बड़ी बड़ी सख्यावाले हिस्सेदारों का बैंक के साथ हिस्सेदार होने के अलावा दूसरा स्वार्थ विशेष रूप से होता है, इसलिये वे सब काम अपने स्वार्थों को सामने रखकर करते हैं। चूँकि बहुमत इनका होता है, इसलिये कम सख्या में हिस्से खरीदनेवालों की कोई सुनाई नहीं होती और उनका हितों की सदैव उपेक्षा होती रहती है, हालाँकि कम्पनी की पूँजी के बड़े भाग के मालिक छोटे हिस्सेदार हो होते हैं, इसलिये एक हिस्सेदार को केवल एक मत देने का अधिकार होना चाहिये। चाहे हिस्से कितनी ही सख्या में ले रखे हों, यह नियम सहकारी बैंकों में है। वहाँ इससे अब तक कोई बाधा उपस्थित नहीं हुई। यदि इतना हो सके तो कम से कम एक व्यक्ति को पाँच से अधिक मत देने की मनाही अवश्य होनी चाहिये।

रोशन रखना, ऋण देना और रुपया लगाना—बैंक की साख, पावनेदारों को चुकाने के लिये पर्याप्त पूँजी रखने की अपेक्षा, अधिकतर अपने खातेदारों की माँग को पूरा करने पर निर्भर होती है। जो बैंक अपने खातेदारों की माँग को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको देने से अधिक पूँजी होते हुए भी अपने दरवाजे बन्द करने पड़ते हैं, इसलिये बैंकों को अपने पास उचित परिमाण में नकद रोशन रखनी चाहिये और पूँजी का बहुत बड़ा भाग इस ढंग से लगाना चाहिये कि आवश्यकता पड़ने पर खातेदारों की माँग को पूरा करने के लिये तुरन्त नकद में परिवर्तन किया जा सके। इसके लिये भी श्री ठाकुर ने कानूनी नियम बनाने के वास्ते प्रस्ताव करते हुए लिखा है* :—

रोशन—१ लाख और इससे कम जनसंख्या के नगरों में काम करनेवाले स्थानीय बैंकों को माँगते ही वापस देने योग्य जमा का १५ प्रतिशत और दूसरी प्रकार की जमाओं का ५ प्रतिशत, रोशन में नकद रखना चाहिये। दूसरे बैंकों को २० प्रतिशत माँगते ही वापस दी जानेवाली जमा का और ५ प्रतिशत दूसरी जमा का नकद, रोशन में रखना चाहिये।

इस रोशन को इस प्रकार वितरण करना चाहिये :—

(अ) कम से कम $\frac{1}{3}$ बैंक की तिजूरों में।

(ब) दूसरा $\frac{1}{2}$ सेण्ट्रल बैंक या स्थानीय क्लियरिंग बैंक या अपनी ही तिजुरी में, ज़िल प्रकार सुविधाजनक हो ।

(स) बाक़ी $\frac{1}{2}$ दूसरे बैंकों में ।

रुपया लगाना—उपरोक्त रॉशन के अलावा ३० प्रतिशत माँगते ही वापस दी जानेवाली जमा का और १० प्रतिशत दूसरी प्रकार की जमा का, तुरन्त भुननेवाली जमानतों पर लगाना चाहिये, ताकि बँडू आकस्मिक माँग को पूरा करने में समर्थ रहे ।

क़या देना—निर्जोखिम (safety) तुरन्त भुनने योग्य (Liquid) जोखिम वितरण (Distribution of Risk) इन तीन सिद्धान्तों को सामने रखते हुए लिखा है :—

(१) अचल सम्पत्ति पर, प्राप्त पूँजी और रक्षित-धन या दिये हुए कुल ऋण में जो कम हो, उसके २० प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जावे ।

(२) एक व्यक्ति या संस्था को प्राप्त पूँजी और रक्षित-धन के $\frac{1}{4}$ से अधिक नहीं दिया जावे ।

(३) सब प्रकार की कुल जमाओं के २० प्रतिशत से अधिक एक ही किस्म की जमानतों पर नहीं दिया जाय ।

श्री० टेनन ने भी उपरोक्त बातों का समर्थन करते हुए थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ ऐसे ही प्रस्ताव किये हैं ।* इस प्रकार के क़ानूनी नियम डेनमार्क, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी है ।

इसमें सन्देह नहीं कि बैंकों का वृद्धिमत्ता पूर्वक संचालन करने के चास्ते उक्त नियम बड़े उपयोगी हैं, इसलिये बैंकों के प्रबन्धकों को रुपया लगाते समय सदैव इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये, लेकिन इन्हें क़ानून का रूप देने की बात अधिक उपयुक्त नहीं जँचती है। सेएट्रल बैंकिंग इम्पवाइरी कमेटी ने भी इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से विचार किया है और वह भी इसी परिणाम पर पहुँची है। क़ानून को बक के दैनिक धन्धे के सम्बन्ध में निर्णय करने की कसौटी नहीं बनाया जा सकता। यदि ऐसा करने की कोशिश की गई तो उससे लाभ का अपेक्षा हानि की अधिक सम्भावना है; क्योंकि क़ानून यह निश्चय नहीं कर सकता कि जिस धन्धे में जोखिम है और कौन सा निजोखिम है। रोज़ाना आर्थिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, उसके अनुकूल क़ानून को तैयार नहीं रखा जा सकता। जिस धन्धे में आज जोखिम फैला की जाती है, वही कल निजोखिम हो सकता है; इसलिये इन सब बातों को व्यवस्थापक-मंडल पर ही छोड़ा जाना अधिक मुनासिब है। क़ानून में इस बात की रूकावट अवश्य होनी चाहिये कि बैंक के डाइरेक्टर, कर्मचारी और ऑडिटर उनके या उनसे सम्बन्धित धन्धों के लिये बैंक की पूँजी का मनमाना उपयोग न कर सकें।

डाइरेक्टरों, कर्मचारियों और ऑडिटरों को ऋण—अनेक अच्छे अच्छे बैंक, डाइरेक्टरों को अन्धाधुन्ध ऋण

देने के कारण, काल ख़वलि़त हुए ह। “बर्मा-बैंक के लिम्बी-डेटर्स की रिपोर्ट से प्रगट होता है कि बैंक की पूँजी का उपयोग उसके डाइरेक्टर मेसेर्स क ख के धन्यों के लिये होता था। मिस्टर फिएडले सिरास भूनपूर्व डाइरेक्टर आर्च स्टेटिस्टिक्स ने इण्डस्ट्रियल कमीशन को जो लिखित बयान दिया था, उसमें उसरो भारत के एक प्रमुख बैंक का उल्लेख करते हुए बतलाया था कि उसकी कुल उधार दो हुई पूँजो का ७० प्रतिशत से भी अधिक अर्थात् १,०७,०७,०००॥=) * में से ७१,७२,६३॥=) उन कम्पनियों और सस्थाओं को उधार दे रक्खा था, जिनसे खन्द डाइरेक्टरों का वैयक्तिक, सामे का या उनके भी डाइरेक्टर होने का सम्बन्ध था।” * अभी हाल १९३१ में दरवाजे बंद करनेवाले पीपल्स बैंक आर्च नार्दन इण्डिया की यही दशा थी। ता० ३१३३ को इसको अपने डाइरेक्टरों की तरफ ८२६५१७१॥=) अर्थात् मूलधन से दूना ओर जमाशुदा अमानतों का ३ भाग था।

डाक्टर चार्लर लीफ के शब्दों में “डाइरेक्टर न केवल हिस्सेदारों के, बल्कि अमानतदारों के भी ट्रस्टी हैं। ट्रस्टियों का इस तरह से अपने विश्वास बर्ताओं की सम्पत्ति का दुरुपयोग करना विश्वास-घातकता है।” डाइरेक्टर ही बैंक के सचालक होते हैं और जब ये ही उधार लेने लगें अर्थात् बाड हो खेत को खाने

* The Journal of the Indian Institute of Bankers, January, 1931, Page 89

लगे' तो उसे कौन रोक सकता है ? कोई भी नहीं । डाइरेक्टरों की इस स्वतन्त्रता से वैद्व हूबते हैं और अमागे अमानतदार, जिनमें अधिकांश गरीब होते हैं और जो समय कुसमय के वास्ते अपनी गाड़ी कमाई में से बचा बचाकर जमा करत हैं, दिन धोले लुट जाते हैं । खेद है कि उनकी रक्षा के लिये भारत में कोई कानून नहीं है ।

इंग्लैण्ड में "डाइरेक्टरों की इस प्रकार की चालाकी को मालूम करने के वास्ते कम्पनी-कानून सन् १९२६ में इस सम्बन्ध में कुछ नियम बने हुए हैं । उनके अनुसार प्रत्येक उवाइण्ड स्टॉक कम्पनी के लिये अपनी बैलेन्स-शीट में, तत्सम्बन्धी वर्ष के अन्दर समय समय पर जो ऋण डाइरेक्टरों और अफसरों को दिया गया हो, उसका ब्योरा और बैलेन्स शीट की तारीख को रही हुई बकाया, प्रगट करना अनिवार्य है ।" अर्थात् न केवल बैलेन्स शीट की तारीख को रही हुई बकाया ही बतलाई जाती है, बल्कि तत्सम्बन्धी वर्ष के अन्दर दिया हुआ कुल कर्जा बतमा पड़ता है । इससे डाइरेक्टरों को बैलेन्स शीट तैयार होनेवाली तारीख के दिन अपनी ओर की बकाया रकम जमा कराकर और दूसरे रोज फिर उधार लेकर वास्तविकता छिपाने का अवसर नहीं मिलता । डाइरेक्टरों के ऋण में वह ऋण भी शामिल किया जाता है, जो उन्होंने उन दूसरी सस्थाओं से लिया हुआ है, जिनकी कि बैलेन्स शीटवाली कम्पनी जामिन होती है । यह कानून, बैंकिंग कम्पनी हो अथवा दूसरे प्रकार

की, सब पर समान रूप से लागू है।* इन नियमों से हिस्सेदारों को अपने चुने हुए डाइरेक्टरों की करतूतें मालूम हो जाती हैं और दूसरे चुनाव के समय वे उन्हें निकाल बाहर करने में समर्थ हो जाते हैं।

कनाडा में "बैंक ऐक्ट में डाइरेक्टरों को ऋण देने की हद्दें नियत करने का अधिकार केवल हिस्सेदारों की जनरल मीटिंग को है और समस्त डाइरेक्टरों को दिये हुए ऋण की संख्या उस बैंक की प्राप्त पूँजी के $\frac{1}{4}$ से अधिक बढ़ाने की सख्त मनाही है।"†

भारत में मध्य प्रांतीय बैंकिंग इंक्यूआईरी कमेटी ने डाइरेक्टरों को ऋण देने की प्रथा को क़तई रोकने के वास्ते क़ानूनी नियम बनाये जाने को सिफ़ारिश की है। श्री० मनुसूयेदार ने भी अपनी अल्पमत रिपोर्ट में यही सम्मति दी है।‡ यम्बई शेयर-होल्डर-एसोसिएशन ने इस पर खूब जोर लगाया है। खेद है कि से० बैंकिंग इंक्यूआईरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में क़ानूनी रोक लगाने की आवश्यकता नहीं धतलाई। इस पर आलोचना

* Bombay chronicle, 20th March, 1931.

† The journal of the Indian Institute of Bankers, April 1931, Page 70.

‡ The Journal of the Indian Institute of Bankers, April 1931, Page 70.

करते हुए उक्त सस्था के तीसरे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष श्री० काजी जी ने अपने भाषण में कहा है :—

“इस घृणित प्रथा को रोकने के, सर्वविदित कारण कमेटी के सामने बहुत आग्रह के साथ उपस्थित किये गये थे, किंतु आश्चर्य है कि बहुमत ने इस प्रणाली को बिलकुल ही रोकने के पक्ष में सम्मति क्यों नहीं दी, हालाँकि ऐसे प्रमाण मौजूद हैं कि डाइरेक्टरों के लिये हुए ऋण ने अनेक बैंकों को डुबोया है। दुःख की बात है कि बहुमत ने कानून द्वारा इसको रोकने के लिये सिफारिश करना उचित नहीं समझा”।

श्री० काजी जी का कहना यथार्थ है। बैंकों की सुव्यवस्था की दृष्टि से डाइरेक्टरों का ऋण लेना अनुचित है और इसकी कतई रकामट के वास्ते कानूनी नियम होना आवश्यक है। यदि इतना न हो सके तो कमांडे के समान नियम अवश्य होना चाहिये, तभी यह अति को पहुँची हुई प्रथा काबू में आ सकेगी, अन्यथा नहीं।

अपने हिस्सों की जमानत पर ऋण—एक बैंक के वास्ते अपने ही हिस्सों की जमानत पर ऋण देना अज्ञानता है। दी हुई उधार की जमानत में आई हुई जमानतें ऐसी होनी चाहिये कि जिन्हें तुरन्त भुनाया जा सके, लेकिन आवश्यकता पडने पर निज के हिस्से बेच लेना न केवल बहुत कठिन, बल्कि कभी कभी असम्भव हो जाता है। “ग्रहले घनारस

बैंक* का दिवाला निज के हिस्सों की जमानत पर उधार देने के कारण ही निकला था। इम्पीरियल बैंक ने अपने हिस्सों की जमानत पर उधार देना आरम्भ ही से बन्द कर रखा है, हालांकि दूसरे बैंक उनको प्रथम श्रेणी की जमानतें समझते हैं। कनाडा में तो बैंकों के लिये न केवल निज के हिस्सों की जमानत पर, बल्कि दूसरे बैंकों के हिस्सों की जमानत पर भी उधार देना कानून द्वारा वर्जित है†, अतएव भारत में भी इसकी रूकावट होना अत्यन्त आवश्यक है और इसके लिये ऐसा कानूनी नियम होना चाहिये कि कोई बैंक न तो अपने निज के हिस्से खरीद सके न उनकी जमानत पर उधार दे सके, सिवाय इसके कि ऐसे हिस्से नेक नीयती के साथ दिये गये पूर्व ऋण की वसूली में लिये जायें। इस प्रकार आये हुए हिस्से भी छः महीने के अन्दर लाजिमी तौर पर बिक जाने चाहिये।

एजेन्सी—इस आधुनिक जगत् में बैंक, बैंकिंग धन्धे के अतिरिक्त अपने खातेदारों के वास्ते दूसरे कई काम करते हैं, उनमें एजेन्सी का धन्धा विशेष स्थान रखता है, जैसे—विनिमय-साध्य हिस्से, जमानतें तथा चाँदी सोने के पाट खरीदना और बेचना, किराया, बीमा की किस्में डिविडेण्ड (लाभ) चुकाना और प्राप्त करना, साख पत्रों का संग्रह करना और दूस्ती बनना

* Minority Report, Para 381

† Regulation of Banks in India by Tannan, P 15

इत्यादि। इंगलैण्ड, अमरीका और जर्मनी के व्याज कमानेवाले लोगों (investors) ने बैंकों द्वारा जमानतें खरीदने और बेचने के लाभ को अच्छी तरह समझ लिया है। इस प्रथा को उत्तरोत्तर बढ़ाने के उद्देश्य से वहाँ के बैंक आम तौर पर अपने खातेदारों से इस काम के लिये कोई अलग खर्चा वसूल नहीं करते हैं, सिर्फ दलालों से आधा हिस्सा बँटा लेते हैं। चूँकि दलालों को बैंकों द्वारा बहुत बड़ी सख्या में काम मिलता है, इसलिये बैंकों द्वारा बँटाये हुए हिस्से की वे परवाह भी नहीं करते। बैंकों के खातेदारों को अपने अपने बैंकों की मारफत जमानतें खरीदने, बेचने में सबसे बड़ी सुविधा यह होती है कि रुपया देने और लेने की भ्रंश से बच जाते हैं और कोई विशेष खर्चा नहीं लगता। इसके अतिरिक्त जब खातेदार उन खरीदशुदा जमानतों को बैंक में ही रक्षार्थ जमा कर देते हैं और उनको लाभ और व्याज वसूल करने का अधिकार दे देते हैं तब जमानतों के खोने, जलने इत्यादि के भय और व्याज या लाभ प्राप्त करने के लिये उपस्थित करने की तारीखों को याद रखने की चिन्ता से मुक्त हो जाते हैं। इसके साथ साथ जमानतों का भेजने और मँगाने में होनेवाले डाकखर्च की बचत भी होती है। इसी प्रकार दूसरे कामों में भी खातेदारों को बैंकों से आराम मिलता है। बैंकों के लिये भी इस धन्धे में लाभ के सिवाय किसी प्रकार की आर्थिक हानि होने की कोई सम्भावना नहीं है। भारत में भी कुछ बैंक इन कामों को करते हैं, लेकिन अभी इस धन्धे को बहुत उत्तेजना

देना है; इसलिये इस सम्बन्ध में बैंकों को स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिये। किसी प्रकार के कानूनी नियम बनाकर श्रद्धाचन पैदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

ट्रस्ट व्यवसाय—किसी एक आदमी या आदमियों के हाथ में, किसी दूसरे आदमी या आदमियों, एक संस्था या संस्थाओं के लाभार्थ, जायदाद वसीयत से छोड़ना 'ट्रस्ट' कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरीका में ट्रस्ट-कम्पनियों को ट्रस्ट-व्यवसाय के साथ साथ बैंकिंग धन्धा करते हुए देखकर वहाँ के बैंकों ने भी ट्रस्ट-व्यवसाय करना प्रारम्भ कर दिया है। इसका अनुकरण दूसरे देशों के बैंकों ने भी किया है। इंग्लैण्ड के 'बडे पांच' बैंकों ने इस व्यवसाय को करने के लिये अपने यहाँ या तो पृथक् विभाग खोले हैं या अपने स्वामित्व और प्रबन्ध में सहायक कम्पनियाँ स्थापित की हैं।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बैंक इस काम के लिये बहुत ही उपयुक्त संस्था है। प्रथम तो बैंक व्यक्तियों के समान नाशवान् नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति को ट्रस्टी बनाने की हालत में यदि ट्रस्टी, वसीयत-कर्ता से पहले मर गया तो वसीयत-कर्ता के सामने फिर वही ट्रस्टी तलाश करने की मुसीबत आ जाती है, जो अच्छे बैंक को ट्रस्टी बनाने की हालत में नहीं आ सकती। यदि खातेदार यह चाहे कि बैंक वसी (executor) के मरने पर काम करे तो कई बैंक इसके लिये उद्यत हो सकते हैं, जिनमें से किसी को भी मरनेवाले वसी या

ट्रस्टी का स्थानापन्न बनाया जा सकता है और ऐसा परिवर्तन आसानी से तितम्मा बसीयत (Codicel) द्वारा हो सकता है। दूसरे कई मित्रों में कुछ ही ऐसे होते हैं, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो, लेकिन बैंक आमतौर पर व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय माने जाते हैं। तीसरे ट्रस्ट में आई हुई जायदाद का प्रबन्ध करने की समस्या बड़ी कठिन होती है, इसके लिये विशेष अनुभव और व्यापारिक कुशलता की आवश्यकता है, जिसकी पूर्ति, बैंक अधिक काम मिलने के कारण अपने अमले में तत्सम्बन्धी काम के विशेष अनुभवी भौकर रखकर कर सकते हैं। इस प्रकार ट्रस्टों का प्रबन्ध व्यक्तियों की अपेक्षा बैंकों द्वारा लगातार, सुचारु रूप से और कम खर्च में हो सकता है। इसके अलावा बसीयतकर्ता को अपने मित्रों की, इस काम को हाथ में लेने के लिये खुशामद नहीं करनी पड़ती है। भारतीय बैंकों ने जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस व्यवसाय को ओर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन भविष्य के लिये यह धन्यता उपेक्षा करने योग्य नहीं है, इसलिये भारतीय बैंक कानून में बैंकों के लिये इस काम के करने की आज्ञा होनी चाहिये।

रक्षार्थ वस्तुयें जमा करना—भारतीय बैंकों को अपने खातेदारों से जमानतें (Securities) और मूल्यवान् वस्तुयें, रक्षार्थ प्राप्त करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। दूसरे देशों के आधुनिक बैंक इस धन्ये को बढ़ाने के वास्ते नित्य नई सुवि-

धारण प्रस्तुत करते रहते हैं। यदि कोई बैंक का खातेदार जमानतें या दूसरी मूल्यवान् वस्तुएँ बैंक के दफ्तर का समय समाप्त हो जाने के बाद प्राप्त करता है और रात में अपने पास नहीं रखना चाहता है तो उसके लिये कुछ बैंकों ने 'रात्रि-रक्षा' का प्रवन्ध कर रखा है, जिनमें दूसरे दिन दफ्तर खुलने के समय तक के लिये वस्तुएँ रखली जाती हैं। इस प्रकार बैंक अपने खातेदारों की मूल्यवान् वस्तुओं की रक्षा करने में सहायक हो रहे हैं। भारत में इस धन्धे के लिये अच्छा क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत लोग घर से बाहर जाने की हालत में अपनी मूल्यवान् वस्तुओं को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के यहाँ रक्षार्थ रखने के अभ्यस्त हैं। इसमें कभी कभी उनके साथ विश्वासघात हो जाता है और वे अपनी रफ़ी हुई वस्तुएँ वापस नहीं पाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ अधिक जन सख्या देहात में रहती है, वहाँ जब कभी दूतदार रोग फैलते हैं या किसी प्रकार का कोई विद्रोह खड़ा हो जाता है तब बहुत से लोग उस गाँव या कस्बे का निकास थोड़े दिन के लिये छोड़ देते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पास अपनी बहुमूल्य वस्तुओं की हिफाजत से रखने का कोई साधन नहीं होता। या तो वे अपने मकान में कहीं गाड़ देते हैं या साथ में लिये लिये फिरते हैं। इससे बहुधा उन्हें हानियाँ उठानी पड़ती हैं। यदि बैंक इस काम को हाथ में लेने लग जायें तो धीरे धीरे उनके प्रति विश्वास बढ़ने से भारत की अधिकांश जनता, बैंकों द्वारा उपलब्ध इस सुविधा से लाभ उठाना बहुत

पसंद करेगी। देहात में रक्षा का समुचित प्रबन्ध करना हर एक बैंक के लिये आसान नहीं हो सकता, लेकिन बड़े बड़े नगरों में बड़े बड़े बैंकों की निगरानी में पृथक् रूप से अच्छे मज़बूत 'रक्षित-गृह' स्थापित किये जा सकते हैं, जिनमें मुद्रास्फोटा के बैंक रक्षार्थ आई हुई वस्तुओं को लेकर भेज सकते हैं और जमा करनेवालों के वापस माँगने पर मँगवाकर दे सकते हैं। इस प्रकार यह धन्या छोटे बड़े बैंकों के सहयोग से अच्छी तरह चल सकता है।

लाभ-वितरण—बैंकों के पास हिस्सापूँजी (Share Capital) कम होती है। इनकी कार्य-शील पूँजी (Working Capital) में अधिक संख्या अमानतों की होती है, जिनको ये व्याज कमाने के हेतु सरकारी, रेलवे, म्युनिसिपल कमेटी तथा नगरोन्नतिकारिणी-समिति (Improvement Trust) के कर्ज, बोर्ड और अन्य प्रथम-श्रेणी की ज़मानतों पर, निजी और सावजनिक उद्योग स्टॉक कंपनियों के हिस्सों और डिपेन्डर पर, अचल और चल सम्पत्ति की ज़मानत पर तथा प्रतिष्ठित कोठियाँ या कंपनियों का उनकी वैयक्तिक ज़मानत पर भी उधार देते हैं या लगाते हैं। इस बड़े धन्य में ज़मानती वस्तुओं का भाव घटने-बढ़ने या उधार लेनेवाली कंपनियों और फ़र्मों के फ़ेल होने से कमी कमी बैंकों को भारी हानि हो जाने की सम्भावना रहती है। ऐसी आकस्मिक हानियों को बिना अपने हिस्सा या अमानतों को क्षति पहुँचाये, सह सकने में समर्थ होने के

लिये आम तौर पर बँक कई प्रकार के रक्षित और हानि पूरक कोष—रक्षित-कोष (Reserve fund) ऋण परिशोधन-कोष (Sinking fund) आकस्मिक-व्यय कोष (Contingency-fund), साखपत्र मूल्य हास पूरक कोष (Investment Depreciation Reserve), अचल सम्पत्ति मूल्य-हास पूरक कोष (Landed properties Depreciation Reserve) बट्टा खाता पूरक कोष (Bad Debt fund) आदि नाम से स्थापित करते हैं, जिनमें प्रति वर्ष अपनी आय में से सर्वप्रथम कुछ निश्चित भाग निकालकर जमा करते रहते हैं, तत्परचात् घटा हुआ लाभ हिस्सेदारों में बाँटते हैं। कुछ वर्षों में इन कोषों में इतनी अच्छी रकम हो जाती है कि बँक भारी से भारी हानि को भी सहने में समर्थ हो जाते हैं और उनकी स्थिति बड़ी मजबूत समझी जाने लगती है।

इस सम्बन्ध में बँकों के सवालकों के सामने लाभ विभाजित करते समय दो समस्याएँ आती हैं। एक ओर यदि उक्त वर्णित कोषों में रुक्या ले जाते हैं तो हिस्सेदारों को कम लाभ मिलता है। इससे हिस्सों का मूल्य पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और हिस्सों का मूल्य घटने के साथ बँक की कमजोरी की डोंडी पिट जाती है, फलस्वरूप अमानतें कम होने लगती हैं। दूसरी ओर अमानतें बढ़ाने की दृष्टि से हिस्सों का मूल्य बनाये रखने या बढ़ाने के खातिर अधिक लाभ विभाजित करते हैं तो उक्त कोषों के बढ़ाने में उपेक्षा होती है, इसलिये बहुत से नजीन

खुलनेवाले बैंक पिछली बात को ही अपनाया अधिक पसंद करते हैं।

वर्तमान आर्थिक संस्कार में फैली हुई व्यापारिक मंदी के कारण बैंकिंग संस्थाओं पर आयेदिन आर्थिक संकट आते रहते हैं, जिनका सामना करने के लिये पहली आवश्यकता इस बात की है, बैंक अपने धन्य में होनेवाली हानियों को सहने में समर्थ हो, ताकि अपनी हस्ती कायम रख सकें। व्याज से मूल पूँजी की रक्षा अधिक अपेक्षित होती है; इसलिये लाभ अधिक घाटने के खातिर रक्षित और हानि पूरक कोषों को बढ़ाने की अपेक्षा करना दुःखिमानी का काम नहीं है। दूसरे देशों में इसके लिये कानूनी नियम मौजूद हैं :—

अमरीका—“नेशनल बैंक ऐक्ट आबू अमरीका के अनुसार प्रत्येक बैंक के लिये यह आवश्यक है कि वह अपने निःखर्ची-लाभ में से सर्वप्रथम १० प्रतिशत रक्षित कोष में प्रतिवर्ष जमा करता जावे, जब तक कि वह कोष मूलधन का २० प्रतिशत न हो जावे। याद में कण्ट्रोलर के निर्णय पर निर्भर होता है।”*

जापान में “नवीन कानून सन् १९२७ के अनुसार कोई बैंक तब तक लाभ नहीं घाट सकता, जब तक निःखर्ची लाभ का १० प्रतिशत रक्षित फंड में न ले जावे।”*

कनाडा में “बैंक कानून की धारा ५६ के अनुसार वहाँ के बैंक = प्रतिशत से अधिक लाभ नहीं घाँट सकते, जब तक कि तमाम आनुमानिक और निश्चित हानियों की पूर्ति के निमित्त यथोचित रकम न रख ली गई हो और रक्षित-कोष में प्राप्त-पूँजी के १० प्रतिशत के बराबर रकम जमा न हो चुकी हो।”*

इटली में “बैंकों के लिये अपने लाभ में से १० प्रतिशत प्रति वर्ष रक्षित कोष में ले जाना अनिवार्य है, जब तक कि यह कोष मूलधन के ४० प्रतिशत के बराबर न हो जावे।”*

भारत में बैंकिंग धन्या न केवल शिशु-व्यवस्था में है, बल्कि कमजोर भी है। इसको शक्ति देने के लिये ऊपर प्रस्तावित अन्य नियमों के साथ साथ रक्षित कोष को बढ़ाने रहने के लिये भी कानूनी नियम होने की अत्यन्त आवश्यकता है ताकि लाभ का विभाजन करने समय उसका भाग निकालने की उपेक्षा न की जाय; यथा—

(१) लाभ घोषित करने से पहले निःस्वर्ची लाभ में से १० प्रतिशत रक्षित कोष में प्रतिवर्ष ले जाया जावे, जब तक कि प्राप्त पूँजी के बराबर रकम न हो जावे, बाद में कम से कम ५ प्रतिशत ।

(२) जब तक रक्षित कोष बिकी हुई हिस्सा-पूँजी के १ के बराबर न हो जावे तब तक ६ प्रतिशत ओर इसके बाद ३ के बराबर होने तक ६ प्रतिशत से अधिक लाभ न बाँटा जावे । तत्पश्चात्

* Regulation of Banks in India, page 12

६ प्रतिशत से अधिक लाभ लाइसेन्स देनेवाले अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके बाटा जा सकता है।

उचित निरीक्षण

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य हिस्सेदारों के साथ साथ जमा करनेवालों के हितों की भी रक्षा करना है, इसलिये केवल हिस्सेदारों के चुने हुए निरीक्षकों या हिसाब परीक्षकों द्वारा की गई जाँच को पर्याप्त न समझकर कई देशों की सरकारें, बैंकों का निरीक्षण अपने निरीक्षकों से कराती हैं :—

कनाडा में "मिनिस्टर को सिफारिश पर सपरिवद्व गवर्नर जनरल, इन्सपेक्टर जनरल आर्बू वेक्स को नियुक्ति करते हैं, जिसको कुव्यवहार, अयोग्यता तथा सुपुर्द किये हुए काम को पूर्ण रूप से सम्पादन न करने आदि कारणों से अलहदा करने का अधिकार भी सपरिवद्व गवर्नर जनरल ही के हाथ में है। इन्सपेक्टर जनरल पूरे समय का अफसर होता है, उसकी आधीनता में आवश्यकतानुसार शिक्षित और अनुभवी अमला रहता है, जो बैंकों का निरीक्षण करता है। उसका यह काम होता है कि पूरी छान बीन और पूछताछ द्वारा यह मालूम करे कि कानून की उन शर्तों का, जो हिस्सेदारों और अमानतदारों के हितों की रक्षार्थ लागू की गई है, ठीक ठीक पालन किया जाता है या नहीं और बैंक की आर्थिक अवस्था सन्तोष जनक है या नहीं। अमले से इस प्रकार जाँच की प्राप्त रिपोर्टों के

आधार पर इन्सपेक्टर जनरल वर्ष में एक बार मिनिस्टर की सेवा में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करते हैं। इसके अलावा जब कभी इन्सपेक्टर जनरल को किसी बैंक की हालत निर्बल (Insolvent) मालूम होती है तो वह तुरन्त उस बैंक की हालत की सविगत रिपोर्ट मिनिस्टर को करता है। वहाँ से उस पर विचार होकर अति शीघ्र, बैंक के द्वार बन्द होने की प्रतीक्षा किये बिना ही आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी जाती है।”।*

जापान में “अर्थ-सचिव बैंकों के कारोबार पर पूरी निगरानी रखते हैं। वहाँ के कानून के अनुसार बैंक के हिसाब-परीक्षक (auditor) उसके धन्धे का गहरा अनुसन्धान करके उसकी वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट अर्थ-सचिव के सामने वर्ष में दो बार प्रेषित करते हैं। इन रिपोर्टों में क़ानून-द्वारा धाँचिद्धत महों का परिणाम भी दर्ज किया जाता है। सन् १९२७ ई० के संशोधन के अनुसार अर्थ-सचिव अपने ही निरीक्षकों से बैंकों की जाँच कराते हैं। इसके लिये वहाँ १८ निरीक्षक और ५४ उनके असिस्टेंट नियुक्त हैं, जो पाँच डिवीजन में बँटे हुए हैं”।†

संयुक्त राज्य अमरीका में “कण्ट्रोलर आफ़ करेन्सी, नेशनल बैंकों के काम-काज की जाँच के लिये जब वे उचित

* The Journal of the Indian Institute of Bankers, January 1931, Page 86-87

† Regulation of Banks in India, by M. L. TANNAN, Page 20

समझते हैं, अच्छे व्यक्तियों को निरीक्षक नियुक्त करते हैं और उनसे बैंकों की स्थिति के बाबत रिपोर्ट लेते हैं। ये निरीक्षक बिना किसी पूर्व सूचना और अनिश्चित समय में पहुँचते हैं और बैंकों के तमाम कारोबार की जाँच करते हैं; जैसे—रोशन गिनना, डिस्काउंट किये बिल, कर्जें और दूसरी प्रकार से लगी हुई रकमों के लिये यह छान-बीन करना कि उनकी ज़मानत में प्राप्त ज़मानतें संतोषजनक हैं न, ये डाइरेक्टरों की ओर लेनी रकम की विशेष रूप से देखभाल करते हैं। इस प्रकार ये निरीक्षक बैंकों के व्यवसाय से पूरे तौर पर वाकिफ़ होकर निर्णय करते हैं कि बैंक कहां तक सुरक्षित अवस्था में चल रहे हैं और इसकी रिपोर्टें कण्ट्रोलर ऑफ़ करेन्सी और सम्बन्धित बैंकों में भेजते हैं। यदि आवश्यकता होती है तो कण्ट्रोलर ऑफ़ करेन्सी खास खास बातों की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उनको हिदायत करते हैं कि सन्देहजनक और हवी हुई पूँजी को बट्टा खाते लिखकर उसकी क्षति-पूर्ति रक्षित-कोष को कम किया जाकर को जावे”।*

इन सरकारी निरीक्षकों और परीक्षकों को वेतन सरकार से मिलता है। इस खर्च को सरकार बैंकों पर कर लगाकर वसूल करती है।

* Regulation of Banks in India, by M. L. Tannan,

भारत में बैंकों के काम-काज पर सरकारी हस्तक्षेप बहुत ही सूक्ष्म रूप में है। कम्पनी कानून की धारा १३७ के अनुसार ज्वाइंट स्टॉक कम्पनियों के रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कं० से विशेष हालात मालूम कर सकते हैं। यदि उन हालात से वह सन्तुष्ट न हो या पूछे हुए हालात न बताये जायें तो यह उस मामले की रिपोर्ट स्थानीय सरकार को कर सकता है। इसका व्यवहार में कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसी प्रकार स्थानीय सरकार को, मूलधन के ५ हिस्सों के मालिक हिस्सेदारों के प्रार्थना करने पर, बैंक के हालात की जाँच कराने का अधिकार होने के नियम से भी कोई वास्तविक लाभ दिखाई नहीं दिया। भारतीय बैंकों के हिसाब-परीक्षा की परीक्षा कम्पनी-कानून की धारा १४४ की मद नं० ३ के अनुसार हिस्सेदारों की जनरल मीटिंग में छुने हुए हिसाब-परीक्षकों के द्वारा होती है। इन हिसाब-परीक्षकों को इसी कानून की धारा १४५ के अनुसार बैंक की सब हिसाब की कितायें और वाउचर देखने के अधिकार हैं। ये समस्त हिसाब-परीक्षा की जाँच करते हैं और बैंक के आवजाय का मिलान करके बैलेन्स शीट तैयार करते हैं, जिसकी तस्दीक करते हुए लिखते हैं—

“यह बैलेन्स शीट कानून के अनुसार दिखाई हुई हिसाब की कितायों से प्राप्त उत्तम से उत्तम सूचना और दिये हुए जवाब-दात के आधार पर तैयार की गई है, जो कम्पनी के कारबार की सच्ची हालत प्रकट करती है।” यह व्यवस्था लगातार फ़ेल होने-वाले बैंकों की सख्या और उसके कारणों को देखते हुए सन्तोष-

जनक साबित नहीं हुई। कई काल-कुवलिप्त बैंकों के ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जिनमें पेशेवर ऊँची योग्यता-प्राप्त अनुभवी हिसाब-परीक्षक जाँच करते थे, जो व्यवस्थापकों के किञ्चित् विरोध पर गम्भीर से गम्भीर अनियमितताओं और घुराइयों को निर्भीकता-पूर्वक हिस्सेदारों के सामने रखने के बजाय चुप गये। इसका स्पष्ट कारण यह है कि इन पेशेवर निरीक्षकों की दूकानें व्यवस्थापकों की अनुग्रह ही पर निर्भर रहती है; क्योंकि उनको न केवल उन बैंकों के निरीक्षण का काम मिलता है, बल्कि कई दूसरी कम्पनियों का, जिनके भी डाइरेक्टर वे ही व्यक्ति होते हैं, काम मिलता है। यह माना कि इन हिसाब-परीक्षकों का चुनाव हिस्सेदार करते हैं, जो उन्हें अलहदा करने का भी अधिकार रखते हैं, लेकिन यह सब कुछ सिद्धान्त ही सिद्धान्त है, व्यवहार में आम तौर पर डाइरेक्टरों द्वारा ही चुने जाते हैं; इसलिये ऐसा प्रबन्ध होने की आवश्यकता है कि जिससे निरीक्षण निर्भीकता-पूर्वक हो और कार्यकर्ताओं की तमाम अनुचित कार्यवाइयों की सब्बो रिपोर्टें सरकार और हिस्सेदारों को प्राप्त हो सकें ताकि समय पर उचित कार्यवाही की जा सके। इसके लिये सरकारी निरीक्षक नियुक्त होने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है।

सरकारी निरीक्षण का प्रश्न भारत में नया नहीं है। सन् १९१३ ई० के अर्थसंकट के बाद और सन् १९१४ ई० के पहले जब इम्पीरियल कौन्सिल में, उस समय फ़ेल होनेवाले

बैंकों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त करने के निमित्त सर गंगाधर चिन्तामणि के प्रस्ताव पर विचार हो रहा था, उस समय फजली माई करीम माई ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत में बैंकों के लिये सरकारी निरीक्षण की गहरी आवश्यकता है। बम्बई के ऐडवोकेट जनरल सर थामस्टेगमेन ने भी बम्बई सरकार से, बैंकों का सरकारी निरीक्षण होने की सिफारिश की थी। इसके अतिरिक्त आलाम बेकिंग इन्वाइरी कमेटी ने भी लिखा है:—

“हम उत्तम समझते हैं कि उगाइर स्ट्राक-बैंकों का निरीक्षण सरकारी निरोक्षक द्वारा हो, जो उस निरीक्षक की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र होगा, जिसका कि पुनः निर्वाचन हिस्सेदारों और मैनेजिंग डाइरेक्टरों की इच्छा पर निर्भर है।”*

खेद है कि संसदुल बेकिंग इन्वाइरी कमेटी ने निरीक्षण-सम्बन्धी वर्तमान कानूनों नियमों में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं बतलाई। लेकिन सत्तारके दूसरे देशों के रियाज और भारतीय बैंकों की हालत को देखते हुए बैंकों और सर्व-साधारण के हित की दृष्टि से सरकारी निरीक्षण का होना अधिक उत्तम मालूम होता है।

* The Journal of the Indian Institute of Bankers, January 1931, Page 87-88

सरकारी निरीक्षण से लाभ—इससे न केवल अनियमित कार्यवाइयाँ और बुराइयाँ; जैसे—अधिकारों का दुरुपयोग करना व क़ानून-विरुद्ध काम करना आदि की रुकावट होगी, बल्कि जमा रखनेवालों के दिलों में बैंकों के साथ व्यवहार करने के लिये गहरा विश्वास हो जायगा। फल-स्वरूप जो रुपया इस समय यत्र तत्र अटकता हुआ है, बैंकों में जमा होगा। यह निरीक्षण लगातार हिसाब की जाँच का भी काम करेगा, जिसका प्रबन्ध करने में बैंक समर्थ नहीं हो पाते। इससे विशेष लाभ यह होगा कि बैंकों की ब्रांचों के हिसाबों की जाँच भी हो जाये करेगी, जो इस समय नहीं हो पाती और हेड आफ़िस के हिसाब-परीक्षक (auditors) ब्रांच मैनेजर्स के हस्ताक्षर-युक्त हिसाब ही का सही समझकर स्वीकार कर लेते हैं।

प्रस्ताव—भारत सरकार के अर्थ-विभाग के आधीन प्रत्येक प्रान्त में एक इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ़ बैंक्स नियुक्त होने चाहिये और उनके आधीन आवश्यकानुसार निरीक्षक नियुक्त किये जाने चाहिये, जो अपने अपने डिबोज़न के बैंकों की, बिना किसी पूर्व सूचना और निश्चित समय के मासिक जाँच करते रहें और देखते रहें कि बैंकों का धन्य कहां तक सुरक्षित है, सब कार-वार विवेक-पूर्ण और नियमानुसार होता है न। इस जाँच की रिपोर्ट समय समय पर इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ़ बैंक्स के पास पेश होती रहे। वहाँ से त्रुटियाँ, ग़लतियाँ और नियम-विरुद्ध कार्यवाइयों के लिये बैंकों से जवाब लिये जायें, मविष्य के लिये

उनको सावधान किया जाय और हिस्सेदारों तथा अमानतदारों के हितार्थ प्रत्येक उचित कार्यवाई की जावे ।

बैलेन्स शीट—बैंक के हिस्सेदारों और अमानतदारों को यह जानने का अधिकार है कि उनका रुपया किस प्रकार लगाया हुआ है । एक ऐसे बैंक के लिये, जो सावधानी से सुरक्षित और मजबूत अवस्था में काम कर रहा है, अपने लेने देने का स्पष्ट और पूरा हिसाब प्रकाशित करने में डर की कोई बात नहीं है, बल्कि इससे उसके प्रति खातेदारों का विश्वास बढ़ता है । इसी वास्ते इंग्लैण्ड में प्राइवेट बैंक भी अपने हिसाबों की प्रमाणित हिसाब परीक्षकों से जाँच कराकर पर्याप्त सूचना के साथ बैलेन्स शीट प्रकाशित करते हैं, लेकिन भारत के सार्वजनिक बैंक कानून के अनुसार स्थिति सूचक बैलेन्स शीट प्रकाशित करने में भी भिन्न होते हैं । ब्रिटिश भारत के बैंकों से देशी राज्यों द्वारा सहायता प्राप्त बैंक, जैसे—माईमोर बैंक, बैंक ऑफ़ बड़ोदा, ट्रायन कोर स्टेट एंडेड बैंक और कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक अपनी बैलेन्स शीट अधिक स्पष्ट प्रकाशित करते हैं । ऐसी हालत में भारत सरकार पर इस बात की जिम्मेदारी आती है कि वह बैंकों को, जनता के प्रति उनके इस कर्तव्य का पालन करने को, विवश करे ।

बैलेन्स शीट बैंक की सच्ची स्थिति सूचक और सरलता से समझने योग्य होनी चाहिये । इसकी पूर्ति के लिये वर्तमान

प्रचलित फार्म 'एफ' अपूर्ण है; अतः इसमें सुधार होना आवश्यक है :—

अमानतों का पृथक्-करण—आजकल बैंक सब प्रकार की जमाशुदा अमानतों को; जैसे—मियादी सेविंग्स बैंक और चलू जमाओं को मिश्रित करके बैलेन्स शीट में दिखाते हैं, यह अनुचित है। मियादी और मांगते ही वापस अदा करने योग्य अमानतों में गहरा अन्तर है। पहली प्रकार की अमानतें शान्तिदायक होती हैं, लेकिन दूसरी प्रकार को जमायें चिन्ता-जनक होती हैं; क्योंकि इन्हीं की मांग की अधिकता होने और उसको पूरा कर सकने में असमर्थ रहने पर ही बैंकों के दिवालें निकलने हैं; इसलिये बैलेन्स शीट के पढ़नेवाले को यह ज्ञात होने के लिये कि बैंक मांगते ही वापस करने योग्य जमाओं को चुकाने के लिये कहाँ तक पर्याप्त साधन रखता है, दोनों प्रकार की जमाओं को पृथक् पृथक् दिखलाना चाहिये। इसी प्रकार बैंक द्वारा उधार ली हुई रकम और अमानतें मिश्रित नहीं होनी चाहिये। अमानतें बैंक में बिला मांगे जमा होती हैं और उधार बैंक खुद आवश्यकता पड़ने पर कोशिश करके लेता है। दोनों का रूप अलग अलग है और दोनों भिन्न भिन्न प्रकार की सूचना देती हैं। इनको मिश्रित करने से लोगों को गलतफ़हमी होती है, इसलिये इनको अलग अलग ही दिखाना चाहिये।

लगे हुए रुपयों का पृथक्करण—बैंक कई प्रकार की जमानतों पर रुपया लगाते हैं, इन सबको मिश्रित करके

इकजाई रकम दिखाने से वास्तविकता मालूम नहीं होती, क्योंकि सबकी कीमत समान रूप में घटती बढ़ती नहीं है। एक प्रकार की जमानत की कीमत घटती है तो दूसरी की बढ़ती है, ऐसी हालत में सबके मिश्रित हो जाने से यह नहीं मालूम होता कि बैंक के पास किस प्रकार की जमानतें कितनी सख्या की हैं और उनमें कितना टोटा नफा है, इसलिये जमानतों पर लगे हुए रुपये (Investment) के पेटे में इस प्रकार पृथक्करण होना चाहिये:—

- (१) सरकारी, अर्घ सरकारी या दूसरी प्रकार की ट्रस्टी जमानतों पर।
- (२) रेलवे तथा अन्य सार्वजनिक कार्यकर्त्री कम्पनियों की जमानतों पर।
- (३) औद्योगिक और व्यावसायिक कम्पनियों के डिबेन्चर, हिस्से आदि पर।

नोट—इन जमानतों का मूल्य असली बाजार भाव से दोनों में जो कम हो, वह बतलाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त उधार दिया हुआ रुपया भी उधार (Loan) के पेटे में इस प्रकार अलग अलग दिखाना चाहिये:—

- (१) माल या माल के स्वत्व पत्र (Documents of title) की जमानत पर।
- (२) डाइरेक्टर्स या बैंक के दूसरे अफसरों को या उनसे सम्बन्धित कम्पनियों से या उनकी जमानत पर।

(३) ज्वाइएट स्टॉक कम्पनियों या दूसरे व्यक्तियों को
वैयक्तिक जिम्मेदारियों (personal guarantees)
पर ।

इन रकमों में जितनी रकम सन्देह-जनक हो, वह और
उसकी पूर्ति के लिये कितना साधन है या नहीं है, स्पष्ट दिखाया
जावे ।

फार्म का नमूना—वैलेन्स शीट के फार्म का एक नमूना
शेयर-होल्डर्स एसोसियेशन बम्बई ने सेण्ट्रल बैंकिंग इक्वाइटी
कमेटी के सामने पेश किया है । वास्तव में यह नमूना बड़े
परिश्रम से छपे हुए ४ पृष्ठों में तैयार किया गया है और
सविगत स्थिति सूचक है, लेकिन इसमें लेने और देने की विगत
इतनी विस्तार के साथ लिखी गई है कि उसने 'अति' का रूप
धारण कर लिया है, इसलिये 'अति सर्वत्र वर्जयेत्' के सिद्धान्त
का अनुसरण करते हुए उक्त कमेटी ने इस फार्म को स्वीकार
नहीं किया और इस सम्बन्ध में आये हुए समस्त प्रस्तावों पर
विचार करते हुए अपनी रिपोर्ट के पारा ७३० में इसका एक
नमूना तजवीज किया है ।

इसमें शक नहीं वैलेन्स शीट, हिस्सेदारों व अतिरिक्त सर्व
साधारण के सामने आती है और विरोधी समस्याओं के हाथों में
भी पहुँचती है, अतएव भारतीय बैंकों के लिये जो विदेशी बैंकों की
प्रतियोगिता के कारण बहुत ही प्रतिकूल दशा में काम कर रहे
हैं, अपने धन्धे की विगत, विदेशी बैंकों की विगत (जो अपने

देश में प्रकाशित करते हैं) से अधिक स्पष्ट प्रकाशित करना कभी कभी हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए बैलेन्स शीट का जो नमूना (देखो परिशिष्ट न० २) सैं० बें० इ स्वाइरी कमेटी ने तजवीज किया है, उपयुक्त है। वह वर्तमान फार्म 'एफ' की अपेक्षा अधिक स्थिति सूचक है और उसमें सर्वसाधारण के जानने योग्य ऊपर बताई हुई लगभग सभी आवश्यक बातों का समावेश कर दिया गया है।

मासिक स्थिति-सूचक पत्र—वर्तमान कानून के अनुसार बैंक वर्ष में २ बार बैलेन्स शीट प्रकाशित करते हैं—इंग्लैण्ड में यद्यपि कानूनी नियम नहीं है तो भी वहाँ के बैंक प्रतिमास स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित करत रहते हैं। बर्लिन के बैंक अपनी स्वतन्त्र इच्छा से दो महीने में एक बार स्थिति सूचक पत्र प्रकाशित करने पर स्वयं ही राजी हुए हैं। न्यू बेनियुपेलिन बैंक कानून (२ जुलाई, १९२७) के अनुसार वहाँ के बैंक मासिक बैलेन्स शीट प्रकाशित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बैंकों के लिये आवश्यक है कि वे अपने साप्ताहिक स्थिति सूचक पत्र उस क्लियरिंग हाउस में, जिसके वे मेम्बर हैं, प्रेषित किया करें। इन पत्रों में कर्ज और डिस्काउण्ट्स, अन्य लगी हुई रकमें, नकद रोशन अपने पास और बैंकों में जमा—मियादी और माँगने पर चुकाने योग्य, अलग अलग और अन्य देने तथा पुन डिस्काउण्ट्स आदि के अंक प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकार बार बार स्थिति सूचक पत्र प्रकाशित होते रहने से

बैंकों को वास्तविकता छिपाने का अवसर नहीं मिलता। भारत के कई मौजूदा बैंक अपनी स्थिति को अधिक सुन्दर रूप से रखने के लिये अर्ध-वर्ष के अन्त पर अपनी लगे हुई पूँजी का काफी हिस्सा चसूल कर लेते हैं और वास्तविकता को छिपाते हुए बहुत मज़बूत हालत दिखाने में सफल हो जाते हैं; इसलिये भारतीय उबाइएट स्टॉक बैंकों के लिये क़ानून-द्वारा यह आवश्यक होना चाहिये कि वे मासिक स्थिति-सूचक पत्र प्रकाशित किया करें (भमूना परिशिष्ट नं० २ में दिया है।) लाभ-हानि-सूचक पत्र वर्षभर की भाँति वर्ष में दो बार ही प्रकाशित होते रहे, लेकिन इस समय इनका प्रकाशित करना क़ानून में अनिवार्य नहीं है सो होना चाहिये। इसके साथ ही यह भी उचित प्रतीत होता है कि बैंकों को इस बात के लिये भी विवश किया जावे कि उक्त पत्र अंग्रेज़ी के अतिरिक्त प्रान्तीय देशी भाषाओं में भी प्रकाशित किये जावें। यह नई बात नहीं है। आजकल भी सेण्ट्रल बैंक ऑफ़ इण्डिया लि० और बैंक ऑफ़ बड़ोदा अपनी बैलेन्स शीटें अंग्रेज़ी और गुजराती में प्रकाशित करते हैं। ट्रायनकोर-स्टेट-एंडेड-बैंक, अपनी बैलेन्स शीट अंग्रेज़ी में मलयालम भाषा के अनुवाद-सहित प्रकाशित करता है, कोटा-स्टेट-कोऑपरेटिव-बैंक लि० केवल हिन्दी ही में बैलेन्स शीट प्रकाशित करता है। इसी ही प्रकार अन्य कई कोऑपरेटिव बैंक प्रान्तीय भाषाओं में बैलेन्स शीटें प्रकाशित करते हैं। इसके अलावा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये उक्त पत्र संक्षिप्त रूप से स्थानीय समाचार

पत्रों में सप्ताह भर तक छपते रहने चाहिये। इसमें बैंकों को कोई हानि नहीं है; बल्कि उनको अधिक जनसंख्या जानने लगेगी और फलस्वरूप अधिकाधिक काम मिलने लगेगा।

बैंकों की रक्षा

हमलों से—पिछले पृष्ठों में अनेक बार लिखा जा चुका है कि 'विश्वास' बैंकिंग धन्धे का 'प्राण' है; इसके कम होने से बैंकिंग-संगठन को गहरी क्षति पहुँचती है; इसलिये धेप-बरा या भ्रमवश बैंकों के विरुद्ध उड़ाई जानेवाली गप्पों को रोकने की महती आवश्यकता है। "इस गप्पों के कारण जापान में १५ मार्च से लेकर २१ अप्रैल (स० २७) तक फेल होनेवाले बैंकों की संख्या लगभग ३० थी और उनमें ६० करोड़ 'येन' जमा थे।" * भारत में भी इन निराधार गप्पों के कारण आये दिन बैंकों पर संकट आते रहते हैं। सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया लि० की जनरल मीटिंग ता० २५ फरवरी, १९३० में सर फीरोज़ सेठाना ने अपने अध्यक्ष-पद से दिये हुए भाषण में कहा था कि "हमारी साज़ को क्षति पहुँचाने के लिये बार बार हम पर बुरी तरह हमले हुए हैं"†। इसके बाद सन १९३३ के अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया आदि घम्बई के

* Regulation of Banks in India, by M. L. Tannan, Page 17.

कई बैंकों पर पावनेदारों ने जोर का धावा बोला था, उस समय पहले बैंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री० एस० एन० पोचखाना-वाला ने एक प्रेस-प्रतिनिधि को बयान देते हुए कहा था—“ऐसा मालूम होता है कि कुछ अप-स्वार्थी लोगों ने ऐसी गप्प उड़ाई है कि बम्बई के कुछ बैंक, करीम भाई के मिलों और रुई की एक बड़ी फ़र्म पर—जिन्होंने गत सप्ताह में देना चुकाने से इंकार किया है—अधिक लेना होने के कारण, गहरे नुक़सान में आ गये हैं। फनम्बरूप अमानतदार अधीर हो उठे हैं। सेण्ट्रल बैंक करीम भाई की मिलों से बहुत अर्से से लेन-देन नहीं कर रहा है, केवल कुछ हजार के डिस्कों पर उधार दिया हुआ है। रुई की फ़र्म पर तो इस बैंक का कुछ भी बाकी नहीं है, इस-लिये सेण्ट्रल बैंक पर यह धावा अकारण और अनुचित है इत्यादि।*

पाठको ! सेण्ट्रल बैंक, भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों में सबसे बड़ा और सोलह आना स्वदेशी संस्था है। इसकी आर्थिक स्थिति भी बड़ी मज़बूत है। उसके साथ भारतीय जमा करने-वालों का यह व्यवहार है तो दूसरे बैंकों के प्रति कैसा हो सकता है ? इसका अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। भारतीय जमा करनेवालों की इस नादानी के कारण कई अच्छे बैंक काल-रुधिरित हुए हैं। इसको रोकने के लिये सरकार को

* National Call, 13th October, 1933.

अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। अमरीका जैसे उन्नत देश में भी बैंकों के काम-काज के सम्बन्ध में भूठी ख़बरें फैलानेवालों को दंडित करने के लिये एक वर्ष की कैद और एक हजार डालर जुर्माना नियत किया हुआ है। यदि भारतीय-बैंक क़ानून में भी इस प्रकार का क़ाई विधान रख दिया जावे तो बैंकों पर अकारण होनेवाले हमलों की बहुत कुछ रूकावट होगी।

मुकद्दमों से—वर्तमान कम्पनी-क़ानून के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को दूसरी प्रकार की कम्पनियों के समान ही बैंकिंग कम्पनी पर फ़ौजदारी दावा करने की स्वतन्त्रता होने से कई बैंकों पर आये दिन मुकद्दमे चलते रहते हैं। यद्यपि बैंक सम्मान-पूर्वक घरी होते हैं, लेकिन उन्हें लम्बी तहकीक़ात की पैरवी में भारी क्षति उठाना पड़ती है और लोगों का आलोचना का शिकार बनना पड़ता है।* इसलिये बैंकों पर भूठे दावे दायर होना

* "In fact it (Central Bank of India) has been the target, for over a decade, of a virulent campaign of civil and criminal suits brought against it for most frivolous reasons. The Bank has come out successful in all this vexatious litigation. But suits are still being persisted in, and this means distraction of the attention of its officers, heavy expenses and constant worry." Indian Finance Year Book, 1932, page 101

रोकने के लिये कानूनी सहायता की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके लिये माननीय चीफ जस्टिस सर अम्बरसन मार्टन ने शामदसानी बनाम टाटा आयरन ऐण्ड स्टील क० लि० के मुकद्दमे में फैसला देते हुए लिखा है—“वर्तमान कम्पनी-कानून की दफा २३२ में, विशेष कर बैंकिंग कम्पनियों की झूठे मुकद्दमों से रक्षा करने के लिये, परिवर्तन होने की गहरी आवश्यकता है, क्योंकि दूसरी कम्पनियों की अपेक्षा बैंकों की साख अधिक कोमल होती है”।*

इस सम्बन्ध में यह उपाय बतलाया जाता है कि मुकद्दमा चलाये जाने से पहले, इन्स्पेक्टर जनरल आर्च बँक्स या ऐडवोकेट जनरल या रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कम्पनीज से प्रार्थी को आज्ञा प्राप्त करना चाहिये, लेकिन कुछ अनुभवी सज्जनों का इसके विरोध में यह कहना है कि केवल किसी अधिकारी से मुकद्दमा चलाने की आज्ञा हो जाने की खबर पारु ही लोगों के हृदय विचलित हो जावेंगे और बिना अदालत के फैसले की प्रतीक्षा किये, उस बैंक पर धावा बोल दिया जावेगा, इस लिये इस नियम से बंधे वर्तमान की अपेक्षा अधिक सख्त में पड़ेंगे, क्योंकि बाजार और गलियों में रहनवाले लोग ऐसी आज्ञा का कानूनी प्रभाव नहीं जानते। सेण्ट्रल बैंकिंग इन्वाइरी कमेटी ने इस प्रश्न को गहरे विचार के पश्चात् धारा सभा पर

छोड़ दिया है। हमारे ख्याल में मुकद्दमा चलानेवाले के लिये इस प्रकार की पाबन्दियाँ लगाई जावें कि उनसे भय खाकर कोई व्यक्ति किसी बैंक पर भूठा मुकद्दमा चलाने का साहस न करे, जैसे—मुकद्दमे को सुनवाई करने से पहले ऐसी भारी जमानत लेना, जो बैंक की पैरवी के खर्च व क्षति पूर्ति के लिये मजिस्ट्रेट के नजदीक आवश्यक हो और बैंक के बरी होने पर भूठे वादी को सख्त कैद की सजा देना। इसके अतिरिक्त तहकीकात और तजवीज जल्दी से जल्दी होने के लिये भी विशेष नियम होने चाहिये, जेमे कि बुनाय नमयन्वी भूगडों को निबटाने के लिये हैं।

दसवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—भारतीय विनिमय बैंक

“The extent of a nation's participation in its foreign trade depends considerably on the facilities which the Banking system gives to its traders” *

अर्थात्—एक राष्ट्र का अपने विदेशी व्यवसाय में अधिक हाथ बँटाना, उन सुविधाओं पर निर्भर है, जो बैंकिंग प्रणाली से उसके व्यापारियों को प्राप्त होती हैं।

भारतीय सेण्ट्रल बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी का उक्त कथन सत्य से ओतप्रोत है। जापान ने इस सम्बन्ध में जो उन्नति की है, उसका श्रेय योकोहामा स्पेसी बैंक को है। यह बैंक सन् १८८० ई० में स्थापित हुआ था। इसकी सहायता से जापान के विदेशी व्यापार में जापानियों का, जहाँ सन् १८७४ ई० में एक प्रतिशत से भी कम हाथ था, वहाँ सन् १९२२ ई० में १६.६ और ८६.६ प्रतिशत निर्यात और आयात व्यवसाय पर क्रमशः अधिकार हो गया। भारत का विदेशी व्यवसाय भी भारतीयों के हाथ में १५ प्रति शत से भी कम है। शेष सबका सब विदेशी व्यापारियों और कोठियों के अधिकार में है। इसका कारण भारत स्थित विदेशी-विनिमय-बैंकों की भारतीयों के प्रति तंगदिली और सहानुभूति-रहित व्यवहार है। यदि वर्तमान विदेशी बैंकों ने

* Indian Central Banking Enquiry report, Para 478

विदेशी और भारतीय व्यापारियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया होता और भारतीय व्यापारियों को वे तमाम सुविधाएँ, जिनके प्राप्त होने की एक स्वदेशी बैंक से आशा की जाती है, दी होतीं तो निस्सन्देह आज भारतीयों के हाथ में इस व्यवसाय का बहुत बड़ा भाग होता। उक्त वर्णित कमेटी के सामने भारतीय व्यापारियों और प्रमुख-प्रमुख भारतीय व्यापारिक संस्थाओं की गवाहियों से यह सिद्ध हो गया है कि वर्तमान विदेशी-विनिमय-बैंक जातीय पक्षपात से काम करते हैं। इसके फल-स्वरूप भारतीयों की हानि हो रही है; इसलिये अब यह अनिवार्य हो गया है कि भारत को विदेशी-विनिमय बैंकों के ऊपर निर्भर न रहकर विदेशी व्यापार में गति रखनेवाले व्यापारियों को समुचित सुविधा और सहायता देने के लिये थोकोहामा स्पेसी बैंक जैसा एक भारतीय विनिमय बैंक की स्थापना करना चाहिये। इस सम्बन्ध में सेण्ट्रल बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी ने भी यह सम्मति दी है कि “हमारे विचार में यह उचित नहीं है कि यह देश, विदेशी व्यापार के लिये विदेशी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की हुई सुविधाओं पर ही निर्भर रहे”। *

भारत में अब तक स्वतन्त्र रूप से विनिमय बैंक खोलने का तो विचार नहीं हुआ; लेकिन प्रेसीडेंसी बैंकों और इम्पोरियल बैंक को

* “We have come to the definite conclusion that it is not desirable that the country should be dependant for all times on the facilities afforded by non-Indian institutions for the financing of foreign trade” Report, para 481.

लंदन में अपनी शाखा रखते हुए भी विनिमय-व्यवसाय करने की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई। इसका कारण एक तो यह बताया जाता है कि “विदेशी-विनिमय” के धन्धे में अधिक जोखम है; इसलिये जब तक भारत सरकार का रुपया इंपीरियल बैंक में जमा रहे तब तक वह इस बैंक को ऐसा जोखम उठाने की आज्ञा नहीं दे सकती। दूसरा कारण यह है कि इंपीरियल बैंक विनिमय बैंकों का रुपया जमा रखता है, इसलिये उनका रुपया उन्हीं से प्रतियोगिता करने के काम में लाया जाना उचित नहीं समझा जाता। कुछ भी हो, भारत सरकार ने यह पक्ष विदेशी बैंकों की अनुचित माँग के आगे सर झुकाकर लगाई है, ताकि कोई भी भारतीय संस्था विदेशी बैंकों के अधिकृत मार्ग में बाधक न हो।

अपने दयाल से यह धन्धा जितना जोखमी ख्याल किया जाता है, उतना जोखमी नहीं है। जोखमी धन्धा होने का अनुमान ऐसा धन्धा करनेवाले बैंकों के फ़ेल होने की संख्या से लगाया जा सकता है। इसके लिये सेण्ट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी, अपनी बहुमत रिपोर्ट के पैरा ४५२ में लिखती है—“No case of a non-Indian Bank going into liquidation with resultant loss to the Indian depositors has been brought to our notice” अर्थात्—“किसी विदेशी बैंक (जो विनिमय का धन्धा करता है) का कोई ऐसा उदाहरण हमारे सामने उपस्थित नहीं किया गया, जिसने दिवाला निकाला हो और फल-स्वरूप भारतीय अमानतदारों की हानि उठानी पड़ी हो।” इसके अतिरिक्त यह भी देखने

में आया है कि इनमें भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की अपेक्षा कम सूद देने पर भी अधिक अमानतें जमा हैं और उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। यदि यह धन्धा जोखमी होता तो इसके करने-वाले बैंकों के फेल होने की संख्या अधिक होती और लोग उनमें अधिक जमा नहीं रखते। हाँ, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि विनिमय का धन्धा भिन्न भिन्न प्रकार के देशों से होता है, जहाँ भिन्न भिन्न भाषायें, भिन्न-भिन्न कानून और भिन्न-भिन्न प्रकार की मुद्रायें हैं, इसलिये इस धन्धे में उलझनें अग्रश्य हैं। इससे सनातन के वास्ते अधिक चातुर्य, कौशल और अनुभव की आवश्यकता है, लेकिन कोई ऐसा खतरा नहीं है कि जिससे भय खाकर इस धन्धे को छोड़ा हो न जावे।

इसकी बात है कि भारतीय अर्थ-शास्त्री और व्यापारी इस बात में एकमत हैं कि भारतीय विनिमय का धन्धा करनेवाली एक बलवान् संस्था—भारतीय विनिमय-बैंक जल्दी से जल्दी संगठित की जावे, लेकिन उसकी संगठन प्रणाली के सम्बन्ध में थोड़ा सा मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इसका समस्त मूलधन सरकारी हो और कुछ चाहते हैं कि सरकार और ज्वाइंट स्टॉक बैंक दोनों में विभाजित हो, लेकिन सब इस बात को मानते हैं कि इस प्रकार के बैंक का बिना सरकारी सहायता के चलना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त कठिन अग्रश्य है।

इसमें सन्देह नहीं कि सरकारी सहायता और प्रबन्ध-युक्त बैंक की साथ और प्रतिष्ठा अच्छी होगी और उसको ज्वाइंट स्टॉक

बैंकों के कार्य-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने से पूरे तौर पर रोका भी जा सकेगा, लेकिन साथ में यह बात भी नहीं भुलाई जा सकती कि नवीन भारतीय विनिमय बैंक की सफलता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह अपने ग्राहकों के लिये देश के भीतरी व्यापारी और आयात-निर्यात के व्यापारी के बीच में सीधा सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करे। उसका यह कार्य ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों के साथ प्रतियोगिता करनेवाला समझा जावेगा, क्योंकि इससे पिछले बैंकों को हानि पहुँचना सम्भव है और जिसका रोका जाना अव्यावहारिक है। ऐसी परिस्थिति में विनिमय बैंक की पूँजी में वर्तमान भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के हिस्से रखना अधिक उपयुक्त है। इससे ज्वाइंट स्टॉक बैंकों को जो कुछ विनिमय बैंक के कार्य-विस्तार से हानि होगी, उसकी पूर्ति उनके द्वारा खरीद किये हुए हिस्सों पर प्राप्त लाभ (डिविडेंड) से हो सकेगी; अतएव भारतीय-विनिमय-बैंक का मूलधन इस प्रकार विभाजित होना चाहिये :—

(१) आधा मूलधन सरकारी हो ।

(२) आधा मूलधन ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों में विभाजित किया जावे । नियत अवधि की समाप्ति पर ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों के खरीदने से जितने हिस्से शेष रहें, वे अवधि बढ़ाई जाकर सर्व-साधारण को दिये जावें । इसमें पहला अधिकार भारतीयों का हो, लेकिन किसी भी हालत में बचे हुए हिस्से पन्चीस प्रतिशत से अधिक विदेशियों को न दिये जावें ।

सेण्ट्रल बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटी (बहुमत) द्वारा प्रस्तावित और उक्त वर्णित मूलधन के विभाजन में थोड़ा ही अन्तर है, उसने तमाम मूलधन भारतीय ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के लिये प्रस्तुत करने को कहा है। उनसे बचे हुए हिस्से सरकार के लिये छोड़े हैं। इसमें सरकार के भाग का परिमाण अनिश्चित है। बैंक को साख और प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिये और इसलिये कि भारत सरकार की विदेशी भुगतान का कामकेवल इसी बैंक का मिल सके, आधे मूलधन का सरकारी होना अधिक उत्तम है।

भारत की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह बैंक ऐसा शक्तिशाली होना चाहिये कि मौजूदा विदेशी बैंकों का पूर्ण रूप से मुकाबला कर सके, इसके लिये मूलधन की सख्या अच्छी होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न सख्याएँ पतलाई हैं, जो २ और १० करोड़ के बीच में हैं। अधिक मूलधन के पृष्ठपोषक सूर्याश में पब्लिक बैंक के प्रस्तावक हैं, जिसकी प्रतिष्ठा केवल मूलधन पर ही अवलम्बित होती है। जो कम सख्या के प्रस्तावक हैं, वे सरकारी बैंक के अनुयायी हैं, जिसकी साख और प्रतिष्ठा केवल मूलधन पर ही अवलम्बित न होकर राज्य की सहायता और गारंटी के अंश पर निर्भर रहती है। उक्त प्रस्तावित बैंक सरकारी और पब्लिक दोनों का मिश्रित होगा। इसके लिये केवल पब्लिक बैंक के समान बहुत अधिक मूलधन की आवश्यकता नहीं है, पाँच करोड़ की पूँजी पर्याप्त होगी।

इस बैंक के फलने-फूलने के लिये यह परमावश्यक है कि

सरकारी विदेशी भुगतान का काम इसी बैंक को दिया जाय। जापान के अर्थ सरकारी याकोहामा स्पेसी बैंक की सफलता का श्रेय न केवल जापान बैंक-द्वारा दी गई दो करोड़ येन की आर्थिक सहायता को है, बल्कि उसके विदेशी लहने-पावने की भुगतान करने के सिपुर्द किये हुए अधिकार को है। यह विदेशी भ्रूण जारी करने, उसका सूद चुकाने और जापानी सरकार के लेने, वसूल करने आदि में बैंक ऑफ जापान की सहायता करता है। इसी सीमा तक यह सरकारी बैंक है और इसीलिये सरकार इसके प्रबन्धक श्रमले में डाइरेक्टर, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति में पूर्ण रूप से हाथ रखती है। भारत के लिये भी लगभग इन्हीं कामों के लिये और ऐसा ही प्रबन्ध युक्त बैंक उपयोगी जेंवता है। बिना इस प्रकार की रिआयत और प्रबन्ध के ऐसा बैंक उन्नति नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में विदेशी विशेषज्ञों का मत विरुद्ध है, उनका कहना है कि यह अव्यावहारिक है। विदेशी भुगतान का समय और परिपाटी का निर्णायक अधिकारी अकेला रिजर्व बैंक ही है। यदि इसका प्रबन्ध दूसरा संस्था के सिपुर्द किया तो विनिमय की नीति में दोनों संस्थाओं के बीच झगडा होने की सम्भावना है। इस रु उत्तर में मिस्टर अय्यर का यह कहना अधिक युक्तियुक्त है :—“भारतीय विनिमय बैंक, रिजर्व बैंक व स्थापित हो जाने पर उसके एजेण्ट के रूप में काम करेगा। रिजर्व बैंक अपनी आवश्यकतानुसार खरीदे जानेवाले स्टर्लिंग को तादाद और दर से उसे (विनिमय बैंक को) सूचित कर देगा, वह जितने

स्टर्लिङ्ग खुद बेचना चाहेगा, उतने अपने पास से बेच देगा, शेष दूसरे बैंकों से खरीदकर दे देगा। इसमें विदेशी-विनिमय बैंकों में आपसी प्रतियागिता वैसी ही होगी, जैसी आजकल होती है। ऐसे खरीदे हुए स्टर्लिङ्ग पर वह रिजर्व बैंक से कोई कमीशन नहीं लेगा और खरीदे हुए माघ पर ही दे देगा”।

“ऐसा ही उस हालत में भी हो सकेगा, जब कि रिजर्व बैंक स्टर्लिङ्ग खरीदना खुद अपने पास ही रखेगा। उस वक्त वह जिस सख्या में स्टर्लिङ्ग खरीदना चाहेगा, उसके लिये सूचना प्रकाशित करके टेण्डर मागेगा। आये हुए टेण्डरों में से पहले भारतीय विनिमय बैंक के टेण्डर की पूरी रकम स्वीकार करेगा और शेष का दूसरे बैंकों में विभाजित कर देगा। इसी प्रकार जब रिजर्व बैंक स्टर्लिङ्ग बेचना चाहेगा तो पहले भारतीय विनिमय बैंक को पड़ेगा, उससे बचे हुए दूसरे बैंकों को”।

“यह भी हो सकता है कि रिजर्व बैंक मौजूदा टेण्डर प्रणाली से छुले तोर पर स्टर्लिङ्ग की लिया बेची न करे तो भी भारतीय विनिमय बैंक को दो हुई रिआयत में कमी नहीं आ सकती। पत्र-व्यवहार-द्वारा भाव तय किया जाकर उस भाव पर अव्वल भारतीय बैंक को अवसर दिया जावेगा, उससे बचने पर दूसरे बैंकों का नम्बर आवेगा। इस प्रकार काम बड़ी आसानी से चल सकेगा और झगडा हाने की नौबत उपस्थित नहीं होगी”।*

* Foreign Exchange in India, by N Sankara Aiyar,

यह बैंक दूसरे ज्वाइंट स्टॉक बैंकों के साथ प्रतियोगिता न कर सके, इसलिये इसकी शाखाएँ बन्दरगाहों और बड़े-बड़े शहरों तक सीमित कर दी जावें। भारत के दूसरे स्थानों में एजेन्सी-द्वारा काम करे, एजेन्सी किसी एक बैंक को न दो जावे, किन्तु यह काम इस प्रकार प्रमुख-प्रमुख भारतीय बैंकों में विभाजित किया जावे कि किसी बैंक को किसी प्रकार की कोई शिकायत करने का अवसर प्राप्त न हो। इसके साथ-साथ ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों का भी यह कर्तव्य होना चाहिये कि वे इस बैंक को हर प्रकार का सहयोग देने में तत्पर रहें और सबकी यही लगन हो कि इसको पूर्ण सफलता प्राप्त हो। इसके लिये यह आवश्यक है कि ज्वाइंट-स्टॉक बैंक अपना ध्यान केवल देश के भीतरी व्यवसाय की ओर ही रन्वें और विदेशी विनिमय-संबन्धी तमाम काम इस बैंक के लिये छोड़ दें; क्योंकि मित्त-मित्त सस्थाओं-द्वारा थोड़ा-थोड़ा कार्य हाने की अपेक्षा एक प्रमुख और शक्तिशाली सस्था-द्वारा सम्पूर्ण काम का सगठित रूप से संचालन होना अधिक श्रेयष्कर है। इसमें संदेह नहीं कि इससे ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों को कुछ हानि होगी और संभव है उसकी पूर्ति शेयरों पर प्राप्त मुनाफे से न हो तो भी एक भारतीय सस्था को शक्तिशाली और सफल बनाने के लिये थोड़ा स्वार्थ-त्याग करना चाहिये।

यदि भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों और भारतीय व्यापारियों ने इसकी सच्चे हृदय से सहायता की तो चाहे जितनी शक्ति इसने विरुद्ध काम करे, इसकी सफलता निश्चित है।

ग्यारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—सेंट्रल या रिज़र्व बैंक*

मुद्रा वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करने के लिये मध्यस्थ होती है। इसलिये हममें घटा-बढ़ी होने से उत्पादकों और क्रय-विक्रय-कर्त्ताओं को बहुत हानि-लाभ होता है; अतः मुद्रा का संचालन, उसका मूल्य स्थिर रखने के लिये, देश के हित को ध्यान में रखते हुए होना चाहिये।

अब तक भारतीय करेंसी को बाग-डोर भारत सरकार के हाथ में चली आ रही है। सरकार ने इसका संचालन भारत के हित में नहीं किया, यह सर्वविदित बात है। सन् १८६६ ई० में फ़ाउलर कमेटी ने निश्चित रूप से स्वर्ण-माध्यम स्थापित करने और स्वर्ण-मुद्रा का प्रचार करने की सिफ़ारिश की थी, इसको उचित मानते हुए भी भारत-सरकार ने कार्य-रूप में परिणत नहीं किया। इसके बाद चेम्बरलेन कमीशन ने सन् १८९३ ई० में सिफ़ारिश की थी कि सरकार को करेंसी का बहो रूप रखना चाहिये, जो जनता चाहती है। इसकी बात भी अनसुनी रही। इन दोनों कमेटियों ने जो कुछ कहा था, उसमें थोड़ा-बहुत भारत का हित सम्मिलित था—इसलिये सरकार ने इनकी सिफ़ारिशों पर अमल नहीं किया। इनके बाद

* यह अध्याय इंडियन फ़ाइनेन्स के 'रिज़र्व बैंक सप्लीमेण्ट' नामक विरोपांक ३१ सहायता से लिखा गया है।

वेबिंग्टन स्मिथ कम्पेटी ने रुपये का मूल्य २ शिलिंग कायम करने की बहुत ही असंगत सिफारिश की थी। उसको सरकार ने गहरे विरोध के उपरांत भी व्यावहारिक रूप देने में बड़ी तत्परता दिखाई। इस दुराग्रह के फल-स्वरूप देश का ५ करोड़ रुपया स्वाहा हुआ और अंत में सरकार भी इस मूल्य को कायम रखने में समर्थ नहीं रही। इसी प्रकार हिल्टन यंग कमीशन ने भी सन् १९२६ ई० में रुपये का मूल्य १ शिलिंग ६ पेंस निश्चित करने की सिफारिश की थी। उसको मानते हुए सरकार ने तुरन्त क़ानून बना दिया। इसका देश ने, हानिकारक सिद्ध करते हुए, एक स्वर से विरोध किया था, किंतु सरकार ने उसकी कुछ भी परवाह नहीं की।

३१ सितम्बर, सन् १९३१ ई० को जब इङ्गलैण्ड ने स्वर्णधार का त्याग किया था, उस समय रुपये का सम्बन्ध भा स्वर्णधार से विच्छेद हो गया था और वह अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिये स्थतन्त्र हो गया था, लेकिन भारत-सरकार ने दुराग्रह-पूर्वक इसका सम्बन्ध उसी मूल्य पर, स्वर्णधार-रहित कान्गज़ी मुद्रा (Sterling) से जोड़ दिया। यह भारतीय करेंसी का पुराना इतिहास है।

इसके अतिरिक्त जब से प्रिटेन की सरकार ने स्वर्णधार तोड़ा है तब से उसको सोने की गहरी आवश्यकता आ रही है, उसकी पूर्ति के लिये भारत ने अपनी अतुलित स्वर्णराशि को सप्ताह प्रति सप्ताह जहाजों में लाद लादकर लंदन भेजा है। फल-स्वरूप २०० करोड़ का सोना भारत से बाहर जा चुका है।

इससे ही प्रिटेन अपने स्वर्ण-कोष में ७-८ करोड़ पौंड सोने की वृद्धि कर सका है। इस पर भारत में बड़ा असंतोष फैला, लोगों ने पड़ी से लेकर चांदी तक का जोर लगाया कि स्वर्ण का निर्यात बंद किया जावे, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी, बल्कि यह कहा कि अधिकांश देशों ने स्वर्णाधार छोड़ दिया है, जिनका निकट भविष्य में स्वर्णाधार पर आना दुश्भार है। ऐसी हालत में भारत का सोना खरीदना निरी मूर्खता है। कैसी विचित्र बात है कि एक आर प्रिटेन तो अपना स्वर्ण कोष अधिकाधिक बढ़ाता जा रहा है, इसलिये कि वह पहले से भी अधिक मजबूती के साथ स्वर्णाधार पर बहुत जल्द वापस आ जावे, दूसरी ओर भारत आशा रहित होकर अपनी स्वर्ण राशि को लुटाता जा रहा है। जो सरकार इस देश की हितों की इतनी उपेक्षा करती हो, उससे समार की हालत सुधरने पर भी भारत की मुद्रा प्रणाली में समयानुकूल और उचित परिवर्तन होने की कोई आशा नहीं की जा सकती।

सरकार की आर स करेंसी का संचालन करने के लिये एक कण्ट्रोलर आन्ड करेंसी नियुक्त किया जाता है, जो आम तौर पर इण्डियन सिविल सर्विस की मंडली में से लिया जाता है और वह करेंसी संचालन का ज्ञान कण्ट्रोलर आन्ड करेंसी के पद पर आकर प्राप्त करता है, उसको पहले से प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा सम्बन्धी और दूसरे बाजारों की स्थिति का कोई उत्तम ज्ञान नहीं होता, इसलिये उससे समय समय पर बहुत

बड़ी गलतियाँ होना स्वाभाविक है। इसमें कण्ट्रोलर ऑफ़ करेंसी का कोई दोष नहीं है, बल्कि वह प्रणाली दोष-पूर्ण है, जिसमें एक सरकारी अधिकारी को, जिसे मुद्रा सम्बन्धी पूर्ण ज्ञान और पर्याप्त अनुभव नहीं होता, ऐसा विभाग सिपुर्द कर दिया जाता है, जिसके संचालन के लिये गहरे चातुर्य, दूरदर्शिता, तत्सम्बन्धी स्वाभाविक ज्ञान और हाजिर जवाबी की आवश्यकता है, इसलिये करेंसी के उत्तम और उपयुक्त संचालन की दृष्टि से इस बात की गहरी आवश्यकता है कि यह काम सरकारी अधिकारियों के हाथ में से तुरन्त हटाया जाकर एक ऐसी सेंट्रल बैंकिंग संस्था को सौंपा जावे, जिसका अमला बड़ा होशियार और इस विषय का विशेषज्ञ हो।

क्रेडिट और करेंसी का सम्बन्ध—वर्ष के एक भाग में सरकार बाजार से टैक्स के रूप में बहुत बड़ी रकम वसूल करती है और उसका धीरे-धीरे खेतन तथा अन्य बातों में खर्च करती है। एतदर्थ वर्ष के कुछ महीनों में सरकार के पास बहुत रुपया इकट्ठा हो जाता है। उस समय में व्यापार भी गहरा होता है, अतएव सरकार के उस रुपये से बाजार को सहायता मिलनी चाहिये। इस काम को इस समय इम्पीरियल बैंक करता है, लेकिन करेंसी और क्रेडिट एक के हाथ में न होने से सराफ़ा बाजार का उचित रूप से काम नहीं चल सकता; इसलिये मुद्रा जारी करना और सरकारी रोशन का रखना दोनों काम एक ही अधिकारी के पास होना चाहिये,

ताकि रकम का संचय और वितरण-समय और स्थिति के अनुसार एक ही स्थान से हो सके।

स्वर्ण, मुद्रा का आधार है, मुद्रा बैंक की साख का आधार है। एक व्यक्ति क पास एक हजार रुपया है, उसमें से वह अपने पास २०) मुद्रा के रूप में रखता है। शेष ६८०) बैंक में जमा कर देता है, बैंक इस रकम से उन लोगों को आर्थिक सहायता पहुँचाता है, जिनको कि इसकी आवश्यकता है। दूसरे शब्दों में ६८०) की साख के आधार स्वरूप २०) की मुद्रा है और इस मुद्रा क स्वर्णाधार का मूल्य केवल ७) है। जब उक्त व्यक्ति का बैंक पर से विश्वास उठ जाता है तब वह ६८०) बैंक से निकालकर करेंसी के रूप में समझ करता है। उस वक्त बैंक क्रेडिट का सकाच होता है और मुद्रा का विस्तार, फल-स्वरूप बहुत से सांन की आवश्यकता उपस्थित हो जाती है।

सामान्य यह सम्पत्ति (Reserve) है, जिसको सेण्डल बैंक अपनी करेंसी क लिये जुटाता है। करेंसी यह सम्पत्ति है, जिसको बैंक सम्पूर्ण बैंक क्रेडिट क लिये जुटाते हैं, अस्तु करेंसी और क्रेडिट का सवालन एक ही स्थान से होने पर बाजार में मुद्रा आवश्यकता से अधिक कम नहीं हो सकेगी और मुद्रा का मूल्य स्थिर रह सकेगा, इसलिये यह परम आवश्यक है कि एक उपयुक्त संस्था इस उद्देश्य से स्थापित की जावे कि वह जहाँ तक रिजर्व, क्रेडिट और करेंसी का संबंध है, बाजार को भली प्रकार संतुलन पर रख सके।

इसके अनिश्चित यह सस्था बैंकों को उचित जमानत पर विशेष क्रेडिट प्रदान करने में भी समर्थ हो। बैंकों के पास उचित जमानत तब होगी, जब व्यापार अच्छा होगा और व्यापारी के पास अधिक उधार लेने के अवलम्बन होंगे। ऐसे अवसर पर यदि दूसरे बैंक सेण्ट्रल बैंक की नीति और उद्देश्य के विरुद्ध कोई पड़यंत्र रखे तो उसका असफल करने के लिये सेण्ट्रल बैंक को समर्थ होना चाहिये। उस हालत में सेण्ट्रल बैंक बाजार में सीधी उधार देकर पड़यंत्र के प्रभाव को निरर्थक कर सकता है।

अस्तु, सेण्ट्रल बैंक की आवश्यकता इसलिये है कि —

(१) सरकारी लेन-देन का धन्धा, जिसका बाजार से सम्बन्ध है, ऐसी एजेंसी के द्वारा होना चाहिये, जो इसमें निपुण हो।

(२) करेंसी और क्रेडिट का एकीकरण हो।

(३) एक ऐसी सस्था हो, जो एक ओर तो बैंक को आवश्यक और पर्याप्त सुविधायें प्रदान करे और मुद्रा का सग्रह इस रूप में रखे कि देने की मांग की पूर्ति कर सके और दूसरी ओर बैंकिंग संस्थाओं के कार्यों पर पूर्ण रूप से निगरानी रख सके, ताकि सर्वसाधारण के दिल में यह विश्वास उत्पन्न हो जाय कि बैंकों की देख-रेख भली प्रकार से होती है और वह निश्चिन्त होकर बैंकों के साथ धन्धा करने लगे।

करेंसी और क्रेडिट की संचालन-विधि—यूरोपियन बैंक करेंसी और क्रेडिट का संचालन सरकारी जमानतों, विलस

और डिस्काउंट-रेट द्वारा करते हैं। वे कुछ प्रतिबन्धों के साथ सर्वसाधारण से व्यवसाय करने, जमा रखने, उधार देने में स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस प्रकार के व्यवसाय को केवल क्रेडिट का मूल्य स्थिर रखने की दृष्टि से ही करते हैं न कि व्यावसायिक बैंकों की भांति लाभ कमाने के लिये। इन बैंकों का सबसे पहला और प्रमुख उद्देश्य देश के सामान्य हितों की ओर देखना होता है और कमाई करने का उद्देश्य गौण रूप से हाता है। इनकी पूँजी नकदी में या अल्पावधिवाली या स्वयं भुगतान योग्य (self-liquidating) जमानतों में रहती है, जिनका हर समय नकद में तुरन्त परिवर्तन किया जा सकता है। जब कभी बाजार में नाणे की अधिकता (inflation of credit) होती है तब सैंड्रल बैंक मुद्रा का सकोच (contract) करता है और जमानतें बेचकर या नियमानुसार किसी दूसरे प्रकार से बाजार का फालतू रुपया (surplus money) समझ करता है, इसी प्रकार जब बाजार में नाणे का कमी होती है तब बैंक मुद्रा का प्रसार करता है और बाजार में जमानतें और बिल खरीदकर रुपया फैलाता है। जब कभी रुपया देश की आवश्यकता से अधिक और लाभ के विपरीत विदेशों में निर्यात हाता दिखाई देता है तब सैंड्रल बैंक अपना डिस्काउंट रेट घटाकर रुपये का बाहर जाने से रोकता है। इसी प्रकार जब देश में व्यापारिक आवश्यकताओं से अधिक रुपया फालतू होता है तब सैंड्रल बैंक डिस्काउंट रेट घटाकर रुपये को देश से बाहर ऊँची दर का व्याज

कमाने के लिये निर्यात होने का अवसर देता है। बाजार के लिये बैंक-रेट का अनुकरण करना अनिवार्य होता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक नोट जारी करनेवाली अकेली संस्था होती है, जो बाजार को करेंसी और क्रेडिट प्रदान कर सकती है। सेंट्रल बैंक वह जगह है, जहाँ देश की नकद रोशन और स्वर्ण राशि जमा रहती है। जब बैंक रेट ऊँचा जाता है तब बाजार की व्याज की दर बढ़ती है। फलस्वरूप दूसरे देशों में व्याज की दर कम होने से रुपया बाहर जाने से रुक जाता है, इतना ही नहीं बल्कि अधिक व्याज मिलने के कारण विदेशों से उलटा रुपया खिंचता है, ऊँचे व्याज की दर क्रेडिट को घटाती भी है, इसलिये वह रुपये की माँग और सप्लाई के बीच समतुल्यता लाने में समर्थ हो जाती है। इसी प्रकार विरुद्ध परिस्थिति में कम व्याज की दर का उपयोग किया जाता है। नोट जारी करनेवाला बैंक अपने पास विदेशी बिल रखता है, उनका उपयोग क्रेडिट की माँग और सप्लाई को समतुल्य करने के लिये किया जाता है। जब देश में करेंसी या क्रेडिट की बाहुल्यता होती है तब फालतू रकम विदेशों में लगाई जाती है और जब कमी आती है तब विदेशी बिल बेचकर रकम मँगाई जाती है।

भारत में सेंट्रल बैंक की माँग

भारत में सेंट्रल बैंक की माँग सन् १८३६ ई० से की जा रही है। इसके प्रधान आन्दोलनकर्त्ता श्री० जे० विलसन सेम्पुल

लॉग, सर जे० अग्राहाम्स और एम० किन्स हैं। इनमें पिछले महा-
शय ने सन् १९१३ ई० में इस सम्बन्ध में बड़े परिश्रम और
विद्वत्ता के साथ एक नोट तैयार किया था। उसमें आपने भारत
में सेंट्रल बैंक स्थापित करने के लिये बड़ा जोर दिया था। इसके
बाद सन् १९२६ ई० में हिल्टन यंग कमीशन ने भी इस सम्बन्ध में
बड़ी जोरदार सिफारिश की थी, जिसके आधार पर सन् १९२७ ई०
में एसेम्बली में रिजर्व बैंक बिल पेश हुआ था। उस समय
एसेम्बली का बहुमत स्टेट-बैंक चाहता था और सरकार शेयर-
होल्डर बैंक। इसी झगड़े में बिल उठा लिया गया। अभी हाल में
सन् १९३० ई० में सेंट्रल बैंकिंग इन्वेंडरी कमेटी ने भी हिल्टन यंग
कमीशन के मत का समर्थन करते हुए लिखा था :—

“हम रॉयल कमीशन सन् १९२६ ई० से इस बात में सहमत
हैं कि भारत में फरेंसी और क्रेडिट के संचालन की बागडोर
सरकार और इंपारियल बैंक के हाथों में क्रमशः है, दोष पूर्ण है
और हमारा निश्चय है कि जब तक फरेंसी और क्रेडिट का
संचालन किसी एक अधिकारी के हाथ में न सौंपा जायगा तब
तक वास्तविक उन्नति संभव नहीं है, इसलिये हम सेंट्रल बैंक
की स्थापना को बैंकिंग सुविधाओं की उन्नति की दृष्टि से अत्यंत
महत्वपूर्ण समझते हैं और आम तौर से इसको बैंकिंग की
उन्नति का प्रधान साधन मानते हैं, अतः एक सेंट्रल या रिजर्व
बैंक यथासंभव शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये।” अन्त में

भारतीय राउण्ड-ट्रेबल कान्फ्रेंस, लंदन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, यहाँ तक कि भारत में नवीन सुधारों का देना और न देना भी रिज़र्व बैंक पर आन अटका। फल-स्वरूप सरकार को भारत में रिज़र्व बैंक स्थापित करने की जल्दी हुई और उसने तत्सम्बन्धित लोगों से सलाह-मशविरा करके सितम्बर, सन् १९३३ ई० में भारत की लेजिस्लेटिव एसेम्बली में, भारतीय रिज़र्व बैंक बिल सन् १९३३ ई०, उपस्थित करके पास करा लिया। इस पास-शुदा बिल के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक का संगठन इस प्रकार होगा।”

रिज़र्व बैंक का संगठन

मूलधन—यह शेयर-होल्डर्स बैंक होगा और इसका मूलधन ५ करोड़ रुपया होगा। जो १००), १००) के हिस्सों में विभक्त किया गया है। इस मूलधन को समस्त भारत में वॉटने के लिये ५ रजिस्टर कायम किये गये हैं, जिनके द्वारा नीचे लिखे अनुसार हिस्से बेचे जावेंगे :—

बम्बई रजिस्टर से १४० लाख			
कलकत्ता	”	”	१४५ ”
दिल्ली	”	”	११५ ”
मद्रास	”	”	७० ”
रंगून	”	”	३० ”
जोड़			५०० ”

हिस्सेदार—इस बैंक के हिस्से, वे व्यक्ति या कम्पनियाँ या सहकारी समितियाँ प्रीद सकेंगी—

(अ) जो भारत-निवासी होंगे, चाहे सम्राट की प्रजा हों चाहे देशी राज्यों की ।

(ब) जो इंगलिस्तान की प्रजा हों और साधारणतया भारत में रहते हों और युनाइटेड किंगडम या सम्राट के किसी उपनिवेश के निवासी हों ।

(स) वह कम्पनी, जो भारतीय कम्पनी क़ानून सन् १९१३ ई० के अनुसार रजिस्टर्ड हो या कोओपरेटिव सोसाइटी क़ानून सन् १९१२ ई० के अनुसार रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या किसी दूसरे क़ानून के अनुसार, जो इस समय ब्रिटिश भारत में सहकारी समितियाँ या स्वीकृत नामावली में वर्णित बैंकों के सम्बन्ध में हो या वह कोरपोरेशन या कम्पनी हो, जो पार्लियामेंट के किसी क़ानून के अनुसार, जो इस समय सम्राट के उपनिवेशों में चालू हो, स्थापित हुई हो और ब्रिटिश भारत में एक शांच रखती हो ।

सेण्ट्रल-बोर्ड—इसके संचालन के लिये एक सेण्ट्रल बोर्ड होगा, जिसके डाइरेक्टरों का चुनाव इस प्रकार होगा :—

(अ) एक गवर्नर और द्वा डिप्टी गवर्नरों को सपरिपट्ट गवर्नर जनरल बोर्ड की सिफ़ारिश पर विचार करके नियुक्त करेंगे ।

(व) चार डाइरेक्टर सपरिपट्टु गवर्नर जनरल द्वारा नियोजित होंगे ।

(स) आठ डाइरेक्टर हिस्सेदारों-द्वारा चुने जावेंगे । इनमें बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली के रजिस्ट्रों से दो-दो और मद्रास तथा रंगून के रजिस्ट्रों से एक-एक डाइरेक्टर लिया जावेगा ।

(द) एक सरकारी अफसर सपरिपट्टु गवर्नर जनरल-द्वारा नियुक्त किया जावेगा ।

स्थानीय बोर्ड—रजिस्ट्रों के अनुसार स्थानों में एक-एक स्थानीय बोर्ड होगा । उसका संगठन इस प्रकार होगा :—

(अ) पाँच मेम्बर उस क्षेत्र के हिस्सेदार अपने में से चुनेंगे ।

(ब) तीन मेम्बर तक सेएट्टल बोर्ड उस क्षेत्र के हिस्सेदारों में से चुन सकेगा । इनके चुनाव में वह सम्बन्धित क्षेत्र के आर्थिक हितों के प्रतिनिधित्व का, विशेष कर कृषि-सम्बन्धी और कोआपरेटिव बैंकों के प्रतिनिधि लेने का ध्यान रखेगा ।

जनरल मीटिंग—बैंक की जनरल मीटिंग, उसके वार्षिक हिसाब के समाप्त होने के बाद छः सप्ताह के अन्दर-अन्दर, जहाँ उसका दफ्तर होगा, वहाँ किसी एक स्थान पर बुलाई जावेगी । उसमें प्रत्येक हिस्सेदार को उपस्थित होने का अधिकार होगा, लेकिन मत वही हिस्सेदार दे सकेगा, जो पाँच या उससे अधिक

हिस्सों का मालिक होगा। एक हिस्सेदार को पाँच हिस्से पीछे एक मत देने का अधिकार होगा, लेकिन इस प्रकार एक हिस्सेदार १० से अधिक मत नहीं दे सकेगा। मत प्रोफ़सी-द्वारा भी दिये जा सकेंगे।

शाखायें—बैंक स्थापित होते ही बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और रंगून में अपने दफ़्तर और एक शाखा लंदन में स्थापित करेगा। यह भारत में और जगह भी शाखायें खोल सकता है। दूसरी जगह शाखायें खोलने के लिये सपरिपट्ट गवर्नर जनरल से पहले आज्ञा लेनी होगी।

फॉय—(१) यह बैंक रिज़र्व बैंक-विल की दफा १७ में वर्णित बन्धनों के साथ बिना ब्याज जमा रखना, प्रोमेसरी नोट व चिनिमय विल डिस्काउण्ट करना और उधार देना आदि बैंकिंग धन्धा करेगा और—

(२) नोट जारी करने का अकेला अधिकारी होगा।

(३) सरकारी खज़ाने का काम करेगा।

(४) सार्वजनिक श्रृण का प्रबन्ध करेगा।

(५) रुपये का मूल्य १ शिलिंग ६ पेंस स्थिर रखने के वास्ते सीमा-रहित स्ट्रलिंग को लिया-वेची करेगा।

(६) देश के बैंकों का रिज़र्व रखेगा। रिज़र्व बैंक-विल की धारा ४२ के अनुसार स्वीकृत नामावली में वर्णित बैंकों को, अपने माँगते ही चुकाने-योग्य देने का ५ प्रतिशत और मियादी

देने का २ प्रतिशत, इस बैंक में अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ेगा।

कृषि की सहायता—यह बैंक धारा १७ की मद २ के अनुसार प्रान्तीय कोऑपरेटिव बैंकों के इस्ताफर-युक्त बिल डिस्काउंट करने और मद नं० ४ (उ) के अनुसार उधार देने के अतिरिक्त एक कृषि-क्रेडिट-विभाग भी अपने यहाँ खोलेंगा, जो कृषि को, कृषि-बैंकिंग संस्थाओं-द्वारा आर्थिक सहायता पहुँचाने का प्रयत्न करेगा।

समालोचना—संसार के बड़े बड़े देशों के सेंट्रल बैंक शेयर-होल्डर्स बैंक हैं। अब तक जितनी भी अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसें हुई हैं, उन सबने सेंट्रल बैंक का स्टेट बैंक होना हानिकारक अनुभव करते हुए शेयर-होल्डर बैंक के पक्ष में ही सम्मति दी है;* इसलिये भारत में रिज़र्व बैंक का शेयर-

* "The dangers attending the establishing of a state Bank have during the course of time been so universally admitted that all the great international economic conferences held during the past six years warnings have been sounded against a State Bank and it was recommended that in countries where a state Bank was established, it should be converted into an independent private Bank, naturally, however, under sufficient supervision by the state." Dr. G. Visering President of Netherlands

होल्डर बैंक होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन इसमें कई ऐसी न्यूनताएँ रह गई हैं, जिनकी वजह से भारत के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा होने में सदेह हो गया है, यथा—

(१) बैंक ऑफ इंग्लैंड और नेदरलैंड बैंक के शेयर-होल्डर केवल उनके असली देशवासी ही हो सकते हैं। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक के हिस्से भी केवल भारतवासियों के लिये ही सुरक्षित रहने चाहिये थे। यह माना कि भारत में अंगरेजी राज्य होने के कारण इंगलिस्तान वासियों का यहाँ काफी व्यापार है और उनकी यहाँ बहुत सी पूँजी लगी हुई है। इस नाते से उनको हिस्से देना आवश्यक है, लेकिन उनके लिये हिस्सों की एक सख्या निश्चित होनी चाहिये थी, जो कुल मूलधन के १५ प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये थी। इसके अलावा सेण्ट्रल बोर्ड व स्थानीय बोर्डों में भारतीय डाइरेक्टरों का बहुमत रहने के लिये भी कोई विधान नहीं है। भारत के हितों की पूर्ण रक्षार्थ इस बात की अन्यतम आवश्यकता थी कि एक गवर्नर और दो डिप्टी गवर्नर्स की तीन जगहों में से कम से कम दो जगह अवश्य भारतीयों के लिये सुरक्षित रखी जाती और किसी भी अवस्था में सेण्ट्रल बोर्ड के समस्त डाइरेक्टरों में, (गवर्नर और डिप्टी गवर्नरों को

शामिल करते हुए) विदेशी डाइरेक्टर तीन से अधिक न होने का नियम होता ।

(२) कृषि-प्रतिनिधित्व—कृषि को उत्तम रूप से आर्थिक सहायता पहुँचाने के लिये कृषि-उधार-विभाग पृथक् रूप से स्थापित किया गया है । कृषि के प्रतिनिधि लेने के लिये सेण्ट्रल बोर्ड स्थानीय बोर्डों के डाइरेक्टरों के चुनाव के बक्त विशेष तौर पर ध्यान रखेगा; किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । भारत कृषि-प्रधान देश है, यहाँ कृषि की उन्नति पर ही देश की उन्नति निर्भर है; इसलिये इसके हितों की रक्षार्थ पैरवी करने के लिये सेण्ट्रल बोर्ड में कम से कम दो प्रतिनिधि प्रान्तीय कोआपरेटिव बैंकों-द्वारा चुने हुए लिये जाने चाहिये थे ।

(३) प्रबन्ध—रिज़र्व बैंक की स्थापना का प्रधान उद्देश्य यह है कि करेंसी और क्रेडिट का धन्धा सरकारी अधिकारियों के हाथों से निकालकर बैंकिंग के अनुभवी और देश-विदेश के बाज़ारों की गति से सुपरिचित व्यक्तियों को सौंपा जाय; इसलिये इस बैंक के गवर्नर वे ही व्यक्ति होने चाहिये, जिनको व्यापारिक और बैंकिंग संसार का पूर्ण अनुभव हो, न कि केवल सरकारी अफ़सरी का; अतः ऐसा नियम होना चाहिये था कि कोई भी भारतीय या अंगरेज़ी सिविल सर्विस का मेम्बर, बैंक के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने योग्य नहीं समझा जावेगा ।

(४) रुपये का मूल्य—रिज़र्व बैंक के कर्त्तव्यों में रुपये का अन्तराष्ट्रीय मूल्य स्थिर रखना भी एक कर्त्तव्य है। भारतीय व्यापार, उद्योग-धन्धों और कृषि की दृष्टि से रुपये का क्या मूल्य उपयुक्त हो सकता है, इसका निर्णय रिज़र्व बैंक के अनुभवों और इस विषय के पंडित गवर्नर्स ही भली प्रकार कर सकते थे; इसलिये इसको रिज़र्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड पर ही छोड़ना चाहिये था, लेकिन भारत सरकार ने इसके विपरीत अपनी पुरानी ज़िह्न के अनुसार बिल में रुपये का मूल्य १ शि० ६ पैसे निश्चित कर दिया और इसको परिवर्तन करने पर बिल को वापिस लेने और नवीन सुधार न देने की धमकी से पास करा लिया। इस दर का भारत में सन् १९२७ ई० से बड़े ज़ोरों के साथ विरोध हो रहा है। यह दर भारत के व्यापार, उद्योग-धन्धों और कृषि के लिये बड़ा घातक सिद्ध हो चुकी है। इसी दर की बदौलत भारत की अपार स्वर्ण-राशि विदेशों को बहती चली जा रही है। दुःख है कि इतनी अपरिमित हानि-कारक होते हुए भी भारत सरकार इसको क़ायम रखने का हठ कर रही है। यह ठीक है कि यह दर अस्थायी रूप से नियत की गई है, लेकिन भारत सरकार की मनोवृत्ति को देखते हुए अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-स्थिति सुधारने पर भी इसमें परिवर्तन होने के लक्षण दिखाई नहीं देते। अस्तु,

अब रिज़र्व बैंक बिल पास हो गया है, जो कुछ होना या सो हो गया “बिंध गये सो मातो हैं”; लेकिन सरकार और सर्वसाधारण

का यह कर्तव्य होना चाहिये कि इस बैंक को मौजूदा नियमों के अनुसार अधिक से अधिक भारत के हितों की रक्षा का साधन बनाया जाय। पहले सेएट्रल बोर्ड का चुनाव सपरिपट्टु गवर्नर जनरल के हाथों में है और बाद में भी लगभग आधे बोर्ड का चुनाव साहब मौसूफ़ के हाथ में रहेगा। आशा है सपरिपट्टु गवर्नर जनरल कभी भा. आई० सी० एस० के मेम्बरों में से गवर्नरों का चुनाव करने की भूल नहीं करेंगे और इस विषय के जानकारी लोगों को लेने की कृपा करेंगे। इसके अतिरिक्त भारतवासियों को भी चाहिये कि उनमें से प्रत्येक अपनी शक्ति के अनुसार इसके हिस्से खरीदने की कोशिश करें। जो पाँच हिस्से ले सकता हो, उन्हें अवश्य पाँच हिस्से खरीदकर इस राष्ट्रीय संस्था में देश के हितार्थ भत देने का अवसर प्राप्त करना चाहिये। बोर्ड आफ़ डाइरेक्टर्स से भी हमारा निवेदन है कि यह कम तादाद में हिस्से खरीदनेवालों का विशेष ध्यान रखने की कृपा करें ताकि इस संस्था के मेम्बरों को संख्या अधिक हो और यह सच्चे अर्थ में राष्ट्र की संस्था बना सके।

वारहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—कृषि-सहायक बैंक

एक चीनी विद्वान् ने कहा है—“मनुष्य-समाज का जीवन एक वृक्ष के समान है, कृषि उसकी जड़ है, उद्योग-धंधे उसकी शाखाएँ और प्राण हैं। यदि जड़ को हानि पहुँची तो पत्ते झड़ जायेंगे, शाखाएँ टूटकर गिर पड़ेंगी और वृक्ष मर जावेगा”। यह उदाहरण भारत के लिये पूर्ण रूप से लागू होता है। वास्तव में कृषि की हानि में हमारा विनाश और उसकी उन्नति में हमारा मुख सन्निहित है। कृषि केवल उत्पादन बढ़ाकर धन कमाने की वस्तु नहीं है और न यह उद्योग-धंधा तथा व्यवसाय ही है। यह राष्ट्र को जीवित रखने का साधन है। कृषकगण इस धंधे के द्वारा राष्ट्र का हित कर रहे हैं; इसलिये कृषकों को कृषि की उन्नति के लिये, दूसरे शब्दों में संसार को जीवित रखने के लिये, हर प्रकार की सहायता देना परमावश्यक है।

इस धंधे को कई प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, उनमें आर्थिक सहायता भी एक प्रमुख स्थान रखती है। आर्थिक सहायता देने के लिये ऐसी समस्याएँ होनी चाहिये, जो स्वार्थ-रहित होकर सच्चे रूप में कृषकों के हित की दृष्टि से सहायता देने का कार्य करें। साहूकारों से इस प्रकार की

आशा नहीं की जा सकती। ज्वाइंट-स्टॉक बैंक भी सेवा-भाव से सहायता करने में असमर्थ हैं। इस समस्या को हल करने के हेतु विशेष प्रकार की संस्थाएँ होने चाहिये। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान आदि देशों में कृषि को सहायता देने के लिये अलग बैंक स्थापित हैं। इंग्लैण्ड ने भी इस ओर ध्यान देकर विशेष प्रकार की संस्थाएँ स्थापित की हैं, जिनका दिग्दर्शन कृषि और बैंक शीर्षक अध्याय में कराया जा चुका है। भारत में कृषि प्रमुख धंधा है; इसलिये इसको आर्थिक सहायता देनेवाली उपयुक्त संस्थाओं को स्थापित करने की यहाँ गहरी आवश्यकता है।

कृषि को दो प्रकार की आर्थिक सहायता की आवश्यकता है:—

(१) थोड़ी अवधि के वास्ते।

(२) लम्बी अवधि के वास्ते।

पहली प्रकार की सहायता—बीज और खाद खरीदने, जुताई, हकाई और फटाई की मजदूरी चुकाने, दूसरे घरेलू खर्च चलाने तथा मालगुजारी चुकाने के लिये चाही जाती है। यह सब खर्च उपस्थित फसल से सम्बन्ध रखते हैं; इसलिये इन खर्चों के लिये ली हुई रकम फसल पकने ही बाज़ार में बेचकर चुकाई जा सकती है।

दूसरी प्रकार की सहायता—भूमि में स्थायी उन्नति करने, पैदावार को बढ़ाने के लिये बहुमूल्य मशीनें खरीदने, नई भूमि खरीदने और पुराना कर्जा चुकाने के वास्ते माँगी जाती

है। इन कामों में आरम्भ में इतना रुपया लग जाता है कि जो एक या दो साल की फ़सलों से नहीं चुकाया जा सकता, इसलिये दोनों प्रकार की उधार की वापसी की अवधि में गहरा अंतर है; अतः दोनों के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थायें स्थापित होनी चाहिये।

थोड़ी अवधि के लिये

कृषि को सहायता देने के लिये किस प्रकार की संस्थायें होनी चाहियें ? इस पर विचार करने के लिये देश और विदेश में कई कमीशन और कमेटियाँ बैठी हैं। उन सबने एक स्वर से सहकारी समितियों को स्थापित करने की सिफ़ारिश की है :—

“सहकारी समितियाँ कृषि-उद्योग को आवश्यक आर्थिक सहायता देने के लिये एक मात्र उपयुक्त साधन हैं।”

“अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन”

“कृषि को ठीक प्रकार से आर्थिक सहायता पहुँचाने का संतोषजनक मार्ग सहकारी समितियाँ हैं।”

“भारतीय कृषि रॉयल कमीशन”*

“भिन्न-भिन्न ध्रेणियों के लोगों ने हमारे सामने गवाहियों पर गवाहियाँ देते हुए यह मत प्रकट किया है कि ग्रामीण अर्थ (Rural Finance) की समस्या को हल करने के लिये संतोष-प्रद साधन केवल सहकारी समितियाँ हैं और लगभग सब इस

* Its report, page 436.

वात को मानते हैं कि चाहे दूसरे साधन व्यावहारिक साबित हों, लेकिन वे सफल प्रमाणित नहीं हो सकते, इसलिये हम सिफारिश करते हैं और यह हमारी प्रधान सिफारिश है कि जहाँ तक हो सके, निकट समय में प्रत्येक उपयुक्त और इच्छुक ग्राम में सहकारी समिति स्थापित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

“पञ्जाब प्रांतीय बैंकिंग इक्वायरी कमेटी”*

सहकारी समितियाँ और साहूकारों में अन्तर—साहूकार, व्यापारिक सिद्धांतानुसार अपने लाभ के अतिरिक्त दूसरी बात नहीं सोचता, लेकिन सुसंगठित सहकारी समिति अपने सदस्य का समान रूप से लाभ चाहती है। साहूकार जहाँ तक रुपया सुरक्षित रहता है, वहाँ तक वह आवश्यक और अनावश्यक सभी कामों के लिये बिना किसी सावधिचार के उधार दे देता है, वह न केवल वापस जल्दी बसूल करने की चिन्ता करता है, बल्कि उत्तरोत्तर उधार लेने के लिये रुपयों को उकसाता रहता है। सहकारी समिति काम की उपयुक्तता, आवश्यकता और आय व्यय की तुलना करके रुपया उधार देती है। अव्यय करने और कमाई की गुआइश के बाहर उधार लेने से सदस्यों का रोकती है। इसके अतिरिक्त समय पर चुकाने के लिये भी रुपयों का विवश करती है। इसका ऋण पर केवल नियन्त्रण ही नहीं होता, बल्कि यह उधार देने के साथ साथ उसके उपयोग

पर भी निगरानी रखती है। साहूकार सूद इतना अधिक लेता है कि रकम २-३ वर्ष ही में दूनी हो जाती है, लेकिन सहकारी-समितियाँ बहुत बाजिव सूद लेती हैं। साराश यह है कि साहूकार कृषक का सदैव ऋण-ग्रस्त देखने में प्रसन्न होता है और सहकारी समिति उसका ऋण मुक्त देखकर प्रसन्न होती है। अस्तु, आत्मीयता और परकीयता अथवा स्वार्थ और परार्थ में जितना अंतर होता है, उतना साहूकार और सहकारी-समिति में हाता है।

सहकारी-समिति और ज्वाइंट स्टॉक बैंक में अंतर—
ज्वाइंट स्टॉक बैंक भी वही काम करता है, जो सहकारी-समिति करती है, लेकिन दोनों की प्रणाली और भावों में गहरी भिन्नता है। पहली सस्था लाभ का अपन सदस्यों (हिस्सदारों) में विभक्त करती है, दूसरी अपने सदस्यों की वचत में जमा करके उनका रक्षित काय को बढ़ाती है। पहली सस्था पूँजी का सघ है, दूसरी मनुष्य का सघ (union) है। सहकारी-समितियाँ पूँजी का उपयोग करती हैं, लेकिन यह उस पर निश्चित दर से व्याज देती हैं। पहली प्रणाली में पूँजी का आधीन मनुष्य होता है, दूसरी में मनुष्य का आधीन पूँजी हाता है, इसलिये पहली प्रणाली धन सत्तात्मक है, दूसरी सहयोग पूर्ण। पहली प्रणाली में शासनाधिकार का आधार हिस्सों की संख्या है, इसलिये वहाँ एक हिस्से पीछे एक मत है। दूसरी का आधार समानता है, इसलिये वहाँ एक सदस्य को केवल एक ही मत

देने का अधिकार है, चाहे वह एक से अधिक कितने ही हिस्सों का मालिक हो। सबसे बड़ा अन्तर यह है कि ज्वाइंट-स्टॉक कम्पनी सफलता प्राप्त करने में अपने ही समान दूसरी संस्थाओं से प्रतिस्पर्धा रखती है, लेकिन सहकारी समितियाँ सहयोग रखती हैं और समान हित का ध्यान रखती हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वार्थ (Individualism) नहीं होता है। सहकारी समितियों का प्रधान उद्देश्य है—उस संस्था में शामिल होनेवाले व्यक्तियों के दिल और दिमाग के विरोधी विचारों का परिवर्तन करके उनके स्थान पर पारस्परिक प्रेम, सहायता, सहानुभूति और सेवा के भाव संचार करना। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सबके लिये और सब प्रत्येक व्यक्ति के लिये शामिल होते हैं।

भारत और सहकारी—भारत में सहकारी का प्रचार तीस वर्ष से है। इस देश की आवश्यकता को देखते हुए, इसका प्रचार बहुत ही कम हुआ है तब भी इसके प्रचार से ग्रामीण जनता को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक लाभ बहुत कुछ अंश में पहुँचे हैं :—

आर्थिक लाभ—सहकारी-समितियों के द्वारा कृषकों को बहुत बड़ी रकम वाजिव सूद पर उधार मिल सकी है और ग्रामीण-साख-प्रणाली का संगठन उत्तमता के साथ जम गया है। इसने निर्धन कृषकों को उस ऊँचे व्याज की दर के बोझ से रक्षा की है, जिसको वे जीवन भर वेवसी के साथ सहते रहते थे। इन समितियों से सहकारिता के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है।

मितव्ययिता और बचाकर जमा करने की आदत को उत्तेजना मिली है। धन का सदुपयोग करने की शिक्षा और प्रारम्भिक बैंकिंग विद्या का प्रचार हुआ है। जहाँ पर सहकारी संगठन की जड़ पूरे तौर पर जम गई है, वहाँ पर साहूकारों के ऊँचे व्याज की दर बहुत कम हो गई है। फल-स्वरूप पूँजीपतियों का चक्कर ढीला पड़ गया है और ग्रामीण जनता के जीवन में भारी परिवर्तन हाँ आया है।

सामाजिक लाभ—सहकारी-समिति ने ग्रामीण जनता को जातीय और धार्मिक भेद-भाव भुलाकर आपस में मिलकर अपनी भलाई-बुराई सोचने और एक दूसरे की सहायता करने का पवित्र पाठ पढ़ाया है, जिसके कारण आज समितियों की बैठकों में लोग बिना किसी ऊँच-नीच के भेद-भाव के प्रेम-पूर्वक एक साथ बैठते-उठते हैं और सलाह-मशविरा करते रहते हैं।

राजनीतिक लाभ—सहकारी-समितियों ने राजनीतिक क्षेत्र में भी भारी सेवाएँ की हैं, जो हाज़ाँकि प्रत्यक्ष में नहीं आई हैं, परन्तु किसी सस्था से कम नहीं हुई हैं, ग्राम की सहकारी समिति एक बड़ा शिक्षक है, जिसने सदियों से नींद में सोये हुए कृषक-समुदाय को मत का प्रयोग करना, सुसंगठित रूप से काम करना, अपने पैरों खड़े होना, स्वयं पर विश्वास करना, आपस के झगड़े आपस में निवटाना और निर्वाचन-प्रथा आदि उन्नतिशील देशों की नागरिक शिक्षा-सम्बन्धी अनेक बात सिखाई हैं और ग्रामीण जनता को जाग्रत करने में गहरा हाथ

वँटाया है। जब राजनीतिक संगठन का अभाव था, उस समय समितियों ने राजनीतिक और तामरिक शिक्षा देने के सम्बन्ध में बड़े-बड़े विद्यालयों का काम किया है।

यह सब कुछ होते हुए भी इस प्रणाली में अनेक दोष ऐसे आ चुके हैं, जिनके कारण इसकी उपयोगिता के प्रति लोगों का विश्वास शनैः-शनैः कम होता जा रहा है। बहुत से लोग उन दोषों के आधार पर बिना किसी सोच-विचार के सहसा कह उठते हैं कि सहकारिता असफल हो गई और इससे कृषकों की उन्नति की आशा करना निरर्थक है। ऐसे लोग ग़लती पर हैं, जिस दिन सहकारिता असफल हो जावेगी, उस दिन कृषि रोयल कमीशन के शब्दों में भारतीय कृषकों की उन्नति की आशा भी अवश्य नहीं रहेगी। (*If Co-operation fails there will fail the best hope of rural Indian*)*

सहकारिता के असफल होने की सबसे अधिक गूँज संयुक्त प्रान्त से आती है, वहाँ इसका प्रचार भी कम हुआ है, वहाँ की प्रांतीय बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपना मत देते हुए अपनी रिपोर्ट के पैरा १४१ के अन्त में लिखा है "In short, co-operation has not only been unsuccessful but to some extent even positively injurious." अर्थात् सारांश यह है कि सहकारिता न केवल असफल हुई है, बल्कि किसी हद तक हानिप्रद भी सिद्ध हुई है। ऐसा मत रखते

* Its report, para 374.

हुए भी इस कमेटी ने गहरे विचार के बाद दूसरे ही पैरा नं० १४२ के अन्त में यह स्वीकार किया है, " We believe that any improvement in that (Rural credit) system depends mainly on more or better co-operation " अर्थात्—हमारा विश्वास है कि ग्रामीण साख प्रणाली की उन्नति मुख्यतया विस्तृत और उत्तम सहकारिता के ऊपर ही निर्भर है।

इसके अलावा सेण्ट्रल बैंकिंग-इंक्वाइरी कमेटी को परामर्श देने के लिये भारत सरकार ने विदेशों से तीन प्रमुख विशेषज्ञ यहाँ बुलाये थे। उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना मत देते हुए लिखा है :—*

The co operative movement in spite of imperfections and of unavoidable set backs deserves every possible assistance from all quarters, because there is no better instrument for raising the level of the agriculturists of this country (India) than the co-operative effort "

अर्थात्—सहकारिता बहुत से दोषों और दूर न हो सकने योग्य त्रुटियों के होते हुए भी चारों ओर से प्रत्येक उचित सहायता पाने की अधिकारिणी है; क्योंकि इस देश में कृषकों

*Their memorandum on Commercial Banking, attached with Central Banking Enquiry Committee's report, Page No 628

की दशा सुधारने के लिये सहकारिता के अतिरिक्त दूसरा कोई उत्तम साधन नहीं है।

जब समस्त प्रामाणिक व्यक्ति बहुत गहरे विचार और पूर्ण अनुसंधान के पश्चात् कृषि की सहायता के लिये एक मात्र उपाय सहकारी समितियाँ ही बतलाते हैं तो बिना सोच-विचार और निराधार बातों पर इसके विरुद्ध कहनेवालों की बातें कोई मूल्य नहीं रखती; अस्तु,

भारतवर्ष में सहकारी-समितियों (ग्राम्य बैंक) के वेग-पूर्ण प्रचार की गहरी आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिये जैसा चाहिये, वैसा उद्योग नहीं किया है, लेकिन अब सरकार को इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। व्यापारिक हास और वस्तुओं के भावों के असाधारण रूप से घट जाने के कारण कृषकों की स्थिति उत्तरोत्तर धुरी से धुरी होती जा रही है। यदि कुछ अर्से तक और ध्यान नहीं दिया गया तो इनकी हालत लाइलाज हो जायगी और उसके फल-स्वरूप सरकार को भी भारी आर्थिक सङ्कट का सामना करना पड़ेगा; इसलिये प्रत्येक प्रान्तीय सरकार को यथासम्भव शीघ्र प्रत्येक उपयुक्त गाँव में सहकारी-समिति स्थापित करने के उद्देश्य से निश्चित और पूर्ण स्कीम स्वीकार करनी चाहिये।

२० साला स्कीम—सहकारिता-विस्तार-स्कीम अधिक से अधिक २० साला होना चाहिये। इसकी पूर्ति के लिये प्रत्येक प्रांत में सहकारिता के लिये सत्पात्र, उपयुक्त और इच्छुक प्रामा

को एक नामावली तय्यार कराई जावे और उसके अनुसार ५ प्रतिशत ग्रामों में प्रति वर्ष सहकारी समितियाँ बढ़ाते रहने से २० वर्ष के भीतर-भीतर प्रांत भर में सहकारिता का विस्तार किया जा सकता है। यह बात अस्मभव नहीं है। इस प्रश्न पर पंजाब प्रांतीय बैंकिंग-इंक्वायरी कमेटी ने बहुत विचार किया है और उसने अपने प्रांत में पिछले पाँच वर्षों की प्रगति को देखते हुए लिखा है कि “यदि सरकार सहायता करे तो एक हजार ग्रामों में प्रति वर्ष नई समितियाँ खोलते हुए पन्द्रह वर्ष के अन्दर समस्त प्रांत के प्रत्येक पात्र ग्राम में सहकारी समितियाँ स्थापित की जा सकती हैं”।* जब पंजाब प्रान्त में ऐसा हा सकता है तो कोई कारण नहीं कि दूसरे प्रान्तों और देशी रियासतों में ऐसा न हो सके। सध जगह सब कुछ हो सकता है, केवल आवश्यकता है सरकारी लगन की।

पिछला अनुभव—पिछली असफलता से बहुत महँगा अनुभव हुआ है; इसलिये सरकार, सहकारो-विभाग के कर्मचारी और अन्य सहयोगियों को चाहिये कि सहकारिता के भावी प्रचार में पिछली धुराइयों को न आने दें। इसके लिये नीचे लिखी सावधानियाँ रखनी चाहिये :—

(१) **रजिस्ट्रार—**सहकारिता की उन्नति रजिस्ट्रार की योग्यता, समता और कार्य करने की लगन पर निर्भर है। रजिस्ट्रार सहकारिता की बुनियाद है; इसलिये सरकार इस

*Its report, para 162.

पद पर ऐसे योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया करे, जिनको सहकारिता व ज्ञान के साथ साथ बैंकिंग और व्यापार का भी गहरा अनुभव हो और ग्राम की आर्थिक अवस्था तथा लोगों के रीति रिवाज व आदतों का ज्ञान हो।

(२) ग्रन्थ कर्मचारी—लगभग सभी प्रांतीय बैंकिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कमेटियों ने सहकारिता की असफलता का एक खास कारण यह बतलाया है कि सहकारी का अमला स्वयं सहकारिता के निदान्त, नियम और उसके आदर्श उद्देश्यों से अपरिचित है, इसलिये वह समितियों के मेम्बरों को इनका समुचित ज्ञान नहीं करा सका, अतएव रजिस्ट्रार के आधीन कर्मचारी भी सहकारिता के कानून और सिद्धान्तों से भली प्रकार परिचित होने चाहिये। इन कर्मचारियों का उन लोगों में से चुना जाना ज्यादा ठीक होगा, जिनको ग्राम सुधार की लगन है और जो देश-सेवा के इच्छुक हैं। कर्मचारियों के ज्ञान को सदा नवीन रखने के लिये उन्हें सहकारी विभाग की ओर से आवश्यक साहित्य देना चाहिये और वर्ष में एक बार १५ दिन या १ माह के लिये व्याख्यानो का ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, जिससे वे नवीन बातें मालूम कर सकें।

(३) ग्राम—जिस ग्राम में समिति खोलने की आवश्यकता हो, पहले वहाँ के लोगों का चाल-चलन और व्यवहार देखना चाहिये। यदि उसमें बहुमत भले आदमियों का हो तो उसका सहकारी समिति की स्थापना के लिये चुनना चाहिये अन्यथा नहीं।

(४) मेम्बर—प्रारम्भ में मेम्बरों का चुनाव करते समय पात्र-कुपात्र का ध्यान नहीं रक्खा गया, इसकी वजह से बहुत से खराब मेम्बर आ गये, जिनमें बहुत सा रुपया उलझ गया; अतः भविष्य में नवीन मेम्बर बहुत देख-भाल करके अच्छे, भले और साफ लेन देन करनेवाले लिये जायें।

(५) (अ) उधार—सोसाइटी को अधिक से अधिक उधार लेने की सीमा एक नियमित सिद्धान्त से निश्चित करना चाहिये। यह सीमा समस्त मेम्बरों की पूँजी के $\frac{1}{3}$ भाग से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ब) व्यक्तिगत मेम्बरों को अधिक से अधिक उधार देने की सीमा उनकी कुल पूँजी के ५० प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये।

उधार देते समय ऋण का उद्देश्य चुकाने की शक्ति और अन्य खास-खास बातें ध्यान में रखनी चाहिये।

(स) थोड़ी अग्रिम के वास्ते वर्णित कार्यों के अतिरिक्त अनुत्पादक कामों और व्यर्थ के खर्च के वास्ते ऋण नहीं देना चाहिये। इसके अतिरिक्त उधार लेने की आवश्यकता की अच्छी तरह छान-बीन करनी चाहिये।

(६) मेम्बरों की आपस में एक दूसरे पर इस बात की निगरानी रखनी चाहिये कि ली हुई उधार लाभप्रद कार्यों में खर्च की जाती है या नहीं और साथ ही समय पर सभा का रुपया चुकवाने की चिन्ता भी करनी चाहिये।

(इ) उधार की वापसी की क़िश्तें मेम्बर के चुकाने की यथोचित शक्ति के अनुसार निश्चित करनी चाहिये। ऐसी क़िश्तें तीन वर्ष से अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिये। जब कभी किसी उचित कारणवश, जैसे—फ़सल बिगड़ना आदि, ऋणी ऋण चुकाने में असमर्थ हो तो उसे उचित मोदत देनी चाहिये। किसी प्रकार का अनुचित दबाव डालकर ऋणी को दूसरी जगह से ऋण लाने के लिये विवश नहीं करना चाहिये।

(फ) निरीक्षण—निरीक्षक (auditor) को सभाओं के हिसाबत की जाँच के साथ-साथ नीचे लिखी बातों की विशेष रूप से जाँच करके रिपोर्ट करनी चाहिये :—

(१) सभाओं के नक़शा हैसियत को, उनकी जनरल मीटिंग में और स्वतन्त्र रूप से अनम्बन्धित आदमियों से मालूम करके ठीक जाँच करना। इस सम्बन्ध में जाँच कुनिन्दा को तहरीर करनी चाहिये कि उसने किस आधार पर निर्णय किया है।

(२) जो ऋण वादे पर अदा नहीं हुआ हो, उसकी सविगत रिपोर्ट लिखना और अपना मत लिखना कि वह कदा तक उचित और अनुचित है। साथ ही उसको यह भी प्रकट करना चाहिये कि उसकी वसूली की क्या कार्रवाई चल रही है।

(ज) व्याज—व्याज की दर हलकी होनी चाहिये। आजकल सूद अधिक मात्रा में लिया जाता है, जैसा कि निम्नलिखित कोष्ठक से मालूम होता है :—

व्याज की दर*

प्रान्त	सहकारी समितियाँ		सैंद्रल बैंक	
	ऋण लेने की दर	ऋण देने की दर	कम से कम ऋण लेने की दर	ज्यादा से ज्यादा ऋण देने की दर
मद्रास	७½)	६½	२½ से ७)	८)
बम्बई	६½)	६½	१½ से ७½)	२½ से ६½
बङ्गाल	१०½)	१५)	२) से ८)	३) से १२)
बिहार और उड़ीसा	१०½)	१५½	४) से ८)	७) से १२½)
संयुक्त प्रदेश	१२)	१५)	५) से ७)	१२)
पंजाब	८) से ६)	१२½)	२) से ६½)	६½) से ६)
गुजरात	१०)	१५)	८) से १०)	१०) से १२)
मध्य प्रदेश	१०) से १२)	१२)	४) से ७)	७½) से १२)
आन्ध्रप्रदेश	१०½)	१२½) से १५½)	६½) से ८)	१०½) से १२)

उक्त कोष्ठक से मालूम होता है कि अधिकांश प्रान्तों की सहकारी-समितियाँ अपने सदस्यों से १५ प्रतिशत वार्षिक तक व्याज लेती हैं। सिर्फ बम्बई और मद्रास प्रान्त ऐसे हैं, जहाँ ६½ प्रतिशत वार्षिक व्याज लिया जाता है। यह ठीक है कि यह दर भी साहूकारों की अपेक्षा कम है; किन्तु किसानों की आर्थिक

दशा सुधारने के उद्देश्य से काम करनेवाली संस्थाओं के लिये ये दरें बहुत अधिक हैं, जब कि बैंक रेट ३ प्रतिशत है। धीच की एजेंसियों को अधिक लाभ प्राप्त करने की नीयत से इतना व्याज लेना उचित नहीं है; अतः इन सहकारी बैंकों को अपने छर्चें कम करने चाहिये। हिस्सेदारों को अधिक लाभ बांटने की कोशिश नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत (individual) हिस्सेदारों की स्वार्थपरता को रोकने के लिये ऐसा कानूनी नियम होना चाहिये, जिससे कोई भी सहकारी बैंक ६) प्रतिशत से अधिक लाभ अपने हिस्सेदारों में विभाजित न कर सके। इसके अतिरिक्त सहकारी समितियों को भी अपने मेम्बरों से ६) प्रतिशत से अधिक व्याज हरमिज भी वसूल करने की आज्ञा नहीं करनी चाहिये। यदि सभायें इससे अधिक वसूल करें तो स्थानीय सरकारों को जांच करके उसको कम करना चाहिये। इसके लिये अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं को सरकार का ध्यान आकर्षित करते रहना चाहिये।

सरकारी अफसरों का सहयोग—सहकारी समितियाँ आर्थिक सहायता पहुँचाने के अतिरिक्त दूसरी सामाजिक और शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति में भी बहुत भाग लेती हैं। ये ग्रामों की हर प्रकार से उन्नति करने के लिये सुसंगठित साधन हैं। सरकार को ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति के कार्यों से गहरी दिलचस्पी रहती है, इसलिये उसके तमाम महकमे जात के अफसरान् का कर्त्तव्य है कि सहकारिता के प्रचार और कार्यों में हर समय

श्रीर हर प्रकार से प्रत्येक उचित सहायता देते रहें। इनके सहयोग, सदानुभूति और उत्साह का ग्रामीण जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। बिना इनके, खास कर जिला अफसरों के सहयोग न इनके प्रचार में यथोचित सफलता नहीं हो सकती। जहाँ कहीं दूसरे जिला अफसरों और सहकारी विभाग के अफसरों न बीच में निजी या सरकारी तौर पर किसी भी बात पर मतमुटाव हाता है, वहाँ सहकारिता के प्रचार में बड़ी बाधा पहुँचती है। इसमें अफसरों में से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ग्रामोन्नति के कार्य में रुकावट आती है और कृषकों को भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है, अतएव कृषि रोयल कमीशन के शब्दों में “हम यह बहुत आवश्यक समझते हैं कि स्थानीय सरकारें अपने तमाम महकमे जात के अधिकारियों पर जोर डालें कि वे सहकारिता के प्रत्येक कार्य में व्यावहारिक रूप से और पूर्ण दिलचस्पी के साथ भाग लें”।*

सार्वजनिक सेवकों का सहयोग—जो लोग देश सेवा करने के लिये उत्सुक ह, उनको चाहिये कि वे सहकारी विभाग के सहयोग से सहकारिता के प्रचार में सहायक बनें। भारत, ग्रामों में बना हुआ है, इसलिये देश सेवा का सर्वोत्तम स्वरूप ग्राम-सेवा है। ग्रामीण जनों में विद्या का अभाव है, इसलिये उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। वे भोल हैं और अन्धकार में सोये हुए हैं। महकमारी समितियाँ उन्हें उठाकर प्रकाश में लाने का

* Its report, para 380

प्रयत्न कर रही हैं, इनके द्वारा ग्रामीण जनों का संगठन बना-बनाया मिलता है, सेवा के सब प्रकार के साधन उपलब्ध होते हैं, लेकिन इनमें विशुद्ध सेवा-भाव का अभाव है; इसलिये इनको पूरी सफलता नहीं मिल रही है। यह सारा धन्धा राजकर्मचारियों के आधीन है, जिनमें न सेवा-भाव है, न सुधार की लगन, केवल राजसत्ता का अहंकार है, इसलिये प्रत्येक कार्य दूसरे विभागों के समान राज-काज की तरह होता है। यदि देश के सच्चे सेवक, बालू राजनीति से दूर रहकर ग्राम-सेवा के इस ठोस, शान्त और आपत्ति-रहित कार्य में लग पड़ें तो सहकारिता की दूर भागती हुई सफलता जल्दी-जल्दी समीप आ सकती है। सहकारी और विभाग के कर्मचारी सच्चे और शान्त सेवकों की सेवाओं का बड़ी प्रसन्नता से स्वागत करते हैं और करेंगे। मद्रास, बम्बई, पंजाब आदि प्रान्तों में अवैतनिक कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने संघ बना रखे हैं, जो प्रान्तीय-सहकारी संघ या इसके तद्वरूप नामों से प्रसिद्ध हैं। सहकारी-विभाग उनसे पूरा-पूरा सहयोग रखता है। ऐसे सेवा-संघ बहुत थोड़े हैं। इनकी अधिक आवश्यकता है। देश के कष्ट-रहित सेवा करनेवाले नवयुवकों को चाहिये कि इस ओर ध्यान दें और देश की सच्ची सेवा का पुण्य कमावें।

यदि सरकार, उसके कर्मचारी, सहकारी विभाग और सार्वजनिक कार्यकर्ता, चारों मिलकर लगन से सहकारिता के प्रचार में जुट पड़ें तो इसकी सफलता निश्चित है। इनमें से एक

का भी सहयोग प्राप्त न होने पर इसकी सफलता में बाधा उपस्थित होना सम्भव है।

समय पर अदायगी न होने का प्रश्न—सहकारिता की असफलता का प्रमुख कारण यह बतलाया जाता है कि समाजों के सदस्यों पर ऋण प्रतिदिन बढ़ता जाता है और रुपया ठीक समय पर जमा नहीं होता, यह सत्य है। सन् १९२८-२९ ई० में समस्त अदा होने-योग्य ऋण की २१३ प्रतिशत रकम वाकी रही थी, सन् १९२९-३० ई० में यह रकम और बढ़कर २४८ प्रतिशत हो गई। यह दोष सहकारी-समितियों के जन्म-काल से ही चल पड़ा है और अब इसने इतना भीषण रूप धारण कर लिया है कि सहकारिता की असफलता का सारा कलक इसी के सिर मँढ़ा जाता है, जैसा कि मेरुलैंगन रुमेटी ने लिखा है—

There is no defect more prominent or more dangerous in the management of cooperative societies in India than the exceeding laxity and unpunctuality in the repayment of loans.....unless loans are repaid punctually, cooperation is both financially and educationally an illusion अर्थात्—भारत की सहकारी-समितियों के प्रबन्ध में, अदायगी में सुस्ती होने के अतिरिक्त, दूसरा कोई प्रमुख और भयंकर दोष नहीं है। जब तक अदायगी ठीक समय पर

॥ होगी तब तक सहकारिता, अर्थ और शिक्षा दोनों दृष्टि से इन्द्रजाल के समान बनी रहेगी । *

यह बात पंद्रह वर्ष पहले की है । इसके बाद जितने कमीशन और कमेटियों ने सहकारिता के प्रश्न पर विचार किया, सबने इसकी भयंकरता को स्वीकार करते हुए समय पर यत्नपूर्वक वसूली करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को जोरों के साथ चेतावनी दी है । सर के० एम० मेफडोनलड (इम्पीरियल बैंक के गवर्नर) ने तो यहाँ तक लिखा है कि जो मेम्बर समय पर रुपया अदा न करे, उससे मेम्बरी के लाभ छीन लिये जावें और जो सभा रुपया अदा न करे, उसको तोड़ दिया जावे । हमारी राय में सर मेफडोनलड का कथन अव्यावहारिक है । यह उपाय उस समय सफल हो सकते हैं, जब कृपन देने में समर्थ हों और न देते हों । ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन आम तौर पर नहीं होता । वास्तव में बात तो यह है कि कृपों के पास इतना पैदा ही नहीं होता कि वह कृषि-सम्बन्धी खर्च निकालकर श्रृंग चुकाने के लिये कुछ बचा सकें, क्योंकि अब कृषि का धन्य लाभ का नहीं, किन्तु घाटे का रह गया है ।

कृषि घाटे का धन्धा है—भारतवर्ष में कृषक-परिवार के पास बहुत अल्प भूमि (Small holdings) होती है । वह भी संस्था प्रकृति देवी की कृपा पर निर्भर है । कभी वर्षा होती है,

* Coop Movement in India, by Eleanor M. Hough, page 228

कमी नहीं होती और कमी आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो कमी ओले पड़ जाते हैं। अगर इन्द्र भगवान नहीं रुठते हैं तो कमी टिड्डी दल, गेरिया आदि कृषि-शत्रुओं का दौरा हो जाता है और फसल चौपट हो जाती है; इसलिये भारतवर्ष ऐसा अभाग्य देश है, जहाँ पैदावार का औसत सबसे कम है। इस सम्बन्ध में जयपुर-निवासी श्री होरालाल जी शास्त्री, जो सच्चे ग्राम सेवक हैं, अपना स्वयं का अनुभव वर्णन करते हुए लिखते हैं, “भारतवर्ष में खेती लाभदायक व्यवसाय नहीं रहा है। यह सुनी हुई बात थी, जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, दानों साल की खेती में ६७-७७ का नुकसान रहेगा और कृषि विभाग में सहायक कार्यकर्त्ताओं का घेतन २०० के लगभग अलग। हमारा कृषि विषयक अनुभव चित्त को भयभीत करनेवाला है, खेती का व्यवसाय इतना निराधार हो गया है कि किसान ही की हिम्मत है कि वह इसे लिये बैठा है, अथवा दूसरा उपाय नहीं है, इसलिये लिये पड़ा होगा।”*

सेण्ट्रल बैंकिंग इन्वाइरी कमेटी ने एक कृषक की आमदनी का औसत सन् १९२८-२९ के मूल्याधार (Price level) पर ४२ लगाया है। इसके बाद कृष्युत्पादक वस्तुओं का मूल्य ५० प्रतिशत के लगभग गिर गया है, इसलिये आजकल एक कृषक की आमदनी २१ होती है। पुरच का हिमाय लगाते हुए

* जीरन कुटीर वनस्पती P O Niwai (Jaipur) का प्रथम कार्य-विवरण, पृष्ठ ८।

मि० के० टी० शाह ने अपनी पुस्तक (Sixty years of Indian finance) में लिखा है कि भारत में एक क़ैदी की खुराक का खर्च, जो बहुत हलके वर्ज की शरीर और आत्मा को कायम रखने के लिये दी जाती है, ६०) होता है। यह औसत १० वर्ष पहले का है। इस समय इस खर्च का आधा भी गिना जाये तो ४५) प्रति मनुष्य पीछे केवल खाने में खर्च होता है, कपड़ा-लत्ता, बीड़ी-सम्बाकू और छतरी, जूता इसमें शामिल नहीं है, व्याह और ग़मी के खर्च भी इससे अलग होते हैं। इस हालत को देखकर पाठक स्वयं सोच सकते हैं कि जब आमदनी से खर्च तिगुना और चौगुना हो और जिसको किसी भी तरह से कम नहीं किया जा सकता हो, ऋण का उत्तरोत्तर बढ़ना कौनसी आश्चर्य की बात है और इसमें कृपकों का क्या दोष है।

ऋण का भारी बोझ—घाटे का व्यवसाय करते-करते कृपकों पर न केवल सहकारी समितियों का ऋण बढ़ा है, बल्कि दूसरे तरीकों से भी बहुत ऋण हो गया है और उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इसकी अधिक वृद्धि अंगरेज़ी साम्राज्य स्थापित होने के बाद और विशेष कर पिटुली अर्धशताब्दी के अन्दर हुई है। सेण्ट्रल बैंकिंग इन्क्वाइरी कमेटी सन् १९३० ई० ने भारत के समस्त किसानों के ऋण का औसत ६०० करोड़ रुपया लगाया है। श्री० जमना-दास एम० मेहता ने २८ अक्टूबर, सन् १९३३ ई० में होनेवाले डेमोक्रेटिक स्वराज्य पार्टी के धर्म्वई-अधिवेशन के स्वागतार्थ्यत के पद से भाषण देते हुए, कृपकों के कुल ऋण का अनुमान

१२०० करोड़ रुपया लगाया है। इसका व्याज १२ प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से १४४ करोड़ के लगभग होता है। समस्त भारत की मालगुजारी की आमदनी का वार्षिक औसत लगभग ३५ करोड़ रुपया है अर्थात् रुपकों पर व्याज का बोझ मालगुजारी के बोझ से चौगुना है। ऐसी अवस्था में सहकारी-समितियों का बड़ा हुआ ऋण एक दम वसूल नहीं हो सकता। इस प्रश्न पर दिल्ली कोआपरेटिव कॉन्फ्रेंस सन् १९३४ ई० ने बहुत विचार किया है और उसने सिफारिश की है कि मौजूदा छोटी अवधि के ऋण का लम्बी अवधि के ऋण में परिवर्तन कर दिया जावे और वार्षिक क्रिस्तों से वसूल किया जाय। इसके साथ-साथ उक्त कॉन्फ्रेंस ने यह भी प्रस्ताव किया है कि सहकारी बैंक और समितियों को इस ऋण पर अपने व्याज की वर्तमान दर भी कम करनी चाहिये। वास्तव में वर्तमान बड़े हुए ऋण की आसानी से वसूली का इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है; लेकिन ऐसा करने से सहकारी बैंकों की समितियों में लगी हुई रकम का बहुत बड़ा भाग अटक जायेगा और व्याज कम करने से इनको गहरी हानि होगी, इसलिये इसकी पूर्ति के वास्ते प्रान्तीय सरकारों को सहकारी बैंकों की, कम सूद पर रुपया उधार देकर, सहायता करनी चाहिये।

बड़ी कठिन समस्या—एक ओर तो रुपि का धन्धा घाटे का है, दूसरी ओर रुपकों पर भारी ऋण है। इससे रुपकों की दशा अति शोचनीय हो गई है। इस सम्बन्ध में रुपि रॉयल-कमीशन

और भारतीय सेंट्रल तथा प्रान्तीय बैंकिंग इंकवाइरी कमेटियों का मत है कि यह जटिल समस्या केवल सुलभ और सस्ती उधार के साधन उपलब्ध होने से नहीं सुधर सकती, क्योंकि अंग्रेजी उधार घाटे के धन्धे को लाभ में परिवर्तन नहीं कर सकती, इसको हल करने के लिये पहले किसानों को ऋण-मुक्त करना चाहिये, लेकिन स्थायी लाभ के लिये यह भी पर्याप्त नहीं है, जब तक कि इनकी आय बढ़ाने और खर्च घटाने के उपाय नहीं किये जायें।

ग्रामवनी बढ़ाने के लिये इनकी भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों को मिलाकर एक करना, उपज बढ़ाने का उपाय करना, खेती के अतिरिक्त दूसरे एक दो सहायक धन्धे करना सिखाना और उनके लिये उपयुक्त साधन उपस्थित करना आदि प्रयत्न करने की आवश्यकता है। खर्च कम करने के लिये खेती के योग्य भूमि का उचित परिमाण हो, उसकी मालगुजारी की दर निश्चित करने के लिये उपयुक्त और ठोस प्रणाली निश्चित की जावे। सामाजिक अनावश्यक खर्च न करने के लिये उपदेश-द्वारा विचार परिवर्तन किये जावें और विशेष कर शिक्षा का प्रचार किया जावे, जिससे कृषक दानि-लाभ समझने और धोखेबाज़ लोगों से बचने में समर्थ हों।*

* कृषकों को ऋण-मुक्त करने और इनकी आय बढ़ाने तथा खर्च घटाने के उपाय देखने के "कृषि सुधार-योजना", नामक छोटी पुस्तक (Pamphlet) में थलगा बताये हैं।

तेरहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—भूमि-बन्धक बैंक

कृषकों को लम्बी अवधि के लिये सहायता की भारी आवश्यकता है। इसके बिना कृषक-समुदाय की अर्थ-सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी नहीं हो सकतीं। भारत में लम्बी अवधि के लिये उधार देने के वास्ते साधन उपस्थित करने के लिये सरकार-द्वारा नियत की गई कई कमेटियों ने पूर्ण विचार किया है और उन सबकी सम्मति है कि कृषि को लम्बी अवधि के लिये उधार देने के वास्ते विशेष प्रकार की संस्थाएँ 'भूमिबन्धक बैंक' स्थापित होने चाहिये।

भारत के अनुकूल प्रणाली—भारत में इस समय कुछ प्रान्तों में सहकारी-भूमि-बन्धक बैंक स्थापित हैं, किन्तु वे अभी बहुत छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। से० बै० इ० कमेटी ने छोटे कृषकों के लिये तो सहकारी-भूमि-बन्धक बैंक ही उपयुक्त बताया है और बड़े-बड़े जमींदारों के लिये ज्याइएंट स्टॉक भूमि-बन्धक बैंक स्थापित करने की सलाह दी है।

जहाँ तक थोड़ी अवधि की उधार का प्रश्न है, सहकारी सिद्धान्त बहुत ही उपयुक्त है, लेकिन लम्बी अवधि के लिये इस सिद्धान्त को अपनाने से यथोचित सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि कभी-कभी यह हानिप्रद सिद्ध हो सकता है,

क्योंकि सहकारी-समितियों का संगठन असीमित और पार-स्परिक जिम्मेवारी के आधार पर होता है। लम्बी अवधि की उधार के लिये जिम्मेवारी लेना घातक है। भूमि-बन्धक बैंकों के द्वारा इतने लम्बे समय के लिये उधार दी जावेगी, जो मनुष्य की औसत आयु से अधिक हो सकता है; इसलिये यह बहुत कठिन है कि लोग इतनी लम्बी अवधि के लिये सम्मिलित और पृथक् पृथक् जिम्मेवारी लेने को तैयार हो जावें। इस विषय को देखते हुए भूमि-बन्धक बैंकों का संगठन ज्वाइंट स्टॉक-प्रणाली पर होना ज्यादा उपयुक्त मालूम होता है। इसके लिये भारत के समस्त प्रान्तों में एक-एक प्रान्तीय भूमि-बन्धक बैंक होना चाहिये, जो आवश्यकतानुसार उस प्रान्त में अपनी शाखाएँ खोलकर या सहकारी-सेंट्रल बैंकों के द्वारा उस प्रान्त के इच्छुक किसानों को लम्बी अवधि के लिये उधार देता रहे। उसका संगठन इस प्रकार होना चाहिये :—

प्रान्तीय भूमि-बन्धक बैंकों का संगठन*

मूलधन—प्रत्येक प्रान्तीय बैंक का मूलधन २५ लाख रुपया होना चाहिये, जो १००) प्रति हिस्से के हिसाब से २५ हजार हिस्सों में विभक्त किया जावे। ये हिस्से दो श्रेणियों—'अ' और 'ब' में विभक्त किये जावें :—

* यह स्कीम इण्डियन फ्राइडेंस के बैंडिंग इन्क्वायरी ग्रंथ में प्रकाशित Land mortgage bank शीर्षक खंड से ली गई है।

(१) 'अ' श्रेणी के हिस्सों की रकम, २५) दण्डास्त के साथ, २५) स्वीटन होने पर, शेष एक वर्ष के अन्दर अन्दर दो किरातों में वसूल का जावे। इन श्रेणी के हिस्से जनता, बैंक और कोओपरेटिव सासाइटीज आदि सबको दिये जाने चाहिये, इसलिये इम्पीरियल बैंक, रिजर्व बैंक, बड़े बड़े ज्वाइट स्टॉक बैंक, जो उस प्रान्त में काम करते हैं और प्रान्तीय कोओपरेटिव बैंक आदि को अच्छी सख्या में हिस्से खरीदने के लिये उत्तेजित करना चाहिये। हिस्से बेचना प्रारम्भ करने की तारीख से दस महीने के अन्दर अन्दर कुल हिस्से न बिकें तो प्रान्तीय सरकारों को चाहिये कि यच्चे हुए हिस्से खरीद लें।

(२) 'अ' श्रेणी के हिस्सों के द्वारा सगृहीत पूँजी के अतिरिक्त धन बढान के लिये प्रत्येक उधार लेनेवाले के लिये यह अनिवार्य है कि वह उधार ली हुई रकम के ५ प्रतिशत के हिस्से खरीदे और एसी रकम उधार दी जानेवाली रकम में से वसूल की जाय। इस प्रकार के हिस्से 'ब' श्रेणी के होंगे। इनसे बैंक का धन्य बढन के साथ-साथ मूलधन भी बढता जायगा।

हिस्सेदारों का अधिकार—'अ' श्रेणी के हिस्सेदार बैंक के असली मालिक होंगे। उनको डाइरेक्टर चुनने, लाभ निश्चित करने और दूसरे खास-खास मामलों में निर्णय करने का अधिकार होगा, लेकिन उनका हिस्सों पर लाभ मिलने के अतिरिक्त दूसरा कोई फायदा नहीं मिलेगा। 'ब' श्रेणी के हिस्सेदार जनरल-मीटिंग में शामिल हो सकेंगे और वादविवाद

में भाग ले सकेंगे, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं होगा, वे केवल परामर्श-समिति नियुक्त कर सकेंगे, जो बोर्ड को नमय-समय पर उनके हितों की रक्षार्थ उचित बातें सुझाती रहेंगी।

बोर्ड का संगठन—बोर्ड के कुल १२ डाइरेक्टर होंगे, जो इन प्रकार चुने जायेंगे :—

(१) चार डाइरेक्टर 'अ' श्रेणी के हिस्सेदारों-द्वारा—ऐसे डाइरेक्टर वही लोग चुने जायेंगे, जिनके पास ५ हजार के हिस्से होंगे।

(२) एक डाइरेक्टर प्रान्तीय को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से—ऐसा बैंक कम से कम ५० हजार रुपये के हिस्से खरीदेगा।

(३) एक प्रान्त के तमाम व्यावसायिक बैंकों की ओर से—इसके लिये वही बैंक मत दे सकेगा, जिसके पास १०००० के हिस्से खरीदे हुए होंगे।

(४) एक रिजर्व बैंक की ओर से—इसके लिये रिजर्व बैंक को कम से कम १,००,००० रुपये के हिस्से खरीदने होंगे।

(५) एक डाइरेक्टर प्रान्तीय धारा सभा से।

(६) दो सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा, जिनमें एक गैर सरकारी होगा।

(७) एक डाइरेक्टर ऑब् एग्रीकल्चर या दूसरा प्रमुख सरकारी अफसर, जो भूमि सम्बन्धी मामलात से सम्बन्ध रखता हो Exofficio डाइरेक्टर होगा।

(८) एरु लैंड-क्रेडिट बोर्ड (Land Credit Board) द्वारा—इसके लिये आगे वर्णन किया गया है।

बैंक अपना चेयरमैन स्वयं चुन सकेगा। मद् नं० २ से ८ तक में वर्णित डाइरेक्टरों की अवधि २ वर्ष की होगी। मद् नं० १ में वर्णित डाइरेक्टरों की अवधि ४ वर्ष की होगी। इनमें एक डाइरेक्टर प्रति वर्ष अलग होता जावेगा, लेकिन उसका पुनः निर्वाचन भी हो सकेगा।

प्रबन्ध—भूमि बन्धक बैंक का संचालन ऐसे वैतनिक मैनेजर-द्वारा होगा, जिसको बैंकिंग और आर्थिक स्थितियों का पर्याप्त अनुभव होना और बैंक का, सफलता-पूर्वक संचालन करने के लिये भारत एवं विदेशों के प्रमुख प्रमुख व्यापारिक केन्द्रों को मुद्रा (Monetary) और स्टॉक सम्बन्धी बाजारों की गति का पूरा-पूरा ज्ञान होना। इसकी नियुक्ति डाइरेक्टरों के हाथ में होगी, लेकिन उसकी स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल से ली जावेगी। मैनेजर के आधीन अफसर भी ऐसे नियुक्त किये जायेंगे, जिन्हें कृषि और भूमि का मूल्य निर्धारित करने, प्रबन्ध करने और तत्सम्बन्धी कानूनी अधिकारों का ज्ञान होगा।

उधार—यह बैंक निम्नलिखित कामों के लिये उधार दे सकेगा :—

१—भूमि में स्थायी उन्नति करने के लिये।

२—नयीन भूमि में खेतों करने के लिये (re-clamation of land)।

३—पुराने ऋण को चुकाने के लिये ।

४—भूमि खरीदने के लिये ।

५—ऐसे काम बढ़ाने के लिये, जो भूमि की उपज बढ़ाने में सहायक हों; जैसे—नहर या बाँध बनाना ।

६—खेती की उपज में वास्तविक सुधार करने के उद्देश्य से खेती के काम के लिये मशीनें और अन्य आवश्यक औज़ारों के खरीदने के लिये ।

इस दिये हुए ऋण के सम्बन्ध में बैंक यह देखता रहेगा कि लिया हुआ ऋण ठीक उसी काम में खर्च किया जाता है, जिसके लिये कि मंजूरी दी गई है । जब कभी आवश्यकता हो, खरीद किये हुए सामान व भूमि का खर्चा ऋण लेनेवाले की ओर से बैंक स्वयं चुकावे ।

उधार की ज़मानत—उधार दी हुई रकम की ज़मानत में जायदाद रहन रहेगी । इसमें ज़मींदारों (land lords) और भूमि के मालिकों के लिये कोई अड़चन नहीं आती । केवल किरायेदारों का उपयोगाधिकार (occupancy right) को सहकारी-समितियों और भूमि-बन्धक बैंकों के नाम बेचे जाने और परिवर्तन किये जाने के लिये क़ानून में उचित संशोधन होने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त किरायेदारों (tenants) को दिये हुए ऋण को उन सहकारी-समितियों और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंकों की ज़िम्मे-दारी (Endorsement) से सुरक्षित रखा जाना चाहिये, जिनके द्वारा किरायेदार कृषक दरखास्तें भिजवाया करें । ज़मींदारों

और भूमि के मालिकों की दरखास्तें सीधी भी ली जा सकती हैं और उनको सम्मति प्राप्त करने के लिये सहकारी-समितियाँ और सेंट्रल-कोऑपरेटिव बैंकों में भेजा जा सकता है ।

मार्जिन—उधार, भूमि की बाज़ार कीमत का ५० प्रतिशत या वार्षिक खरी पैदावार के दसगुना (इसका औसत पिछले ५ वर्षों की पैदावार से लिया जावेगा) से जो कम होगी, दी जायगी । किरायेदारों का उनकी दस वर्ष की खरी वचन के औसत में से उनके गुज़ारे का सवर्च घटाने पर जो बचेगा, उसके दसगुना से अधिक नहीं दिया जावेगा ।

भूमि का मूल्य निर्धारित करने का आधार यह होना चाहिये :—

१—पिछले ५ वर्षों की खरी पैदावार के औसत और उसी समय उस व्याज की दर के औसत से, जिस पर भूमि-बन्धक बैंक ने उधार दिया हो । प्रारम्भ में इसके लिये इम्पीरियल बैंक और बाद में रिज़र्व बैंक के बैंक-रेट का औसत लेना चाहिये ।

२—आस-पास की भूमि की विक्री के औसत से—इस प्रकार औसत निकालते समय भूमि की मिश्र-भिन्न श्रेणियों, तथा अन्य उपयोगिताओं; जैसे—रेलवे स्टेशन या मंडी का नज़दीक होना आदि और पैदावार की विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिये ।

उक्त वर्णित आधार भूमि की सही कीमत जानने के लिये कसौटी के रूप में है। यदि अन्य कोई कारण ऐसे हो, जिनका भविष्य में भूमि की कीमत पर अच्छा या बुरा असर पड़ता हो तो कीमत का निश्चय करते चक्र उनको भी गिनना चाहिये।

ऋण की वापसी बराबर की वार्षिक या छ माही किश्तों के द्वारा हानी चाहिये। वार्षिक किश्त ब्याज की रकम के ऊपर १ प्रति शत से अधिक नहीं होना चाहिये।

अवधि—ऋण की वापसी की अवधि जमींदारों और भूमि के मालिकों के लिये साधारणतया ५० वर्ष और किरायेदारों के लिये २५ वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

कार्यकारी पूँजी प्राप्त करने के तरीके—बैंक नीचे लिखे अनुसार पूँजी संग्रह कर सकता है :—

(अ) अमानतें और सेविंग्स-सर्टीफिकेट-द्वारा—
इस बैंक को ५ वर्ष से कम की मियाद के लिये जमा स्वीकार नहीं करना चाहिये। इसे सेविंग्स सर्टीफिकेट भी ५, १०, १५ वर्ष या इससे लम्बी अवधि के लिये जारी करने का अधिकार होना चाहिये, लेकिन कुल जमा और जारी किये हुए सेविंग्स-सर्टीफिकेट की इकजाई रकम बैंक के मूलधन और रक्षित फण्ड के दसगुने से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ब) डिबेन्चर—यह बैंक अपनी जनरल पूँजी भी जमा नत पर debentures भी जारी कर सकता है।

(स) उधार—यह बैंक अन्य साधनों के साथ-साथ अपनी जंगल पूँजी को ज़मानत पर दूसरे बैंकों, सरकार और विदेशी बाज़ारों से भी उधार ले सकता है ।

सरकारी सहायता—पहले कुछ वर्षों के लिये आवश्यक है कि डिबेन्चर की रकम की अदायगी को पूरा करने के लिये सरकार गारंटी लेवे ।

क़ानूनी सुविधायें—बैंक अपने धन्य को सस्ता और सुगमता-पूर्ण चला सके और साथ ही यह दुःखदायी मुकद्दमे-बाज़ी से बच सके । इसके लिये निम्नलिखित क़ानूनी सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये—

(१) भूमि-बन्धक बैंकों के debentures ट्रस्टी सिन्डिकेटों में गिने जावें और उनको सरकारी महकमों में ज़मानतों के लिये स्वीकार किया जावे ।

(२) स्टाम्प ड्यूटी, फ़ोस रजिस्ट्री आदि सब सहकारी समितियों की भाँति माफ़ होना चाहिये ।

(३) बैंक, स्थानीय पत्र और सरकारी गज़ट में प्रकाशित कराकर और दफ़्तर रजिस्ट्री में नोटिस चिपकाकर सर्वसाधारण का यह सूचित करेगा कि वह अमुरु-अमुरु भूमि को रहन-रक़र रुपया उधार दे रहा है । जिस किमी को उम जायदाद पर अधिकार और स्वत्व-सम्बन्धी कोई उज्र हो तो उसको चाहिये कि तीन महीने के अन्दर-अन्दर बैंक का सूचित कर दे । इससे

चुक्ने पर बैंक के पक्ष में होनेवाले रहन का, सब प्रकार के लेने-देने से, (बिना किसी लिहाज़ के) प्रथम हक होगा ।

इस सम्बन्ध में बैंक रुपया देने से पहले प्रत्येक सावधानी बरतने की कोशिश करेगा और यह मालूम करेगा कि उधार लेनेवाला उस जायदाद को रहन रखकर उधार लेने का अधिकारी है कि नहीं और जो जायदाद वह रहन रख रहा है, हर प्रकार के भगडों-टंटों से बरी है और उसके सम्बन्ध में अदालत में कोई भगडा तां नहीं है; लेकिन उक्त धर्णित नोटिस देना बैंक के हितों की रक्षार्थ अन्तिम और पर्याप्त साधन माना जायगा ।

(४) बैंक को यह अधिकार होना चाहिये कि ऋणी की प्रतिभा भग होने पर रहन-शुदा जायदाद को बिला अदालती कार्रवाई किये अपने कब्जे में ले सके । राहिन के किसी प्रकार का विरोध करने पर निकटवर्ती अदालत, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जमीन हो, का फर्त्तव्य होगा कि बैंक की ओर से सादी दरदस्ता प्राप्त होने पर कब्जा दिलाये जाने की कार्रवाई करे । इसके लिये बैंक को कोर्ट-फीस माफ़ होना चाहिये ।

(५) समय पर रुपया न चुक्ने की हालत में बैंक को अधिकार हो कि वह रहन शुदा जायदाद का खुद प्रबन्ध कर सके, उसको बेच सके और किराये पर उठा सके ।

(६) बैंक के हिसाबत की नकलें कर्ज़ के औचित्य और जायदाद के प्रबन्ध की गवाही में सही स्वीकार की जावेंगी ।

(७) उपरोक्त रिशायतों के अतिरिक्त बैंक को हर प्रकार के टैक्स व लागतों की भागी होनी चाहिये ।

लाभ का विभाजन और रिजर्व फंड—बैंक का खरा लाभ इस प्रकार विभाजित होना चाहिये —

(अ) दस प्रतिशत रक्षित कोष में, जब तक कि यह मूल-धन के बराबर न हो जावे ।

(ब) शेष में से ५ % लगातार बढ़नेवाले लाभ (Cumulative) में, जो 'अ' श्रेणी के हिस्सों पर बाँटा जायगा । ५ % सादा (non-Cumulative) लाभ में, जो 'ब' श्रेणी के हिस्सों पर बाँटा जायगा वगैरह कि :-

(१) सरकार की कोई रकम ऐसी देनी न हो, जो उसने गारण्टी के अनुसार बैंक के debentures के चुकाने में दी हो या इसके लिये बैंक को उधार दी हो ।

(२) प्रतिज्ञा भग होने पर बैंक-द्वारा ग्राहकों ने खरीदी हुई जायदाद, उसके मूलधन व रक्षित फंड के बराबर और उससे अधिक शेष न रही हो ।

(३) उस कर्जों की तादाद, जिसके समय पर न चुकाने के कारण बैंक ने जायदाद का इन्तिजाम अपने हाथ में लिया हो, उसके मूलधन और रक्षित कोष के ५% से अधिक न हो ।

(४) नं० २ व ३ के अनुसार उलझी हुई कुल रकम की तादाद उसके मूलधन और रक्षित कोष की तादाद के बराबर या उससे अधिक न हो ।

(स) शेष लाभ बराबर-बराबर दो भागों में विभक्त होगा। एक भाग सरकार को दिया जावेगा और दूसरा हिस्सेदारों में बाँटा जावेगा। सरकार बैंक के देने की जिम्मेवारी लेती है, इसलिए उसका बैंक के लाभ में भाग लेना उचित है।

(द) मद् न० 'स' के अनुसार हिस्सेदारों में विभक्त होने वाले लाभ के तीन भाग होंगे। दो भाग 'अ' श्रेणी के और एक भाग 'ब' श्रेणी के हिस्सेदारों में बाँटा जायगा। 'अ' श्रेणी के हिस्सों के लिये यह रिआयत हिस्सा खरीदन के लिये लोगों का उत्तेजित करने के वास्ते नहीं है, बल्कि आर्थिक सिद्धान्तानुसार है। 'अ' श्रेणी के हिस्सों की पूँजी सर्वप्रथम और एक दम सग्रह होगी और वह अरेली ही बैंक का काफी काम बढ़ावेगी। 'ब' श्रेणी के हिस्सों की रकम धीरे-धीरे आवेगी। इनकी अधिक रकम उस वक्त सग्रह होगी, जब 'अ' श्रेणी के हिस्सों के कारण पर्याप्त मात्रा में रक्षित कोष जमा हो जायगा। ऐसी अवस्था में 'अ' श्रेणी के हिस्से अधिक लाभ पाने के अवश्य अधिकारी हैं।

लैंड-क्रेडिट-बोर्ड—समस्त प्रान्तीय भूमि वन्धक बैंक, लैंड-क्रेडिट-बोर्ड नामक एक संस्था के समान रूप से आधीन रहेंगे। इस बोर्ड को प्रान्तीय बैंकों के सब प्रकार के काम का निरीक्षण और नियंत्रण करने का पूर्ण अधिकार रहेगा। यह समय-समय पर बैंकों को मार्गनिर्देश के लिये सूचनाएँ देता रहेगा और अपने प्रभाव द्वारा सब बैंकों की नाति,

कार्य प्रणाली और व्यवहार को एक समान रखने का हर प्रकार से प्रयत्न करेगा ।

बोर्ड का तमाम व्यय भूमि-बन्धक बैंक, प्रान्तीय सरकारें और भारत-सरकार किसी उचित आधार पर चलावेंगे ।

बोर्ड में छः मेम्बर और एक सैक्रेटरी होगा । सैक्रेटरी एक अनुभवी बैंकर और अर्थशास्त्री होगा, जिसकी नियुक्ति बोर्ड से ओग स्वीकृति सपरिषद् गवर्नर जनरल-द्वारा होगी ।

मेम्बरों का कार्य-काल ३ वर्ष होगा; परन्तु कार्य व नीति को निरन्तर चलाये रखने के लिये दो मेम्बर प्रतिवर्ष वृत्तक्रम से अलग होते जावेंगे । बोर्ड अपने जलसे, जिस प्रकार और जब भी आवश्यक हो, करेगा; परन्तु कम से कम ३ मास में एक जलसा आवश्यक होगा । बोर्ड अपना चेयरमेन स्वयं चुनेगा ।

बोर्ड के छः मेम्बरों का चुनाव इस प्रकार होगा :—

- (अ) एक मेम्बर—सपरिषद् गवर्नर जनरल द्वारा ।
- (ब) एक मेम्बर—केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा द्वारा ।
- (स) एक मेम्बर—प्रान्तीय सरकारों-द्वारा ।
- (द) एक मेम्बर—प्रान्तीय भूमि बन्धक बैंकों द्वारा ।
- (ह) एक मेम्बर—ज्वाइंट स्टॉक, विनिमय, इम्पीरियल, प्रान्तीय कोओपरेटिव बैंक्स द्वारा—इसके लिये प्रत्येक बैंक को एक मत देने का अधिकार होगा और इसके लिये प्रत्येक

बैंक के पास २०-२० हजार के हिस्से और एक-एक लाख के डिबेंचर होना आवश्यक हैं । ऐसे मेम्बर के लिये रिज़र्व बैङ्क की स्वीकृति होना चाहिये ।

- (फ) एक मेम्बर या सेक्रेटरी—भारत-सरकार-द्वारा वह व्यक्ति होगा, जिसको भूमि, कृषि और आर्थिक समस्याओं का ज्ञान होगा और जो एक्स-ऑफिशो मेम्बर समझा जावेगा ।
-

चौदहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—औद्योगिक वैङ्क

परम कृपालु परमेश्वर ने भारत को सब प्रकार की निधियाँ, अपरिमित रूप से प्रदान की हैं। यहाँ पर कच्चे माल की बाहुल्यता है, भूमि-माना का गर्भ गाना प्रकार के खनिज पदार्थों से भरपूर है। इस कच्चे माल को निकालकर बनी हुई वस्तुओं में परिवर्तन करने के लिये अनेक कारखानों की ओर उनको चलाने के लिये अपरिमित धन की आवश्यकता है।

भारत में धन की कमी नहीं है। यहाँ इस समय भी अनेक कल, कारखाने और मिलें चल रही हैं। उन सबको पूँजी मिल रही है और वह काम कर रही हैं, लेकिन नियमित रूप से औद्योगिक आर्थिक सहायता का समुचित प्रबन्ध नहीं है; इसलिये करोड़ों रुपये का कच्चा माल विदेशों को जाता है और यहाँ से बनी हुई वस्तुयें यहाँ आती हैं। इसमें सुदूरस्थ स्थानों से माल के आने-जाने का खर्च पड़ता है, यहाँ की मजदूरी पड़ती है। लेने, भेजने, धनाने, भँगाने और बेचनेवाले दुकानदारों का लाम मिश्रित होता है। यह सब भारत और उसकी सर्वसाधारण जनता को भुगतना पड़ता है और यहाँ के करोड़ों लोग बेकार रहते हैं। यदि औद्योगिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने की सुव्यवस्था हो जाय तो बहुत-कुछ अंश में भारत में

उद्योग-धंधे बढ़ सकते हैं। इस सम्बन्ध में इंडस्ट्रियल कमीशन ने पर्याप्त विचार किया है और उसने औद्योगिक (Industrial) बैंक स्थापित करने की सलाह दी है। इसके लिये प्राइवेट प्रयत्न सफल नहीं हुए हैं, इसके लिये टाटा इंडस्ट्रियल बैंक का उदाहरण मौजूद है। अतएव प्राइवेट प्रयत्न के अतिरिक्त दूसरे प्रयत्न की आवश्यकता है, जैसा कि जर्मनी इत्यादि देशों में हुआ है, इसका वर्णन बैंक और उद्योग-धंधा शीर्षक अध्याय में किया गया है। इस प्रश्न पर भारतीय सेंट्रल बैंकिंग इन्क्वायरी कमेटी ने भी अच्छी तरह विचार किया है। उसने एक सलाह तो मजबूत स्थितिवाले ज्वाइंट स्टॉक बैंकों को दी है कि वे जर्मन बैंकों की भांति (देखो पृष्ठ नं० ६२) सहायता पहुँचावें*। दूसरी सलाह प्रान्तीय सरकारों को लम्बी अवधि की सहायता के लिये "प्रान्तीय-इंडस्ट्रियल-कारपोरेशन" स्थापित करने की दी है।†

भारत के उद्योग-धंधों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:—(१) छोटे घरेलू धंधे, (२) बड़े धंधे। पहली प्रकार के धंधों को सहकारी समितियों-द्वारा सहायता दी जानी चाहिये, दूसरी प्रकार के धंधों के लिये दो प्रकार की सहायता चाहिये:—

(१) स्थायी सहायता की नवीन चालू होनेवाले धंधों—इमारत बनाने और मशीनरी खरीदने आदि—के लिये ज़रूरत होती है।

* Its report, para 391.

† Para 401.

(२) कार्यार्थ सहायता—इसकी कच्चा माल खरीदने, उसकी चीजें बनाने के लिये मज़दूरी चुकाने, उनका स्टॉक रखने और प्रत्येक दैनिक खर्च को पूरा करने के लिये ज़रूरत होती है।

पहली प्रकार की उधार को चुकाने की अवधि बहुत लम्बी होती है और दूसरे प्रकार की उधार की अवधि थोड़ी होती है, लेकिन इसमें भी कुछ रक़म तो ऐसी होती है, जो हमेशा ही लगी रहती है और लम्बी अवधि की उधार में आती है। कुछ का आव-जाव घना रहता है, वह छोटी अवधि की उधार में आती है, जैसा कि एक नवीन लेखक ने लिखा है—“कच्चा माल और धनी तथा अधवनी वस्तुओं का स्टॉक कम नहीं होता है। इस स्टॉक का कुछ भाग ऐसा होता है, जो हमेशा घना रहता है; इसलिये इसमें जो रुपया लगता है, वह स्थायी लागत में आता है। इससे ऊपर के स्टॉक में लगी हुई रक़म थोड़ी अवधि की लागत में आती है” । *

थोड़ी अवधि के लिये भारतीय-सेंट्रल-बैंकिंग-इंक्वायरी कमेटी की सिफ़ारिश के अनुसार भारतीय ज्वाइंट-स्टॉक बैंकों को सहायता पहुँचानी चाहिये और लम्बी अवधि के लिये प्रान्तीय श्रीद्योगिक बैंक होने चाहिये। तमाम प्रान्तीय श्रीद्योगिक बैंकों को एक सूत्र में बाँधने के लिये एक सेंट्रल-बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिये, जिसके द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार समस्त प्रान्तीय बैंकों का संचालन होता रहे।

* Central Banking Enquiry Committee Report, Para 336.

प्रान्तीय औद्योगिक बैंकों का संगठन*

(१) मूलधन—प्रत्येक अञ्चले, बड़े प्रान्त में एक बैंक हो और उसका मूलधन दो करोड़ रुपया हो। इसका आधा तो कार्य प्रारम्भ होने से पहले वसूल कर लिया जावे और आधा सुरक्षित जिम्मेदारी के रूप में या आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिये धाकी रक्का जावे। इस मूलधन को जैसे-जैसे आवश्यकता हो, बाद में भी बढ़ाया जा सकता है। इसके हिस्से बैंक, प्रजा, कम्पनी आदि सबके सामने खरीदने के लिये उपस्थित किये जावें; लेकिन मूलधन के $\frac{1}{3}$ से अधिक हिस्से विदेशी लोगों व संस्थाओं को न दिये जावें। हिस्से बेचने की तारीख से छः महीने के अन्दर-अन्दर जितने हिस्से बिकें, उतने बेचे जावें, शेष रहे हुए हिस्सों को प्रान्तीय सरकार खरीद ले।

(२) बोर्ड आर्वाइरेक्टर में बारह मेम्बर होंगे, जिनका चुनाव इस प्रकार होगा :—

- (अ) तीन हिस्सेदारों द्वारा ।
- (ब) एक औद्योगिक कम्पनियों द्वारा ।
- (स) एक उस प्रान्त में काम करनेवाले बैंकों द्वारा ।
- (ड) एक प्रान्तीय कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ।
- (इ) एक रिजर्व बैंक द्वारा ।

* यह स्कीम सी० बी० टी० डाकुन की पुस्तक (Organisation of Indian Banking) के इण्डस्ट्रियल बैंक्स नामक १३वाँ अध्याय से ली गई है।

(फ) एक प्रान्तीय धारा सभा द्वारा ।

(ज) दो सपरिषद् गवर्नर जनरल-द्वारा, लेकिन इनमें एक से अधिक सरकारी अफसर नहीं होना चाहिये ।

(■) एक इंडस्ट्रियल-क्रेडिट बोर्ड द्वारा ।

(य) एक डाइरेक्टर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ पन्स-ऑफिशिओ मेम्बर होगा ।

(३) बैंक का काम—उद्योग-धन्धों को उन्नति देना और इसके लिये सब प्रकार के आर्थिक साधन नीचे लिखानुसार उपस्थित करना—

(अ) माँगते ही वापस चुकाने-योग्य अमानतें स्वीकार करना, इस शर्त के साथ कि पाँच वर्ष से कम अवधि की अमानतें प्राप्त मूलधन और रक्षित कोष के बराबर से अधिक न हों । लम्बी अवधि के लिये सेविंग्स सर्टीफिकेट जारी करना ।

(ब) भारत और विदेशों में सीधे तौर पर बोलण्ड जारी करके उधार लेना और इसके लिये बैंक के पास जो भी ज़मानत हो, रहन रहना । ऐसे बोलण्ड की तादाद एक समय में कभी भी प्राप्त मूलधन और रक्षित कोष के बीस गुने से अधिक न हो ।

(स) श्रौद्योगिक कम्पनियों को उधार देना या खाता पेटे बाँकी रखना; लेकिन ऐसी उधार बीस वर्ष से अधिक मियाद के लिये नहीं होनी चाहिये ।

(ड) औद्योगिक कम्पनियों के हिस्से और डिबेन्चर खरीदना और जब कभी आवश्यकता हो, उन्हें अएडर-राइट करना ।

(इ) उन कम्पनियों के लिये व्यावसायिक वैज्ञानिक धन्या करना, जिनको आर्थिक सहायता दी गई हो या जिनके लिये उधार का प्रबन्ध किया गया हो ।

(फ) मद्दन० 'स' और 'ई' में धारित धन्या किसी स्थानीय सस्था (Local body), सरकार तथा अन्य सस्थाओं के साथ भी करना यदि इण्डस्ट्रियल बोर्ड स्वीकृति दे दे ।*

(ज) जब आवश्यकता हो, औद्योगिक सस्थाओं को अपने अधिकार में लाना, उनका प्रबन्ध, संचालन और सुधार करना ।

(ह) स्टॉक एक्सचेंज का मेम्बर होना और स्टॉक एक्सचेंज सिन्डोरिटी का धन्या करना ।

(झ) दूसरे बे काम करना, जिनके लिये इण्डस्ट्रियल बोर्ड इजाजत दे ।

(ङ) दूसरे बैंकों के साथ हिसाब रखना और देश के क्रिय रिग हाउसों का मेम्बर बनना ।

(४) बैंक के बोर्ड ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट के लिये और रिजर्व बैंक की लगती हुई रकम के जमानत-पत्र के तौर पर स्वीकार किये जावें और पहले दर्जे की जमानतों में समझे जावें ।

* जब बैंक के पास फ्राजिल रुपया हो तो वह व्याज के जुस्तान से बचने के लिये उचित जमानत-पत्रों पर रुपया लगा सके, इसलिये यह नियम तय है।

(५) रिज़र्व बैंक—इस बैंक को जब और जिस प्रकार आवश्यकता हो, सहायता देवे ।

(६) इस प्रकार के बैंकों को सफलता दिलाने के लिये प्रान्तीय सरकारों को निम्नलिखित तरीकों पर सहायता करनी चाहिये :—

(अ) हिस्सेदारों को दस या अधिक वर्षों के लिये पाँच प्रतिशत लाभ देने की गारण्टी करना ।

(ब) बैंक के बोर्ड की गारण्टी लेना, जब या जिस प्रकार भी उन्हें स्याप्रिय बनाने के लिये ऐसा करने की आवश्यकता हो ।

(स) विदेशी बाजारों से रुपया उधार लेने के लिये बैंक को अपनी साख़ उधार देना ।

(द) शल्प या दीर्घ कालिक उधार देना, जब भी ऐसी सहायता देना आवश्यक और सम्भव हो । इसके बोर्ड्स भी खरीदना ताकि उनपर जनता का विश्वास मज़बूती से बढ़े ।

(ह) बैंक को उसके लाभालाभ के प्रश्नों के परीक्षण या देख-भाल करने में सहायता देने के लिये अपने कला या उद्योग-सम्बन्धी जानकार अधिकारियों को, बिना किसी मुआवज़े के या नाम-मात्र के मुआवज़े पर (जो परिस्थितियों पर निर्भर होगा) बैंक के आधीन रखना ।

(७) बैंक का लाभ इस प्रकार बाँटा जावे :—

(अ) गारण्टी दिये हुए हिस्सों का पाँच प्रतिशत लाभ बाँटने में ।

- (ब) सरकार के उस देने के चुकाने में, जो उसने गारण्टी लिये हुए मुनाफ़े की अदायगी में दिया हो, पाँच प्रतिशत ब्याज-सहित ।
- (स) शेष में से पूरे वार्षिक लाभ का दस प्रतिशत, (इस-से अधिक नहीं) बिना अ, ब में वर्णित रकमें घटाये, रक्षित कोष में ले जाने में, जब तक वह प्राप्त मूलधन के बराबर न हो जाय ।
- (द) बाकी बचा हुआ भाग ३ : १ के हिसाब से सरकार और हिस्सेदारों में बाँट देना चाहिये । इस लाभ का भाग सरकारी आमदनी में नहीं ले जाना चाहिये, बल्कि कला-सम्बन्धी शिक्षा और औद्योगिक सुविधाओं की उन्नति करने के उपायों में, औद्योगिक बैंकों और सहकारी समितियों को उधार देने में तथा अन्य लाभदायक कार्यों में लगाना चाहिये । बैंक को उन सब करों को देने के लिये बाध्य होना चाहिये, जो उस प्रान्त के दूसरे बैंक या कम्पनियों देने को बाध्य हैं ।

इण्डस्ट्रियल-क्रेडिट-बोर्ड—समस्त प्रान्तीय-औद्योगिक बैंक इस बोर्ड के समान रूप से आधोन रहेंगे । इसके सात मेम्बर होंगे और उनका चुनाव इस प्रकार होगा :—

- (अ) २ समस्त प्रान्तीय बैंकों और प्रान्तीय सरकारों-द्वारा सम्मिलित रूप से चुने हुए प्रत्येक बैंक और

सरकार को एक-एक मत देने का अधिकार होगा ।
इन दोनों में से एक से अधिक सरकारी अफसर
नहीं होगा ।*

(ब) १ देश के इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन-द्वारा ।

(स) १ देश के दूसरे अच्छे बड़े बैंकों-द्वारा । एक बैंक को
केवल एक मत देने का अधिकार हो ।

(द) १ रिज़र्व बैंक-द्वारा ।

(य) १ केन्द्रीय धारा सभा-द्वारा ।

(फ) १ सपरिपट्टु गवर्नर जनरल द्वारा ।

(ङ) इन सात मेम्बरों के अतिरिक्त एक एक्से-ओफिशो
मेम्बर होगा, जो गवर्नर जनरल की कौंसिल का उद्योग-धन्यों
का ईंचार्ज मेम्बर होगा ।

(६) बैंक का काम एक मैनेजर चलायेगा, जो बोर्ड ऑफ़
डायरेक्टर्स-द्वारा नियुक्त होकर इण्डस्ट्रियल क्रेडिट बोर्ड-
द्वारा स्वीकृत होगा । उसके नीचे आवश्यकतानुसार अफसर
नियुक्त होंगे ।

(१०) इस बैंक को अपने प्रान्त में अपनी शाखाएँ खोलने के
सम्बन्ध में स्वतंत्रता होनी चाहिये ।

* यदि ऐसा सम्भव न हो तो प्रान्तीय सरकार और प्रान्तीय श्रीयोगिक
बैंक मलग-मलग एक-एक मेम्बर चुन सकते हैं ।

पन्द्रहवाँ अध्याय

सुधार के उपाय—अन्य प्रयत्न

पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक*

पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक के सम्बन्ध में तीसरे अध्याय में प्रकाश डाला गया है, वहाँ पर बताया गया है कि इनके बढ़ने की अभी बहुत गुंजाइश है। इनके बढ़ाने के लिये निम्नलिखित सुधार होने की आवश्यकता है :—

चेक द्वारा जमा व बरामद—अभी भारत में सेविंग्स बैंक के खातेदार अपने खातों में चेक-द्वारा लेन-देन नहीं कर सकते। सरकार को चेक-प्रणाली का उत्तेजना देने के लिये यह बाधा दूर करनी चाहिये। ब्रिटिश पोस्ट आफिस में रकम चेक-द्वारा जमा की जाती है, केवल उन चेकों को रकम दस रोज़ तक बरामद नहीं कराई जा सकती, इसलिये कि इस अर्थ में पोस्ट आफिस चेकों का परिणाम मालूम कर सके। ऐसा ही अमल भारत में होना चाहिये।

वार्षिक जमा की सीमा—इस समय एक खातेदार अपने सेविंग्स बैंक के खाते में ५५०) प्रति वर्ष से अधिक जमा नहीं कर

*यह भाग सी० टी० ठाकुर की Organisation of Indian Banking नामक पुस्तक के अध्याय १४ से लिया गया है।

सकता। यह रुकावट अनावश्यक है। मान लीजिये एक गरीब आदमी को इतिफ़ाक से कुछ हजार रुपये मिल जाते हैं। उनमें से वह पोस्ट आफ़िस सेविंग्स बैंक के खाते में केवल ७५०) ही जमा कर सकता है। शेष के लिये वह दूसरा इन्तिज़ाम करेगा या गाड़ेगा। ब्रिटिश पोस्ट आफ़िस में यह सीमा ५०० पाँड तक है। इसकी तुलना में ७५०) बहुत कम है; इसलिये यह सीमा ५०००) वार्षिक होनी चाहिये।

अधिक से अधिक जमा की सीमा—इस समय एक पाने में ५०००) से अधिक रकम कमी भी जमा नहीं की जा सकती। यदि खाता नाथालिग के नाम से खोला जायेगा तो उसमें १०००) से अधिक जमा नहीं हो सकता। इन सीमाओं से बचत करने की आदत को यथोचित उत्तेजना नहीं मिल रही है। ब्रिटिश पोस्ट आफ़िस में इस प्रकार की सीमा नहीं है। इसके पक्ष में यह दलील दी जाती है कि यदि जमा करनेवाले लोग पोस्ट आफ़िस से एक दम अधिक तादाद में रुपया माँग लें तो उसको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस कठिनाई का निराकरण एक निश्चित रकम—कम से कम ५०००) से अधिक माँगने की हालत में एक सप्ताह पहले नोटिस दिया जाने का नियम रखा जाकर किया जा सकता है।

जमाशुदा रकम की कुर्की—भारतीय पोस्ट आफ़िस सेविंग्स बैंक में जमा-शुदा रकम की उचित अदालत के हुक्म से कुर्की हो सकती है। इसके लिये ब्रिटिश पोस्ट आफ़िस में

स्पष्ट नियम यह है—A Deposit Book is not a proper Security for money lent, and no claim by any person holding a deposit book in respect of a loan can be recognised. Deposits in the post office savings banks are not liable to 'attachment' or to its Scottish equivalent 'arrestment' अर्थात्—“एक जमा बुक उधार दी हुई रकम के लिये उचित सीन्यारिटी नहीं है, इसलिये किसी जमा-बुक पानेवाले व्यक्ति का उधार-सम्बन्धी कोई दावा उचित नहीं माना जावेगा। पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में जमा-शुदा रकमें, कुर्की होने योग्य नहीं हैं।”

भारत में ब्रिटिश कानून की पूरी नकल करने की आवश्यकता नहीं है, इससे लोग अपन पावनेदारों को अधिक धोखा दे सकेंगे, लेकिन फिर भी लोगों का अपने कुटुम्ब के आकस्मिक खर्च के लिये कुछ बचाकर रखने के लिये कम से कम ५०००) की रकम ऐसी हानी चाहिये, जिसको कुर्क न कराया जा सके। बहुधा देखने में आया है कि जब एक व्यक्ति किसी कारण से बहुत कर्जदार हो जाता है और अदालतें उसकी सारी जायदाद कुर्क करने का हुक्म दे देती हैं तो उस समय वह और उसका परिवार निःसहाय हो जाता है, उसके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलने पाती और वह दाने-दाने को तरसते रहते हैं। ऐसी भीषण परिस्थिति में पडकर वह परिवार उदर-पोषण के लिये नाना प्रकार के पाप करने को उतारु हो जाता

है और समाज में अशान्ति पैदा करने का कारण बन जाता है। अतएव बढ़ती हुई दम्बिता का रोकने के लिये पोस्ट आफिस में जमा शुद्ध प्रस्तावित रकम को कुर्की से मुस्तसना करना अनुचित नहीं है, जब कि प्रिटेन जैसे न्याय निपुण देश में भी ऐसा कानून है।

ग्रामीण जनो को सुविधा—प्रत्येक गाँव में पोस्ट आफिस न होने से ग्रामीण जनता अपनी वचत को अधिकांश में जमोन में गाड़ देती है, क्योंकि वह दूर न गाँव में रुपया ले जाकर जमा कराना दिक्कत तलब समझती हैं, इसलिये पोस्ट मेन द्वारा सेविंग्स-बैंक में रुपया जमा व बरामद कराने की उचित सुविधा होनी चाहिये।

वेड्जर्स-एसोसियेशन

भारतीय उद्योगिक वर्गों का प्रतिपक्ष फेल होने की वरुण कदा पिछले पन्नों में पूर्णरूप से वर्णन की जा चुकी है। इसने अनेक कारणों में से एक कारण भारतीय-बैंकों के बीच में आपसी सहयोग का अभाव है। जब किसी एक पर आपत्ति आती है तो दूसरे उसको और उदासीन होकर तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन उसको येन इन प्रकारेण सहायता देकर बचाने की चेष्टा नहीं करते। यही कारण है कि अनेक भारतीय-बैंकों का, सतोष जनक पूँजी रहत हुए भी, नकद रुपये का अभाव में दिवाला निम्न जाता है, अतएव भारतीय बैंकों का कर्तव्य है कि वे एक सूत्र में बाँधकर रहें और विपत्ति काल में एक

दूसरे की सहायता करने के हेतु तत्पर रहें। इसके लिये आवश्यक है कि ब्रिटिश बैंकर्स-एसोसियेशन के समान भारतीय बैंकर्स का भी एक एसोसियेशन स्थापित किया जावे, जो इस धन्धे की रक्षा और उन्नति के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहे। जहाँ हमारे देश में अनेक व्यापारिक एसोसियेशन-चेम्बर ऑफ कामर्स, मिल-घोमर्स-एसोसियेशन, शेयर-होल्डर्स-एसोसियेशन और काटन-एसोसियेशन आदि हैं, जो अपने-अपने व्यवसाय की वृद्धि और रक्षा के लिये सदैव उद्योग करते रहते हैं वहाँ भारतीय बैंकर्स की शक्ति का, संयुक्त-हिता की रक्षार्थ संगठित न होना दुःख की बात है। जिस दिन यह संगठित होकर एक दूसरे के लाभ और भलाई के लिये प्रयत्न करेंगे और यह सोचेंगे कि किस प्रकार अपनी और अपने धन्धे की उन्नति करनी चाहिये, उस रोज़ निश्चय ही भारतीय बैंकिंग की पिछड़ी हुई अवस्था उन्नति की ओर झुड़म बढ़ाना शुरू कर देगी; क्योंकि व्यक्तिगत प्रयत्न की अपेक्षा सम्मिलित और संगठित शक्ति अधिक प्रभावशाली होती है।

एसोसियेशन की स्थापना के लिये यह अधिक उपयोगी प्रतीत होता है कि प्रत्येक प्रांत में बैंकिंग-एसोसियेशन स्थापित हो और उस प्रांत के समस्त बैंकर्स ज्वाइंट-स्टॉक बैंक व देशी बैंकर्स उसके नियमानुसार सदस्य हों और समस्त प्रांतीय एसोसियेशन मिलकर अखिल भारतवर्षीय बैंकर्स-एसोसियेशन की स्थापना करें। इसका प्रांतीय एसोसियेशन-द्वारा निर्वाचित

एक कार्यवाहक बोर्ड हो, जिसका चर्च भर में एक बार या जब भी आवश्यक हो, अधिवेशन बुलाया जावे। इन प्रान्तीय एसोसियेशन के मेम्बरों को अपने नाम के आगे “वैकर्स एसोसियेशन के मेम्बर” शब्द का प्रयोग करने की आज्ञा होनी चाहिये।

देशी भाषाओं को अपनाया जावे

सातवें अध्याय में भारतीय-वैकिंग की पिछड़ी हुई अवस्था के बताये हुए अनेक कारणों में से एक कारण अंगरेजी भाषा का प्राधान्य घतलाया गया है। वास्तव में अंगरेजी न पढ़े हुए लोग पैदों से लेन-देन करने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि उनके लिये अनेक प्रकार की अड़चनें उपस्थित होती हैं। इम्पीरियल पैद तो इस सम्बन्ध में बहुत ही सख्ती से काम लेता है। इसलिये सर्व साधारण और पैदों के बीच निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने के लिये यह आवश्यक है कि तमाम भारतीय-वैक अंगरेजी न जाननेवालों के साथ देशी भाषा में व्यवहार करें। पास बुकें, चेक बुकें, और अन्य आवश्यक फार्म देशी भाषा में छपावें और उनमें इन्द्राज देशी भाषा में करें। देशी भाषा में आये हुए पत्रों का उत्तर देशी भाषा में दें। कम्पनियों के नियम (articles of association) संस्थाओं के प्रस्ताव देशी भाषा में स्वीकार किये जावें।

देशी भाषा से अभिप्राय प्रांतीय भाषाओं से है जैसे बङ्गाल में बंगला, गुजरात में गुजराती, संयुक्त प्रान्त में हिन्दी व उर्दू, पंजाब में उर्दू, महाराष्ट्र में मराठी आदि, लेकिन हिन्दी भाषा को सब प्रान्तों में अपनाया जावे; क्योंकि यह भाषा बहुत सरल है इसलिये हर जगह आसानी से बोली और समझी जा सकती है तथा भारतीय कांग्रेस के निर्णयानुसार देश की राष्ट्र भाषा होने की अधिकारिणी है।

इसमें बैंकों को कोई असुविधा और कष्ट नहीं होगा। कोटा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० कोटा अपने जन्म-काल से ही हिन्दी में काम करता है। यह बैंक भी उवाइन्ट-स्टॉक और प्रांतीय कोऑपरेटिव बैंकों के समान सब प्रकार का बैंकिंग धन्धा करता है। जैसे—सेविंग्स-बैंड, चल्लू-खाता और मियादी-अमागत जमा रखना, अपने मेम्बरों को कूपोत्पादक वस्तुओं, सोना, चाँदी, और उनके गहने तथा अन्य आवश्यकता की वस्तुओं पर उधार देना, चेक, एण्डी, बिलस का संग्रह करना और देश के अन्दर भुगतान का काम करना आदि। इसको अब तक कोई दिक्कत नहीं आई और न कभी कोई जाल हुआ। बड़ी सुगमता से काम चल रहा है। अतः कोई कारण नहीं है कि दूसरे बैंकों में इस प्रकार काम न चले। यदि बैंक के कर्मचारी भारतीय हैं और उस प्रांत के नहीं हैं जहाँ के बैंकों में काम करते हैं तो वह बहुत जल्दी उस प्रांत की भाषा को सीख सकते हैं।

सोलहवाँ अध्याय

उपसंहार

पिछड़ी हुई भारतीय-बैंकिंग को उन्नत करने के कुछ प्रयत्न इस पुस्तक के पिछले पन्नों में बतलाये गये हैं। उनमें अधिकांश सरकार पर निर्भर हैं। उनके लिये यह मान भी लिया जाये कि सरकार तदनुसार सुधार कर देगी तो भी वह पर्याप्त नहीं होगा। भारतीय-बैंडिंग की वास्तविक सफलता भारतीय प्रजा-जनों के हाथ में है। बिना इनके विश्वास और सहायता के इस धन्धे की पूर्ण रूप से उन्नति होना नितान्त अशक्य है। क्योंकि इसकी दुरावस्था के अनेक कारणों के साथ-साथ भारतीय-प्रजा का अपने बैंकों के प्रति कम विश्वास रखना भी एक प्रधान कारण है। यह ठीक है कि जो व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से बचकर कुछ पूँजी संग्रह करता है, वह उसको कमज़ोर बैंकों में जमा रखने की जोखिम उठाने से डरता है; लेकिन यह समझ में नहीं आता है कि एक बैंक केवल इस आधार पर कि उसका संचालन अंगरेज़ों द्वारा होता है अच्छी स्थिति वाला समझा जाता है और दूसरा बैंक भारतीय प्रबन्ध के अधीन होने से कमज़ोर माला किया जाता है। भारतीय लोगों की इस भ्रमता का

कारण भारतीय बैंकों का फेल होना बतलाया जाता है और जिसको विदेशी सस्थाओं के हितैषियों ने अधिक महत्व दे दिया है। यदि विचार पूर्वक देखा जावे तो भय खानेवाली कोई बात नहीं है। भारतीय प्रबन्ध के आधीन केवल एक दो उदाहरण ही ऐसे मिलेंगे जिनमें बेईमानी या भ्रष्टता हुई हो। बेईमानी या कुप्रबन्ध का ठेका अकेले भारतवासियों ने तो ले ही नहीं लिया, ससार के समस्त देशों में ऐसा ही नहीं बल्कि इससे भी अधिक होता है। ग्रेट-ब्रिटेन में भी उसके व्यापारिक विस्तार के अनुसार अनगिनत सख्या में बैंक फेल हुए हैं। अमेरिका में व्यापारिक मंदी के साथ-साथ उत्तरोत्तर बैंक फेल होते जा रहे हैं।

अतएव भारत के लिये यह कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ चढ़ बैंकों का दियाला निकलना, दूसरे देशों की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक बैंक पंजाब में फेल हुए हैं वहाँ इनकी जाँच के लिये सन् १९१३ ई० में एक कमेटी बैठी थी, उसकी सम्मति है कि सन् १९१३ ई० में बैंकों के फेल होने के कारण में भारतीय कर्मचारियों की अयोग्यता या अकर्मण्यता नहीं थी, बल्कि ऐसे अनिवार्य कारण थे जो ऐसे उद्योगों की प्रारम्भिक अवस्था में प्रत्येक देश में होते हैं।

एक ओर तो हमारी यह दशा है कि बेईमानी इत्यादि कोई विशेष शिकायत नहीं होते हुए भी हम अपने बैंकों पर जैसा चाहिये वैसा विश्वास नहीं करते, हालांकि भारतीय बैंकों की

वैलेंस-शीट विदेशी पैकों की अपेक्षा अधिक स्थिति-सूचक होती है, जिससे इनकी आन्तरिक अवस्था का बहुत कुछ ज्ञान हो जाता है। इनके हेड आफिस भारत में ही हैं। इनके वार्षिक अधिवेशन में जाकर इनकी स्थिति के संबंध में और आवश्यक बातें मालूम की जा सकती हैं। दूसरी ओर विदेशी-बैंकों पर बिना किसी सोच-विचार के सहज ही विश्वास कर लिया जाता है। इनकी वैलेंस-शीटों से इनकी वास्तविक स्थिति का मालूम करना आसान नहीं है। इनके हेड आफिस विदेशों में हैं, जहाँ हम में से अधिकांश भारतीयों की पहुँच नहीं है और न हम इनके व्यवस्थापकों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी ही रखते हैं। ये सब बातें ऐसी हैं, जिनसे होना ता यह चाहिये था कि हमारा विदेशी-बैंकों पर संदेह और कुछ कम विश्वास होता; किन्तु जो कुछ हो रहा है, वह उल्टा है। हमारे इस रुढ़ से हमारे देश के राष्ट्रीय उद्योग-धंधे आर्थिक सहायता के अभाव से पनपने नहीं पाते हैं और विदेशी उद्योग-धंधे फलते-फूलते जाते हैं।

तात्पर्य यह है कि भारतीय-वैकिंग का उत्थान भारतीय प्रजा-जनों के दार्शनिक सहयोग और सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार पर निर्भर है। इसके लिये आवश्यकता है कि हमारी मनोवृत्ति में स्थायी परिवर्तन हो और हम अपने को, अपनाना सीखें। हमें चाहिये कि संकट के समय हम अपने बैंकों की सहायता करें ताकि उनके पैर दृढ़ता के साथ जम जायें, न कि घबरा कर उनके दूधने के कारण बनें।

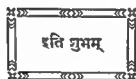
प्रचार की आवश्यकता

भारतीय प्रजा-जनों की उक्त मनोवृत्ति को उचित रूप में परिवर्तन करने के लिये गहरे प्रचार की आवश्यकता है, जिसका कि अभी तक पूर्ण अभाव रहा है। दुःख की बात है कि भारत को प्रभावशाली संस्था कांग्रेस ने भी यह अनुमय नहीं दिया कि जिस प्रकार आर्थिक-स्वतंत्रता के बिना राजनैतिक-स्वतंत्रता कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार वैकिंग-स्वतंत्रता के बिना आर्थिक-स्वतंत्रता भी कुछ नहीं है। स्वदेशी की सीमा केवल उद्योग-धंधों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसमें उद्योग-धंधों को पालन-पोषण करनेवाले बैंक, बीमा और जहाज़ी कंपनियाँ भी शामिल हैं, इसलिये स्वदेशी के प्रचार के समान भारतीय-वैद्यों को अपनाने के सम्बन्ध में कांग्रेस तथा दूसरी संस्थाओं के अधिवेशनों पर गहरा प्रचार होना चाहिये। प्रत्येक स्वदेशी-प्रचारक-संस्था और भारतीय-व्यापारिक-संस्था को चाहिये कि वह अपने यहाँ ऐसे प्रस्ताव पास करे कि जिससे उनके सब मेम्बर अपना लेन-देन केवल भारतीय-वैद्यों से रखने के लिये वाञ्छ्य हों, जैसे कि स्वदेशी वस्तु व्यवहार की प्रतिज्ञा कराई जाती है।

पाठकों ! जिस रोज़ हम अपने वैद्यों पर पूर्ण विश्वास करने लग जावेंगे, निश्चय जानिये कि उस रोज़ इस देश का आर्थिक

संकट टल जावेगा, उद्योग-धंधों की उन्नति होगी और बेकारी नौ दो ग्यारह हो जावेगी ।

अंत में बैंकों के कार्य-कर्त्ताओं संचालकों और निरीक्षकों से भी निवेदन है कि देश का आर्थिक-जीवन आपके हाथ में है । इस देश की धनराशि का देश के हित में उपयोग होना केवल आपकी कार्य-कुशलता, सावधानी और ईमानदारी पर अवलम्बित है, इसलिये वंधुओं आपकी ओर से कोई ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिये, जिससे भारतीय बैंक बदनाम हों और इस धन्दे को ठेस पहुँचे ।



परिशिष्ट नं० १

साख-पत्र

दर्शनी हुन्डी

श्री

१॥ सिष्य श्री बम्बई बम्बर सुभ स्थाने भाई मारायण दास गणेशदास जोग श्री फोटा सू लखतू गणेशदास शिवप्रसाद को जै गोपाल धन्वाधजो उपरंख हुन्डी एक रुपया १०००) अक्षरे रुपया एक हजार की नेमे रुपया पाँच सो का दूणा पूरा इठे राख्या भाई सोभागमल चांदमल पास मित्ती आसोज बदी १ सं० १६७६ पूर्या तुरत साह जोग रुपया हुन्डी चलण का दीउयो समयत १६७६ आसोज बदी १॥

(२)

दर्शनो हुण्डी की पुस्त

रु० १०००)

नेमे नेमे रुपया दो सो पचास का चोगणा पूरा रुपया एक
हजार कर दीजो ।

भाई नारायण दास गणेश दास
वम्बई

मुदती हुणडी

श्री परमेश्वर जी

१॥ सिद्ध श्री वम्बई वन्दर शुभ स्थाने भाई नारायण दास गणेशदास जोग श्री कोटा से लखतू गणेश दास शिव प्रसाद को जै गोपाल धंवावजो उपरच हुणडी १ रुपया १०००) अक्षरे रुपया एक हजार का नेमे रुपया पांच सो का दूणा पूरा इठे राखया भाई सोभागमल चाँद मल पास मिती आसोज यदी १ सम्मत १६७६ से ६१ दिन पीछे पाँचे दाम की नामे धनो शाह जोग ठिकाना लगाये चौकसी कर दाम देना । हुणडी लिखो मिती आसोज यदी १ सम्मत १६७६ ॥

मुहत्ती हुण्डो की पुस्त

रु० १०००)

नीमे का नीमे रुपया दो सौ पचास का खोगना पूरा रुपया
एक हजार कर दीजो

भाई नारायण दास गणेश दास
वम्बई

(५)

(स) पैठ

श्री

सिन्धु श्री यम्बई बम्बर शुभ स्थाने भाई नारायण दास गणेश दास जोग श्री कोटा से लखतूँ गणेशदास शिवप्रसाद को जै गोपाल बंछायजो उपरंच हुण्डी १ रुपया १०००) अक्षरे रुपये एक हजार की नीमे रुपया पाँच सौ का दूणा पूरा इठे राख्या सांभाग मल चांदमल पास मिती आसोज बदी १ सम्यत् १६७६ पूर्वां तुरत नामे धनी साह जोग ठिकाना लगाय चोकसकर सिकार दाम देना । मिती आसोज बदी १ सम्यत् १६७६ को लिखी थी सो उपर वाला धनी कहता है कि हुण्डी यो गई सो हुण्डी यो गई होये तो अपना रोकड़ नरुल रोजनामचा सब यहियां देकर इस पैठ परमाणे सिकार दाम दीजो । यदि हुण्डी सिकर गई होवे तो पैठ रद्द समझना और पैठ सिकर जावे तो हुण्डी रद्द समझना । सनद नग दो तुम्हारे ऊपर कीनी छै जिसमें १ सनद का दाम मुजरा देस्यां सम्मत १६७६ आसोज सुदी १

पेठ की पुस्त

पेठ छुः

नीमे का नीमे रुपया दो सो पचास का खोगणा पूरा रुपया
एक हजार कर दीजो ।

भाई नारायण दास गणेश दास

बम्बई

परपेठ

श्री

सिद्ध श्री बम्बई बन्दर शुभ स्थाने भाई नारायण दास गणेश दास जोग श्री काटा सँ लम्बतू गणेश दास शिख प्रसाद को जैगोपाल बचावजो उपरंच हुण्डी १ रु० १०००) अक्षरे रुपया एक हजार का नीमे रुपया पाँच सो का देवणा पूरा इठे राख्या सोभागमल चाँदमल पास निनी आसोज बदी १ स० १६७६ पूर्या तुरत नामे घनी शाहजोग डिगना लगाय चोकस कर रुपया हुण्डी चलण की लिखी इती जिणा की पेठ लिपी मिती आसोज सुदी १ स० १६७६ मो राख्या गाला घनी कहना है कि हुण्डी तथा पेठ दोनों खो गई है सो हुण्डी तथा पेठ दोनों खो गई होये तो अपना रोकड, नरल, राजनामचा सब बहियाँ चोकस कर इन परपेठ प्रमाणे सिकार दाम दीजो। यदि हुण्डी सिकर गई हो तो पेठ और पर पेठ रद्द है, पेठ सिकर गई हो तो हुण्डी और परपेठ रद्द है, और यदि परपेठ सिकर जाये तो हुण्डी और पेठ रद्द है। सनद नम ३ तुम्हारे उपर कीनी जिनमें सनद नम १ का दाम मुजग भर देस्या। सम्यत् १६७६ आसोज सुदी ११।

(=)

पुस्त परपेठ

परपेठ

नीमें का नीमे रुपया दो सौ पचास का चोगणा पूरा रुपया
एक हजार कर दोजो ।

माई नारायण दास गणेश दास
वम्बई

मेजर

थी

१॥ सिध्द थी यमई यन्दर शुभ स्थाने सरख ओपमान लायक सकल सराफे का पच समसत, जोग थी कोठा से लखतू सकल पच समस्त का जोहार याच जो। उपरच हुएडी १ रुपया १०००) अन्तरे रुपया एक हजार की नारायण दास गणेश दास उपर लिखी, इठा लूँ गणेश दास शिव प्रसाद की, राख्या सामागमल चादमल पास आसोज बदी १ सम्मत् १६७६ की पूषा तुरत नामे धनी शाह जोग हुएडी चलण की थी, जिसकी पेठ लिखी मित्ती आसोज सुदी १ और परपेठ आसाज सुदी ११ की लिखी थी सो राख्या वाला धनी कदता है कि हुएडी तथा पेठ तथा परपेठ तीनों प्यो गई है सो हुएडी, पेठ तथा परपेठ प्या गई होयें तो उनका रोकड, नरल रोजनामचा तथा सब बहियाँ चोफस कर इस मेजर परमाणे सीकार दाम दीजो। यदि हुएडी, पेठ तथा परपेठ में स कोई पहले सिक्करी हाये तो मेजर रह है याच कर फेर दीज्यो। सनद नग ४ तुम्हारे उपर करी है जिनमें से सनद नग १ का दाम भर देस्या। सम्मत् १६७६ काती बदी १।

साख १—मगनी राम बभूत सिंह की

साग १—नल्लमन दास समीर मल की

साख १—गणेश दास किमना जी की

साग १—शिव लाल मोती लाल की

साग १—धनरूप मल राज मल की

प्रोनोट (Pronote)

र०)

बम्बई ता०

मैं/हम

इफ्तार करता हूँ/करते हैं कि तलब करते ही दी स्वदेशी बैंक
लिमिटेड को अक्षरे रुपये
जो मैं/हम ने उक्त बैंक से उधार लिये हैं) प्रति सैकड़ा
मासिक व्याज सहित (जो लु माही चक्रवृद्धि व्याज से होगा)
अदा कर दूंगा/देंगे ।

द० उधार लेने वाले के

(मय पता)

No. _____

Bombay _____ 1934.

The Swadeshi Bank Limited Bombay.

Pay _____ or bearer.

Sum of Rs _____

Rs.

(१२)

देशी-विनिमय बिल

Stamp.

No. 390.

Kotah January 16 1932.

Rs. 10000

One month after date pay to J. M. Mehta
or order the sum of ten thousand rupees Value
received

Gupta & Sons

To

Messrs, Roy Martin & Co.,

53 Simla street,

CALCUTTA

(१३)

विदेशी-विनिमय बिल

पहली प्रति

Stamp.	No 139	Calcutta, January 19, 1932
	£ 5000.	43, 2, Clive Street

Thirty days after Sight of this First of Exchange, Second and Third of the Same Tenor and date unpaid, pay to the order of Messers, Aukland & Co., the Sum of Five Thousand Pounds. Value received

Ghosh and Midland

H Ghosh

To.

M/S. James Wallis & Co.,

50 Ladney Avenue

LONDON.

(१४)

विदेशी-विनिमय बिल

दूसरी प्रति

Stamp	No 139.	Calcutta January 19, 1932
	£ 5000.	43, 2, Clive Street.

Thirty days after Sight of this Second of Exchange,
First and Third of the same Tenor and date unpaid,
pay to the order of Messers Aukland & Company
the Sum of Five Thousand Pounds Value received

Ghosh & Midland
L Ghosh

To,

Messers James Wallis & Co.,
50 Lidney Avenue,
LONDON.

(१५)

विदेशी-विनिमय विल

तीसरी प्रति

Stamp.

No 139.

£ 5000.

Calcutta, January 19, 1932.

43, 2, Clive Street.

Thirty days after Sight of this Third of Exchange, First and Second of the Same tenor and date unpaid, pay to the order of Messers Auklaud & Co., the Sum of Five Thousand Pounds Value received

Ghosh & Midland

H Ghosh

To,

M/S James Wallis & Co ,

Lidney Avenue,

LONDON.

परिशिष्ट नं० २

स्थिति-सूचक-पत्र

मासिक-स्टेटमेंट

अमुक बैंक*

मासिक-स्टेटमेंट

ता० ११३४ ई०

देना	रुपये	लेना	रुपये
विका हुआ मूलधन	...	रोशन हाथ में और सेंट्रल तथा मित्रपरिण बैंकों में	...
प्राप्त मूलधन	..	रोशन इस्तरे बैंकों में	...
रक्षित कोष	...	लगी हुई पूँजी—	...
जमा	...	तुरंत नकद में परिवर्तन होने योग्य जमानतों पर	...
चलाने	..	इस्तरी तरह पर	...
सेविंग्स	...	डिस्काउण्ट किये हुए बिलस	...
मियादी	...	खता देते और ओवर ड्राफ्ट	...
दीगर देना	...	ग्रहण	...
मीजान	...	दीगर सम्पत्ति	...
		मीजान	...

परिशिष्ट नं० ३

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
३६	२१	वैदु में	वैदु के
"	२२	का बहुमत	में बहुमत
४४	१७	उधार को हुई	उधार ली हुई
४६	७	दिया जावेगा	दे सकेगा
५०	३	लेने वालों का	लेने वालों की
५६	६	चुकाती हैं	लेती हैं
६४	६	फलक	फलक
१००	४	को	की
"	"	अप्रेज़ो	अप्रेज़ी
११७	१६	दुरावस्था	दुरावस्था
१३१	१०	उपयुक्त होना	उपयुक्त कानून होना
१५१	३	न लगाये जाने	लगाये जाने
१७०	६, ८, ११	रजिस्टर्ड	रजिस्ट्री
१८०	८	बक	वैदु
१८०	१४	क्षयाल	क्षयाल
१८५	७	यजित	यजित
१८६	१७	ज़मानतों का	ज़मानतों की
१९०	२१	अपने हिस्सा	अपनी हिस्सा—पूँजी

पृष्ठ	लाइन	अशुद्ध	शुद्ध
२०१	११	वैङ्क-कानून	वैङ्क, कानून
२२१	१७	दानों	दोनों
२२५	१८	अधिक कम	अधिक व कम
२३३	१०	फॉय	कार्य
२३८	७	लागों	लोगों
२४४	१५	राजनितिक	राजनैतिक
२४५	१४	"	"
२४६	१,२	"	"
२५४	१२	करनी	होगी
२५६	११	सहकारी श्रौर विभाग	सहकारी विभाग
२६६	१३	उसी समय	उसी समय के
२७०	२१	पूँजी भी	पूँजी की

समर्पण की पहली लाइन में बी० ए० के बजाय बी० एजी० पढ़िये

भारतवर्षीय हिन्दी-अर्थशास्त्र-परिषद्

(सन् १९२३ ई० में संस्थापित)

सभापति

श्रीयुत पंडित दयाशङ्कर दुबे, एम० ए०, एल०एल० बी० अर्थ-शास्त्र अध्यापक, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग ।

मंत्री :—

(१) श्रीयुत जयदेव प्रसादजी गुप्त, एम० ए०, बी० काम०, एस० एम० कालेज, चंदौसी ।

(२) साहित्यरत्न पंडित उदयनारायण जी त्रिपाठी एम० ए० अध्यापक, दारामंज हाई स्कूल, दारामंज, प्रयाग ।

इस परिषद् का उद्देश्य है जनता में हिन्दी द्वारा अर्थशास्त्र का ज्ञान फैलाना और उसका साहित्य बढ़ाना । कोई भी सज्जन १) प्रयेश शुरू देकर इस परिषद् का सदस्य हो सकता है । जो सज्जन इसे कम से कम १००) की आर्थिक सहायता देते हैं, वे इसके संरक्षक समझे जाते हैं । प्रत्येक सदस्य और संरक्षक को परिषद् द्वारा प्रकाशित या संपादित पुस्तकें पौने मूल्य पर दी जाती हैं ।

परिषद् की संपादन समिति द्वारा सम्पादित होकर निम्न लिखित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं :—

(१) भारतीय अर्थशास्त्र (दो भाग) ।

(२) विदेशी विनिमय ।

(३) अर्थशास्त्र शब्दावली ।

(४) कौटिल्य के आर्थिक विचार ।

(५) भारतीय बैंकिंग ।

(६) संपत्ति का उपयोग ।

इनके अतिरिक्त, निम्न लिखित पुस्तकों का सम्पादन हो रहा है:—

(७) भारत की जनता ।

(८) राजस्व शास्त्र ।

(९) अंक शास्त्र ।

(१०) भारत के उद्योग धंधे ।

हिन्दी में अर्थशास्त्र सम्बन्धी साहित्य की कितनी कमी है, यह किसी साहित्य प्रेमी सज्जन से छिपा नहीं है। देश के उत्थान के लिये इस साहित्य की शीघ्र वृद्धि होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक देश प्रेमी तथा हिन्दी प्रेमी सज्जन से हमारी प्रार्थना है कि वह इस परिपद का संरक्षक या सदस्य होकर हम लोगों को सहायता देने की कृपा करें। जिन महाशयों ने इस विषय पर कोई लेख या पुस्तक लिखी हो, वे उसे समापति के पास भेजने की कृपा करें। लेख या पुस्तक परिषद् द्वारा स्वीकृत होने पर सम्पादन समिति द्वारा बिना मूल्य सम्पादित की जाती है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण परिपद अभी तक कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं कर पायी है, परन्तु वह प्रत्येक लेख या पुस्तक को सुयोग्य प्रकाशक द्वारा प्रकाशित कराने का पूर्ण प्रयत्न करती है। जो सज्जन अर्थशास्त्र सम्बन्धी किसी भी विषय पर लेख या पुस्तक लिखने में किसी प्रकार की सहायता चाहते हों, वे नीचे लिखे पते से पत्र व्यवहार करें।

दयाशंकर दुवे, एम० ए०

दारागज, प्रयाग ।